शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION

समग्र शिक्षा
समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा ओड़िशा

वार्षिक रिपोर्ट २०२५-२६



ओड़िशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओसेपा)
शिक्षा सौध, यूनिट - V, भुवनेश्वर, ओड़िशा, 751001
वेबसाइट : www.osepa.odisha.gov.in

समग्र शिक्षा
ओड़िशा

वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

ओड़िशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओसेपा)
शिक्षा सौध, यूनिट - V, भुवनेश्वर, ओड़िशा, 751001
वेबसाइट: osepa.odisha.gov.in

मुख्य संपादक

श्रीमती अनन्या दास, आईएएस
राज्य परियोजना निदेशक, ओसेपा

संपादक - मंडल

- श्रीमती संगीता बेहरा
अपरनिदेशक (सामान्य)
- श्रीमती अमिता पटनायक
अपरनदिशक (गुणवता)
- डॉ. जस्मीन पट्टनायक
संरुक्तनिदेशक (प्रशासन)
- श्रीमती सुदेश्ना कर
वित्तीय सलाहकार एवंमुख्यलेखाअधिकारी (FA & CAO)
- श्री प्रणय कुमार नायक
संरुक्त निदेशक (योजना एवं विधि)
- डॉ. संतोष कुमार राउत
संरुक्तनिदेशक (बालिकाशिक्षाएवं REA)
- श्रीमती सस्मिता साहू
संरुक्तनिदेशक (एमआईएस, आईसीटीएवंवीएसके)
- श्रीमती प्राचीतनया गिरि
संरुक्तनिदेशक (समता, सामुदायिकसहभागिताएवंपहुँच)
- श्रीमती निरुपा बेहरा
संरुक्त निदेशक (शैक्षणिककार्य)
- श्री हिमांशु भूषण सामर्थ
संरुक्तनिदेशक (शिक्षकप्रशिक्षण)
- श्रीमती ममता मिश्रा
संरुक्तनिदेशक (SSH)
- श्री सुषांत कुमार घुटा
संरुक्त निदेशक (समावेशीशिक्षा – IE)
- श्री बिश्वनाथ साहू
संरुक्त निदेशक (सिविल)
- श्री प्रदोषकुमार नायक
उपनिदेशक (पुस्तकालय)
- श्रीमती इतिश्री नायक
उपनिदेशक (प्रशासन एवं पाठ्यपुस्तक)
- श्री तन्मय कुमार बेहरा
उपनिदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)
- श्रीमती शैलाधिराज तनयासत्पथी
उपनिदेशक (शैक्षणिककार्य)

सदस्य संयोजक (Member Convener)
श्री दीपक राय
सहायक निदेशक (योजना)

समन्वय (Coordination)
- श्रीमती निबेदिता महापात्र- वित्तअधिकारी
- श्री मतीएस.एस.स्वरूपा- योजना समन्वयक
- श्री रंजन कुमार पाणि- वित्तीय परामर्शदाता
- श्री प्रफुल्लकुमार सेनापति- वरिष्ठ कार्यक्रम सहायक
- सुश्री सरिता सत्पथी- शैक्षणिकसमन्वयक
- सुश्री नमिता पांडा- प्रोग्रामर







Dr. N. Thirumala Naik, IAS
Commissioner-cum-Secretary to Govt
-cum-Vice Chairperson, OSEPA

ओड़िशा सरकार
स्कूल और गण शिक्षा विभाग,
लोक सेवा भवन, भुवनेश्वर-1
कार्यालय : 0674-5236631
ई-मेल : secysme@gmail.com

संदेश

शिक्षा एक न्यायसंगत, समावेशी, प्रगतिशील एवं सशक्त समाज के निर्माण का आधार है। ओडिशा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, समावेशी एवं अनुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। समग्र शिक्षा इस दृष्टिकोण को साकार करने का एक प्रमुख माध्यम है, जिसके अंतर्गत शिक्षा तक पहुँच एवं समानता को सुदृढ़ करने, अधिगम परिणामों में सुधार लाने, शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करने, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN) को बढ़ावा देने, डिजिटल एवं कौशल शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विद्यालयी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, समावेशन एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। निपुण ओडिशा मिशन के माध्यम से, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिशु वाटिका की शुरुआत, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN) से संबंधित पहलों को सुदृढ़ करने, शिक्षक क्षमता संवर्धन तथा बाल-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने के माध्यम से राज्य ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाया।

'आस स्कूल जिबा' जैसी पहल, विद्यालयों में नामांकन अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा एवं कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रयासों के साथ-साथ विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों ने समानता एवं समावेशन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया है। ये प्रयास इस संकल्प को प्रतिबिंबित करते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने, आगे बढ़ने, नवाचार करने और अपनी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

मुझे विश्वास है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत तैयार यह वार्षिक प्रतिवेदन 2025–26 हमारी सामूहिक उपलब्धियों का प्रतिबिंब होने के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना के लिए एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध होगा। निरंतर प्रतिबद्धता, सहयोग एवं नवाचार के माध्यम से हम एक समावेशी, न्यायसंगत एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को आकार प्रदान करेगी।

आयुक्त-सह-सचिव, उपाध्यक्ष
ओड़िशा सरकार, ओसेपा


SCHOOL STUDENT HELP LINE
TOLL FREE NO-18003456722
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ମୋ ପ୍ରଥର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି





श्रीमती अनन्या दास, आईएएस
राज्य परियोजना निदेशक,
ओसेपा, ओड़िशा

ओड़िशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण,
(ओसेपा) भुवनेश्वर
कार्यालय : 0674-2395325
ईमेल : opepaedu@yahoo.co.in

प्रस्तावना

शिक्षा एक न्यायसंगत, समावेशी, प्रगतिशील और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज के निर्माण का आधार है। समग्र शिक्षा, ओडिशा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, समावेशी, बाल-अनुकूल एवं अनुकूल शैक्षिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो तथा उसे सीखने, आवश्यक दक्षताएँ विकसित करने, प्रासंगिक कौशल अर्जित करने और अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों।

वर्ष 2025–26 में ओडिशा की स्कूली शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की परिकल्पना को सार्थक रूप से कार्यान्वित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए। राज्य ने निपुण ओडिशा मिशन के माध्यम से बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करने, अधिगम परिणामों में सुधार लाने, शिक्षकों की क्षमता का विकास करने, समावेशी एवं समानतापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना जारी रखा। इसके साथ ही, कौशल शिक्षा एवं व्यावसायिक अनुभव को अधिक महत्त्व दिया गया, ताकि विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान, रोजगारपरक कौशल, रचनात्मकता, नवाचार तथा उद्यमशीलता संबंधी क्षमताएँ विकसित कर सकें और भविष्य की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें।

ओडिशा सरकार द्वारा संचालित 'आस स्कूल जिबा' तथा 'ओडिशा शिक्षा सर्वेक्षण' जैसी पहलों ने विद्यालय से बाहर के बच्चों, विद्यालय छोड़ चुके बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं उनके मानचित्रण के प्रयासों को सुदृढ़ किया है। इन पहलों के माध्यम से ऐसे बच्चों के नामांकन, विद्यालय में ठहराव, समावेशन तथा शिक्षा तक उनकी निरंतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को बढ़ावा मिला है।

विद्यालयों के आधारभूत ढाँचे एवं शिक्षण-अधिगम परिवेश को सुदृढ़ और बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत FLN-अनुपालक विद्यालयों के विकास सहित यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि विद्यालय शिक्षण एवं अधिगम के लिए सुरक्षित, सुगम्य, समावेशी और अनुकूल वातावरण प्रदान करें। राज्य ने नवाचारी एवं प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खेलकूद तथा विद्यालय सुरक्षा को भी गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वांगीण शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उदाहरणों के रूप में बढ़ावा देना जारी रखा।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत उपलब्धियाँ विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, समुदाय के सदस्यों, क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों तथा राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर की टीमों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब हैं। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं सहयोगात्मक प्रयासों ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा पूरे राज्य में सार्थक परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुझे विश्वास है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत तैयार यह वार्षिक प्रतिवेदन 2025–26, योजना की विभिन्न पहलों, प्रगति एवं उपलब्धियों का एक महत्त्वपूर्ण अभिलेख सिद्ध होगा।

मैं ओडिशा में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में समर्पण एवं निष्ठा के साथ कार्य करने वाले सभी हितधारकों के बहुमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ।

राज्य परियोजना निदेशक
ओसेपा




ବିଶ୍ରାମ ଘର
vivo T2
Apr 2, 2024, 10:26

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	संक्षेपाक्षर	12
2	OSEPA के बारे में	13
3	समग्र शिक्षा: एक अवलोकन	15
4	प्रशासनिक रूपरेखा	16
5	राज्य प्रोफ़ाइल	18
6	जनसांख्यिकीय संकेतक	18
7	शैक्षणिक सूचक	19
8	प्रमुख उपलब्धियाँ	26
9	प्रमुख पहल और कार्यान्वयन की प्रगति	34
9.1	लिंग और समानता	34
9.2	मातृभाषा आधारित शिक्षा	50
9.3	आरटीई पात्रता	56
9.4	सामुदायिक गतिशीलता	57
9.5	स्कूल यूनिफार्म का वितरण	69
9.6	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	72
9.7	पहुंच और प्रतिधारण	74
9.8	मौजूदा को मजबूत बनाना	84
9.9	समावेशी शिक्षा	93
9.10	शिक्षा की गुणवत्ता	103
9.11	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान	104
9.12	कला उत्सव	109
9.13	गुणवत्ता, एलईपी और नवाचार के लिए निधि	113
9.14	शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम	116
9.15	समग्र प्रगति कार्ड	119
9.16	स्कूल सुरक्षा	121
9.17	सुरवी	126
9.18	मातृभाषा दिवस पर प्रदर्शनी	131
9.19	ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम	135
9.20	बीआरसी/सीआरसीसी के माध्यम से अकादमिक सहायता	140
9.21	पुस्तकालय अनुदान	142
9.22	बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान	146
9.23	खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा	157
9.24	व्यावसायिक शिक्षा	160
9.25	प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली	165
9.26	ओड़िशा शिक्षा सर्वेक्षण	168
9.27	विद्या समीक्षा केंद्र	172
10	योजना प्रक्रिया	178
11	सामाजिक अडिट	185
12	दीक्षा (डीआईकेएसएचए)	190
13	स्कूल-छात्र हेल्प लाइन	193
14	टीई और एससीईआरटी	198
15	प्रिंट मीड़िआ, सामाजिक माध्यम की एक झलक	212


ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ


ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା
MAGIC BOX

1. संक्षेपाक्षर

AWP&B	Annual Work Plan and Budget
BRP	Block Resource Person
BAS	Baseline Achievement Study
BPL	Below Poverty Line
BEO	Block Education Officer
BRC	Block Resource Centre
CCE	Continuous Comprehensive Evaluation
CR	Completion Rate
CRC	Cluster Resource Centre
CTE	College of Teacher Education
CTS	Child Tracking System
CPD	Continuous Professional development
CWSN	children with Special Needs
DLI	District Linked Indicators
D.P.C	District Project Coordinator
CSS	Centrally Sponsored Scheme
DEO	District Education Officer
DIET	District Institute of Education and Training
DR	Dropout rate
ECCE	Early Childhood Care and Education
FA&CAO	Financial Advisor & Chief Account Officer
FA&CAO	Financial advisor & Chief Account Officer
FLN	Foundational Literacy and Numeracy
GER	Gross Enrolment Ratio
GP	Gram Panchayat
HHS	House Hold Survey
IASE	Institute of Advanced Studies in Education
I.O.C	Intervention for Out-of-School Children
ICT	Information and Communication Technology
KGBV	Kasturava Gandhi Balika Vidyalaya
KRP	Key Resource Enhancement Programme
MIS	Management Information System
NSA	Non-State Actors
NAS	National Achievement Survey
NER	Net Enrollment Ratio
OOSE	Out of School Children
OSEPA	Odisha School Education Programme Authority
PM	Project Management
PFMS	Public Financial Management System
PAB	Project Approval Board
PTR	Pupil-Teacher Ratio
QMT	Quality Monitoring Tool
RTE Act	Right to Education Act
RCFCE Act	Right of children to free & Compulsory Education Act
RFD	Result Framework Document
RMSA	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
RR	Retention Rate / Repetition rate
S.A.C	State Assessment Cell
SIS	State Implementing Society
S.I.G	State Incentive Grant
S.P.D	State Project Director
SC/ST	Schedule Cast & Schedule Tribe
SS	Samagra Shiksha
SCERT	State Council of Educational Research and Training
SDG	Sustainable Development Goal
SDMIS	Student Data Management Information System
SMC	School Management Committee
SIG	State Incentive Grant
STARS	Strengthening Teaching-learning and Results for States
TEI	Teacher Education Institute
TT	Teacher Training
U.C.	Utilization Certificate
VSK	Vidya Samikhya Kendra

2. ओसेपा के बारे में

ओड़िशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओसेपा) ओडिशा सरकार के विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसका पंजीकरण 30 जनवरी, 1996 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकरण संख्या 19964/192 के साथ हुआ था, जिसका उद्देश्य राज्य भर में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करना था। विद्यालय शिक्षा को सुदृढ़ करने के राज्य के प्रयास ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओसेपा) के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू किए गए और 2018 तक जारी रहे। समग्र शिक्षा की शुरुआत के साथ,इन पहलों को ओसेपा के अंतर्गत लाया गया,जिससे ओडिशा में विद्यालय शिक्षा के समग्र विकास के लिए एक एकीकृत संरचना उपलब्ध हुआ।

ओसेपा के पास पेशेवरों की एक बहु-विषयक कोर टीम है जो स्कूली शिक्षा संबंधी हस्तक्षेपों की प्रभावी योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए समर्पित है।



विद्या समीक्षा केंद्र साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, प्रबंधन और कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए वास्तविक समय की निगरानी, डेटा विश्लेषण और समय पर सूचना संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

यूडाइस+ प्लेटफॉर्म का उपयोग नामांकन,शिक्षकों और स्कूल के आधारभूत संरचना सहित महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा डेटा के व्यवस्थित प्रबंधन और विश्लेषण के लिए किया जाता है।

संस्थागत जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई है।

ओसेपा के पास एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें बाल-केंद्रित पुस्तकों, विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों की पाठ्यपुस्तकों, ओसेपा के कार्यों से संबंधित प्रकाशनों, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों, सूचना और सूचना अधिकार (आरटीआई), पत्रिकाओं, संपादकीयों और समसामयिक विषयों का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो ज्ञान साझाकरण, पेशेवर संवाद और क्षमता विकास में सहायक है।

विद्या समीक्षा केंद्र साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, प्रबंधन और कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए वास्तविक समय की निगरानी, डेटा विश्लेषण और समय पर सूचना संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

यूडाइस+ प्लेटफॉर्म का उपयोग नामांकन,शिक्षकों और स्कूल के आधारभूत संरचना सहित महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा डेटा के व्यवस्थित प्रबंधन और विश्लेषण के लिए किया जाता है।

संस्थागत जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी शुरू की गई है।

ओसेपा के पास एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें बाल-केंद्रित पुस्तकों, विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों की पाठ्यपुस्तकों, ओसेपा के कार्यों से संबंधित प्रकाशनों, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों, सूचना और सूचना अधिकार (आरटीआई), पत्रिकाओं, संपादकीयों और समसामयिक विषयों का समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो ज्ञान साझाकरण, पेशेवर संवाद और क्षमता विकास में सहायक है।

सहयोग और सामूहिक कार्रवाई के महत्व को पहचानते हुए, ओसेपा स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और पहुंच को मजबूत करने के लिए सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से काम करता है।

प्रशासनिक रूपरेखा, जवाबदेही, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र ओसेपा का अभिन्न अंग है। राज्य स्तर पर प्रत्येक सोमवार को शिकायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जनता की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है।

हितधारकों की क्षमताओं का विकास, संस्थागत क्षमता बढ़ाने, कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रभावी शैक्षिक प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए संरचित प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास क्षमता निर्माण एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।

अपनी एकीकृत प्रणालियों, संस्थागत साझेदारियों, डेटा-आधारित शासन व्यवस्था, क्षमता-निर्माण पहलों और समानता एवं समावेशन पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, ओसेपा ने स्कूलों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा है।



3. समग्र शिक्षा - एक सिंहावलोकन

शिक्षा पर एकीकृत योजना में 'विद्यालय' को पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों तक एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप पूर्व-विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एसडीजी-4.1 के लक्ष्य में कहा गया है कि "2030 तक, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लड़के और लड़कियां मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें जिससे प्रासंगिक और प्रभावी शिक्षण परिणाम प्राप्त हों"।

इसके अलावा, एसडीजी 4.5 में कहा गया है कि "2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना और विकलांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और कमजोर परिस्थितियों में बच्चों सहित कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।"

यह योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन समिति (एसआईएस) अर्थात् ओएसईपीए के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- गुणवत्तापूर्णशिक्षाप्रदानकरनाऔरछात्रोंकेसीखने के परिणामों को बेहतर बनाना;
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को दूर करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना;
- स्कूली शिक्षा व्यवस्था में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना;
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना;
- बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना;
- राज्य शिक्षा संस्थानों (एससीईआरटी/राज्य शिक्षा संस्थानों) और डीआईटी को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सुदृढ़ और उन्नत बनाना।

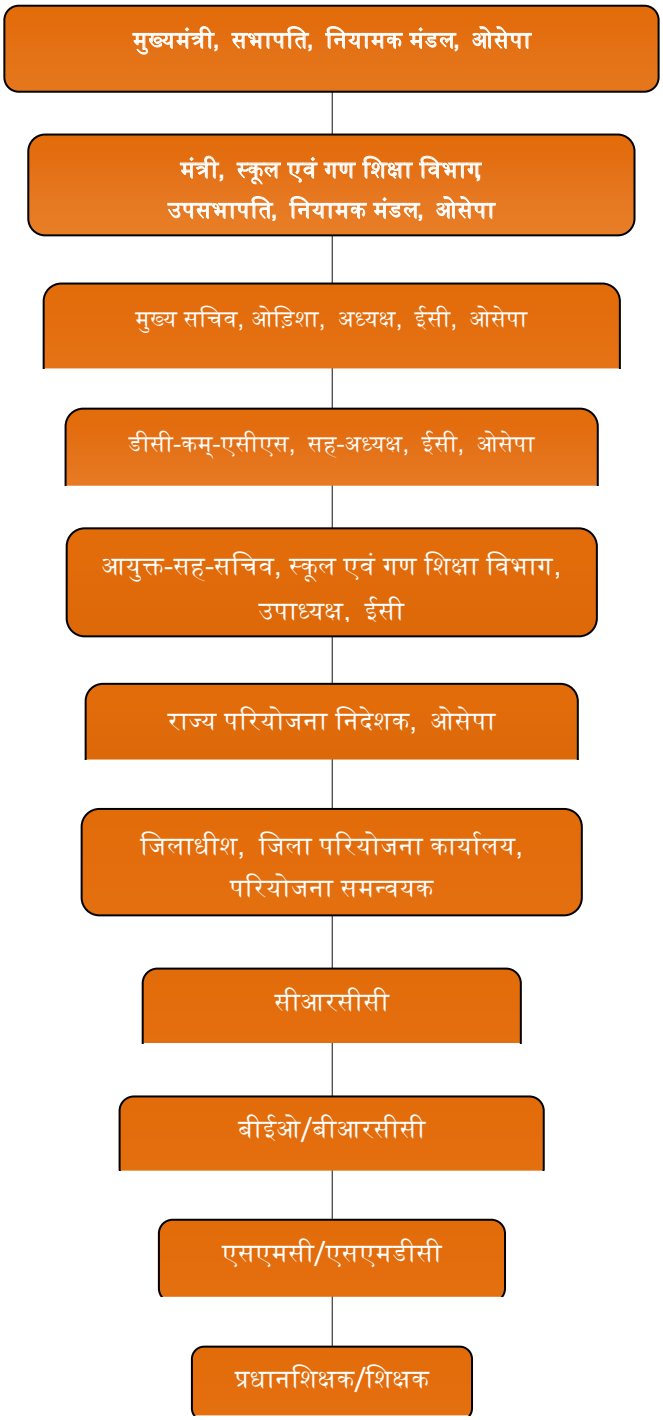
परिणाम

सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (टीईआई) को मजबूत करना।

मार्गदर्शन सिद्धांत

स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना में एक समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जो शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण, समानता, पहुंच, लैंगिक सरोकार, शिक्षक की केंद्रीयता और नैतिक बाध्यता जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।

4.प्रशासनिक संरचना



3.1 OSEPA – DPO INTERVENTION



3.2.OSEPA – SPO INTERVENTION STRUCTURE



5. राज्य प्रोफाइल

क्र.सं	प्रशासनिक इकाई	संख्या
1	राजस्व जिला	30
2	शैक्षिक ब्लॉक	314
3	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	316
4	क्लस्टर संसाधन केन्द्र	4,806
5	ग्रामपंचायत	6,798
6	राजस्व ग्राम	53,845
7	आवास	1,23,781

6.जनसांख्यिकीय संकेतक

विवरण	2011	2001
कुल जनसंख्या	41,974,218	36,804,660
पुरुष	21,212,136	18,660,570
महिला	20,762,082	18,144,090
लिंग अनुपात	979	972
कि.मी2 क्षेत्र	155,707	155,707
घनत्व/कि.मी 2	269	236
साक्षरता	72.87	63.08
पुरुष साक्षरता	81.59	75.35
महिला साक्षरता	64.01	50.51

कवरेज

राज्य मेंपूर्व-प्राथमिकसे लेकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक की सभी श्रेणियों के 61594 स्कूल है, जिनमें 7788567 विद्यार्थी और 341910 शिक्षक हैं।

7. शैक्षिक संकेतक

7.1 स्कूल/ अनुभाग का सारांश (2025-26)

स्कूलों का सारांश (2025-26)							
स्कूल प्रबंधक	पूर्व प्राथमिक विद्यालय(PP3-PP1)	प्राथमिक विद्यालय (I-V)	उच्च प्राथमिक विद्यालय (I/VI - VII/VIII)	कुल प्राथमिक विद्यालय	कुल माध्यमिक विद्यालय	कुल उच्च माध्यमिक विद्यालय	कुल
शिक्षा विभाग		26348	14942	41290	4599	864	46753
जनजातीय कल्याण विभाग + एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय		429	782	1211	382	118	1711
अन्य राज्य सरकार प्रबंधित		6	2	8	5	6	19
कुल सरकारी स्कूल (राज्य)		**26783**	**15726**	**42509**	**4986**	**988**	**48483**
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल		285	1266	1551	3333	803	5687
कुल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल		**27068**	**16992**	**44060**	**8319**	**1791**	**54170**
एसएसईपीडी द्वारा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त		15	33	48	20	0	68
केंद्र सरकार. प्रबंधित		0	1	1	3	9	13
निजी गैर-सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त)		745	3501	4246	828	1270	6344
निजी. गैर-मान्यता प्राप्त		393	413	806	55	29	890
केवी/जेएनवी		9	1	10	8	89	107
आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES)	2						2
कुल विद्यालय	**2**	**28230**	**20941**	**49171**	**9233**	**3188**	**61594**
स्रोत: यूडाइस+2025-26							

7.2 शिक्षक (2025-26)

नामांकन विवरण (2025-26)

स्कूल प्रबंधक	पूर्व प्राथमिक विद्यालय/ शिशुवाटिका	प्राथमिक विद्यालय (I-V)	उच्च प्राथमिक विद्यालय (VI-VIII)	कुल प्राथमिक विद्यालय (I-VIII)	माध्यमिक विद्यालय (IX-X)	उच्च माध्यमिक विद्यालय (XI-XII)	कुल नामांकन (I-XII)	कुल नामांकन (PP-XII)
शिक्षा विभाग	309851	2033609	1415632	3449241	710566	128913	4288720	4598571
जनजातीय कल्याण विभाग + एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	8165	166936	169943	336879	70021	16514	423414	431579
अन्य राज्य सरकार प्रबंधित	120	761	1176	1937	825	1878	4640	4760
कुल सरकारी स्कूल (राज्य)	**318136**	**2201306**	**1586751**	**3788057**	**781412**	**147305**	**4716774**	**5034910**
सरकारी सहायता प्राप्त	2169	20880	107094	127974	359084	445204	932262	934431
कुल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	**320305**	**2222186**	**1693845**	**3916031**	**1140496**	**592509**	**5649036**	**5969341**
एसएसईपीडी द्वारा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त	22	2244	1419	3663	545	0	4208	4230
केंद्र सरकार. प्रबंधित	48	1154	2352	3506	1082	1215	5803	5851
निजी गैर-सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त)	126329	718099	329458	1047557	163622	304353	1515532	1641861
निजी. गैर-मान्यता प्राप्त	8751	49870	14274	64144	5252	6376	75772	84523
केवी/जेएनवी के बिना नामांकन	**455455**	**2993553**	**2041348**	**5034901**	**1310997**	**904453**	**7250351**	**7705806**
केवी/जेएनवी (चलित वर्ष)	1188	29017	25351	54368	16189	10861	81418	82606
आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES)	155							155
केवी/जेएनवी के साथ नामांकन	456798	3022570	2066699	5089269	1327186	915314	7331769	7788567

स्रोत: यूडाइस+2025-26

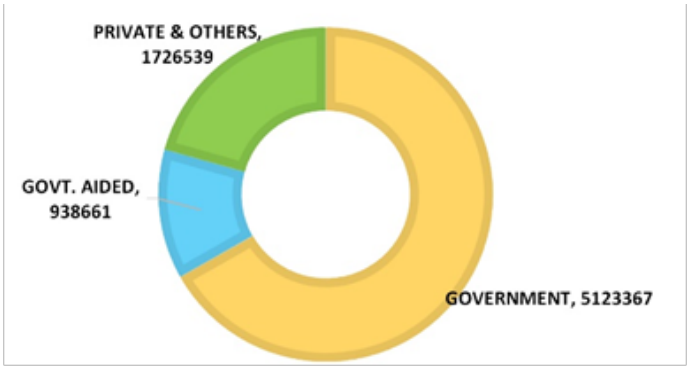
7.3 कक्षा के अनुसारशिक्षक

कक्षा के अनुसारशिक्षक (2025-26)

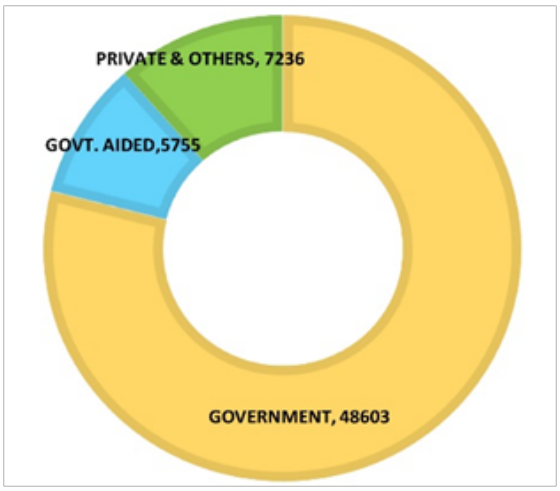
स्कूल प्रबंधन	पूर्व प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय	कुल शिक्षक
शिक्षा विभाग	16	80539	75149	155688	40953	3214	199871
जनजातीय कल्याण विभाग + एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	3	1879	3940	5819	3416	698	9936
अन्य राज्य सरकार प्रबंधित	0	22	14	36	46	42	124
कुल सरकारी स्कूल (राज्य)	**19**	**82440**	**79103**	**161543**	**44415**	**3954**	**209931**
सरकारी सहायता प्राप्त	1	915	2225	3140	18520	9504	31165
कुल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	**20**	**83355**	**81328**	**164683**	**62935**	**13458**	**241096**
एसएसईपीडी द्वारा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त	0	215	229	444	64	0	508
केंद्र सरकार. प्रबंधित	0	26	45	71	97	92	260
निजी गैर-सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त)	1520	29079	36303	65382	11017	11784	89703
निजी. गैर-मान्यता प्राप्त	129	4145	2342	6487	502	241	7359
केवी/जेएनवी	0	47	2	49	147	2778	2974
आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES)	10						10
कुल शिक्षक	**1679**	**116867**	**120249**	**237116**	**74762**	**28353**	**341910**

स्रोत: यूडाइस+2025-26

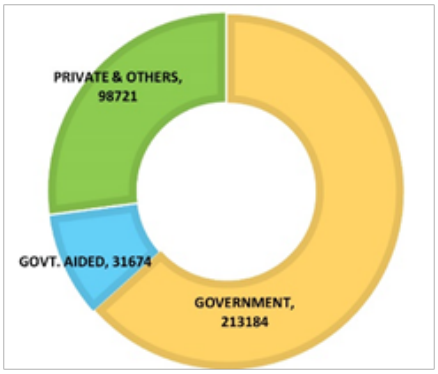
7.4 ओडिशा में स्कूलों, शिक्षकों और नामांकन का संक्षिप्त विवरण: प्रबंधन के अनुसार (UDISE+ 2025-26)



छात्रों की 77.89 लाख (कक्षा पीपी से 12वीं तक)



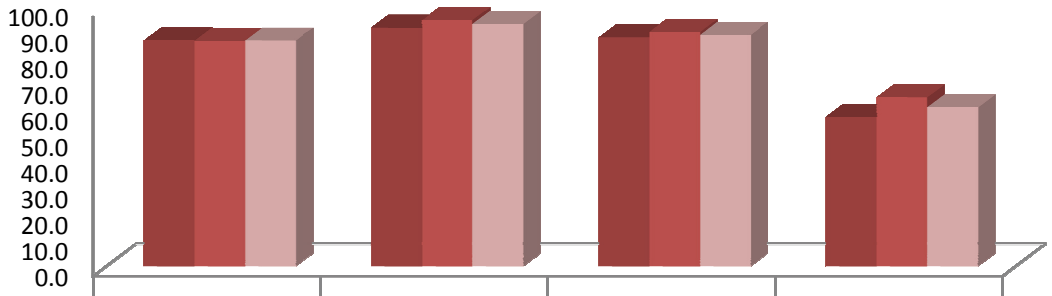
स्कूलों की संख्या 61594



शिक्षकोंकीसंख्या 3.4 लाख

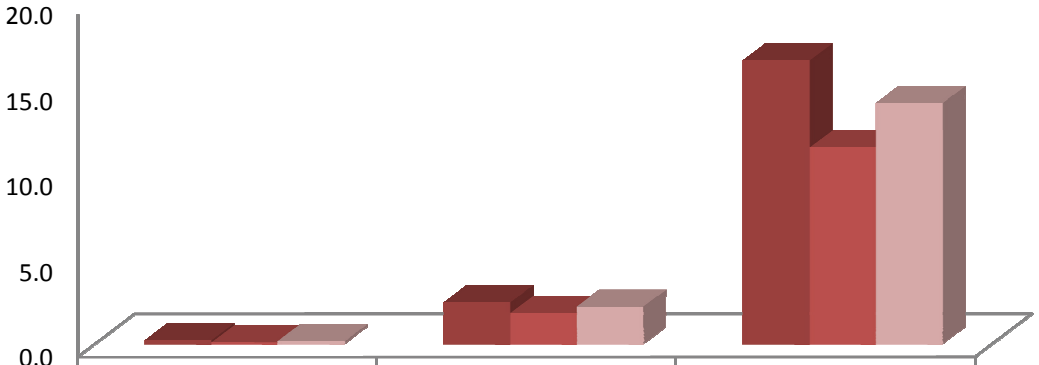
✓ सरकारी	79% स्कूल	66% छात्र	62% शिक्षक
✓ सरकारी सहायता प्राप्त	9% स्कूल	12% छात्र	10 %शिक्षक
✓ निजी	12% स्कूल	22% छात्र	28% शिक्षक

7.5 GER (GROSS ENROLMENT RATIO)



	PRIMARY	UPPER PRIMARY	SECONDARY	HIGHER SECONDARY
BOYS	87.0	92.0	88.1	57.5
GIRLS	86.9	94.8	90.3	65.0
TOTAL	87.0	93.3	89.2	61.2

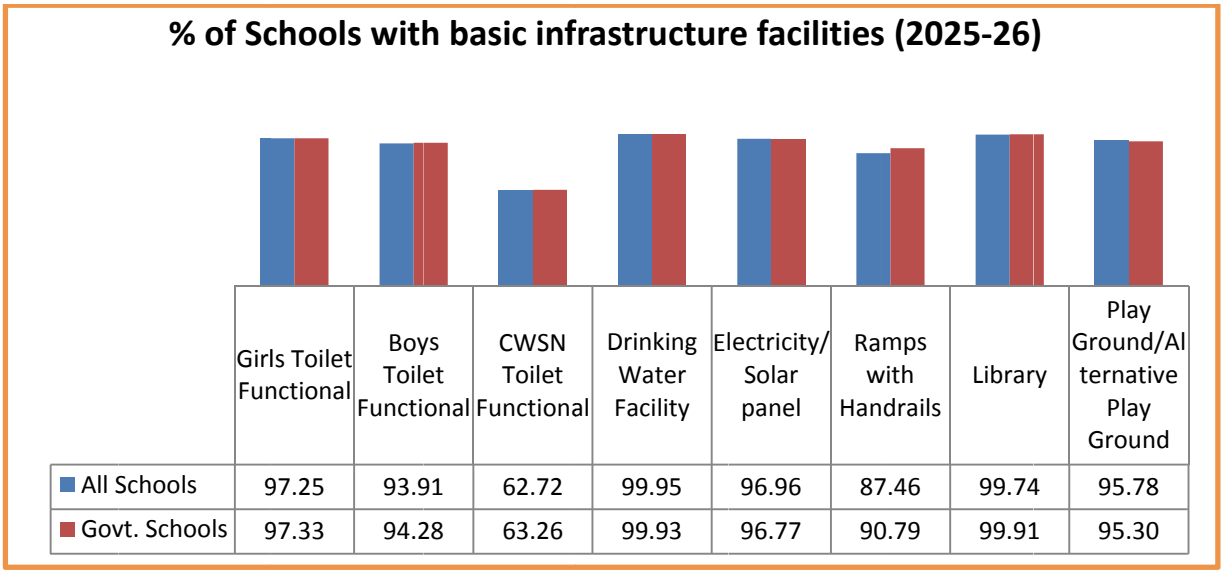
7.6 ANNUAL AVERAGE DROPOUT RATE



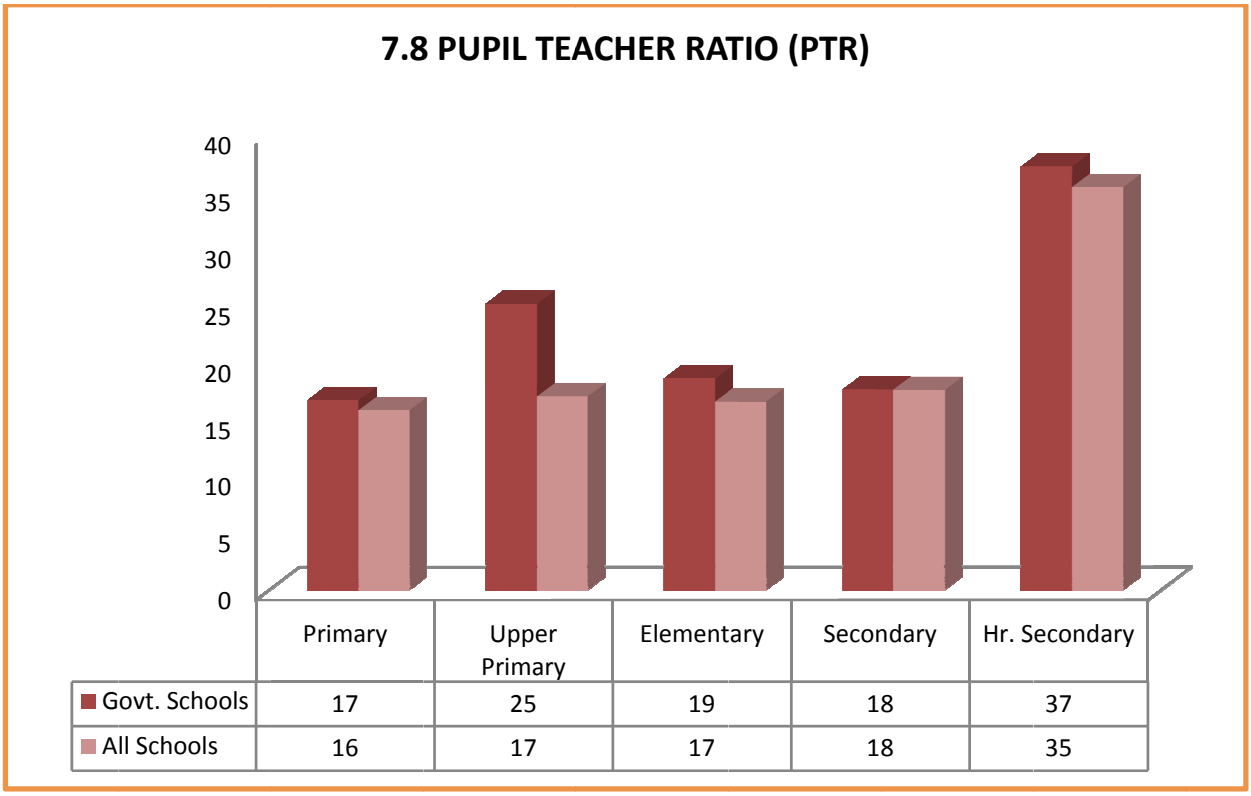
	PRIMARY	UPPER PRIMARY	SECONDARY
BOYS	0.2	2.4	16.6
GIRLS	0.1	1.8	11.5
TOTAL	0.1	2.2	14.1

Source: UDISE+- 2025-26

7.7 आधारभूत संरचना



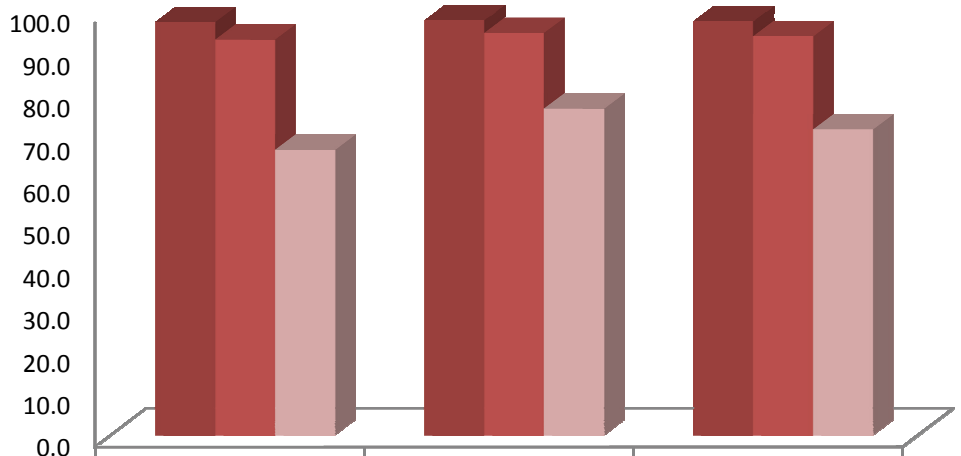
	Girls Toilet Functional	Boys Toilet Functional	CWSN Toilet Functional	Drinking Water Facility	Electricity/ Solar panel	Ramps with Handrails	Library	Play Ground/Alternative Play Ground
All Schools	97.25	93.91	62.72	99.95	96.96	87.46	99.74	95.78
Govt. Schools	97.33	94.28	63.26	99.93	96.77	90.79	99.91	95.30



	Primary	Upper Primary	Elementary	Secondary	Hr. Secondary
Govt. Schools	17	25	19	18	37
All Schools	16	17	17	18	35

Source: UDISE+ 2025-26

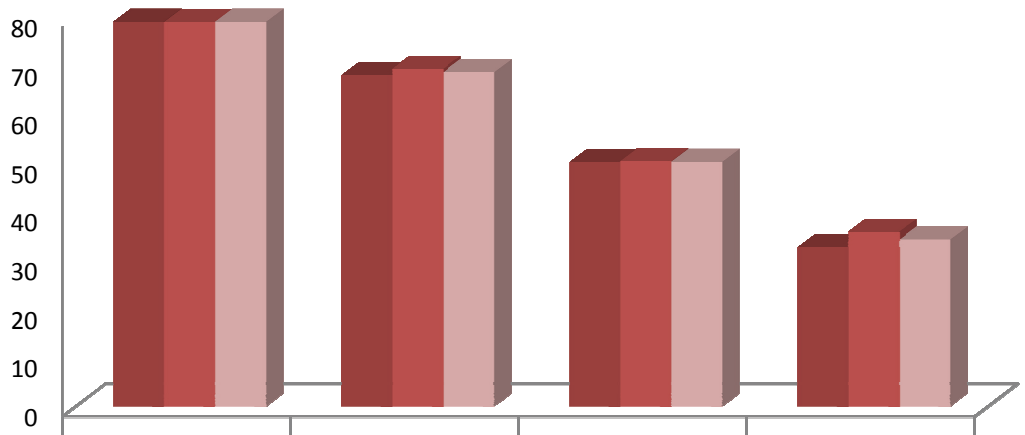
7.9.TRANSITION RATE



	BOYS	GIRLS	TOTAL
P TO UP	97.4	97.8	97.6
UP TO SEC	93.3	94.8	94.0
SEC TO HR. SEC	67.3	77.0	72.1

Source: UDISE+ 2025-26

7.10. NET ENROLMENT RATIO(NER)



	PRIMARY	UPPER PRIMARY	SECONDARY	HIGHER SECONDARY
BOYS	79.1	68.1	50.2	32.7
GIRLS	79	69.4	50.4	35.9
TOTAL	79.1	68.7	50.3	34.3

Source: UDISE+ 2025-26

8. प्रमुख उपलब्धियाँ

8.1. पहुंच और प्रतिधारण

- स्कूलसेबाहररहनेवाले15 बच्चों (6-14 वर्ष) को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया गया है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- 17 शहरी वंचित बच्चों (1050 क्षमता) के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय छात्रावास) खोर्धा, केंदुझर, मयूरभंज बरगढ़, कटक, गजपति, गंजम, कलाहांडी, कंधमाल, मलकानगिरी, कोरापुट और रायगड़ा जिले में कार्य कर रहे हैं। 993 शहरी वंचित बच्चों को छात्रावास में रखा जाता है और पढ़ाई जारी रखी जाती है।
- कोरापुट और मलकानगिरी जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय विद्यालय) की 4 इकाइयाँ (प्रत्येक में 100 छात्रों की क्षमता) कार्यरत हैं। इनमें से 400 बच्चे आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं।
- 04 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय छात्रावास) जिसकी क्षमता 100 है, को पीएबी 2025-26 द्वारा अनुमोदित किया गया है। छात्रावास खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- बरगढ़, बलंगीर, कालाहांडी, नूआपड़ा, बालेश्वर, कटक, गंजाम और खोर्धा जिलों के मूल और गंतव्य जिलों के 2528 प्रवासी बच्चों को पीएबी 2025-26 द्वारा अनुमोदित 2672 बच्चों में से 69 छात्रावासों (47 आवासीय और 22 गैर-आवासीय) में रखा गया है।
- पीएबी 2025-26 द्वारा अनुमोदित 31635 बच्चों में से 28120 बच्चों को परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की गई है।
- राज्य मुक्त शिक्षा संस्थान (एसआईओएस) केंद्रों में स्कूल से बाहर रहने वाले 35 बच्चों (15-18 वर्ष) को प्रवेश दिया गया है।
- पीएबी की मंजूरी के अनुसार 46 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत कर दिया गया है।
- पीएबी की मंजूरी के अनुसार 56 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत कर दिया गया है।
- पीएबी की मंजूरी के अनुसार 104 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत कर दिया गया है।

8.2. बालिका शिक्षा

- कक्षा। से कक्षा VIII तक समग्र शिक्षा योजना के तहत पात्र छात्रों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण दिशानिर्देशों के साथ सुनिश्चित किया गया।
- गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धी योजना (राज्य अनुदान) के तहत कक्षा । से VIII तक के पात्र छात्र लाभार्थियों (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त छात्रों) को दिशा-निर्देशों के साथ मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित किया गया।

- मुख्यमंत्रीछात्र-छात्रपरिधानयोजना (राज्यअनुदान) केतहतकक्षा 9 और 10 केछात्र-छात्राओंकोनिःशुल्कविद्यालयवर्दी का वितरण नियमित निगरानी के साथ सुनिश्चित किया गया।
- पीएम-श्री योजना के अंतर्गत कक्षा प्रथम से दस तक के पात्र छात्रों को निःशुल्क विद्यालय वर्दी का वितरण नियमित निगरानी के साथ सुनिश्चित किया गया।
- शिशु वाटिका (राज्य अनुदान) योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को निःशुल्क विद्यालय वर्दी का वितरण दिशानिर्देशों के साथ सुनिश्चित किया गया।
- प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा छह से आठवीं तक) की छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का संचालन करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित करना।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12 तक), 458 पीएम श्री विद्यालयों और सभी 182 तृतीय प्रकार के केजीबीवी में छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) का संचालन।
- राष्ट्रीय बालिका दिवस का ब्लॉक और जिला स्तर पर 24 जनवरी 2025 को आयोजन।
- विज्ञान एवं शिक्षा विभाग, जे-पाल एसए और ब्रेकथ्रू के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य में कक्षा VI से X तक के लिए BARNALI (लिंग समानता कार्यक्रम) का कार्यान्वयन।

8.3. केजीबीवी

- राज्यमेंटाइप-III और टाइप-IV के 335 केजीबीवी कार्यरत हैं जहाँ 23 जिलों में 51300 अंतेवासियों को रखा गया है।
- केजीबीवी में लड़कियों के लिए राखी बनाना, बांस से संबंधित हस्तशिल्प प्रशिक्षण, शिल्प प्रशिक्षण, सिलाई, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, बेकार सामग्री से बेहतरीन चीजें बनाना, खिलौने बनाना आदि जैसे विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- केजीबीवी छात्राओं की नियमित मासिक स्वास्थ्य जांच की जाती है।
- केजीबीवी (मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, सहायक कर्मचारी और चौकीदार) में रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित की गई है।
- सभी केजीबीवी में खुसी योजना के तहत केजीबीवी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण सुनिश्चित किया गया है।

8.4. समावेशी शिक्षा

- सरकारीऔरसरकारीसहायताप्राप्तविद्यालयोंमेंकक्षा। से XII तक 85934 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CwSN) नामांकित हैं। (स्रोत: UDISE 2025-26 अनंतिम आंकड़े)
- दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल पुस्तकों के 1616 सेट उपलब्ध कराए गए।
- कम दृष्टि वाले छात्रों को 3470 बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं।
- ब्लॉक स्तर पर 314 चिकित्सा मूल्यांकन शिविर आयोजित किए गए।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे(CwSN)को 8524 एड्स और उपकरणों आपूर्ति किए गए।
- 15930 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे(CwSN)को एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किया गया।
- 28785 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे(CwSN) को परिवहन भत्ता प्रदान किया गया।
- 1194 दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने के लिए भत्ता प्रदान किया गया।
- 21918 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- ब्लॉक स्तर परविशेष आवश्यकता वाले बच्चे(CwSN)के लिए खेल एवं एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस ब्लॉक स्तर पर मनाया गया।

8.5. शिक्षणशास्त्र

- राज्यकेसरकारीऔरसहायताप्राप्तविद्यालयोंमेंकक्षा 1 से 8 तककेलिएशैक्षणिकसत्र 2025-26 की 100% निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।
- एफएलएन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और सभी एफएलएन ग्रेड के छात्रों द्वारा साक्षरता और संख्यात्मकता में मूलभूत दक्षता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 सितंबर, 2024 को निपुन ओडिशा मिशन का शुभारंभ किया गया है। एफएलएन कार्यक्रम के इस उद्देश्य को प्राप्त करने और सभी एफएलएन ग्रेड के छात्रों द्वारा वांछित दक्षता की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ शिशु वाटिका का उद्घाटन करते हुए, प्राथमिक अनुभाग वाले सभी सरकारी स्कूलों में 5 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के नामांकन के लिए शिशु वाटिका के लिए एक अतिरिक्त कक्षा खोली गई है।
- शिशु वाटिका की कार्यपुस्तिका, छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री और शिक्षक पुस्तिका उन सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है जिनमें शिशु वाटिका के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- टीएलएम किट (साक्षरता) जिसमें चित्र पोस्टर (24), बड़ी किताबें (20), कविता पोस्टर (23) और कहानी कार्ड (33) आदि शामिल हैं, विकसित किए गए हैं और स्कूलों में वितरित किए गए हैं ताकि कक्षा गतिविधि के दौरान पूरक सामग्री के रूप में उनका उपयोग किया जा सके।
- प्राथमिक कक्षाओं वाले सभी सरकारी स्कूलों में गणित किट वितरित किए गए हैं, जिनका उपयोग संख्यात्मक गतिविधि के दौरान संसाधन सामग्री के रूप में किया जाएगा।
- प्राथमिक कक्षाओं वाले सभी सरकारी स्कूलों में जादू पेड़ी किट की आपूर्ति की प्रक्रिया चल रही है ताकि सीखने को और अधिक आनंददायक और रोचक बनाया जा सके।
- कक्षा 1 के छात्रों के लिए विद्या प्रवेश मॉड्यूल विकसित किया गया है और 2022-23 से स्कूलों में इसका संचालन किया जा रहा है ताकि छात्रों को स्कूल के वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके और वे इसके लिए तैयार हो सकें।
- एफएलएन वर्कबुक कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को उनके नियमित अभ्यास के लिए पूरक पठन सामग्री के रूप में प्रदान की गई हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि एफएलएन ग्रेड के सभी छात्र वांछित दक्षता प्राप्त कर लें।

- कक्षा I से III तक के लिए शिक्षण सोपान रजिस्टर विकसित किए गए हैं और छात्रों के उपलब्धि स्तर पर नज़र रखने के लिए प्राथमिक अनुभाग वाले सभी सरकारी स्कूलों को उपलब्ध कराए गए हैं।
- छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिशु वाटिका के सुचारू और प्रभावी संचालन, शिक्षण, श्रम और गणित के उपयोग, बहु-श्रेणी कक्षा के प्रबंधन, व्यावसायिक विकास आदि के लिए शिक्षकों को विभिन्न मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- एफएलएन मानकों के अनुरूप कक्षा परियोजना शुरू की गई है ताकि एफएलएन ग्रेड के छात्रों के लिए कक्षा का वातावरण बच्चों के अनुकूल, आकर्षक और आनंददायक बनाया जा सके। इस परियोजना के तहत कक्षाओं को डिस्प्ले बोर्ड, प्रिंट सामग्री टांगने के लिए बैटन, टीएलएम प्रदर्शित करने के लिए टीएलएम कॉर्नर आदि जैसी सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
- शिक्षकों को प्रदर्शन और चर्चा के माध्यम से शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक माह के पहले शनिवार को प्रधानाध्यापक और एक एफएलएन ग्रेड शिक्षक की मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है।
- एफएलएन कार्यक्रम की निगरानी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर मासिक/त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- छात्रों के मूलभूत कौशल के स्तर का आकलन करने और ग्रेड स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए एफएलएन ग्रेड के लिए आवधिक मूल्यांकन किया गया है।
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) में विद्यालय स्तर के नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को मनाने और प्रदर्शित करने के लिए क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर एफएलएन मेला आयोजित किया गया है।
- विज्ञान एवं शिक्षा एवं विकास विभाग के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा चतुर्थ से VIII तक के विद्यार्थियों को एलईपी वर्कबुक उपलब्ध कराई गई है। ये वर्कबुक गणित, अंग्रेजी और ओडिया जैसे विषयों के अधिगम परिणामों पर आधारित हैं।
- S&MEएवं SSD विभाग के तहत सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा IV से VIII तक छात्रों को LEP कार्यपुस्तिका दी गई है। ये कार्यपुस्तिका गणित, अंग्रेजीऔर ओड़िआ जैसे विषयों के शिक्षण परिणाम पर आधारित है।
- कक्षा नौ के विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता बढ़ाने के लिए एलईपी उत्कर्ष कार्यक्रम लागू किया गया है। विज्ञान एवं बौद्धिक विकास एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और ओडिया जैसे विषयों की छात्र पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- ओडिशा के TE&SCERT द्वारा विकसित समग्र प्रगति कार्ड (HPC) प्राथमिक कक्षा (कक्षा-1-8) के सभी छात्रों को प्रदान किया गया है।
- विज्ञान एवं चिकित्सा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा प्रथम से आठवीं तक के छात्रों को छात्र डायरी (मो डायरी) प्रदान की गई है, ताकि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संपर्क बना रहे और समय-समय पर संवाद सुनिश्चित हो सके।
- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर और स्कूल की गतिविधियाँ सभी सरकारी स्कूलों (एस एंड एमई और एससी एसटी विभाग दोनों) को उपलब्ध करा दी गई हैं, जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक अनुभाग हैं।
- सभी सरकारी विद्यालयों (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों) के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को उनके उपयोग के लिए नोटबुक उपलब्ध कराई गई है।

- सभी सरकारी विद्यालयों (विज्ञान एवं तकनीकी एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों) के कक्षा 9 और 10 के छात्रों को विज्ञान संबंधी गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट नोटबुक प्रदान की गई है।
- डाएट-सीआरसी संपर्क कार्यक्रम के तहत 30 जिलों के डीआईईटी को सीआरसीसी से जोड़ा गया है। डीआईईटी के शिक्षक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरसी और शिक्षकों को मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- कक्षा अवलोकन उपकरण (सीओटी) को कक्षा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का आकलन करने के साथ-साथ शिक्षकों को ऑनसाइट सहायता प्रदान करने के लिए विकसित और संचालित किया गया है।
- छात्रों को स्व-अध्ययन के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, ई-सामग्री के माध्यम से डिजिटल शिक्षा विकसित की गई है और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड की गई है।
- कक्षा I से X तक के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान सीखने की गतिविधियों में शामिल करने के लिए सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
- बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 10 के छात्रों को परीक्षा दर्पण की पुस्तक स्कूलों को उपलब्ध कराई गई है।
- विज्ञान एवं शिक्षा एवं विकास विभाग के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा चतुर्थ से VIII तक के विद्यार्थियों को एलईपी वर्कबुक उपलब्ध कराई गई है। ये वर्कबुक गणित, अंग्रेजी और ओडिया जैसे विषयों के अधिगम परिणामों पर आधारित हैं।
- कक्षा नौ के विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता बढ़ाने के लिए एलईपी उत्कर्ष कार्यक्रम लागू किया गया है। विज्ञान एवं बौद्धिक विकास एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और ओडिया जैसे विषयों की छात्र पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- ओडिशा के TE&SCERT द्वारा विकसित समग्र प्रगति कार्ड (HPC) प्राथमिक कक्षा (कक्षा-1-8) के सभी छात्रों को प्रदान किया गया है।
- विज्ञान एवं चिकित्सा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा प्रथम से आठवीं तक के छात्रों को छात्र डायरी (मनोरंजन डायरी) प्रदान की गई है, ताकि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संपर्क बना रहे और समय-समय पर संवाद सुनिश्चित हो सके।
- शिशुवाटिकासेलेकरकक्षाआठवींतककेसभीविद्यालयोंमेंविद्यार्थियोंमेंपढ़नेकीआदतकोबढ़ावादेनेकेलिएपठनप्रोत्साहनअभियानशुरूकियागयाहै।यह अभियान मार्च 2026 तक जारी रहेगा।
- राज्य में सभी प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण ओडिशा पाठ्यक्रम ढांचे और नई पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पूरा किया जाता है।
- पीएमश्री स्कूल के प्रधानाध्यापकों/प्रिंसिपलों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आरआईई द्वारा संपन्न किया जाता है।
- भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 1387 सरकारी माध्यमिक स्तर के पीईटी (शारीरिक प्रशिक्षक) को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष पीईटी के लिए यह प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा।
- 127 शैक्षणिक प्रशासकों को प्रेरण प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।
- सितंबर 2025 में केरल के कोझी कोड में 26 अन्य शैक्षिक प्रशासकों को अभिविन्यास प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
- ओईएस (एसबी) ग्रुप (बी) के 64 अधिकारियों के लिए एमडीआरएएफएम, बीबीएसआर में विभिन्न विषयों पर प्रेरण प्रशिक्षण पूरा हो गया है।

- राज्य स्तर पर माध्यमिक स्तर के गृहाध्यक्षों के लिए 'संभाव' मॉड्यूल पर 5 दिवसीय डीआरजी प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। जिला स्तर पर गृहाध्यक्ष प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है।
- उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर पूरा किया जाता है।
- माध्यमिक स्तर के नव नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दो चरणों में पूरा किया जाता है।
- कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर में 16009 कनिष्ठ शिक्षकों (योजनाबद्ध) का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- नव नियुक्त प्राथमिक कनिष्ठ शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डीआरजी (प्रशिक्षण मंडल) का अभिविन्यास राज्य स्तर पर पूर्ण हो चुका है। जिला/ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

8.6. अवसंरचना विकास

- प्राथमिकविद्यालयोंमेंकुलमिलाकर 81512 अतिरिक्तकक्षाकक्षऔरमाध्यमिकविद्यालयोंमें 2964 अतिरिक्तकक्षाकक्षोंकानिर्माणकार्यपूराहोचुकाहै।
- प्राथमिक स्तर पर, 7033 विद्यालयों में पेयजल, 15252 विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय, 49688 विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, 32476 विद्यालयों में बाल एवं शिशु सहायक शौचालय, 11599 विद्यालयों में विद्युतीकरण की सुविधा और 22642 विद्यालयों में रैंप और रेलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- माध्यमिक स्तर पर, सिविल कार्यों के अंतर्गत कुल मिलाकर 838 विद्यालयों में पेयजल, 1029 विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय, 2101 विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, 43 विद्यालयों में बाल एवं महिला शौचालय और 7 विद्यालयों में विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की गई है।
- 182 केजीबीवी (टाइप-III) भवन का निर्माण कार्य संचयी रूप से पूरा हो चुका है।

8.7. व्यावसायिक शिक्षा

- 935 विद्यालयोंमें 95,479 छात्र (50,537 लड़के और 44,942 लड़कियां) नामांकित हैं, जिससे कार्यक्रम का निरंतर विस्तार सुनिश्चित होता है।
- स्वास्थ्य सेवा, बिजली और बीएफएसआई जैसे नए क्षेत्रों सहित 15 व्यावसायिक क्षेत्रों और 27 नौकरी भूमिकाओं तक इसका विस्तार किया गया है।

- सभी जिलों में 3100 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की तैनाती और 23 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई।
- एक सरल एकल निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पहले से लंबित सभी 311 स्कूलों को सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- राज्य, जिला और वीटीपी (व्यावसायिक विकास कार्यक्रम) को शामिल करने वाले त्रि-पक्षीय समझौतों के माध्यम से संस्थागत शासन सुधार।
- कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार के लिए जिला स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण।
- सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ नए एसएलए पर हस्ताक्षर किए गए और 72,455 छात्रों के लिए व्यावहारिक मूल्यांकन आयोजित किए गए।
- 2,32,315 विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यपुस्तकों का विकास, सत्यापन और 100% समय पर वितरण सुनिश्चित किया गया।
- विभिन्न स्थानों पर 18 बैचों के माध्यम से 2,122 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करते हुए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

8.8. बहुभाषी शिक्षा

- मातृभाषाआधारितबहुभाषीशिक्षा (एमएलई) ओडिशाके 17 आदिवासीबहुलजिलोंमेंस्थित 21 आदिवासीभाषाओंके 1317 विद्यालयोंमेंसंचालित है। एमएलई कार्यक्रम के तहत बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए 3188 एमएलई शिक्षा सहायक और 143 एमएलई ईवीएस (शिक्षक एवं शिक्षा सहायक) कार्यरत हैं।
- एमएलई जिलों में जनजातीय संसाधन केंद्र (टीआरसी) स्थापित किए गए हैं।

8.9 सामुदायिक लामबंदी

- परीक्षापेचर्चा2026 के 9वें संस्करण में माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले 23.28 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की अभूतपूर्व भागीदारी दर्ज की गई है।
- राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने और शिक्षार्थियों में युवा भावना पैदा करने के लिए युवा और पर्यावरण क्लबों का गठन किया जाता है।
- मिशन लाइफ पोर्टल के लिए ईसीओ क्लब में 48676 स्कूलों ने अपनी अधिसूचना अपलोड की है। "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत अब तक 3829926 पौधे लगाए जा चुके हैं।
- चौथी पीटीएम का आयोजन 17.01.2026 को एक ही दिन में किया गया और इसमें लगभग 30 लाख अभिभावकों ने भाग लिया।
- 2 अप्रैल 2025 को "प्रवेश उत्सव" और "खादी चुआं" के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी व्यापक अभियान मनाया गया।
- आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 2 से 5 अप्रैल, 2025 के दौरान राज्य भर में "शिक्षा सचेतनता रथ" का भ्रमण कराया गया है।

- राज्य भर के 60359विद्यालयों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" विषय के साथ मनाया गया, जिसमें 50,38,689 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया।
- 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
- सभी विद्यालयों में 16 से 30 सितंबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया।

8.10.सुरवी

- सुरवी -सितंबरसेनवंबर2025 के दौरान युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक बाल महोत्सव का आयोजन किया गया है।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, छात्रों को दर्शनीय स्थलों (राज्य संग्रहालय, नंदनकानन चिड़ियाघर, ऐतिहासिक स्थल, क्षेत्रीय विज्ञान पार्क आदि) का भ्रमण करने का अवसर मिला।
- विभिन्नप्रतियोगिताओं, मॉडल संयुक्त राष्ट्र, व्यक्तित्व परिचय सत्र, कार्यशालाओं, स्टॉलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

8.11 डिजिटल शिक्षा

- विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की व्यवस्था:4000 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, 6065उच्च प्राथमिक, 909 माध्यमिक और 74 व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 7048 स्मार्ट कक्षाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- 96718 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।
- स्कूलों की गतिविधियों की निगरानी के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।
- सभी 316 ब्लॉक संसाधन केंद्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से सुसज्जित हैं।

8.12. स्कूली छात्रों के लिए हेल्पलाइन

- आरटीईअधिनियम2009 के अंतर्गत बच्चों की शिकायतों का निवारण एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2010 में 'स्कूल स्टूडेंट हेल्पलाइन' नामक एक अनूठी व्यवस्था स्थापित की गई थी। जनवरी 2015 से शिकायतें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त की जाती हैं।



9. प्रमुख पहल और कार्यान्वयन प्रगति

9.1. लिंग और समानता

9.1.1.कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

परिचय

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में शुरू की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना, वंचित समुदायों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलों में से एक है। यह योजना अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक समुदायों और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों की लड़कियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक सुरक्षित, समावेशी और बाल-अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करके शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना है, जिससे लड़कियां अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें।

प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) और महिला समाख्या (एमएस) के साथ अभिसरण में एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई, केजीबीवी योजना को 1 अप्रैल 2007से एक अलग घटक के रूप में सर्व शिक्षा अभियान में एकीकृत किया गया और वर्तमान में इसे **समग्र शिक्षा** के तहत लागू किया जा रहा है।

प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) और महिला समाख्या (एमएस) के साथ अभिसरण में एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई, केजीबीवी योजना को 1 अप्रैल 2007 से एक अलग घटक के रूप में सर्व शिक्षा अभियान में एकीकृत किया गया और वर्तमान में इसे समग्र शिक्षा के तहत लागू किया जा रहा है।

यह योजना मूल रूप से उन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में लागू थी, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम थी और साक्षरता में लैंगिक अंतर अधिक था। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आबादी की सघनता, कम महिला साक्षरता, बिखरी हुई बस्तियों और बड़ी संख्या में विद्यालय से बाहर रहने वाली लड़कियों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी।

वित्तीय **वर्ष 2025-26** के दौरान, समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिका शिक्षा कार्यक्रम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं के तहत मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म वितरण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पहल, लैंगिक समानता कार्यक्रम, किशोर शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से छात्राओं के लिए समान पहुंच, शिक्षा में उनकी भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और नियमित क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के माध्यम से निरंतर निगरानी ने राज्य भर में सभी अनुमोदित गतिविधियों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया।

उद्देश्य

बालिका शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- वंचितवर्गकीलड़कियोंकेलिएगुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एक सुरक्षित, संरक्षित और लड़कियों के अनुकूल विद्यालयी वातावरण प्रदान करना।
- स्कूलोंमेंलड़कियोंकेनामांकन, उपस्थिति, स्कूल में बने रहने और आगे के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में सुधार करना।
- जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और किशोरियों को सशक्त बनाना।
- बालिकाओं की शिक्षा के प्रबंधन और सुधार में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना।
- सहपाठ्यचर्या और व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व और जीवन कौशल को बढ़ाना।

लाभार्थी

बालिका शिक्षा कार्यक्रम से मुख्य रूप से राज्य भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में पढ़ने वाली छात्राओं को लाभ मिलता है। अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक समुदायों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनाथ बच्चों, एकल-अभिभावक परिवारों की छात्राओं और अन्य कमजोर समूहों से संबंधित छात्राओं पर विशेष जोर दिया जाता है।

2025-26के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत 23जिलों में फैले 338बाल एवं शिशु सुरक्षा शिविरोंमें मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म वितरण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, किशोर शिक्षा, लैंगिक समानता कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल विकास और आवासीय शिक्षा सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से छात्राओं को लाभ पहुँचाया गया,जिनमें 182टाइप-III और 156टाइप-IV बाल एवं शिशु सुरक्षा शिविर शामिल थे। समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और निरंतर निगरानी से सभी स्वीकृत हस्तक्षेपों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ।

लाभार्थी

बालिका शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन हेतु निधियों को समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) के अंतर्गत प्रतिवर्ष स्वीकृत किया जाता है। भारत सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर, राज्य स्तर पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं और समय पर कार्यान्वयन के लिए सभी जिलों को सूचित किए जाते हैं।

केजीबीवी के प्रबंधन, मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म के वितरण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के आयोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधियों, व्यावसायिक कौशल विकास, लैंगिक समानता कार्यक्रमों और अन्य अनुमोदित पहलों के लिए जिलों और विद्यालयों को वित्तीय सहायता जारी की जाती है। स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी), जिला परियोजना कार्यालय और ब्लॉक प्राधिकरण निधि के कार्यान्वयन, निगरानी और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के उद्देश्यों के गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन और समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए पूरे वर्ष नियमित समीक्षा बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फील्ड विजिट और प्रगति निगरानी तंत्र का संचालन किया गया।

केजीबीवी की प्रमुख गतिविधियाँ

क. स्वास्थ्य एवं पोषण

2025-26 केदौरानसभीकस्तूरबागांधीबालिकाविद्यालयोंमेंस्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती रही।

- सभी केजीबीवी में खाद्य पदार्थों की तैयारी और गुणवत्ता की निगरानी के लिए खाद्य समितियाँ अपना कार्य जारी रखती हैं।
- सभी कैदियों को निर्धारित मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन परोसा जाता था।
- सभी केजीबीवी कैदियों की मासिक स्वास्थ्य जांच निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से कराई जाती थी।
- सभी 338 केजीबीवी में खुसी योजना के तहत मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण सुनिश्चित किया गया।
- व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण और किशोर स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते थे।

ख. बोर्डिंग छात्रों द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ

- केजीबीवीकैदियोंकेसीखनेकेपरिणामोंमेंसुधारकेलिएशैक्षणिकसहायतागतिविधियांपूरेवर्षजारीरहीं।
- नियमित कक्षा शिक्षण और उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन किया गया।
- समग्र विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक समारोह और सहपाठ्यचर्या प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- विद्यार्थियों ने विद्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ग. विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण

केजीबीवी में रहने वाली लड़कियों में व्यावसायिक कौशल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बना रहा। वर्ष के दौरान, सभी 182 टाइप-III केजीबीवी ने विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल थीं:

- सिलाई
- बांस के हस्तशिल्प
- राखी बनाना
- ग्रीटिंग कार्ड की तैयारी
- खिलौना बनाना
- नष्ट वस्तुओंमें सर्वश्रेष्ठ

- शिल्प कार्य
- सजावट का साजो-सामान
- अन्य स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक व्यावसायिक गतिविधियाँ
  इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केजीबीवी अंतेवासियों के बीच रचनात्मकता, उद्यमिता और आजीविका कौशल विकसित करना था, साथ ही आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था।

घ. खेल-कूद वाले खेल

खेल-कूद को समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में बढ़ावा देना जारी रहा। छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी बालवाड़ी विद्यालयों में फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, योग और इनडोर गेम्स जैसी विभिन्न खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया गया। सभी 182 बालवाड़ी विद्यालयों में खेल गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिससे विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। वर्ष के दौरान आयोजित शारीरिक फिटनेस गतिविधियों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और योग सत्रों का भी समावेश रहा।

ङ. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

केजीबीवी कैदियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और समग्र कल्याण पर विशेष जोर दिया गया।वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं:

- सभीकेजीबीवीएस में कैदियों की मासिक स्वास्थ्य जांच।
- बीमार छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।
- खुशी योजना के तहत सेनेटरी नैपकिन का वितरण।
- किशोरावस्था के स्वास्थ्य, पोषण और मासिक धर्म स्वच्छता पर परामर्श।
- व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम।
- इन पहलों ने किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता और व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

च. केजीबीवी कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा पर प्रशिक्षण

आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, केजीबीवी कर्मचारियों के लिए अग्नि सुरक्षा और आपदा तैयारी पर अभिविन्यास कार्यक्रम जारी रहे।

छात्रावास के वार्डन, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, सहायक कर्मचारी, चौकीदार और विद्यालय प्रमुखों को अग्नि सुरक्षा उपायों, आपातकालीन निकासी प्रक्रियाओं और बिजली एवं रसोई उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। नियमित जागरूकता कार्यक्रमों से केजीबीवीएस में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिली।

छ. गतिविधियाँ और विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26के दौरान, राज्य भर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के समग्र प्रबंधन और कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अंतर्गत अनुमोदित 338 बालिका विद्यालयों (182 प्रकार-III और 156 प्रकार-IV) के प्रभावी प्रबंधन हेतु समय पर निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। समीक्षा बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित निगरानी से सभी अनुमोदित गतिविधियों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ।

छात्रावास के सुचारू प्रबंधन और छात्र कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, सहायक कर्मचारी और चौकीदार के रिक्त पदों को भरा गया। मासिक स्वास्थ्य जांच, खुशी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का वितरण, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का आयोजन और खेल गतिविधियों का संचालन किया गया।

सभी बाल एवं शिशु एवं शिशु शिक्षा केंद्रों (केजीबीवी) में नियमित रूप से जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थागत प्रबंधन में सुधार लाने और लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से केजीबीवी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पहलों को भी वर्ष के दौरान मजबूत किया गया।







9.1.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

क. उद्देश्य

- लड़कियोंकेखिलाफलिंगआधारितभेद-भावकोरोकना।
- बालिका के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित करना
- विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति और उनकी पढ़ाई जारी रखने को बढ़ावा देना
- लड़कियों को शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों में आत्मविश्वासपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति सामुदायिक जागरूकता को मजबूत करना।

ख.तौर-तरीके

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम जागरूकता अभियानों, विद्यालय स्तर की गतिविधियों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जारी रहा। विद्यालयों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी), मातृ समितियों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि बालिकाओं की शिक्षा के महत्व, बाल विवाह की रोकथाम, लैंगिक समानता और किशोरियों के सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

ग. उपलब्धियाँ

वर्षकेदौरान, राज्य भर के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को बालिका शिक्षा के महत्व और बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जा सके। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, चित्रकला और नारा लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विजेता विद्यार्थियों को विद्यालय और जिला स्तर पर सम्मानित किया गया।

9.1.3. आत्मरक्षा प्रशिक्षण

उद्देश्य

- छात्राओंमेंआत्मविश्वासविकसितकरनाऔरभयएवंअसुरक्षा को दूर करना।
- लड़कियों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए व्यावहारिक आत्मरक्षा कौशल से सशक्त बनाना।
- शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देना।
- व्यक्तिगत सुरक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता और आत्मरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति और उनकी पढ़ाई जारी रखने में सुधार करना।

तौर-तरीके

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम) समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी रहा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संरचित आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा VI से VIII और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा IX से XII तक की छात्राओं के लिए लागू किया गया। इस कार्यक्रम का विस्तार राज्य के 458 पीएम श्री विद्यालयों और सभी 182 तृतीय-प्रकार के केजीबीवी (किंडरगार्टन गार्डिंग स्कूल) तक किया गया। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों को विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन विधियां सूचित की गईं। समीक्षा बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित निगरानी ने सभी जिलों में समय पर कार्यान्वयन और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित किया।

उपलब्धियाँ

इस वर्ष के दौरान, 19,876 प्राथमिक विद्यालयों और 6,177 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों और टाइप-III केजीबीवी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिससे स्वीकृत लक्ष्य का 100% प्राप्त हुआ।

इस कार्यक्रम ने छात्राओं के आत्मविश्वास, जागरूकता और आत्मरक्षा कौशल को काफी हद तक बढ़ाया और उन्हें स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।









9.1.4 राष्ट्रीय बालिका दिवस

अवलोकन और उत्सव

क. उद्देश्य

- छात्राओंकोसहपाठ्यक्रमऔरपाठ्येतरगतिविधियोंमेंसक्रियरूपसेभागलेनेकेलिएप्रोत्साहितकरना।
- बालिकाओं की उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना।
- लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रेरित करना।
- लड़कियों की शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

ख. तौर-तरीके

राष्ट्रीय बालिका दिवस के पालन और बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता से संबंधित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सभी जिलों और ब्लॉकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए।

छात्रों, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी), अभिभावकों और समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए विभिन्न जागरूकता अभियान, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए।

ग. उपलब्धियाँ

राज्य के सभी जिलों और ब्लॉकों में 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया।



9.1.5 बर्नाली - लैंगिक समानता कार्यक्रम

घ. उद्देश्य



- माध्यमिकस्तरपरलड़कियोंकीशिक्षाजारीरखनेकीदरमेंसुधारकरना।
- किशोरवय लड़कों और लड़कियों के बीच लैंगिक समानता वाले व्यवहार को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के बीच लिंग-संवेदनशील शिक्षण पद्धतियों को मजबूत करने के लिए।
- लिंग-संवेदनशील विद्यालय नेतृत्व का विकास करना।
- कक्षाशिक्षण-अधिगमप्रक्रियाओंमेंलैंगिकसमानताकीअवधारणाओंकोएकीकृतकरना।
- विद्यालयों में लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने के लिए संस्थागत तंत्रों को मजबूत करना।

ङ. तौर-तरीके

ओडिशा सरकार के विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग, जे-पाल साउथ एशिया और ब्रेकथ्रू के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, कक्षा VI से Xतक के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में बर्नाली लैंगिक समानता कार्यक्रम का कार्यान्वयन जारी रहा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य संरचित कक्षा गतिविधियों, शिक्षक मार्गदर्शन मार्गदर्शिकाओं और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, विद्यालय प्रमुखों और शैक्षिक प्रशासकों के बीच लैंगिक समानता वाले दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देना था।

राज्य भर में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा तंत्र को अपनाया गया।

च. उपलब्धियाँ

सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता को मजबूत करने के लिए 2025-26 के दौरान बरनाली कार्यक्रम के सत्र सफलतापूर्वक जारी रहे। इस कार्यक्रम ने लैंगिक समानता, आपसी सम्मान, साझा जिम्मेदारियों और लैंगिक रूढ़ियों को दूर करने पर केंद्रित कक्षा चर्चाओं, अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों और जागरूकता को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन ने सुरक्षित, समावेशी और लैंगिक रूप से संवेदनशील विद्यालय वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

9.1.6. किशोरियों का कार्यक्रम

छ. उद्देश्य

- किशोरोंकेस्वास्थ्यऔरपोषणकेबारेमेंजागरूकताबढ़ानेकेलिए।
- किशोरियों में जीवन कौशल और नेतृत्व क्षमता विकसित करना।
- मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
- आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और संचार कौशल को बढ़ाने के लिए।
- लैंगिक समानता, सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ज. तौर-तरीके

किशोरवय बालिका कार्यक्रम को पीएम श्री स्कूल के 458 विद्यालयों में कक्षा VI से XII तक की छात्राओं के लिए कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम में किशोरवय स्वास्थ्य, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल, लैंगिक संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और करियर मार्गदर्शन पर जागरूकता सत्र शामिल थे। विभिन्न विभागों के संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने किशोरवय बालिकाओं के बीच प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए संवादात्मक सत्रों का संचालन किया।

झ. उपलब्धियाँ

यह कार्यक्रम 458पीएम श्रीविद्यालयों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और स्वीकृत लक्ष्य का 100% कवरेज प्राप्त हुआ। छात्राओं ने जीवन कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, नेतृत्व गतिविधियों और परामर्श सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और आत्मविश्वास निर्माण में योगदान मिला।

9.1.7. लड़कियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

उद्देश्य

- बालिकाशिक्षासंबंधीपहलोंकेप्रभावीकार्यान्वयनकेलिएसंस्थागतक्षमताकोमजबूतकरना।
- केजीबीवी के पदाधिकारियों की व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाना।
- नेतृत्व, प्रबंधन और छात्रावास प्रशासन में सुधार करना।
- सभी जिलों में लिंग-संवेदनशील कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए।

ञ. तौर-तरीके

बालिका शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास भागीदारों के सहयोग से वर्ष के दौरान विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

केजीबीवी वार्डन और जेंडर कोऑर्डिनेटरों के व्यावसायिक विकास पर विशेष जोर दिया गया, जिसके लिए संरचित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहयोगी संगठनों से तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

ट. उपलब्धियाँ

एनआईईपीए और भारत सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई), भुवनेश्वर में 8 से 12 दिसंबर 2025 तक 26 केजीबीवी वार्डन के लिए पांच दिवसीय आवासीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यूनिसेफ और ब्रेकथ्रू के सहयोग से राज्य भर में बालिका शिक्षा संबंधी पहलों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए सभी लिंग समन्वयकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

9.1.8.केजीबीवी प्रदर्शनी स्टॉल

उद्देश्य

- राज्यस्तरीयसुरवीकार्यक्रमकेदौरानकेजीबीवी के कैदियों को अपनी बहुमुखी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना।
- केजीबीवी के छात्रों की संस्कृति, परंपरा, रचनात्मकता और व्यावसायिक कौशल को राज्य स्तर पर प्रदर्शित करना।
- राज्य में सहभागिता को सक्षम बनाकर केजीबीवी कैदियों को अनुभव प्रदान करना।
- सुरवी कार्यक्रम का स्तर। केजीबीवी के छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- केजीबीवी में रहने वाली लड़कियों की प्रतिभाओं को पहचानना और उनकी सराहना करना।

तौर-तरीके

पिछले वर्षों की तरह, राज्य स्तरीय सुरवी कार्यक्रम के दौरान केजीबीवी के कैदियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों और शिक्षण परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित किया गया था। राज्य भर के विभिन्न केजीबीवी से चयनित छात्रों ने छात्रावास वार्डन, प्रधानाध्यापकों और सहायक कर्मचारियों के मार्गदर्शन में प्रदर्शनी में भाग लिया। सफल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवास, परिवहन और प्रदर्शनी सामग्री की आवश्यक व्यवस्था की गई थी।

इस प्रदर्शनी ने केजीबीवी के छात्रों को शिक्षाविदों, अधिकारियों, छात्रों और आम जनता के समक्ष अपने व्यावसायिक कौशल, कलात्मक प्रतिभा और नवीन शिक्षण अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

उपलब्धियाँ

भुवनेश्वर के गवर्नमेंट कैपिटल हाई स्कूल, यूनिट-III में 12 से 14 नवंबर 2025 तक आयोजित राज्य स्तरीय सुरवी कार्यक्रम के दौरान केजीबीवी प्रदर्शनी स्टॉल का सफल आयोजन किया गया। विभिन्न केजीबीवी के छात्रों ने हस्तशिल्प उत्पादों, बांस की वस्तुओं, चित्रों, सजावटी वस्तुओं, सिलाई उत्पादों, ग्रीटिंग कार्ड, बेकार वस्तुओं से निर्मित मॉडल और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित अन्य नवीन शिक्षण सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की।

इस प्रदर्शनी ने दर्शकों, शिक्षा अधिकारियों और अन्य हितधारकों से सराहना प्राप्त की और रचनात्मकता, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता कौशल को प्रोत्साहित करके केजीबीवी के छात्रों को मूल्यवान अनुभव प्रदान किया।







9.1.9. वर्ष 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिका शिक्षा कार्यक्रम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जो राज्य भर में लड़कियों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रति विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समग्रशिक्षा, गंगाधर मेहर शिक्षा मानक बुद्धि योजना (जीएमएसएमबीवाई), मुख्यमंत्री छात्र छत्री परिधान योजना (एमसीसीपीवाई), पीएम श्री और शिशु वाटिका योजनाओं के तहत मुफ्त स्कूल वर्दी का 100% वितरण।
- रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का सफल कार्यान्वयन 19,876 प्राथमिक विद्यालयों और 6,177 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों और तृतीय-प्रकार के केजीबीवी में किया गया।
- समय पर धनराशि जारी करके, नियमित निगरानी और आवश्यक छात्रावास कर्मचारियों की नियुक्ति के माध्यम से 338 कस्तूरबा गांधी बालिकाविद्यालयों (182 टाइप-III और 156 टाइप-IV) का प्रभावी प्रबंधन।
- सभी 182 टाइप-III केजीबीवी में विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें सिलाई, बांस हस्तशिल्प, शिल्प कार्य, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना, खिलौने बनाना और अन्य आजीविका-उन्मुख कौशल जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ शामिल हैं।
- सभी केजीबीवी में मासिक स्वास्थ्य जांच का संचालन और खुसी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का 100% वितरण हुआ है।
- स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग, जे-पाल साउथ एशिया और ब्रेकथ्रू के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत सरकारी स्कूलों में बर्नाली लैंगिक समानता कार्यक्रम का निरंतर कार्यान्वयन।
- 458पीएम श्री स्कूलों मेंकिशोरियों के कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन किया गया है, जिसमें कक्षा VI से XII तक की छात्राओं को स्वास्थ्य, पोषण, जीवन कौशल, नेतृत्व और लैंगिक समानता पर जागरूकता सत्रों के माध्यम से शामिल किया गया है।
- एनआईईपीए और भारत सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर में 26 केजीबीवी वार्डन के लिए पांच दिवसीय आवासीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे आवासीय विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि हुई।
- यूनिसेफ और ब्रेकथ्रू के सहयोग से सभी जेंडर कोऑर्डिनेटरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन और निगरानी को मजबूत करना।
- सभीपीएम श्री विद्यालयों में किशोरी क्लबों की स्थापना का उद्देश्य किशोरियों में नेतृत्व क्षमता, जीवन कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता और लिंग-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- राज्य स्तरीय सुरवी कार्यक्रम2025 के दौरान केजीबीवी प्रदर्शनी स्टॉल का सफल आयोजन, जिसने केजीबीवी के छात्रों को अपनी रचनात्मकता, नवाचार और व्यावसायिक कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

निष्कर्ष



समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिका शिक्षा कार्यक्रम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच, समानता, गुणवत्ता और सशक्तिकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेपों के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति जारी रखी।



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का प्रभावी प्रबंधन, निःशुल्क विद्यालय वर्दी का समय पर वितरण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यान्वयन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कौशल विकास, लैंगिक समानता की पहल, किशोर शिक्षा कार्यक्रम और कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की निरंतर क्षमता निर्माण ने सामूहिक रूप से निम्नलिखित में योगदान दिया:

राज्य भर में लड़कियों की शिक्षा को मजबूत करना।

विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग, ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए), जिला परियोजना कार्यालयों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, विकास भागीदारों और अन्य हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रम के उद्देश्यों से संबंधित सभी स्वीकृत गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ। विभाग सुरक्षित, समावेशी और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए ऐसे विद्यालय बनाकर बालिकाओं की शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो प्रत्येक बालिका को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने और समाज में सक्रिय योगदानकर्ता बनने में सक्षम बनाएँ।





9.2. ओड़िशा में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (एमटीबी-एमएलई)

बच्चों की मातृभाषा तक पहुँचने का प्रवेश द्वार



प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों के बीच भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, राज्य के 17 जिलों में 21 आदिवासी भाषाओं में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है।

बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के शुरुआती वर्षों में मातृभाषा का उपयोग करके वंचित आदिवासी बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना है और धीरे-धीरे उनकी मातृभाषा (पहली भाषा) से राज्य भाषा (दूसरी भाषा) और फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषा (तीसरी भाषा) की ओर बढ़ना है। बहुभाषिक(एमएलई) में पहली भाषा को प्राथमिकता देने का सिद्धांत लागू होता है। एमएलई के मुख्य बिंदु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य जनजातीय सलाहकार समिति की सिफारिश पर आधारित हैं। राज्य ने वर्ष 2007-08 में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (एमटी आधारित एमएलई) कार्यक्रम को आदिवासी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अभिनव मॉडल के रूप में शुरू किया।



इस पद्धति का कार्यान्वयन: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करके बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में 2007-08 से बहुभाषिक(एमएलई) कार्यक्रम शुरू किया गया है और चिन्हित विद्यालयों द्वारा भाषा मानचित्रण के माध्यम से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

- ओड़िशाकेलिएएमएलईनीतिऔरकार्यान्वयनदिशानिर्देशकोसरकारद्वाराअधिसूचनासंख्या14118 दिनांक 01.07.2014 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है।

- बहुभाषिक(एमएलई) कार्यक्रम 21 जनजातीय भाषाओं यानी संताली, सौरा, कोया, कुई, कुवी, किशन, ओरम, मुंडा, जुआंगा, बोंडा, गदाबा, हो, गोंडी, परोजा, खरिया, दिदाई, भिंझल, पौडी भुइयां, भूमिया, भतरा और भुंजिया में प्राथमिक शिक्षा को शामिल करता है।

- बहुभाषिक(एमएलई) कार्यक्रम 17 जिलों यानी अनगूल, बालेश्वर, बरगढ़, ढेंकानाल, गंजम, गजपति, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट, केंदुझर, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चालू है।

- 89942 अनुसूचित जनजाति के बच्चे 1317 एमएलई स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

- मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए 3188 शिक्षकों (शिक्षा सहायक) और 143 भाषा प्रशिक्षकों/शिक्षा स्वयंसेवकों (ईवी) को नियुक्त किया गया है।

- प्राथमिक कक्षाओं के लिए 21 आदिवासी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें और पूरक पठन सामग्री विकसित की गई हैं।





अभ्यास के परिणाम:

- गैर-बहुभाषिकस्कूलोंकीतुलनामेंबहुभाषिक (एमएलई)स्कूलोंकेबच्चोंद्वाराभाषाऔरगणितमेंशैक्षणिकप्रदर्शनमेंमहत्वपूर्ण उपलब्धिकेसंदर्भमेंआदिवासीछात्रोंकेसंज्ञानात्मककौशलकाविकासहुआहै।
- सभी बहुभाषिक(एमएलई) स्कूलों में छात्रों के बने रहने की दर में वृद्धि हुई।
- शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और वेबहुभाषिक(एमएलई) पद्धति और पाठ्यचर्या सामग्री से भलीभांति परिचित हैं।

सीखे गए पाठ:

- प्रारंभिकवर्षों (प्राथमिककक्षाओं) मेंमातृभाषाकाउपयोगकरकेआदिवासीबच्चोंकोशिक्षाप्रणालीसेपरिचितकरानाऔरधीरे-धीरेउनकीमातृभाषा (L1) से राज्य भाषा (L2) और फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषा (L3) की ओर अग्रसर करना।
- प्राथमिक स्तर पर भाषा की बाधा को दूर करके मातृभाषा शिक्षण (एमएलई) की शुरुआत के माध्यम से बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना।
- प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों की मातृभाषा का उपयोग करके उनके पढ़ने-लिखने के कौशल और सीखने में सुधार करना।
- प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सेतु प्रक्रिया के माध्यम से ओडिया भाषा का परिचय कराना।
- आदिवासी बच्चों में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सराहना और सामाजिक सम्मान की भावना का विकास करना।





फ़ायदे:

- मातृभाषाआधारितबहुभाषीशिक्षाकीशुरुआतकेकारणइसकार्यक्रमसे1317 बहुभाषी विद्यालयों में पढ़ रहे 89942 अनुसूचित जनजाति के बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
- यही अभ्यास उन छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा जो उड़िया के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं और उन्हें विद्यालय में अनुकूल वातावरण में लिखकर सिखते हैं।

संपार्श्विकफायदे:

- आदिवासीछात्रोंकोप्रारंभिककक्षाओंमेंयथासंभवउनकीमातृभाषामेंशिक्षाप्रदानकरनेकाप्रयास किया जाता है, जिससे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आती है।
- बहुभाषिक (एमएलई) शिक्षा का उद्देश्य घर और स्कूल की भाषा के बीच के अंतर को पाटना है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ:

- एनईपी2020 बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) को बढ़ावा देता है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए।
- इस नीति का उद्देश्य बच्चे के मौजूदा भाषा ज्ञान को आधार बनाकर, अधिक समावेशिता सुनिश्चित करके और बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणितीय कौशल विकसित करके सीखने के परिणामों में सुधार करना है। प्रमुख कार्यान्वयन रणनीतियों में भाषाई मानचित्रण, क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम निर्माण और स्थानीय भाषा जानने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता

  देना शामिल हैं।

जनजातीय शिक्षा संसाधन केंद्र: जनजातीय संस्कृति की एक प्रतिकृति

राज्य के मध्यम आय एवं शिक्षण (एमएलई) जिलों में आदिवासी संसाधनों के प्रसार के लिए आदिवासी संसाधन केंद्र (टीआरसी) स्थापित किए गए हैं। इन संसाधनों के केंद्र का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को उनकी जनजातियों, संस्कृति, परंपरा, जीवनशैली, साहित्य, भाषा आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना है। आदिवासी संसाधन केंद्र (टीआरसी) में पाठ्यपुस्तकें, पूरक पठन सामग्री, प्रशिक्षण पुस्तिका, संदर्भ पुस्तकें, टीएलएम, कहानियां, कविताएं, विभिन्न सांस्कृतिक वस्तुएं, सामुदायिक संसाधन, प्रख्यात आदिवासी नेताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, मॉडल, प्रदर्शन बोर्ड आदि रखे गए हैं ताकि सामुदायिक ज्ञान को विद्यालय के पाठ्यक्रम से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जा सके। भविष्य में संदर्भ के लिए सामुदायिक ज्ञान को संरक्षित करने हेतु सभी संसाधन सामग्री टीआरसी में रखी गई हैं।




GPS Map Camera
Bhawanipatna, Odisha,




BIRD TRAP
RABBIT TRAP



Front Side of the Tribal Resource Centre



Backside of the Tribal Resource Centre



Side View of the Tribal Resource Centre



Inside View Room No-1



9.3. आरटीई पात्रता

9.3.1. विशेष प्रशिक्षण:

ओड़िशा सरकार के विज्ञान एवं बौद्धिक विकास विभाग ने अधिसूचना संख्या 6939 दिनांक 31.3.2014 के माध्यम से विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की परिभाषा घोषित की है। 6-14 वर्ष आयु वर्ग के कुल 15 विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान की गई है और उन्हें आयु-उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया गया है। पीएबी 2025-26 के तहत प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, 15 विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित किया गया है।

क्र.सं	गतिविधि	पीएबी लक्ष्य 2025-26	भौतिक उपलब्धि
1	ओओएससी (नए) के लिए गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण	15	15
	कुल	15	15

स्कूल से बाहर रहने वाले कुल 15 बच्चों को सीधे स्कूलों में दाखिला दिया गया है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

9.3.2. प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास

पीएबी 2025-26 के तहत, मूल स्थानों पर स्थित 47 मौसमी छात्रावासों में 1972 प्रवासी बच्चों को रखने और गंतव्य स्थानों पर स्थित 22 गैर-आवासीय मौसमी छात्रावासों में 700 प्रवासी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने को मंजूरी दी गई है। ये छात्रावास नवंबर/दिसंबर 2025 में खोले गए। मौसमी छात्रावासों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रवासी बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास - 2025-26

स्रोत बिंदु: आवासीय				
क्र.सं	जिलों के नाम	**भौतिक**	**उपलब्धियाँ**	
		लक्ष्य	केंद्रों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	बरगढ़	600	12	600
2	बलांगीर	661	16	661
3	कलाहांडी	300	6	295
4	नूआपड़ा	411	13	411
	कुल	1972	47	1967
गंतव्य स्थान: गैर-आवासीय				
5	बालेश्वर	70	2	51
6	कटक	260	7	241
7	गंजाम	244	11	176
8	खोर्धा	126	2	93
	कुल	700	22	561
	कुल	2672	69	2528

9.4. सामुदायिक लामबंदी

“प्रवेश उत्सव”, “खड़ी छुआँ” और “शिक्षा सचेतनता रथ”, 2025-26



राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के निर्देशानुसार, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में “शिशु वाटिका” नामकी एक अतिरिक्त पूर्व-विद्यालय कक्षा होगी और ओडिशा में इसे पहली बार शैक्षणिक वर्ष 2025 में शुरू की गई। सरकारी अधिसूचना 1753 दिनांक 20.01.2025 के अनुसार, 5-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिशु वाटिका कक्षा में प्रवेश दिया गया। इस उद्देश्य से राज्य में 2 अप्रैल 2025 से निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गईं।

- 2 अप्रैल, 2025 को सभी विद्यालयों में “प्रवेश उत्सव” और “खाडीछूआँ” के उपलक्ष्य में एक विशाल राज्यव्यापी अभियान चलाया गया, जिसमें अभिभावकों, प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया।
- प्रवेश उत्सव के लिए विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम को 3 से 5 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया।
- आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 अप्रैल, 2025 को राज्य मुख्यालय में राज्य स्तर पर “शिक्षा सचेतनता रथ” के माध्यम से एक राज्यव्यापी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।



शिक्षा सचेतनता रथ

प्रवेशउत्सवऔरशिशुवाटिकाकेबारेमेंजागरूकतापैदाकरनेकेलिएब्लॉक, जिला स्तर पर शिक्षा सचेतनता रथ घुमा गया।

- कार्यक्रमकेसफलकार्यान्वयनकेलिएइसेसभीजिला/ब्लॉकस्तरोंपरआयोजितकियागयाऔरओडिशाकेमाननीयमुख्यमंत्रीद् वारा विधिवत हस्ताक्षरित निमंत्रण पत्र शिशु वाटिका-III में प्रवेश पाने वाले पात्र छात्रों के अभिभावकों को वितरित किया गया।

राज्यव्यापी अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम) और एसएमसी/एसएमडीसी पहल (2025-26)



शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में रणनीतिक रूप से नियोजित राज्यव्यापी पीटीएम और एसएमसी/एसएमडीसी सत्रों के माध्यम से विद्यालय-समुदाय सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इन बैठकों में 14 करोड़ से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया, जिनका उद्देश्य अधिगम परिणामों और सर्वांगीण बाल विकास को बढ़ावा देना था।

पीटीएम के उद्देश्य:

- शैक्षणिकमार्गदर्शन:अभिभावकोंकोशैक्षणिकविकासऔरव्यक्तिगतप्रदर्शनकेबारेमेंजागरूककरना।
- समग्र रणनीति: छात्रों के सर्वांगीण विकास और स्कूल के आधारभूत संरचना के लिए मिलकर योजना बनाना।
- सरकारीपहल:मूलभूतसाक्षरताऔरसंख्याज्ञान (एफएलएन) औरनिपुणओडिशा जैसी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- नामांकन और प्रतिधारण: 100% नामांकन और शून्य ड्रॉपआउट के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।
- साझेदारी निर्माण: शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना।

पीटीएमकैलेंडरऔरभागीदारी

पीटीएम का समय	दिनांक	फोकस क्षेत्र	शामिल होने वाले स्कूल	योग देने वाले अभिभावक		
पहली बैठक	19thअप्रैल,2025			शैक्षणिक वर्ष का शुभारंभ और योजना	53,215	44.33लाख
दूसरी बैठक	30th जुलाई,2025			एफएलएन, मो स्कूल और कल्याण स्किम	53,715	29.52लाख
विशेष बैठक	16th अगस्त 2025			आस स्कूल जिबा (ड्रपआउट बच्चे)	70,537	41.16लाख
चौथी बैठक	17th जनवरी 2026			बोर्ड परीक्षा और स्ट्रेस मेनेजमेंट	53,308	29.02 लाख



परिणाम:

- मजबूतसाझेदारी: स्कूलों और अभिभावकों के बीच विश्वास और सहयोग में वृद्धि।
- जागरूक पालन-पोषण: माता-पिता साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और एनईपी 2020 के आदेशों जैसी पहलों के बारे में अधिक जागरूक हो गए।
- बेहतर शासन व्यवस्था: विद्यालय प्रबंधन में 27.5 लाख से अधिक एसएमसी/एसएमडीसी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी।
- परीक्षा की तैयारी: कक्षा V और VIII की बोर्ड परीक्षाओं पर केंद्रित मार्गदर्शन से छात्रों का तनाव कम हुआ और तैयारी का स्तर बेहतर हुआ।





9.4.1. मिशन लाइफ केलिए इको क्लब पर अभियान– एक पेड़ माँ के नाम



- 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' को 5 जून को "विश्व पर्यावरण दिवस, 2025" के अवसर पर मनाया गया।
- "एक पेड़ मां के नाम 2.0" (वृक्षारोपण) कार्यक्रम की अवधि 5 जून, 2025 से 13 अक्टूबर, 2025 तक है।
- मिशन लाइफ के लिए इको क्लबों के माध्यम से ये गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। https://ecoclubs.education.gov.in/main
- गोल्ड पोर्टल पर दर्ज किए गए और लगाए गए पौधों की संख्या के अनुसार, ओडिशा राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है; हालांकि, वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में, राज्य अन्य राज्यों में 11वें स्थान पर है।
- 17 सितंबर, 2025 को 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' विषयवस्तु के तहत एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 3829926 पौधे लगाए गए और तस्वीरें अपलोड की गईं।

गतिविधियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	उपलब्धियाँ प्रतिशत
पौधे रोपण (छात्रवार लगाए गए पौधों की जानकारी और अपलोड की गई तस्वीरें)	43,11,720	38,29,926	88.83
स्कूलों का पंजीकरण	61,596	56,201	91.24
मिशन लाइफ के लिए यूथ क्लब की अधिसूचना अपलोड करना	61,596	48,647	78.97









9.4.2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का उत्सव

11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 21 जून, 2025 को राज्य के 60359 विद्यालयों में "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग" विषय के साथ मनाया गया, जिसमें 50,38,689 से अधिक छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया।



- 11 वेंअंतर्राष्ट्रीय योगदिवसकी पूर्वसंध्यापर आयुषपोर्टलमें 18530 स्कूलोंका पंजीकरण हुआहै।
- राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों के पंजीकरण में चौथा स्थान प्राप्त किया है।



9.4.3. 16th से 30th सितंबर, 2025-26 में स्वच्छता पखवाड़ा

'स्वच्छता पखवाड़ा' एक पखवाड़े भर चलने वाला स्वच्छता अभियान है जो विद्यालयों में 16 से 30 सितंबर, 2025 तक और 'स्वच्छता ही सेवा' 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और समुदाय की भागीदारी के साथ विद्यालयों में स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य

- छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के बीच स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति व्यापकजागरूकता पैदा करना।





- दैनिकजीवनमेंव्यक्तिगतस्वच्छता, सफाई और सुरक्षा प्रथाओं की आदत डालना।
- स्वच्छपर्यावरणकोबनाएरखनेकेप्रतिजिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य की भावना विकसित करना।
- स्वच्छताअभियान, वृक्षारोपण और अपशिष्ट प्रबंधन में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कचरे के पृथक्करण, जल संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल पहलों जैसी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- 'स्वच्छ भारत' के संदेश को फैलाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले माध्यमों के रूप में विद्यालयों की भूमिका को मजबूत करना।



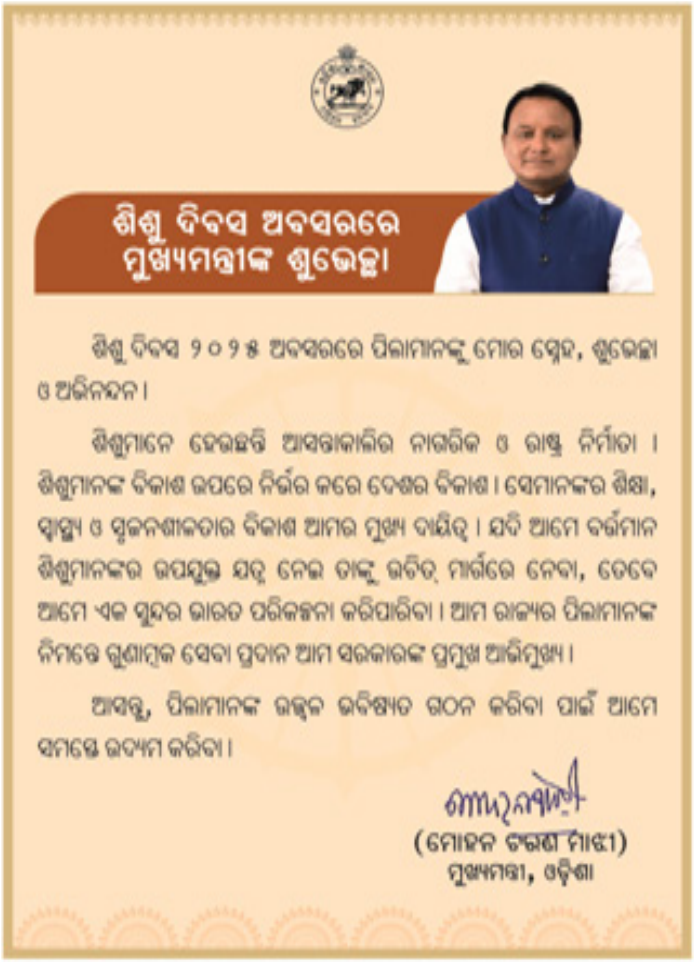


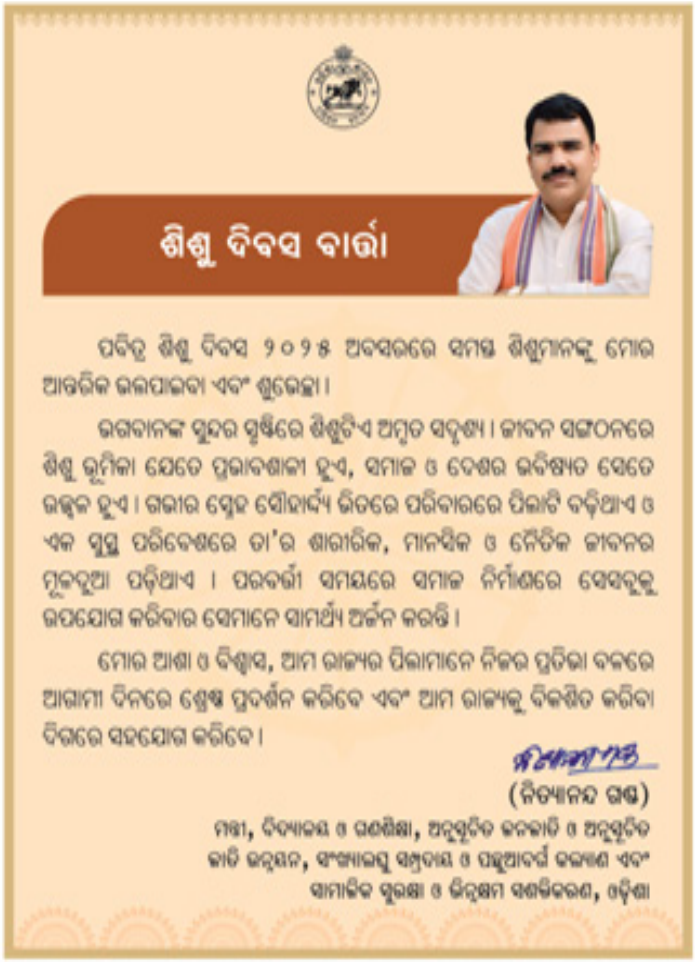
9.4.5. बाल महोत्सव 'सुरवी' 202 का अवलोकन 2025

सितंबर 2025 से नवंबर 2025 तक विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर बाल महोत्सव 'सुरवी'का आयोजन किया गया और छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए 12 से 14 नवंबर, 2025 तक राज्य मुख्यालय में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय बाल महोत्सव 'सुरवी' का आयोजन किया गया,जिसमें 4000 छात्रों, मार्गदर्शक शिक्षकों और अधिकारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री ने शिशु दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी 12 नवंबर 2025 को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।













ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ
୨୦୨୫





9.4.6 वीरता पुरस्कारों के अंतर्गत वीर गाथापरियोजना5.0

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल, वीर गाथा परियोजना 2025 (वीर गाथा 5.0) को गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत स्कूली छात्रों में देशभक्ति, नागरिक जिम्मेदारी और भारत के वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बलिदानों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया था। इस परियोजना के तहत, कक्षा तीन से बारह तक के छात्रों ने निबंध लेखन, कविता, चित्रकला, कहानी सुनाना और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। ये गतिविधियाँ परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित थीं।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुगम बनाने और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश राज्य भर के विद्यालयों में वितरित किए गए। ओडिशा भर के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह-पूर्वक भाग लिया,जिससे देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा मिला। ओडिशा ने इस परियोजना में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की,जिसके परिणामस्वरूप वीर गाथा परियोजना 2025-26 में निम्नलिखित दो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विजेता के रूप में चुना गया:

1. बृंदा रानी पंडा, कक्षा IX (ए), के.सी. पब्लिक स्कूल, बेरहामपुर, गंजाम जिला।

2. प्रज्ञान परिमिता ससमल, दसवीं कक्षा, चंपेश्वर हाई स्कूल, थाइलो, जगतसिंहपुर जिला।

इन विद्यार्थियों की उपलब्धि ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और यह देशभक्ति, रचनात्मकता और राष्ट्र की गौरवशाली विरासत के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के विद्यालयों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ओडिशा सरकार का विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विद्यार्थियों को साहस, अनुशासन, राष्ट्रीय सेवा और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करें।



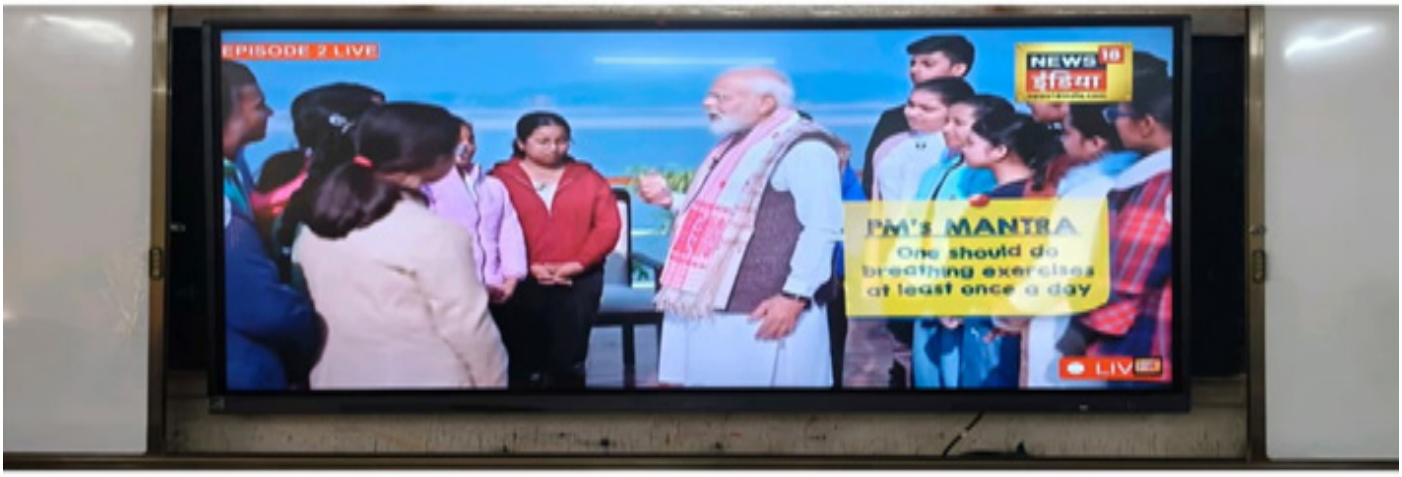


9.4.7 परीक्षा पे चर्चा 2026

माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 10 फरवरी 2025 को राज्य भर में किया गया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग 300 छात्रों से बातचीत की और राज्य स्तर पर तनाव प्रबंधन पर बहुमूल्य सुझाव दिए। "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम को 53,86,698 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने देखा।













सामुदायिक लामबंदी 2025-26 के अंतर्गत संचालित अन्य गतिविधियाँ

- अंतर्राष्ट्रीययोगदिवस (आईडीवाई) काआयोजन21.06.2025 को किया जाएगा।
- मिशन लाइफ - एक पेड़ माँ के नाम के लिए इको क्लब पर अभियान
- 5 सितम्बर 2025 को शिक्षक दिवस एवं मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार
- 16 से 30 सितंबर, 2025 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा
- 31 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस का अवलोकन और शपथ ग्रहण समारोह
- 26 नवंबर, 2025 को संबिधान दिवस का अवलोकन
- बाल महोत्सव 'सुरवी' 2025 का अवलोकन
- 11 दिसंबर, 2026 को 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन।
- 21 फरवरी, 2026 कोमातृभाषादिवसपालन
- शक्ति संरक्षण पर चित्रांकन प्रतियोगीता
- वीरता पुरस्कारों के अंतर्गत वीर गाथापरियोजना5.0
- एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का कार्यान्वयन (ओड़िशा-महाराष्ट्र)
- परीक्षा पे चर्चा 2026
- भारत सरकार का फ्लैगसिप प्रोग्राम का कार्यान्वयन



9.5. निशुल्क विद्यालय पोशाक का वितरण

उद्देश्य

- स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए।
- प्राथमिक स्तर पर छात्रों के बने रहने की दर में सुधार करना।
- सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और शुद्ध नामांकन अनुपात (एनईआर) को बढ़ाने के लिए।
- छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना।
- छात्रों में अपनेपन की भावना पैदा करना।
- छात्रों में आत्मविश्वास जगाना और हीन भावना को दूर करना।

तौर-तरीके

समग्र शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क विद्यालय वर्दी का प्रावधान सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा जारी रखने को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों में से एक रहा। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी जिलों को वर्दी की खरीद और वितरण के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश और समयसीमा की जानकारी दी गई थी। कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय पर धनराशि जारी की गई। विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी), विद्यालय अधिकारियों और जिला परियोजना कार्यालयों ने सभी पात्र छात्रों को वर्दी की पारदर्शी खरीद और वितरण सुनिश्चित किया। समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और फील्ड दौरों के माध्यम से निरंतर निगरानी ने राज्य भर में कार्यक्रम के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित किया।

उपलब्धियाँ

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान, समग्र शिक्षा के तहत कक्षा I से VIIIतक में पढ़ने वाले 40,29,518 पात्र छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म सफलतापूर्वक वितरित की गई, जिससे स्वीकृत लक्ष्य का 100% कवरेज हासिल हुआ।

गंगाधर मेहर शिक्षा मानक बुद्धि योजना (जीएमएसएमबीवाई) के तहत मुफ्त स्कूल वर्दी का वितरण उद्देश्य

- सरकारीऔरसरकारीसहायता प्राप्तस्कूलों मेंछात्रोंकीपहुंचऔरउनकीप ढ़ाईजारीर खनेमेंसुधारकरना।
- छात्रों को नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्कूली बच्चों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए एक समान स्कूल यूनिफॉर्म का उपयोग करना।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए।
- प्रत्येक बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण का निर्माण करना।



तौर-तरीके

गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धी योजना (राज्य अनुदान) के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को निःशुल्क विद्यालय वर्दी प्रदान की गई। वर्दी की समयबद्ध खरीद और वितरण के लिए सभी जिलों और विद्यालयों को विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए गए। पारदर्शिता, निधि के समयबद्ध उपयोग और सभी पात्र लाभार्थियों को वर्दी के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित निगरानी की गई।

उपलब्धियों

2025-26 के दौरान, गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धी योजना के तहत 43,09,441 पात्र छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई, जिससे स्वीकृत लक्ष्य का 100% हासिल किया गया।

मुख्यमंत्री छात्र-छात्रा परिधान योजना (एमसीसीपीवाई) के तहत निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण

उद्देश्य

- माध्यमिकस्तरपरछात्रोंकेनामांकनऔरउनकी उपस्थिति को बढ़ाना
- छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना
- प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में संक्रमण को बेहतर बनाना
- छात्रों के बीच समानता को बढ़ावा देना
- किशोरों में आत्मविश्वास जगाने और उन्हें निरंतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना

तौर-तरीके

मुख्यमंत्री छात्र-छात्र परिधान योजना (एमसीसीपीवाई) के तहत कक्षा नौवीं और दसवीं में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को निःशुल्क विद्यालय वर्दी प्रदान की गई। वित्तीय मानदंडों के साथ-साथ विस्तृत परिचालन दिशानिर्देशों की जानकारी समयानुसार सभी जिलों में कार्यान्वयन किया गया।

समय पर कार्यान्वयन। जिला अधिकारियों ने वर्दी की खरीद और वितरण की नियमित रूप से निगरानी की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र छात्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना के तहत लाभ प्राप्त हो।





उपलब्धियाँ

2025-26के दौरान, कक्षा IX और X में पढ़ने वाले 10,10,789 छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई।इस योजना के तहत स्वीकृत लक्ष्य का 100%हासिल हुआ।



शिशु वाटिका (राज्य अनुदान) के अंतर्गत निःशुल्क विद्यालय पोशाक वितरण

उद्देश्य

- बच्चोंकोऔपचारिकस्कूलीशिक्षामेंसुचारूरूपसेप्रवेशकराना
- प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहित करना
- अभिभावकों पर वित्तीय बोझ कम करना
- बच्चों के अनुकूल और समावेशी शिक्षण वातावरण प्रदान करना
- स्कूली शिक्षा की शुरुआत से ही नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना

तौर-तरीके

शिशु वाटिका (राज्य अनुदान) योजना के तहत, राज्य भर में शिशु वाटिका में नामांकित बच्चों को निःशुल्क विद्यालय यूनिफॉर्म प्रदान की गई। समय पर खरीद और वितरण के लिए जिलों को विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश भेजे गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी की गई कि नियमित कक्षा गतिविधियाँ शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म मिल जाए।



उपलब्धियाँ

2025-26 के दौरान, शिशु वाटिका के 3,10,839 पात्र छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई, जिससे स्वीकृत लक्ष्य का 100% हासिल हुआ।

9.6. निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक

ओडिशा के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों/मदरसों सहित कक्षा प्रथम से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्णयानुसार, भुवनेश्वर स्थित टीबीपी एंड एम द्वारा पाठ्यपुस्तकों की छपाई की जाती है और राज्य के 30 जिलों के सभी ब्लॉक केंद्रों (एबीईओ-सह-बीआरसी केंद्र) और फिर विद्यालयों में आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाती है। पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति दिसंबर 2025 से शुरू हुई और 2025-26 के दौरान राज्य के सभी 30 जिलों में 100% नई पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं।

सत्र	लाभार्थियों की संख्या (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)	बजट (लाख रुपये में)	उपलब्धि का प्रतिशत (भौतिक)	निगरानी तंत्र	समस्याओं के समाधान के लिए रणनीतियाँ
2025-26(एसएस)	4312274	13326.353	100%	जिले के सभी नोडल अधिकारी। सभी एबीईओ-सह-बीआरसीसी/सीआरसीसी/एचएम/एस एमसी सदस्य आदि।	सभी प्रधान शिक्षक/सीआरसीसी/एबीईओ-सह-बीआरसीसी/एसएमसी सदस्य/बीईओएस/डीपीसीएस पाठ्यपुस्तकों आदि के वितरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगे।
2025-26(एसएस)	128222	464.882	100%	जिले के सभी नोडल अधिकारी। सभी एबीईओ-सह-बीआरसीसी/सीआरसीसी/एचएम/एस एमसी सदस्य आदि।	सभी गृह मंत्री/सीआरसीसी/एबीईओ-सह-बीआरसीसी/एसएमसी सदस्य/बीईओएस/डीपीसीएस पाठ्यपुस्तकों आदि के वितरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगे।
कुल	**4440496**	**13791.235**			

पाठ्य-पुस्तक वितरण

TEXT BOOK DISTRIBUTION











ढेंकानाल जिले में पाठ्यपुस्तक वितरण

9.7. पहुंच एवं प्रतिधारण

9.7.1. नेताजी सुभाषचंद्र आवासीय विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समग्र शिक्षा के अंतर्गत 6-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने पर जोर देती है। उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। राज्य में कुल 90731 बस्तियों में से 87750 बस्तियों में प्राथमिक और 88721 बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। दूरस्थ और दुर्गम बस्तियों के बच्चों, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और 1 किमी से अधिक दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय, 3 किमी से अधिक दूरी पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय और 5 किमी से अधिक दूरी पर स्थित माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार बच्चों को उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में कई कठिन श्रेणियों के बच्चे, जैसे बाल श्रमिक, सड़क पर रहने वाले बच्चे, कूड़ा बीनने वाले, अनाथ, एकल अभिभावक, बेघर बच्चे आदि, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कुछ स्कूली माहौल में बने नहीं रह पाते और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। 21 नग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय छात्रावास/विद्यालय) बरगढ़, कटक, गंजाम, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज और रायगढ़ जिलों में संचालित हो रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों से बचाए गए वंचित शहरी बच्चों को राष्ट्रीय एवं बाल विकास एवं विकास विभाग (एनएससीबीएवी) (आवासीय छात्रावास/विद्यालय) में पुनर्वासित किया जाता है। दूरस्थ, पहाड़ी, वन या दुर्गम बस्तियों के बच्चों को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, कल्याण विभाग, केजीबीवी आदि के सेवा श्रमों में सुविधा प्रदान की जाती है।

6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान शिक्षकों और सीआरसीसी द्वारा की जाती है और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया जाता है। विद्यालय में आयु-उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को आरटीई अधिनियम के अनुसार विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन एसआईओएस केंद्रों में किया जाता है। प्रवासी बच्चों को उनके माता-पिता के प्रवास से लौटने तक उनके लिए मौसमी छात्रावासों में रखा जाता है और उनकी पढ़ाई जारी रखी जाती है।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय छात्रावास/विद्यालय)

शहरी वंचित बच्चों की कठिन श्रेणी, जैसे बाल श्रम करने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, वयस्क संरक्षण के बिना बच्चे, अनाथ बच्चे, कठिन परिस्थितियों में शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे आदि को शहरी क्षेत्रों से बचाकर आवासीय छात्रावासों में पुनर्वासित किया जाता है, जिससे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित होती है। बरगढ़, कटक, गंजाम, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल, खुर्दा, क्योंझर, मयूरभंज, मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ जिलों में कुल 21 एनएससीबीएवी (आवासीय छात्रावास/विद्यालय) कार्यरत हैं।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय की स्थिति, 2025-26

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय (आवासीय छात्रावास/स्कूल) समग्र शिक्षा, 2025-26							
क्र.सं	जिलों के नाम	ब्लॉक	आवासीय छात्रावास/स्कूल	यूडाइस कोड	चालू वर्ष	दक्षता	छात्रावास में अंतेवासियों की संख्या
1	बरगढ़	बरगढ़	सिमेंट नगर हाईस्कूल	21010303401	2016-17	50	19
2	कटक	सदर	मधुसूदन, सरकारी हाईस्कूल	21121804614	2016-17	50	26
3	गजपति	पारलाखेमुंडी	गांधी मेमोराल .यूपीएस	21200900702	2016-17	50	38
4	गंजाम	छत्रपुर	रघुनाथपुर यूपी स्कूल	21190605801	2016-17	50	33
5	कलाहांडी	भवानीपाटना	बापुजी यूपीएस, भवानीपाटना	21261401302	2016-17	50	47
6	कंधमाल	बालिगुड़ा	ब्लक कलोनी पीयूजीएस, बालिगुड़ा	21211501201	2016-17	50	50
7	केंदुझर	केंदुझर, सदर	अत्तपुर नोडाल यूपी स्कूल, केंदुझर सदर	21061700501	2012-13	100	66
8	केंदुझर	बड़बिल	बड़बिल नोड़ाल यूपी स्कूल, बडॉबिल	21061500602	2012-13	100	85
9	खोर्धा	भुवनेश्वर एमसी	सरकारी, हाईस्कूल यूनिट-1, भुवनेश्वर	21171303604	2012-13	50	47
10	खोर्धा	भुवनेश्वर एमसी	राजिवभवन प्रकल्प, यूपी स्कूल, यूनिट-VIII भुवनेश्वर	21171302905	2013-14	50	50
11	खोर्धा	भुवनेश्वर एमसी	सरकारी हाईस्कूल, यूनिट-VI,भुवनेश्वर(बालिकाओं के लिए)	21171303503	2013-14	50	49
12	खोर्धा	भुवनेश्वर एमसी	सरकारी, प्राइमरी स्कूल आईआरसी विलेज, सेक्टर-1 भुवनेश्वर	21171301002	2013-14	50	44
13	कोरापुट	सिमिलागुड़ि	एमआईजी IV पीयूपीएस, सुनाबेड़ा	21291800104	2018-19	50	50
14	कोरापुट	पोटांगि	नेरिदिवालास पीएस, आरजूवलसा, कोटिआ जीपी(एलडब्लूई) सह-शिक्षा	21291304201	2018-19	100	100

15	कोरापुट	दशमंतपुर	गुरलिगुमा यूजिएचएस, दशमंतपुर (एलडब्लूई) बालिकाओं के लिए	21290407601	2018-19	100	100
16	मालकानगिरि	मालकानगिरि	सरकारी, नोडाल यूपीएस	21300900804	2016-17	50	50
17	मालकानगिरि	कोरकोंडा	नीलाद्रिनगर पीयूपीएस, नीलकांबेरू जीपी, कोरकुंडा(एलडब्लूई)	21300307004	2018-19	100	100
18	मालकानगिरि	पोडिआ	कलदापालि यूजीएचएस, पोडिआ (एसडब्लूई)	21300701001	2019-20	100	100
19	मयूरभंज	बारिपदा	पूर्णचंद्रपुर प्रोजेक्ट यूपी स्कूल,बारिपदा	21072701501	2014-15	100	99
20	मयूरभंज	बिसोई	बिसोई यूजी हाईस्कूल	21070705602	2015-16	100	100
21	रायगढ़ा	रायगढ़ा	जीबीएम हाईस्कूल, रायगढ़ा	21271400501	2016-17	50	50
कुल						**1450**	**1303**

आवासीय विद्यालय में गतिविधियाँ

अंतेवासी छात्रावास में एक साथ बैठकर अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं



अंतेवासियों का आत्मरक्षा और योगा क्लास





व्यावसायिक क्लास





9.7.2 परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधाएं:

सरकार के विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग ने दिनांक 25.2.2019 को अधिसूचना संख्या 4661 के माध्यम से उन बच्चों के लिए परिवहन/सहायक सुविधाओं की सहायता प्रदान करने के प्रावधान किए हैं जो विरल आबादी वाले दूरस्थ बस्तियों में या पहाड़ी क्षेत्रों, घने वन क्षेत्रों आदि में स्थित बस्तियों में या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां भूमि की उपलब्धता एक समस्या है या अत्यंत वंचित समूह से संबंधित बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो निम्नलिखित शर्तों के अनुसार विद्यालय तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

क. जहां स्कूलों के युक्तिकरण की नीति के अनुसार सैटेलाइट स्कूल (कम नामांकन) का मुख्य स्कूल में विलय होने के कारण बच्चों को आसपास के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है और उन्हें प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए 1 किमी से अधिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए 3 किमी से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है।

ख. जहां कम आबादी वाली बस्तियों के बच्चे हों और जहां स्कूल खोलना संभव न हो और जहां आस-पास का प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो।

ग. जहां बच्चे घने जंगल वाले इलाकों में स्थित बस्तियों में रहते हैं और स्कूल जाते समय जंगली जानवरों द्वारा उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न होने का डर रहता है।

घ. जहां बरसात के मौसम में नदी/खाई आदि के कारण बच्चों को किसी प्राकृतिक बाधा का सामना करना पड़ता है।

परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा की स्थिति 2025-26

वर्ग	पीएबी द्वारा अनुमोदित बच्चों की संख्या (प्राथमिक और माध्यमिक)	बच्चों की संख्या जिन्हें परिवहन/सहायक सुविधा प्रदान की गई है
दूरस्थ बस्तियों और संयुक्त विद्यालयों के बच्चे	31635	28120

9.7.3 नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उद्घाटन:

ओडिशा सरकार, विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ने अधिसूचना संख्या 22554, दिनांक 26.09.2013 के माध्यम से आरटीई अधिनियम के अनुसार एनपीएस और एनयूपीएस खोलने की अधिसूचना जारी की है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-6 के तहत ओडिशा में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियम, 2010 के नियम 6(4) के अनुसरण में, राज्य सरकार ने उक्त नियम की धारा-6(1) में निर्दिष्ट सीमा के साथ बाल मानदंड जोड़कर राज्य में नए प्राथमिक एवं नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए निम्नलिखित प्रावधान लिए हैं।

(i) नए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन:

क. गैर-केबीके जिलों और गैर-आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में, 6-11 वर्ष आयु वर्ग के कम-से-कम 40 बच्चों वाली बस्तियों में नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, बशर्ते कि ऐसी बस्तियों से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर कोई प्राथमिक विद्यालय न हो।

ख. केबीके जिलों और जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में, ऐसे बस्तियों/ क्लस्टर के समूहों में नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं जिनमें 6-11 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 25 बच्चे हों, बशर्ते कि ऐसी बस्तियों से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर कोई प्राथमिक विद्यालय न हो।

(ii) नए उच्च प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन:

क. सभी जिलों में, ऐसे बस्तियों/ क्लस्टरों के समूहों में नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं जिनमें 11-14 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 25 बच्चे हों, बशर्ते कि ऐसी बस्तियों से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो।

सभी जिलों में, नदी, पहाड़ी इलाका, घना जंगल आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं के मामले में नए प्राथमिक और नए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के लिए दूरी के मानदंड में छूट दी गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सरकार ने स्कूल खोलने के मानदंडों को पूरा करने वाले 92 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत करने की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति डीईई द्वारा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता रद्द करने के बाद दी गई है। जिलेवार उन प्राथमिक विद्यालयों की सूची नीचे दी गई है जिन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत किया गया है और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क्र.सं	जिलों का नाम	ब्लक का नाम	प्राथमिक विद्यालयों का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति
1	अनगूल	अनगूल	कुंभकर्नसाहि पीएस
2	अनगूल	पालाहारा	सरकारी प्राथमिक विद्यालय,चुंगामाटिआ
3	अनगूल	छेंदिपड़ा	कुशकिला प्राथमिक विद्यालय
4	अनगूल	छेंदिपड़ा	सरकारी, प्राथमिक विद्यालय, दुवानालि
5	अनगूल	तालचेर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, चलगड़
6	बालेश्वर	सदर	भागलपुर पीएस
7	बालेश्वर	सोरो	सोलागाँव प्राथमिक विद्यालय
8	बालेश्वर	सोरो	आदिआ सरकारी प्राथमिक विद्यालय
9	बालेश्वर	औपदा	धिमपुरा प्राथमिक विद्यालय
10	बालेश्वर	औपदा	कंदागारड़ि प्राथमिक विद्यालय
11	बालेश्वर	सदर	अलुमेदा सरकारी प्रहाथमिक विद्यालय
12	बालेश्वर	सदर	सुलाद सरकारी प्राथमिक विद्यालय
13	बालेश्वर	भोगराई	महम्मदपुर प्राथमिक विद्यालय
14	बालेश्वर	भोगराई	पुरुषोत्तमपुर प्राथमिक विद्यालय
15	बालेश्वर	भोगराई	चांदकुसुमि प्राथमिक विद्यालय
16	बालेश्वर	भोगराई	कांताबानी प्राथमिक विद्यालय
17	बालेश्वर	बस्ता	सरकारी प्राइमरी स्कूल, धानहंडा
18	बालेश्वर	जलेश्वर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, तेंतुला
19	बालेश्वर	जलेश्वर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, एकतालि
20	बालेश्वर	जलेश्वर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, उत्तरपड़ा
21	बालेश्वर	जलेश्वर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, हातीगड़
22	बालेश्वर	जलेश्वर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पुरुणापानी
23	बालेश्वर	बस्ता	तलतपंडा सरकारी पीएस
24	बालेश्वर	रेमुणा	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बाउँसमुँहा
25	भद्रक	भंडारीपोखरी	बालिपुर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय
26	भद्रक	चंदाबली	उत्तकुडा सरकारी पीएस
27	भद्रक	चंदाबली	करंजामाल सरकारी पीएस
28	भद्रक	बअंत	सरकारी पीएस पनपड़ी
29	भद्रक	बअंत	सरकारी पीएस हसिनपुर
30	भद्रक	भंडारीपोखरी	आकुलिकना सरकारी पीएस
31	भद्रक	भंडारीपोखरी	मधुपड़ा पीएस

32	भद्रक	तिहिड़ि	मालपुर पीएस
33	कटक	माहांगा	मोगलपाटना प्राथमिक विद्यालय
34	देवघर	तिलेइबणि	कलंदा सरकारी पीएस
35	ढेंकानाल	भूवन	दयानबिलि पीएस
36	ढेंकानाल	कामाक्षानगर	खोकासा नूआसाहि प्राथमिक स्कूल
37	ढेंकानाल	हिंदोल	कंटिमिलि सरकारी पीएस
38	ढेंकानाल	कामाक्षानगर	अघोरीगोड़ा प्राथमिक विद्यालय
39	गंजाम	दिगपहांडी	सरकारी पीएस बनमाली
40	गंजाम	दिगपहंडी	राजपुर प्राथमिक विद्यालय
41	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, उराली
42	जाजपुर	कोरेइ	गोहमारी सरकारी प्राथमिक विद्यालय,
43	जाजपुर	दशरथपुर	झुंपुरी प्राथमिक विद्यालय
44	जाजपुर	रसुलपुर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बालिगुड़ा
45	जाजपुर	धर्मसाला	कोठडिहा प्राथमिक विद्यालय,कोठडिहा
46	जाजपुर	बड़चणा	रामदासपुर पीएस
47	जाजपुर	जाजपुर	खइराबाड़ प्राथमिक विद्यालय
48	जाजपुर	दानगदि	रावण प्राथमिक विद्यालय
49	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	कुतुम चांदी सरकारी प्राथमिक विद्यालय
50	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, निनिगाँव
51	झारसुगुड़ा	झारसुगुड़ा	कुकुरजंघा पीएस
52	झारसुगुड़ा	लखनपुर	सरकारी पीएस कटरबागा
53	कलाहांडी	धर्मगड़	कदलीमुंडा पीएस
54	कलाहांडी	गोलामुंडा	सरकारी पीएस फंडा
55	कलाहांडी	केसिंगा	सरकारी पीएस डेंडगुड़ा
56	कलाहांडी	गोलामुंडा	गंडामेर सीपीएस
57	केंद्रापड़ा	आली	हाडूआ प्राथमिक विद्यालय
58	केंद्रापड़ा	आली	कुमारटंका सरकारी विद्यालय
59	केंदुझर	पाटना	सरकारी प्राइमरी विद्यालय
60	केंदुझर	साहरपड़ा	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, देउलिपोसी
61	केंदुझर	घटगाँ	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, देनगना
62	केंदुझर	तेलकोई	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सरेई

63	केंदुझर	हरिचंदनपुर	सरकारी पीएस गेह्लामुंडा
64	केंदुझर	हरिचंदनपुर	सरकारी पीएस चस्तांगीरि
65	केंदुझर	हरिचंदनपुर	सरकारी पीएस पेंथाडिही
66	केंदुझर	हाटडिहि	सरकारी पीएस भूतपड़ा, अप्सरा
67	केंदुझर	हरिचंदनपुर	सरकारी पीएस पिथागोला
68	केंदुझर	पाटना	सरकारी पीएस बेगुनखामन
69	केंदुझर	आनंदपुर	सरकारी पीएस भोगपुर
70	खोर्धा	बीएमसी	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, रेलवे कॉलोनी, मंचेश्वर
71	खोर्धा	बाणपुर	सरकारी पीएस बेरुआँबाड़ी
72	कोरापुट	पोटांगी	ताड़िवाल्सा सरकारी प्राथमिक विद्यालय
73	कोरापुट	कुंड्रा	फिलभट्टा पीएस
74	मयूरभंज	कुलिअना	सरकारी पीएस माधपुर
75	मयूरभंज	कस्निपदा	सरकारी पीएस पद्मपोखरी
76	नवरंगपुर	झारिगाँव	सरकारी पीएस कोडभट्टा
77	नवरंगपुर	झारिगाँव	सरकारी पीएस धंदामाल
78	नवरंगपुर	झारिगाँव	सरकारी पीएस अम्लिजोड़ी
79	नवरंगपुर	नवरंगपुर	सरकारी प्राथमिक विद्यालय चुराहांडी
80	नवरंगपुर	राइघर	निनासपानी पीएस
81	नवरंगपुर	राइघर	सालेभट्टा (एम) पीएस
82	नवरंगपुर	दसपल्ला	सरकारी पीएस दसनिपड़ा
83	नयागढ़	नूआगाँव	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, खुंटुबंधा
84	नयागढ़	रानपुर	लुनिसाहि पीएस
85	नयागढ़	ओड़गाँ	सरकारी पीएस बड़पुट
86	पुरी	ब्रह्मगिरि	साहानिकेरा पीएस
87	पुरी	अस्तरंग	बालिडिआ पीएस
88	पुरी	अस्तरंग	देरुनिआ पीएस
89	पुरी	पिपिलि	सिउला सेंटर पीएस
90	पुरी	देलांग	सिंहब्रह्मपुर प्राथमिक विद्यालय
91	पुरी	कणास	ग्राहसनपुट प्राथमिक विद्यालय

9.7.4 विद्यालयों का युक्तिकरण और समेकन:

विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ने अधिसूचना संख्या 5465 दिनांक 11.3.2020 और शुद्धिपत्र संख्या 18905 दिनांक 14.12.2020 के माध्यम से विद्यालयों के युक्तिकरण और एकीकरण की नीति को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, एक ही परिसर में उच्च विद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक एकीकृत माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण करना, बदलाव प्रक्रिया को सुगम बनाना और राज्य संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। एकीकरण के प्रकार नीचे उल्लख हैं।

क) अनुसूचित और केबीके क्षेत्रों में 15 या उससे कम नामांकन वाले तथा अन्य क्षेत्रों में 20 या उससे कम नामांकन वाले सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को दूरी की परवाह किए बिना आसपास के विद्यालयों के साथ समेकित कर दिया जाएगा।

ख) गैर-टीएसपी और गैर-केबीके क्षेत्रों के लिए प्राथमिक विद्यालय जिसमें 40 से कम नामांकन हों और केबीके और टीएसपी क्षेत्रों के लिए 25 से कम नामांकन हों तथा निकटतम प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय की दूरी 1 किमी हो।

ग) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयएक ही परिसर में या 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो।

घ) सरकार ने वर्ष 2020-21 में प्रमुख विद्यालय के साथ समेकित के लिए 7750 विद्यालयों को अधिसूचित और अनुमोदित किया है। अब तक 5633चयन्वित विद्यालयों का प्रमुख विद्यालयों के साथ समेकन हो चुका है।



9.8. मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाना

आरटीई के आलोक में समग्र शिक्षा में सिविल निर्माण विभाग की भूमिका आरटीई के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य भर में आवश्यकतानुसार भौतिक अवसंरचना प्रदान करना है, अर्थात् प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, जिसका मुख्य लक्ष्य प्रासंगिक एवं प्रभावी शिक्षण परिणामों की ओर ले जाने वाली एक सतत प्रणाली स्थापित करना है। स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ एसएमसी/एसएमडीसी के माध्यम से कार्य निष्पादन, न कि किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से, एसएस सिविल निर्माण विभाग की प्रमुख विशेषता है और यह राज्य में सतत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नए रास्ते खोलता है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली कई समस्याओं के समाधान के लिए लगातार उचित योजना बनाई जा रही है। इन समस्याओं में जमीनी स्तर पर विश्लेषण, आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन, प्राथमिकता निर्धारण, सीमित उपलब्ध निधियों से आवश्यक गतिविधियों के लिए सही समय पर धन जुटाना और उसका उपयोग करना, तथा परियोजना को यथासंभव पूर्ण और व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्य विभागों से संभावित संसाधनों की खोज करना शामिल है।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) जैसी सहयोगी परियोजनाओं नेनिश्चित रूप से समान उद्देश्य और लक्ष्य के साथमुख्यधारा के लिए कार्यक्रम को पूरक बनाने में काफी योगदान दिया है।

इस परियोजना का उद्देश्य न केवल नए स्कूल या अतिरिक्त कक्षाएँ जैसी बुनियादी संरचनाएँ बनाना हैबल्कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, विद्युतीकरण आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ प्रदान करना और स्कूलों का बेहतर माहौल बनाना भी है, ताकि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की पहुँच बढ़े और स्कूली शिक्षा छोड़ने वालों की संख्या कम हो। योजना प्रक्रिया में बाल एवं शिशु सहायता (सीडब्ल्यूएसएन) पर विशेष ध्यान देना भी शामिल है।





राज्य में स्कूली शिक्षा स्तर पर बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित योजना बनाई जा रही है और परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई जा रही हैं।

राज्य में पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा की देखरेख कर रहा है। बाल एवं शिशु सहायता प्राप्त बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए विद्यालयों तक बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

प्राथमिक

सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए प्रमुख कार्य

➢ एसएमसी/एसएमडीसी के पक्ष में निधियों की सीमा का निर्धारण तीन चरणों में किया जाएगा, अर्थात् पहले चरण में 40%, दूसरे चरण में 30% और तीसरे चरण में एफएमपी के अनुसार अनुमानित लागत का शेष 30%।

➢ गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समय पर सिविल कार्यों के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सलाहकारों, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकारों और जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा सिविल अवसंरचनाओं की नियमित निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है।

➢ जिला परियोजना कार्यालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन।

➢ राज्य परियोजना कार्यालय में नियमित अंतराल पर व्यक्तिगत रूप से/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

➢ जिला स्तर पर सिविल कार्यों को क्रियान्वित करने वाले समुदाय/एसएमसी/एसएमडीसी तथा कुशल कर्मियों/श्रमिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

➢ विद्यालय भवन के निर्माण के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण विशेषताएं:

➢ स्थानीय कौशल और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग हेतु लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण अनुकूल निर्माण कार्यों को अपनाना।

➢ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विद्यालय सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बहु-खतरा प्रतिरोधी विशेषताएं।

➢ आनंददायक शिक्षण वातावरण

➢ एसएमसी सदस्यों को एसएमसी और तकनीकी कर्मियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, उपयुक्त योजनाओं के चयन, श्रम की व्यवस्था में समुदाय को शामिल करने, सामग्री खरीदने और निर्माण कार्य को गति देने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, लेखा प्रबंधन और निर्माण के बाद रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण देना, जिससे स्थिरता प्राप्त हो सके।

➢ गुणवत्ता नियंत्रण

निगरानी और पर्यवेक्षण

- संबंधितजिलेकेवरिष्ठतकनीकीसलाहकार, तकनीकी सलाहकार और वित्तीय सलाहकार नियमित अंतराल पर एसपीओ में/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं।
- दो महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे छत की ढलाई और खाते का निपटान आदि के लिए टीसी के लिए सप्ताहवार कार्य योजना लक्ष्य निर्धारित करना और साथ ही डीपीओ को इसके यूसी जमा करना।
- जिला परियोजना कार्यालय में डी.पी.सी. द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है और कलेक्टर-सह-अध्यक्ष द्वारा मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।
- भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा।

- बिलों के भुगतान से पहले ओपीडब्ल्यूडी / समग्र शिक्षा के दिशानिर्देशों के अनुसार माप पुस्तिका (एमबी) की जांच करना।
- फील्ड स्तर पर तकनीकी सलाहकारों को जिन विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर चर्चा करें और उनके समाधान बताएं।
- निधि प्रवाह, खाते का निपटान और यूसी जमा करना।

- समुदाय को तकनीकी मार्गदर्शन

ब्लॉकस्तरपरनिर्माणगतिविधियोंमेंएसएमसीकोसहयोगदेनेकेलिएतकनीकीसलाहकारद्वाराइंजीनियरोंकीसेवाएंप्रदानकीजातीहैं औरजिलास्तरपरकार्योंकीनिगरानीकेलिएवरिष्ठतकनीकीसलाहकारद्वारासेवाएं प्रदान की जाती हैं।ये इंजीनियर निर्माण स्थलों का दौरा करके कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सिविल कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए डीपीओ (विधान निर्माण अधिकारी) के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। वे प्रत्येक कार्य के लिए माप पुस्तिका में माप भी दर्ज करते हैं। निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के तकनीकी ज्ञान को उन्नत करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण-सह-अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- विद्यालयभवनकेनिर्माणकेदौरानअपनाईगईमहत्वपूर्णविशेषताएं:

किफायतीप्रौद्योगिकियाँ:

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग,
- विद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए स्थानीय कौशल का उपयोग।

- एसएमसीकोपरंपरागतलालईंटकेस्थानपरफ्लाईऐशईंटकेउपयोगकेलिएप्रोत्साहितकरना, जो न केवल किफायती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।

II. संकट प्रतिरोधी विशेषताएँ :

भूकंप, बाढ़ और चक्रवात संभावित क्षेत्रों में स्थल-विशिष्ट डिज़ाइन तैयार करने के लिए वल्नरेबिलिटी एटलस का अनुसरण किया जा रहा है। नवीनतम कोड विनिर्देशों के अनुसार विभिन्न आपदा-रोधी विशेषताएं प्रदान की गई हैं। कार्य निष्पादन के दौरान एसएस और एनबीसी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

III. भवन निर्माण योजनाएँ और डिज़ाइन (स्थल-विशिष्ट डिज़ाइन)

- बाढ़
- रिकॉर्डकिएगएएच.एफ.एल. केआधारपरप्लिंथलेवलकोठीककरनाऔरदीवारोंमेंपानीकीकेशिकाक्रियाकोरोकना।
- नींव के कटाव को रोकने के लिए चबूतरे की सुरक्षा।
- बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में सीढ़ियाँ।

- चक्रवात
- सीमितरिक्तियांऔरउनकीनियुक्तियां

- भूकंप
- जोखिमक्षेत्रकेमानचित्र, जो भेद्यता एटलस में उपलब्ध हैं, का उपयोग शमन उपायों को तय करने के लिए किया जाता है।
- बॉक्स जैसी संरचना के रूप में व्यवहार करने के लिए, कोडाल विनिर्देशों के अनुसार प्लिंथ और लिंटेल स्तरों पर क्षैतिज पट्टियाँ (बॉक्स क्रिया विकसित करने के लिए) और ऊर्ध्वाधर पट्टी (छत और प्लिंथ के बीच उचित जुड़ाव के लिए) प्रदान की गई हैं।
- भवनडिजाइनऔरविकल्प
- राज्यभरमेंएसबीसीकेअनुसारविभिन्नमृदास्थितियोंकेअनुरूपविकसितनींवडिजाइनोंकेप्रकार।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्री (लेटराइट/ग्रेनाइट/फ्लाई ऐश ईंटें/पत्थर) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।
- निर्माण लागत को कम करने के लिए आरसीसी डिजाइनों में संशोधन किया गया।

IV. भवन में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान:

ड्रिप कोर्स, प्लिंथ प्रोटेक्शन, बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइप आदि।

V. अन्य महत्वपूर्ण भवन घटक:

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए रैंप और रेलिंग, बच्चों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन उपकरण, विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था की गई है।

VI.आकर्षक एवं सीखने का वातावरण:

- बच्चोंकेअनुकूलझूले, स्लाइड, सी-सॉ आदि जैसी सुविधाएं।
- इसमें अंतर्निहित शिक्षण घटक जैसे कि दीवारों पर चित्र, दीवार पेंटिंग, अक्षर और संख्या दर्शाने वाली ग्रिल, बच्चों का चॉक बोर्ड, सीखने के कोने, अलग-अलग डिजाइन वाला बरामदा आदि शामिल हैं।
- क्षमतानिर्माण -1
- एसएमसी
- एसएमसीऔरतकनीकीकर्मियोंकीभूमिकाएँऔरजिम्मेदारियाँ।
- स्थल की उपलब्धता के अनुसार उपयुक्त योजनाओं का चयन करना।
- निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में एसएमसी सदस्यों की क्षमता निर्माण
- निर्माण नियमावली (स्थानीय भाषा / चित्रात्मक प्रस्तुति); निर्माण विनिर्देशों और प्रक्रियाओं को समझाने वाले पत्रक (स्थानीय भाषा); संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल;

  लघु एवं मध्यम आकार की निर्माण कंपनियों (एसएमसी) के बीच आसानी से समझने के लिए, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, डिजाइन विनिर्देशों, निर्माण प्रक्रियाओं आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाली वृत्तचित्र फिल्म, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पत्रक ओडिया भाषा में तैयार किए गए हैं।
- एसएमसीऔरइंजीनियरोंकोनियमितप्रशिक्षणदियाजारहाहैताकि वे समुदाय के माध्यम से निर्माण कार्यों की प्रक्रियाओं, एसएमसी और इंजीनियरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित हो सकें।
- एकसमानयूसीप्रारूप, वित्त सलाहकारों द्वारा आयोजित लेखा रखरखाव पर अलग एसएमसी प्रशिक्षण।
- एमटीएकागठनकरनाऔरएसएमसी (पखवाड़ेमें एक बार), एमटीए और पीटीए की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना।

- क्षमतानिर्माण -2
- राजमिस्त्री
- किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाना और डिजाइन विनिर्देशों को बनाए रखना।
- राजमिस्त्रियों को तकनीकी प्रशिक्षण ओएसईपीए द्वारा स्थानीय भाषा में प्रकाशित तकनीकी पुस्तिका "शिक्षा नीदा" की सहायता से दिया जा रहा है।
- स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार, तकनीकी कर्मियों के निर्णय के अनुसार OPWD कोड और SS मानदंडों का पालन करते हुए नींव के प्रकार, अर्थात् पाइल, कॉलम और ओपन फाउंडेशन को अपनाया जा रहा है।
- क्षमतानिर्माण -3
- कर्मचारी
- गुणवत्तानियंत्रण उपायों पर प्रशिक्षकों के लिए अर्धवार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम।
  परीक्षण (व्यावहारिक प्रदर्शन), पर्यवेक्षण और निगरानी, बिल तैयार करना और यूसी जमा करना।
- वर्तमानमेंस्वीकृत33 पदों में से 30 जिलों में 21 वरिष्ठ टीसीएस (सीनियर टीसी) और 314 ब्लॉकों में 253 टीसीएस तथा स्वीकृत 316 पदों में से 2 यूएलबी (यूएल) में टीसी हैं। इसके अलावा एसपीओ में 3 टीसी हैं।

- गुणवत्तानियंत्रण
- रेत के लिए परीक्षण

बारीक रेत के लिए महीनता मापांक (F.M) परीक्षण किया जाता है और यह 1.5 या उससे अधिक होता है। मोटी रेत के लिए, महीनता मापांक (F.M) 2.5 से 3.5 के बीच होता है। रेत का वर्गीकरण मोटरयुक्त छलनी शेकर द्वारा छलनी विश्लेषण से किया जाता है।

- ईंटकेलिएपरीक्षण

ईंटों का जल अवशोषण परीक्षण खेत स्तर पर किया जाता है।
ईंट की संपीडन शक्ति का भी परीक्षण किया जाता है।
ईंट की कुचलने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है।

- कंक्रीट के लिए परीक्षण
- घनपरीक्षण:

सीमेंट कंक्रीट की संपीडन सामर्थ्य का परीक्षण 15 x 15 x 15 सेमी आकार के कंक्रीट घन का परीक्षण करके संपीडन परीक्षण मशीन द्वारा किया गया।

- स्लंपपरीक्षण:

गाढ़ापन निर्धारित करने के लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है।

- विद्यालयसुरक्षाप्रावधान: भूकंप के लिए प्रावधान विद्यालय के आधारभूत संरचना के डिजाइन में प्रतिरोधी संरचना, अग्नि सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं आदि का ध्यान रखा गया है। (चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, भवनों का निर्माण ऐसी आपदाओं का सामना करने के लिए किया जा रहा है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भवनों को ऊंचे चबूतरे के साथ डिजाइन किया गया है, चक्रवात और भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों के लिए भवन में उचित स्थान पर खिड़कियां और क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पट्टियां लगाई गई हैं। भवनों में अग्निरोधक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।)

माध्यमिक:

माध्यमिक विद्यालयों के सिविल कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग, पंचायती राज की पंचायती राज संस्थाओं, पेयजल विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं।

नया स्कूल (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक):

प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को क्रमशः उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया है। इन विद्यालयों में फर्नीचर सहित कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भौतिकी प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला आदि जैसी प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

आधारभूत संरचना को मजबूत करना:

शहरी विकास और विकास विभाग (यू-डीआईएसई) की रिपोर्टों और आधारभूत संरचना की कमियों के आधार पर मौजूदा आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया गया है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, कला/शिल्प कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा और विद्युतीकरण जैसी सुविधाएं मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अंतर्गत आती हैं।

गर्ल्स हॉस्टल (केजीबीवी-IV):

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, विद्यालयों में अधिक से अधिक बालिकाओं को लाने और उन्हें शिक्षा जारी रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (ईबीबी) और लक्षित समूहों की अधिकता वाले क्षेत्रों में आवास और भोजन सुविधाओं से युक्त छात्रावास स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि सामाजिक कारकों के कारण बालिकाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य अधिक से अधिक बालिकाओं के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को सुलभ बनाना है।

गतिविधियाँ इस प्रकार हैं

➢जमीनी स्तर पर योजना बनाना,
➢आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन,
➢गतिविधियों का प्राथमिकता निर्धारण,
➢उपलब्ध सीमित निधियों में से धन जुटाना और सही समय पर सही गतिविधि के लिए उसका उपयोग करना।
➢परियोजना को यथासंभव पूर्ण और यथार्थवादी रूप देने के लिए अन्य एजेंसियों से संभावित संसाधनों की खोज करना आदि।

आस-पास का वातावरण:

विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्युत सुविधा से युक्त पर्याप्त कक्षा भवन, स्वच्छ वातावरण, परिसर में हरियाली से युक्त विशाल खेल का मैदान, ये सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये विद्यार्थियों की उच्च उपस्थिति दर बनाए रखने में भी योगदान देते हैं।

शौचालय:

बच्चों में स्कूली दिनों से ही स्वच्छता की अच्छी आदतें डालनी चाहिए। समग्र शिक्षा सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाती है ताकि बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के मामलों में शिक्षित किया जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके। लड़कियों के शौचालय में भस्मक (इंसिनरेटर) की व्यवस्था की गई है। कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं;

पेय जल:

जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य के लगभग सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। सभी विद्यालयों में अपशिष्ट जल के निपटान की व्यवस्था है। विद्यालय परिसर में जल संचय न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है।













विद्यालय का वातावरण:





अतिरिक्त कक्षा:





केजीबीवी बिल्डिंग :





एसएस और केजीबीवी के अंतर्गत सिविल कार्यों की प्रगति, मार्च 2025 के अंत तक

मार्च 2025 के अंत तक समग्र शिक्षा (प्राथमिक) के अंतर्गत सिविल कार्यों की स्थितिप्रगति की स्थिति (मार्च 2025के अंत तक)

क्र.सं	गतिविधि	प्रगति की स्थिति (मार्च 2025 के अंत तक)				पूर्णता दर %
		वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक	समाप्ति	प्रगति पर है	शुरू नहीं	पूर्णता दर %
1	ए.सी.आर	2899	1257	503	1139	43%
2	लड़कों का शौचालय	3572	1391	994	1187	39%
3	कम पीएस का निर्माण	4	4	0	0	100%
4	सीडब्लूएसएन शौचालय	2475	916	574	985	37%
5	पेयजल	238	80	104	54	34%
6	विद्युतीकरण	13214	10887	727	1600	82%
7	बालिका शौचालय	2536	1216	698	622	48%
8	नए यूपीएस (VI-VIII)	46	0	0	46	0%
9	हैंडरेल सहित रैंप	2445	1618	184	643	66%
10	सौर पैनल	16	6	2	8	38%
	कुल	**27448**	**17375**	**3786**	**6287**	**63%**

मार्च 2025 के अंत तक समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के अंतर्गत सिविल कार्यों की स्थिति

क्र.सं	विवरण	लक्ष्य	समाप्ति	प्रगति पर है	शुरू नहीं	पूर्णता दर का %
1	एसीआर	535	155	46	334	29%
2	कला/शिल्प कक्ष	104	79	12	13	76%
3	लड़कों का शौचालय	313	138	30	145	44%
4	कंप्यूटर कक्ष	45	31	9	5	69%
5	सीडब्लूएसएन शौचालय	191	43	11	137	23%
6	पेयजल	12	9	3	0	75%
7	विद्युतीकरण	11	7	0	4	64%
8	बालिका शौचालय	1823	1213	406	204	67%
9	पुस्तकालय	95	63	17	15	66%
10	विज्ञान लैब	94	62	22	10	66%
11	गणित एवं वित्रान लैब	310	0	0	310	0%
12	सोलार पैनल	101	47	12	42	47%
13	सेकेंडरी स्तर पर अपग्रेडेशन	87	2	12	73	2%
14	कुल	3721	1849	580	1292	35%

क्र.सं	गतिविधि	संचित लक्ष्य	भौतिक प्रगति (संचित)			
			समाप्ति	प्रगति पर है	शुरू नहीं	पूर्णता दर का %
1	**केजीबीवी भवन(प्राथमिक)**	182	182	0	0	100%
2	**केजीबीवी भवन टाइप -IV (माध्यमिक)**	173	171	1	1	98%

9.9. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा

समग्र शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी विकलांगता किसी भी प्रकार, श्रेणी या स्तर की हो, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए, इसने शून्य अस्वीकृति नीति अपनाई है, अर्थात् विशेष आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे को शिक्षा केअधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

समग्र शिक्षा का लक्ष्य बाल शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सुगम बनाया गया है। आरटीई अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं: छह से अठारह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और किसी भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का शुल्क या व्यय नहीं लगाया जाएगा जो उसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से रोके।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे को सामान्य छात्रों के साथ नियमित सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

दिव्यांगता के 21 प्रकार हैं: 1) अंधापन, 2) कम दृष्टि, 3) श्रवण दोष(बधिर और कम सुनने वाले), 4) वाक् और भाषा संबंधी अक्षमता, 5) चलने-फिरने में अक्षमता, 6) मानसिक बीमारी, 7) विशिष्ट सीखने की अक्षमताएँ, 8) सेरेब्रल पाल्सी, 9) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, 10) बहरेपन और अंधेपन सहित कई अक्षमताएँ, 11) कुष्ठ रोग से ठीक हुए, 12) बौनापन, 13) बौद्धिक अक्षमता (एमआर), 14) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 15) पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, 16) मल्टीपल स्केलेरोसिस, 17) थैलेसीमिया, 18) हीमोफिलिया, 19) सिकल सेल रोग, 20) एसिड अटैक से बचे व्यक्ति और 21) पार्किंसंस रोग।
समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रति वर्ष विशेष प्रस्ताव के अनुसार 3500/- रुपये प्रति बच्चा खर्च किए जाने हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला योजना 3500/- रुपये प्रति बच्चा के मानदंड के अंतर्गत तैयार की गई है। वर्ष 2024-25 में राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ की गईं और प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:-

वर्ष 2025-26 के दौरान समावेशी शिक्षा गतिविधियों की प्रगति

क्र.सं	गतिविधिओं का नाम	2025-26 के दौरान हुई प्रगति
1	पहचान और नामांकन	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I से XII तक नामांकित CwSN की संख्या 85339 है।
2	सहायता एवं उपकरणों का वितरण	ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया गया है और 8524 दिव्यांगोंको सहायता सामग्री और उपकरण वितरित किए गए हैं।
3	अभिभावकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	CwSN के माता-पिता और अभिभावकों को ब्लॉक स्तर पर IE पर एक दिवसीय अभिविन्यास प्रदान किया गया है।
4	ब्रेल पुस्तकें	दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल पुस्तकों के 1616 सेट वितरित किए जा चुके हैं।
5	बड़े प्रिंट वाली किताबें	दृष्टिबाधित छात्रों को बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों के 3470 सेट वितरित किए गए हैं।
6	अनुरक्षण भत्ता	कक्षा I से XII तक के 15930 CwSN को 10 महीने के लिए 5000 रुपए प्रदान किए गए हैं।
7	परिवहन भत्ता	कक्षा I से XII तक के 28785 CwSN को 10 महीने के लिए 2000 रुपये प्रति परिवहन भत्ता प्रदान किया गया।
8	गर्ल्स सीडब्ल्यूएसएन के लिए छात्रवृत्ति	कक्षा I से XII तक की 21918 CWSN छात्राओं को 10 महीने के लिए 2000 रुपये की दर से वजीफा प्रदान किया गया।
9	पाठक भत्ता	कक्षा I से XII तक के 1194 दृष्टिबाधित CwSN को 10 महीने के लिए 5000 रुपये प्रति पाठक भत्ता प्रदान किया गया।
10	थेरेपी सेवाएँ	CwSN ने ब्लॉक और जिला स्तरीय संसाधन केंद्रों में फिजियोथेरेपी के साथ-साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ब्रेल प्रशिक्षण प्रदान किया।
11	कम दृष्टि वाले लोगों के लिए उपकरण और टीएलएम किट का वितरण	Sightsavers India के सहयोग से 86 CwSN को कम दृष्टि उपकरण प्रदान किए गए।
12	स्पोर्ट्स मीट	सीडब्ल्यूएसएन के लिए खेल प्रतियोगिता 30 जिलों के 314 ब्लॉकों में आयोजित की गई।
13	समावेशी शिक्षा स्वयंसेवक	राज्य सरकार के बजट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर 1094 आईई स्वयंसेवक सीडब्ल्यूएसएन को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं।
14	CwSN के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 632 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, सीडब्ल्यूएसएन को संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।
15	पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम	दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन ब्लॉक/जिला स्तर पर किया गया।

समग्र शिक्षा 2025-26 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित गतिविधियाँ।

- चिकित्सामूल्यांकनशिविर:

हर साल ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें डॉक्टरों और पुनर्वास विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों (सीडब्ल्यूएसएन) का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनकी विकलांगता के प्रकार और स्तर का पता लगाना और सहायता एवं उपकरणों की आवश्यकता वाले सीडब्ल्यूएसएन की पहचान करना है। यह ब्लॉक स्तरीय शिविर एसएसईपीडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेडिकल कॉलेजों, एएलआईएमसीओ, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (एनएचएम), एसवीएनआईआरटीएआर और जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) के सहयोग से आयोजित किया जाता है।





स्वास्थ शिविर निगरानी

दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण और सामग्री का प्रावधान:

ब्लॉक स्तर पर आयोजित मूल्यांकन शिविरों के माध्यम से पहचाने गए कक्षा-1 से XII तक के सभी श्रेणियों के जरूरतमंद बच्चों को आवश्यकता आधारित सहायता और उपकरण, जैसे कि तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कैलिपर्स, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, टीएलएम किट, कम दृष्टि वाले लोगों के लिए उपकरण, सीपी चेयर, चश्मा और आईसीटी उपकरण, विभिन्न संस्थानों, संगठनों और एजेंसियों जैसे: ALIMCO, NIEPID, NIEPVD, SVNIRTAR, DDRCS, RBSK, SSD-DY, Sightsavers और अन्य गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से प्रदान किए जा रहे हैं।





वाक् चिकित्सा कार्यक्रम:-

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वाक् चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक नियमित गतिविधि है। कक्षा I से XII तक के श्रवण एवं वाक् बाधित बच्चों को उनके अभिभावकों सहित ब्लॉक स्तरीय संसाधन केंद्रों, NHM के DEIC और DDRC तथा जिला स्तर पर उपलब्ध SSEPD विभाग में वाक् चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

(वाक उपचार)





- फिजियोथेरेपीऔरऑक्यूपेशनलथेरेपीकार्यक्रम

मस्तिष्क पक्षाघात, बहु-विकलांगता, चलने-फिरने में अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त कक्षा एक से बारह तक के बच्चों के लिए ब्लॉक/जिला स्तर पर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विकलांग बच्चे और उनके माता-पिता दोनों ही ब्लॉक/जिला स्तर पर आयोजित इस थेरेपी शिविर में भाग लेते हैं, जिसका संचालन एनएचएम के डीईआईसी और एसएसईपीडी विभाग के डीडीआरसी के समन्वय से किया जाता है।

(फिजियोथेरेपी)



(फिजियोथेरेपी)



- अभिभावकों, संरक्षकों और शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

ब्लॉक स्तर पर समावेशी शिक्षा पर अभिभावकों और संरक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के अभिभावकों को उनकी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका, सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध सुविधाएं, पहचान, मूल्यांकन, रेफरल सेवाएं, शल्य चिकित्सा, सहायक उपकरणों का उपयोग आदि के बारे में जानकारी दी गई।



(अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम)



(प्रधाना चार्य के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम)

- ब्लॉकरिसोर्सपर्सन (सीडब्ल्यूएसएन) केलिएप्रशिक्षणकार्यक्रम

ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (सीडब्ल्यूएसएन) की क्षमता निर्माण के लिए जिला/अंतर-जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।





(बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम)

- ब्रेल और बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों की उपलब्धता





(ब्रेल पुस्तकों का वितरण)

बरहमपुर स्थित रेड क्रॉस कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस के सहयोग से प्रतिवर्ष प्रथम से दसवीं कक्षा तक के दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। भुवनेश्वर स्थित टीबीपी एंड एम द्वारा कम दृष्टि वाले छात्रों को बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

खेल प्रतियोगिता एवं एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम

ब्लॉक स्तर पर बाल वर्ग के विद्यार्थियों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए खेल प्रतियोगिता और एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनकी छिपी प्रतिभा को पहचाना जा सके और उन्हें अपनी पाठ्येतर गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।





- समावेशी टीएलएम (पारंपरिक अंग्रेजी भाषा प्रबंधन प्रणाली) के विकास के लिए जिला स्तरीय टीएलएम कार्यशाला।

समावेशी शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के विकास के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के आकलन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपकरणों के वितरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के वितरण हेतु Sightsavers के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम

Sightsavers, India नामक विकास संगठन ने दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु OSEPA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Sightsavers ने जिला/ब्लॉक स्तर पर कम दृष्टि मूल्यांकन शिविर आयोजित किए और कम दृष्टि वाले छात्रों को आवश्यकता के अनुसार चश्मे, कम दृष्टि उपकरण, DAISY प्लेयर, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण प्रदान किए।







सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए उपकरणों का वितरण

- गंभीरमानसिकआघातवालेरोगियोंकेलिएअनुरक्षक भत्ता प्रदान करना

लोकोमोटर, दृष्टिबाधित, बौद्धिक अक्षमता, बहु-अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार श्रेणी के गंभीर विकलांग व्यक्तियों को, जिनकी 75% या उससे अधिक विकलांगता है और जो सरकारी और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 10 महीनों के लिए 5000 रुपये का एस्कॉर्ट भत्ता दिया गया है।

कक्षा I से XII तक के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों/अभिभावकों के बैंक खातों में IFMS-Digi Gov. के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई।

- गंभीर सीडब्लूएसएन केलिएपरिवहनभत्ताप्रदानकरनेकाप्रावधान

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा बारहवीं तक पढ़ने वाले 40-100% विकलांगता वाले सभी श्रेणियों के दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 महीनों के लिए 2000 रुपये का परिवहन भत्ता दिया गया है। यह धनराशि IFMS-DigiGov के माध्यम से विद्यार्थियों/अभिभावकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

CwSN के लिए रीडर भत्ता का प्रावधान।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I से XII तक पढ़ने वाले दृष्टिबाधित विद्यार्थियों (जिनकी पढ़ने की क्षमता 75% या उससे अधिक है) को 10 महीनों के लिए 5000 रुपये का पाठक भत्ता दिया गया है। यह धनराशि IFMS-DigiGov के माध्यम से विद्यार्थियों/अभिभावकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

- CWSN बालिकायों के लिए छात्रवृत्ति :

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक नामांकित दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त लड़कियों को 10 महीने के लिए 2000 रुपये का वजीफा दिया गया है। यह धनराशि IFMS-DigiGov के माध्यम से छात्रों/अभिभावकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

ब्लॉक स्तर पर पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम:

वर्ष 2024-25 के दौरान, पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधि से जिला/ब्लॉक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिला स्तर पर डिस्लेक्सिया जागरूकता दिवस भी आयोजित किया गया



(डिस्लेसिया दिवस पर रैलि)



(दिव्यांग दिवस पर रैलि)

- ब्लॉक/जिलास्तरपरCwSN के लिए संसाधन केंद्रों का कामकाज:





विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएनएसएन) को चिकित्सा सेवाएं, मूल्यांकन, प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए समर्पित संसाधन केंद्र सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में खोले गए हैं। ये संसाधन केंद्र जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सीडब्ल्यूएनएस के लिए सभी शैक्षिक और संसाधन सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए खोले गए हैं, जिनमें चिकित्सा सेवाएं, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, निगरानी और परामर्श सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं।
(जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत बाल यौन शोषण सहायता संसाधन केंद्र)

- ओड़िशाकेबीएसईऔरसीएचएसईद्वारासीडब्ल्यूएसएनकेलिएप्रावधान/छूट:-

ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई) ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान विशेष प्रावधानों/छूटों के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अभिभावकों और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए लघु वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब वीडियो, पुस्तिका और दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं।



सुरेंद्र साई दिव्य दृष्टि छात्रयोजना (एसएसडीडीवाई)के तहत दृष्टि जांच एवं चश्मावितरण कार्यक्रम
ब्लॉक स्तर पर और आवश्यकता के आधार पर नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं।
चिन्हित विद्यालयों में कक्षा I से X तक के छात्रों को चश्मे वितरित किए जाते हैंस्कूल आई के अंतर्गत सुरेंद्र साई दिव्य दृष्टि योजना (एसएसडीडीवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसईएचपी), जो स्वास्थ्य एवं विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग का एक संयुक्त समन्वित कार्यक्रम है। चयनित विद्यार्थियों कोजिन्हें विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक जांच के माध्यम से शिक्षकों द्वारा दृष्टि संबंधी समस्या पाई जाती है, ब्लॉक स्तरीय दृष्टि जांच शिविर में भेजा जाता है। ब्लॉक स्तरीय शिविरों का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/बाल स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा बाल रोग विशेषज्ञ अधिकारी (बीईओएस) के समन्वय से किया जाता है। डीबीसीएस की नेत्र रोग विशेषज्ञ तकनीकी टीमें विद्यार्थियों की आंखों की जांच और चश्मे का माप करती हैं। ओएसएमसीएल द्वारा चयनित विक्रेता द्वारा आवश्यक संख्या में चश्मे सीडीएमओ/पीएचसी स्तर पर आपूर्ति किए जाते हैं और पीएचसी इन चश्मों को बाल रोग विशेषज्ञ अधिकारियों (बीईओ) को सौंप देते हैं ताकि वे इन्हें विद्यालय के विद्यार्थियों में वितरित कर सकें।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कक्षा में भागीदारी।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत, विशेष आवश्यकताओं वाले विभिन्न प्रकार के बच्चे नियमित विद्यालयों में अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। वे कक्षा की नियमित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। साथ ही, वे कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षा में आयोजित कई गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं।



- विभिन्न गतिविधियों में CwSN की भागीदारी:-

CwSN ब्लॉक स्तर पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे ड्राइंग और पेंटिंग, शिल्प निर्माण, योग में भाग लेते हैं।




(सीडब्ल्यूएएसएन ने पेंटिंग, हस्तशिल्प और योग गतिविधियों में भाग लिया)

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और आईई स्वयंसेवकों द्वारा सीडब्ल्यूएसएन को संसाधन सहायता प्रदान करना





समग्र शिक्षा के तहत, स्कूल स्तर पर बाल एवं शिशु सहायता प्राप्त करने वाली माताओं (सीडब्ल्यूएसएन) को संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। साथ ही, घर स्तर पर बाल एवं शिशु सहायता प्राप्त करने वाली माताओं (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए आईई स्वयंसेवकों को भी नियुक्त किया जाता है।




9.10. गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप

9.10.1. मूल्यांकन

• शैक्षणिकसत्र2025-26 में, कक्षा I से IV, VI और VII तक के 2762599 छात्र सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित हैं। उक्त छात्रों के लिए योगात्मक मूल्यांकन - II में उपस्थित होने का प्रावधान किया गया है।



• 09/07/2025 और संकल्प संख्या 28710/ एसएमई दिनांक 18/10/2025 के अनुसार आयोजित की गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में, कक्षा 5 और 8 के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1074444 छात्र नामांकित हैं। उक्त छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की गई है।



• इसवर्षकक्षा5 और 8 की पूरक परीक्षा राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आयोजित की गई है और लगभग 5686 छात्र उक्त परीक्षा में उपस्थित हुए हैं।

आधारभूत अधिगम अध्ययन (एफएलएस)- 9 और 10 अप्रैल 2026 को ग्रेड-III के छात्रों के 433 नमूना विद्यालयों में आयोजित किया गया था।





9.11. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए) का उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को अवलोकन, प्रयोग और रुचिकर जिज्ञासा के माध्यम से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी सीखने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान कक्षा में पढ़ाए गए पाठों को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यालयों को नवाचार के केंद्र में परिवर्तित करता है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गतएकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख हस्तक्षेपों में विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन भ्रमण, अंतर-विद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान एवं गणित प्रतियोगिताओं/ओलंपियाड में छात्रों की भागीदारी, विद्यालय की विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल मॉडल सहित शिक्षण-अधिगम उपकरण और सामग्री का उपयोग और विज्ञान एवं गणित शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। यह एक सतत कार्यक्रम है और सभी विद्यालय के छात्रों के लाभ के लिए है।

वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए), ओडिशा के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं।

9.11.1. विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक मेला

विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों को नवीन परियोजनाओं, कार्यशील मॉडलों, चार्टों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों की अपनी समझ प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करती है। यह छात्रों में टीम वर्क, सहयोग, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देती है। प्रदर्शनी छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करके वैज्ञानिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है।

उद्देश्य:

- छात्रोंमेंछिपीवैज्ञानिकप्रतिभाओंकोउजागरकरना।
- विद्यालयों में पूछताछ-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आविष्कार करने, प्रयोग करने, सोचने और करने की संस्कृति का निर्माण करना।
- विद्यालयों को नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए।
- छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना।
- समाजकीबेहतरीकेलिएछात्रोंमेंविज्ञानऔरप्रौद्योगिकीकेप्रतिरुचिको बढ़ावादेना।





ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी:

➢ प्राथमिकऔरमाध्यमिकदोनोंस्तरोंकेलिएब्लॉकस्तरीयविज्ञानप्रदर्शनीकाआयोजनअक्टूबर 2025 मेंकिया गया था।

➢ इच्छुकसरकारीप्राथमिकऔरमाध्यमिकविद्यालयोंसेचयनितछात्रोंने आरएएकेअंतर्गतब्लॉकस्तरीयविज्ञानप्रदर्शनीमेंभागलिया।

➢ विद्यार्थियोंनेब्लॉकस्तरकीविज्ञानप्रदर्शनीमेंअपनीपरियोजनाएंऔरमॉडलप्रदर्शितकिए। येमॉडलऔरपरियोजनाएंवैज्ञानिकसिद्धांतोंपरआधारितहोनीचाहिए।



➢ प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन पुस्तक शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से किया गया।

➢ यह प्रदर्शनी जिला प्रशासन के शिक्षाविद/अकादमिक मामलों के समन्वयक (डीएसएस/पेडागोजी समन्वयक) की देखरेख में आयोजित की गई।

➢ विज्ञान परियोजनाओं का मूल्यांकन जूनियर सदस्यों के एक पैनल द्वारा किया जाता है जिसमें प्रत्येक स्तर के लिए 2 सदस्य होते हैं।



➢ ब्लॉकस्तरीयविज्ञानप्रदर्शनियोंकेपहलेतीनपुरस्कारविजेताओं (प्राथमिकस्तरकेलिए3 और माध्यमिक स्तर के लिए 3) को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

➢ कार्यक्रम में भाग लेने और प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए पीआरआई सदस्यों/शिक्षाविदों/विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है।

➢ कार्यक्रमकीव्यापककवरेजकेलिएस्थानीयमीडियाकर्मियोंकोआमंत्रितकियागया।

➢ ब्लॉकस्तरकीविज्ञानप्रदर्शनीकेबादजिलास्तरीयविज्ञानप्रदर्शनीआयोजित की जाएगी।

➢ ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों (प्राथमिक के लिए 3 और माध्यमिक के लिए 3) के पहले तीन पुरस्कार विजेताओं ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया।

जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी (प्राथमिक और माध्यमिक)

➢ प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी अक्टूबर 2025 में आयोजित की जाएगी।

➢प्रदर्शनी का पर्यवेक्षण संबंधित जिले के डीईओ, शिक्षाशास्त्र समन्वयकों और डीएसएस द्वारा किया जाता है।

➢ विज्ञानपरियोजनाओंकामूल्यांकनप्रत्येकस्तरके लिए 2 सदस्यों वाले निर्णायक मंडल द्वारा किया जाता है।

➢ जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों के पहले तीन पुरस्कार विजेताओं (प्राथमिक स्तर के लिए 3 और माध्यमिक स्तर के लिए 3) को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

9.11.2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता:

क्विज़ प्रतियोगिता एक संक्षिप्त, केंद्रित मूल्यांकन है जिसमें आमतौर पर बहुविकल्पीय, सही या गलत, या रिक्त स्थान भरें जैसे प्रश्न होते हैं। व्यापक परीक्षाओं के विपरीत, क्विज़ का उपयोग अक्सर समझ की त्वरित जाँच, कौशल मूल्यांकन या ज्ञान परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑनलाइन क्विज़ प्लेटफॉर्म के विकास ने इन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक परिवेश में स्व-मूल्यांकन, निरंतर सीखने और संवादात्मक सहभागिता के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बना दिया है।

क्विज़ प्रतियोगिता एक प्रकार का दिमागी खेल है जो व्यक्तियों या टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रतियोगियों से सामान्य ज्ञान या अन्य विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर देने वाला व्यक्ति या टीम जीतती है। यह किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का आकलन है। क्विज़ का उद्देश्य सीखने की मनोरंजक तकनीकों को बढ़ावा देना है। क्विज़ प्रतियोगिताएं छात्रों को लीक से हटकर सोचने या विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने का अवसर देती हैं। सब जूनियर और जूनियर समूह के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के दो सेट अलग-अलग मुद्रित किए जाएंगे।





प्रतियोगिता का स्तर:

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी

ब्लॉक स्तर:

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दो अलग-अलग श्रेणियों, जूनियर (कक्षा VI से VIII) और सीनियर (कक्षा IX से XII) में खुली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ये प्रतियोगिताएं क्रमशः सितंबर और दिसंबर में आयोजित की गईं। बीईओ, एडीईओ, शिक्षाशास्त्र समन्वयक और डीएसएस ने ब्लॉक स्तर पर समय सारणी के अनुसार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का संचालन सुनिश्चित किया।

1. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों के लिए डीआईईटी के सहयोग से विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया।

2. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर बीईओ द्वारा चयनित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

3. प्रत्येक प्रतिभागी को सहभागिता का प्रमाण पत्र दिया गया और विजेताओं (शीर्ष 3 छात्रों) को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों में प्रत्येक समूह के अंतर्गत प्रमाण पत्र और ट्रॉफी/स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

4. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर संपूर्ण प्रक्रिया का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण डीईओ-सह-डीपीसी, एसएस, एडीईओ (अकादमिक), डीएसएस और शिक्षाशास्त्र समन्वयक द्वारा किया गया।

5. कार्यक्रम को देखने और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए पीआरआई सदस्यों/शिक्षाविदों/विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

6. कार्यक्रम की व्यापक कवरेज के लिए स्थानीय मीडियाकर्मियों को आमंत्रित किया गया था।





ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

9.11.3. राज्य के भीतर छात्रों के लिए भ्रमण यात्रा

भ्रमण यात्रा किसी विशेष उद्देश्य से की जाने वाली छोटी यात्रा या सैर होती है, जिसका उद्देश्य शीघ्र वापसी करना होता है। शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर सीखने में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। ये विद्यार्थियों को किताबों से परे दुनिया को जानने, बहुमूल्य ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और जीवन भर याद रहने वाली यादें बनाने का अवसर प्रदान करते हैं।

उद्देश्य:

- शिक्षार्थियोंकोउनकीशैक्षणिकउन्नतिकेलिएविभिन्नस्थानोंकीयात्राकरनेकाअवसरप्रदानकरना।
- जांच-आधारित अधिगम में संलग्न होना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास, संस्कृति आदि में रुचि को बढ़ावा देना।
- यह छात्रों को 'देखने', 'सुनने', जांच करने, डेटा एकत्र करने और प्रश्न पूछने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

तौर-तरीके

- ब्लॉकशिक्षाअधिकारियोंनेजिलास्तरपरप्रतिछात्र1000 रुपये के बजट के भीतर ब्लॉक के प्राथमिक छात्रों के लिए राज्य के भीतर एक दिवसीय भ्रमण यात्रा का आयोजन किया।
- यह भ्रमण यात्रा नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2025 के महीनों में होगी।
- प्रत्येक ब्लॉक से दस छात्रों ने प्राथमिक स्तर के कार्यक्रम में भाग लिया।
- छात्रों को राज्य के ऐतिहासिक/भौगोलिक/वैज्ञानिक और अन्य शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाया जाएगा। जिन स्थानों का भ्रमण किया जाएगा उनकी सूची नीचे दी गई है।
- विज्ञान पार्क/विज्ञान संग्रहालय/विज्ञान केंद्र।
- नक्षत्र-भवन
- विश्व कौशल केंद्र
- इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक संस्थान
- आईटीआई स्कूल
- वनस्पति उद्यान/प्राणी उद्यान
- वैज्ञानिक एवं गणितीय संस्थान
- संग्रहालय
- भ्रमण यात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति आवश्यक है।
- भ्रमण में भाग लेने वाले छात्रों का डेटाबेस बीईओ द्वारा रखा जाता है और यात्रा से 7 दिन पहले जानकारी के लिए डीपीओ को भेजा जाता है।
- ब्लॉक द्वारा आवश्यकतानुसार चुने गए महिला और पुरुष दोनों शिक्षक मार्गदर्शक शिक्षकों के रूप में छात्रों के साथ गए।





उच्च संस्थानों का अध्ययन दौरा

स्कूल भ्रमण छात्रों की आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है और उन्हें किसी विषय या मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण से सोचने का अवसर देता है। शैक्षिक भ्रमण शैक्षणिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि ये छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने और उपयोगी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका देते हैं। एक कहावत है, "सुनो तो भूल जाओ, देखो तो याद रखो, करके समझो।" इसका अर्थ यह है कि किसी कार्य को किसी स्थान पर होते हुए देखने से वह बेहतर ढंग से याद रहता है। कई बच्चों को अपने परिवार के साथ स्कूल भ्रमण स्थलों का अनुभव करने का अवसर नहीं मिलता। स्कूल भ्रमण छात्रों को नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

उद्देश्य:



- उच्चशिक्षण संस्थानों की प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करना, जो उन्हें अपने विद्यालयों में नहीं मिल पाती है।
- टीम वर्क और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना
- स्वतंत्र शिक्षा को प्रोत्साहित करना
- रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना
- कक्षा में पढ़ाई की एकरसता से राहत प्रदान करने के लिए।

तौर-तरीके:



माध्यमिकविद्यालयकेछात्रोंकेलिएउच्चशिक्षणसंस्थानोंमेंएकदिवसीयअध्ययनयात्राआयोजितकरनेकीजिम्मेदारीडीईओ-सह-डीपीसीकीहोगी।

- यह अध्ययन यात्रा नवंबर 2025 में आयोजित की जाएगी।
- इस कार्यक्रम में प्रत्येक ब्लॉक से दस छात्र भाग लेंगे।
- अध्ययन यात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति आवश्यक है।
- भ्रमणमेंभागलेनेवालेछात्रोंकाडेटाबेसडीईओ-सह-डीपीसीद्वाराबनाएरखाजाताहै।
- ब्लॉकद्वाराआवश्यकतानुसारचुनेगएमहिलाऔरपुरुषदोनोंशिक्षकमार्गदर्शकशिक्षकोंकेरूपमेंछात्रोंकेसाथगए।

छात्र अध्ययन यात्राओं पर उच्च शिक्षा संस्थानों में गए, जैसे कि:



क. विश्वकौशलकेंद्र

ख. इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान

ग. विज्ञान एवं गणित संस्थान

घ. आईटीआई स्कूल, विज्ञान संग्रहालय और इसी तरह के स्थान

9.12.कला उत्सव

कला उत्सव, शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसई&एल) का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। कला उत्सव का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना है। यह वार्षिक आयोजन छात्रों को कला और सांस्कृतिक विविधता को जानने और उसका जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कला उत्सव का आयोजन विद्यालय, जिला, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

कला उत्सव, एनईपी 2020 की कई प्रमुख सिफारिशों के अनुरूप है, जो समग्र और व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने में इसके महत्व को दर्शाता है।

इस कला उत्सव का विषय था

- "विकसितभारत - वर्ष 2047 मेंभारतकेलिएएकदृष्टिकोण"।
- कला उत्सव 2025 में, कला रूपों की श्रेणियों को पुनर्गठित किया गया है, और प्रतियोगिताओं की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, ताकि समूह और एकल प्रतिभागियों के साथ-साथ महिला और पुरुष छात्रों के लिए समान भागीदारी के अवसर पैदा किए जा सकें।
- गायन, वाद्य संगीत, नृत्य और दृश्य कला में समूह और एकल दोनों प्रतियोगिताएं थीं,

2025-26 के दौरान कला उत्सव प्रतियोगीता का स्तर

जबकि रंगमंच और पारंपरिक कहानी सुनाने में केवल समूह भागीदारी थी।

2025-26 के दौरान, राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता से पहले जिला एवं क्षेत्रीय स्तर (अंतर-जिला) कला उत्सव प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का संचालन जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता के संचालन हेतु संबंधित जिले के डीईओ-सह-डीपीसी, एसएस की जिम्मेदारी थी, और क्षेत्रीय जिले के डीईओ-सह-डीपीसी, एसएस ने निर्धारित समय सारणी के भीतर चिन्हित जिलों के समन्वय से क्षेत्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता का संचालन किया।

कला रूप:

कला उत्सव 2025 में बारह श्रेणियों में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं, जिससे छात्रों को अपनी कलात्मक प्रतिभाओं को व्यक्त करने के अनेक अवसर मिले। सभी छह कला रूपों में एकल और समूह प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं, जिनमें राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत की विविध कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए स्थान बनाने हेतु अनेक श्रेणियाँ शामिल थीं, जो समृद्ध, जीवंत और कला जगत की झलक प्रस्तुत करेंगी। इस प्रकार, सभी टीमें निम्नलिखित बारह श्रेणियों में से प्रत्येक में एक-एक प्रतिनिधि भेज सकती हैं।

यदि क्षेत्रीय स्तर पर चयन होता है तो जिला 2025 के राज्य स्तरीय कला उत्सव में मुख्य श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में भाग लेगा।

कला रूपों का श्रेणीवार विवरण:

क्र.सं	आर्ट फर्म	वर्ग	उप-श्रेणी (प्रत्येक टीम के लिए एकल और समूह स्पर्धाओं में एक-एक भागीदारी)
1	वोकल म्यूजिक	एकल (1)	शास्त्रीय/अर्धशास्त्रीय
2	वोकल म्यूजिक	समूह (अधिकतम 4 प्रतिभागी)	लोक संगीत समूह/ भक्ति समूह/ देशभक्ति समूह/ हल्का संगीत
3	वाद्य संगीत (तार/पवन वाद्य यंत्र)	एकल (1)	शास्त्रीय/अर्धशास्त्रीय
4	वाद्य यंत्रों से बजने वाला ताल वाद्य (लयबद्ध वाद्य यंत्र)	एकल (1)	शास्त्रीय/अर्धशास्त्रीय
5	वाद्य संगीत	समूह (अधिकतम 4 प्रतिभागी)	ऑर्केस्ट्रा लोक /शास्त्रीय संगीत
6	नृत्य	एकल (1)	शास्त्रीय
7	नृत्य	समूह (अधिकतम 4 प्रतिभागी)	क्षेत्रीय (लोक/आदिवासी) समूह समकालीन नृत्यकला (गैर-फिल्म)
8	आर्ट फर्म	वर्ग	उप-श्रेणी (प्रत्येक टीम के लिए एकल और समूह स्पर्धाओं में एक-एक भागीदारी)
9	थिएटर	समूह (अधिकतम 4 प्रतिभागी)	लघु नाटक/भूमिका निर्वाह/ नकल
10	दृश्य कला	एकल (1)	2 आयामी (चित्रकला, पेंटिंग, प्रिंटिंग, कैरिकेचर)
11	दृश्य कला	एकल (1)	त्रिआयामी (मूर्तिकला)
12	दृश्य कला	समूह (अधिकतम 4 प्रतिभागी)	2 आयामी/ 3 आयामी (स्वदेशी खिलौने और खेल/ स्थानीय हस्तशिल्प)
13	पारंपरिक कहानी सुनाना	समूह (अधिकतम 2 प्रतिभागी)	पारंपरिक कहानी सुनाने की कला जिसमें समूह नृत्य, नाटक, संगीत या दृश्य कला या एक से अधिक कला रूपों का समावेश हो।

योग्यता:



किसी भी राज्य या केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध किसी भी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय के कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्रों ने कला उत्सव में भाग लिया।

टिप्पणियाँ:

- सभीजिलोंनेजिलास्तरीयकलाउत्सवप्रतियोगितामेंसभीब्लॉकोंकेविद्यालयोंकीभागीदारीसुनिश्चितकी। जिलास्तरपरचयनितछात्रोंनेक्षेत्रीयस्तरकी प्रतियोगिता में भाग लिया।
- कला उत्सव के पिछले वर्षों के राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान) को कला उत्सव 2025-26 में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई ताकि अन्य छात्रों को भाग लेने का अवसर मिल सके।
- जिलेनेयहसुनिश्चितकियाकिकलाउत्सवप्रतियोगितामेंलड़कियोंऔरलड़कोंकीयथासंभवसमानभागीदारीहो। सामाजिक-आर्थिकरूपसेवंचितसमूह (एसईडीजी) केविद्यार्थियों, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं, को कला उत्सव 2025-26 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया>

निर्णायक मंडल:



प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग निर्णायक मंडल होते हैं, जिनमें संबंधित कला रूपों के शिक्षक और प्रैक्टिशनर शामिल होते हैं। ये निर्णायक मंडल प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों से सीधे बातचीत करते हैं, जहां प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।

जिला स्तरीय कला उत्सव:

जिला स्तरीय कला उत्सव 2025 में लगभग 2500 छात्रों ने भाग लिया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक स्पर्धा के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। प्रत्येक स्पर्धा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ने क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया।



क्षेत्रीय स्तर का कला उत्सव:

क्षेत्रीय स्तर के कला उत्सव 2025 में लगभग 1500 छात्रों ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रत्येक स्पर्धा के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रत्येक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया।

राज्य स्तरीय कला उत्सव:

राज्य स्तरीय कला उत्सव 2025 में लगभग 120 छात्रों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक स्पर्धा के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ने राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव 2025 में भाग लिया।

प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों का लिखित सारांश (राइट-अप), वीडियो फिल्म और एचडी फोटोग्राफ राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव, 2025 में आगे के मूल्यांकन के लिए एनसीईआरटी, नई दिल्ली को भेजे गए।

राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव:

राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव 2025 में 22 छात्रों और उनके साथ आए शिक्षकों ने भाग लिया। पांच स्पर्धाओं में छात्रों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए, जिनमें विजुअल आर्ट 2डी में द्वितीय स्थान, विजुअल आर्ट 3डी में द्वितीय स्थान, विजुअल आर्ट ग्रुप टॉय मेकिंग में द्वितीय स्थान, वोकल म्यूजिक सोलो में तृतीय स्थान और डांस ग्रुप में प्रथम स्थान शामिल हैं।



9.13. गुणवत्ता, एलईपी और नवाचार के लिए निधि

परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, राज्य ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, प्रभावी कक्षा शिक्षण और अधिगम गतिविधियों के लिए छात्रों और शिक्षकों को विभिन्न संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं। इन संसाधनों का उद्देश्य छात्रों को अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रेरित करना, शिक्षकों को अतिरिक्त अभ्यास के अवसर प्रदान करके जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट और सुदृढ़ करने में सहायता करना और छात्रों को कक्षा-विशिष्ट अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए तैयार करना है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक व्यापक छात्र मूल्यांकन ढांचा, समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) अपनाया है। इसका उद्देश्य अंकों और परीक्षा स्कोर से परे जाकर एक शिक्षार्थी के समग्र विकास का आकलन करना है।

यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा के दो चरणों, अर्थात् मध्य विद्यालय शिक्षा (कक्षा VI से VIII) और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा IX और X) के लिए उपरोक्त पहलों को अलग-अलग प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रत्येक मामले में राज्य द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहल, समग्र प्रगति कार्ड की स्थिति और वितरित संसाधन सामग्री, साथ ही स्कूलों में उनके औचित्य और उपयोग को शामिल किया गया है।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा VI-VIII)

एलईपी के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता और कक्षा अभ्यास

माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- छात्रोंकोओडिया, अंग्रेजी और गणित जैसे मुख्य विषयों की कार्यपुस्तिकाएँ प्रदान की गई हैं ताकि छात्र अभ्यास कर सकें और कक्षा-स्तर की दक्षताओं को प्राप्त कर सकें।
- सभी छात्रों को लेखन कार्य और नियमित अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए नोटबुक प्रदान की गई हैं। इससे शिक्षक को छात्रों की सीखने की प्रगति पर नियमित रूप से नज़र रखने में मदद मिलती है। यह निरंतर मूल्यांकन में सहायक है और छात्रों को अपनी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- कक्षा I से कक्षा VIII तक के सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी डायरी उपलब्ध कराई गई है। इससे दैनिक अध्ययन की आदत विकसित होती है, आत्मचिंतन को प्रोत्साहन मिलता है, विद्यार्थियों को अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलती है, आत्म-अनुशासन को बढ़ावा मिलता है और शिक्षक-विद्यार्थी-अभिभावक के बीच संवाद को सुगम बनाता है।
- छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए योग्यता-आधारित, अनुभवात्मक और आनंददायक अधिगम को अपनाना।
- नवीन शिक्षण विधियों, गतिविधि-आधारित अधिगम और बाल-केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से कक्षा अभ्यासों को सुदृढ़ बनाना।
- छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए उनका नियमित मूल्यांकन किया जाता है।
- शिक्षकोंकासततव्यावसायिकविकासऔरकक्षाअवलोकनउपकरण (सीओटी) केमाध्यमसेहितधारकोंद्वारास्कूलोंकीनिरंतरनिगरानी, तथा शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करना।

समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) को अपनाना

राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप एक व्यापक छात्र मूल्यांकन ढांचा अपनाया है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ, अंकों और परीक्षा स्कोर से परे जाकर, एक शिक्षार्थी के समग्र विकास का आकलन करना है:

- रटनेवालीशिक्षासेयोग्यता-आधारितशिक्षाकीओरबढ़ना।
- अनुभवात्मक और आनंददायक अधिगम को बढ़ावा देना।
- सीखने के लिए निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी की अनूठी खूबियों और क्षमताओं को पहचानना।
- शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण, जीवन कौशल और कल्याण के साथ एकीकृत करना।

समग्र प्रगति कार्ड को स्कूली शिक्षा के मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण और मध्य चरण के लिए अनुकूलित किया गया है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विकास पर नज़र रखते हैं, जिसमें जीवन कौशल, मूल्य और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी शामिल है, और आवधिक समीक्षा के माध्यम से अभिभावकों को शामिल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

समग्र प्रगति कार्ड की प्रमुख विशेषताएँ

क. व्यापक मूल्यांकन

- यहसंज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक विकास का मूल्यांकन करता है।
- यह शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों प्रकार की दक्षताओं पर केंद्रित है।

क. योग्यता-आधारितमूल्यांकन

- यहअध्ययनअधिगमपरिणामों, वैचारिक समझ, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या-समाधान और ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करता है।
- योग्यता-आधारित शिक्षा के अनुरूप।

ख. 360-डिग्री मूल्यांकन

- शिक्षकमूल्यांकन
- छात्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन
- समकक्ष मूल्यांकन
- माता-पिता की प्रतिक्रिया (जहां लागू हो)

ग. अपनीखूबियोंऔरविकासपरध्यानकेंद्रितकरें

- यहछात्रोंकीउपलब्धियों, रुचियों, प्रतिभाओं और सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करता है।
- शिक्षार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के बजाय विकासोन्मुखी मानसिकता को प्रोत्साहित करता है।

ङ) जीवन कौशल और मूल्य

- पर्यावरणजागरूकता, और नागरिकता।

च. सहपाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियाँ

- खेल, कला, संगीत, सांस्कृतिक गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा और सामुदायिक सेवा में भागीदारी और उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेज।

शिक्षण-अधिगम सामग्री और प्रभावी उपयोग के लिए दिशानिर्देश

छ. 1. अभ्यास पुस्तिका - कक्षा VI से VIII तक

ज. तर्क - राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यपुस्तिकाएँ गतिविधि-आधारित अधिगम का समर्थन करने और कक्षा शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, बच्चों को ओडिया, अंग्रेजी और गणित में प्रमुख अवधारणाओं का अभ्यास करने में मदद करती हैं, और सतत मूल्यांकन के उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, जिससे शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में मदद मिलती है।

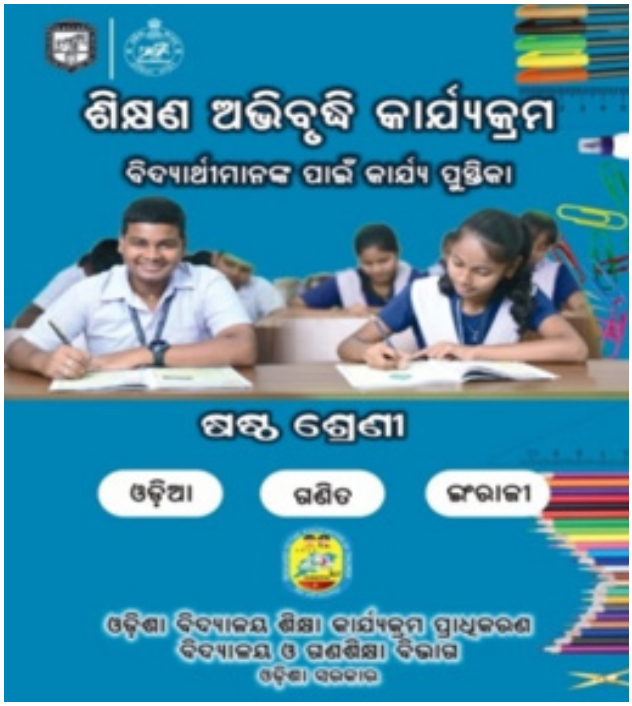
i. विद्यालय में उपयोग - इन वर्कबुक का उपयोग निर्देशित अभ्यास के समय किया जाता है।

कक्षा में हाल ही में पढ़ाए गए विषयों से संबंधित पृष्ठ निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक कार्य पूरा होने की निगरानी करते हैं और

अनौपचारिक जाँच और प्रतिक्रिया के लिए वर्कबुक का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित वर्कबुक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अधिगम संवर्धन कार्यक्रम के तहत विद्यालयों को प्रदान की जाती हैं।

कक्षा	कार्यपुस्तिकाओं की संख्या	विषय-वस्तु
कक्षा - VI	1	ओड़िआ, अंग्रेजी एवं गणित
कक्षा – VII	1	ओड़िआ, अंग्रेजी एवं गणित
कक्षा - VIII	1	ओड़िआ, अंग्रेजी एवं गणित





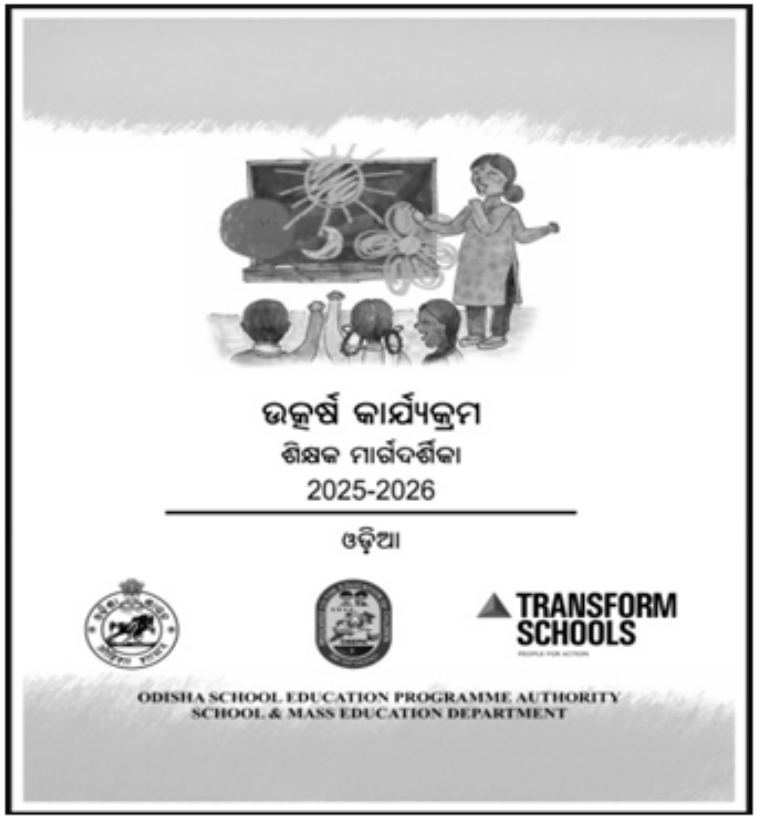


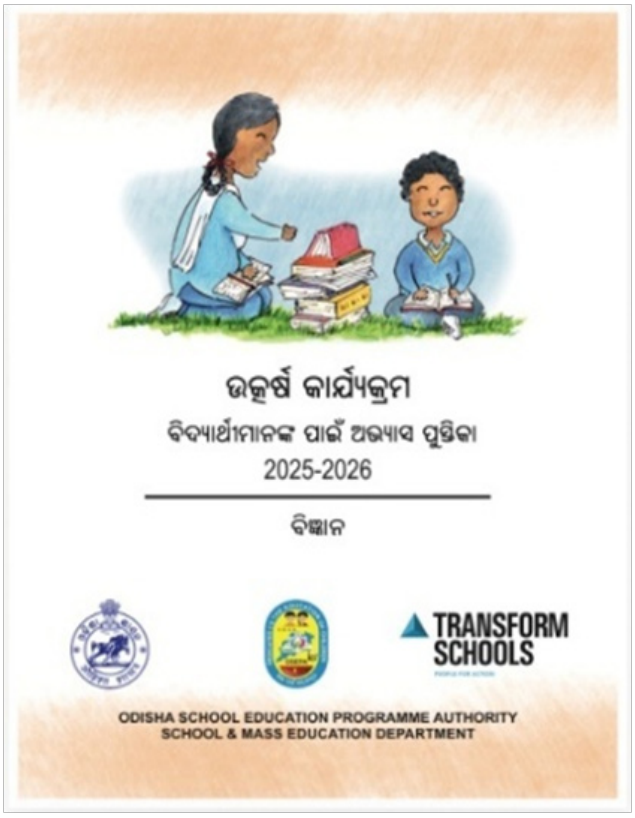
9.14. एलईपी के अंतर्गत अधिगम संवर्धन पहल

एलईपी-उत्कर्ष

उत्कर्ष अधिगम कार्यक्रम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 200 घंटे का एक लक्षित शिक्षण कार्यक्रम है, जिसे ओडिया, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुरूप मूलभूत और आवश्यक दक्षताओं पर केंद्रित है और नियमित शिक्षण के पूरक के रूप में समर्पित सत्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

इस कार्यक्रम में संरचित शिक्षण पद्धति, श्रेणीबद्ध शिक्षण संसाधन, योग्यता-आधारित निर्देश, रचनात्मक मूल्यांकन और निरंतर कक्षा निगरानी को मिलाकर, कक्षा-स्तर के शिक्षण को समर्थन देते हुए, पूर्व-आवश्यक शिक्षण अंतरालों को दूर किया गया। कार्यान्वयन मॉडल में नियमित शैक्षणिक कैलेंडर के भीतर 3 समर्पित शिक्षण चरणों को एकीकृत किया गया, जिनमें आधारभूत और अंतिम मूल्यांकन, फाउंडेशन चरण, समर्थित शिक्षण और समेकन चरण शामिल हैं। यह कार्यक्रम माध्यमिक और जन शिक्षा निदेशालय (डीएसएमई) के अंतर्गत आने वाले 5,311 सरकारी उच्च विद्यालयों में लागू किया गया।





अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग (एसएसडी) के माध्यम से ओडिशा के सभी 30 जिलों में कक्षा IX के लगभग 3,42,676 बच्चों तक यह कार्यक्रम पहुँचाया गया। जुलाई 2025 में जनगणना आधारित प्रारंभिक आकलन किए गए, जिसके बाद पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा में इसका कार्यान्वयन किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, चार विषयों में 350,000 से अधिक छात्र पुस्तिकाएँ मुद्रित कर विद्यालयों में वितरित की गईं, जबकि शिक्षक पुस्तिकाएँ आधिकारिक शिक्षक नेटवर्क और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से डिजिटल रूप से साझा की गईं।

कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम और हस्तक्षेप

कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से, OSEPA, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE) और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नवंबर 2025 में DIKSHA प्लेटफॉर्म के माध्यम से 80 घंटे का स्व-अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया। यह पाठ्यक्रम गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ओडिया और अंग्रेजी में पूर्व-आवश्यक और कक्षा-स्तरीय दक्षताओं को कवर करता है और आसान पहुंच के लिए अध्याय-वार QR कोड से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विषय में आठ इकाइयाँ, 50 बहुविकल्पीय प्रश्न और परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट शामिल है।

जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन सत्रों के बाद, छात्रों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक संरचित स्व-अध्ययन संसाधन के रूप में पाठ्यक्रम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य भर के डीएसएमई और एसएसडी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराया गया था। परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करने तथा समय प्रबंधन कौशल में सुधार लाने के लिए, सात विषयों - ओडिया, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत - में अभ्यास परीक्षा पत्रों का एक पैकेज विकसित किया गया था। इसमें प्रश्न पत्रों के कई सेट शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक के अंत में उत्तर कुंजी दी गई थी। यह संसाधन सभी विद्यालयों को मुद्रित और डिजिटल दोनों प्रारूपों में उपलब्ध कराया गया था, जिससे छात्रों को अपनी परीक्षाओं से पहले व्यवस्थित अभ्यास करने में सहायता मिली।

शिक्षण-अधिगम सामग्री और प्रभावी उपयोग के लिए दिशानिर्देश

1. एलईपी-उत्कर्ष छात्र और शिक्षक पुस्तिकाएं - कक्षा IX

तर्क - यह पुस्तिका छात्रों को कक्षा-स्तर की दक्षता के लिए तैयार करती है और विभेदित शिक्षण में सहायक होती है। इससे बच्चों को ओडिया, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की मूलभूत और पूर्व-आवश्यक अवधारणाओं का अभ्यास करने में मदद मिलती है। ये पुस्तिकाएँ सीखने को सुदृढ़ करने और निरंतर मूल्यांकन के लिए भी उपयोगी हैं, जिससे शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सहायता मिलती है।

विद्यालय में उपयोग - ज़िले द्वारा साझा की गई समय सारिणी के अनुसार नियमित कक्षा शिक्षण में एकीकृत। शिक्षक पुस्तिका से विशिष्ट कार्य सौंपते हैं और प्रगति की निगरानी करते हैं तथा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करते हैं।



कक्षा IX के लिए आधारभूत और अंतिम मूल्यांकन प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी

तर्क -यह विद्यार्थियों के वर्तमान अधिगम स्तर को समझने के लिए एक प्रारंभिक संदर्भ प्रदान करता है। यह शिक्षकों को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर उपचारात्मक या संवर्धनात्मक रणनीतियों की योजना बनाने में मदद करता है। शैक्षणिक वर्ष के दौरान हुई प्रगति का आकलन करने के लिए अंतिम मूल्यांकन किया जाता है।

विद्यालय में उपयोग - राज्य के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन करना। शिक्षक मूल्यांकन के लिए उत्तर कुंजी का उपयोग करते हैं, परिणामों का विश्लेषण करते हैं और सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाते हैं।

विज्ञान प्रैक्टिकल नोटबुक - कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए



तर्क- यह दैनिक सीखने की आदत विकसित करता है, आत्म-चिंतन को प्रोत्साहित करता है और छात्रों को अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। यह आत्म-अनुशासन, सीखने में आनंद और शिक्षक-छात्र संवाद को बढ़ावा देता है।

विद्यालय में उपयोग - परियोजना नोटबुक का उपयोग छात्र विभिन्न विषयों या अवधारणाओं का पता लगाने के लिए करते हैं।

एकीकृत और गतिविधि-आधारित शिक्षण के माध्यम से विषयों का अध्ययन किया जाएगा। विज्ञान प्रयोग सत्र के दौरान छात्रों द्वारा विज्ञान प्रयोग कार्य किया जाएगा, जो कक्षा नौवीं और दसवीं (एससीएल और एससीपी) के लिए शिक्षकों के संसाधन पुस्तिका में प्रयोग, प्रदर्शन और परियोजना कार्य पर दी गई योजना के अनुसार होगा, जो सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध है।

4.2 उत्कर्ष+ सेल्फ-लर्निंग कोर्स (दीक्षा) और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर - कक्षा 10

इसका उद्देश्य मुख्य विषयों में पूर्व-आवश्यक और कक्षा-स्तरीय दक्षताओं को मजबूत करके और संरचित अभ्यास के माध्यम से परीक्षा की तैयारी और समय-प्रबंधन कौशल का निर्माण करके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में परिणामों में सुधार करना है।



9.15. समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी)

राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप एक व्यापक छात्र मूल्यांकन ढांचा अपनाया है।इसका उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ, अंकों और परीक्षा स्कोर से परे जाकर, एक शिक्षार्थी के समग्र विकास का आकलन करना है:

- रटनेवालीशिक्षासेयोग्यता-आधारितशिक्षाकीओरबदलाव।
- अनुभवात्मक और आनंददायक अधिगम को बढ़ावा देना।
- सीखने के लिए निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना।
- प्रत्येक शिक्षार्थी की अनूठी खूबियों और क्षमताओं को पहचानना।
- शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण, जीवन कौशल और कल्याण के साथ एकीकृत करना।



समग्र प्रगति कार्ड को स्कूली शिक्षा के मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण और मध्य चरण के लिए अनुकूलित किया गया है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विकास पर नज़र रखते हैं, जिसमें जीवन कौशल, मूल्य और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी शामिल है, और आवधिक समीक्षा के माध्यम से अभिभावकों को शामिल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

समग्र प्रगति कार्ड की प्रमुख विशेषताएँ

ट. व्यापक मूल्यांकन

- यहसंज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक विकास का मूल्यांकन करता है।
- यह शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों प्रकार की दक्षताओं पर केंद्रित है।

ठ. योग्यता-आधारित मूल्यांकन

- यहअध्ययनअधिगमपरिणामों, वैचारिक समझ, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समस्या-समाधान और ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करता है।
- योग्यता-आधारित शिक्षा के अनुरूप।



ड. 360-डिग्री मूल्यांकन

- शिक्षकमूल्यांकन
- छात्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन
- समकक्ष मूल्यांकन
- माता-पिता की प्रतिक्रिया (जहां लागू हो)



ढ़.अपनी खूबियाँ और विकास ध्यान केंद्रित करें

- यहछात्रोंकीउपलब्धियों, रुचियों, प्रतिभाओं और सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करता है।
- शिक्षार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के बजाय विकासोन्मुखी मानसिकता को प्रोत्साहित करता है जीवन कौशल और मूल्य
- पर्यावरणजागरूकता और नागरिकता.

ण. सहपाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियाँ

खेल, कला, संगीत, सांस्कृतिक गतिविधियों, व्यावसायिक शिक्षा और सामुदायिक सेवा में भागीदारी और उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेज। स्कूल शिक्षा के मूलभूत चरण (शिशु वाटिका से कक्षा-II तक), प्रारंभिक चरण (कक्षा-III से कक्षा-V तक) और मध्य चरण (कक्षा-VI से VIII तक) के लिए समग्र प्रगति कार्ड को अनुकूलित किया गया है, जबकि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए एचपीसी का विकास प्रक्रियाधीन है।

9.16. विद्यालय सुरक्षा

समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। विद्यालय सुरक्षा नीति सभी विद्यालयों में सुरक्षित, समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह नीति न केवल बच्चों की शारीरिक सुरक्षा पर बल्कि उनके भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भी बल देती है।

विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत शुरू की गई कार्रवाई

विद्यालय सुरक्षा के अंतर्गत प्रगति

ओडिशा सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता दी है और भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापक और समन्वित उपायों की एक श्रृंखला अपनाई है।

बच्चों की स्कूली सुरक्षा और संरक्षा संबंधी एनडीएमए दिशानिर्देश सभी जिलों, ब्लॉकों और स्कूलों में वितरित कर दिए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को विद्यालय सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विद्यालय स्तर पर सुरक्षा मानकों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर विद्यालय सुरक्षा सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

स्कूलों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर एक व्यापक कार्य योजना भी सभी जिलों को जारी की गई है ताकि आपात स्थितियों और आपदाओं के लिए प्रभावी तैयारी, रोकथाम, शमन और प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

संस्थागत जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए, स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की संरचना और कार्यों से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। पत्र संख्या 7063 दिनांक 26-06-26 के माध्यम से एसएमसी के गठन के लिए नए दिशानिर्देश उन सभी जिलों को सूचित किए गए हैं जिनमें सभी एसएमसी कार्यरत हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, "यह बाल अधिकारों को बनाए रखते हुए, स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा, पीओसीएसओ अधिनियम और आईसीसी विवरणों को प्रदर्शित करके एक सुरक्षित, समावेशी और बाल-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करेगा। यह स्कूल सुरक्षा योजना तैयार करेगा और उसकी समीक्षा करेगा, त्रैमासिक सुरक्षा निरीक्षण आयोजित करेगा, एंटी-बुलिंग और सीएसए समितियों का समर्थन करेगा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श को बढ़ावा देगा और निरंतर सीखने और कल्याण के लिए आपात स्थितियों के दौरान छात्रों और अभिभावकों की सहायता करेगा।"

अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से विद्यालय सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया गया है। पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ने पत्र संख्या 15191 दिनांक 13.08.2018 के माध्यम से विद्यालय सुरक्षा एवं खतरों संबंधी एनडीएमए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया और जिलों को ग्राम पंचायत स्तर पर कोर टीमें गठित करने का निर्देश दिया। इन टीमों में ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता/जीपीटीए प्रभारी, पंचायत कार्यकारी अधिकारी (पीईओ), क्लस्टर संसाधन

केंद्र समन्वयक (सीआरसीसी) और संबंधित वार्ड सदस्य शामिल हैं। ये टीमें विद्यालय भवनों, चारदीवारी, रसोई शेड, शौचालय और पेयजल सुविधाओं सहित विद्यालय के बुनियादी ढांचे की सूची तैयार करने और मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
इस विकेंद्रीकृत तंत्र स्थानीय स्तर पर कमजोरियों की समय पर पहचान और आवश्यक उपचारात्मक उपायों को सुगम बनाता है।

विद्यालय सुरक्षा और आपदा तैयारी को शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम परिवेश में एकीकृत किया गया है। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी अवधारणाओं को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। स्कूलों में तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को संस्थागत रूप देने के लिए विद्यालय विकास योजना-सह-विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना सुनिश्चित की गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रतिवर्ष विद्यालय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके दौरान विद्यालय सुरक्षा लेखापरीक्षा, जोखिम पहचान अभ्यास, अभिभावक-शिक्षक संघों (पीटीए) और विद्यालय प्रबंधन समितियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षकों एवं छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2025-26 के विद्यालय सुरक्षा सप्ताह दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

विद्यार्थियों और समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अभिभावक-शिक्षक बैठकों और विभिन्न स्तरों पर मासिक समीक्षा बैठकों के दौरान विद्यालय सुरक्षा पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। विद्यार्थियों को वाद-विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और अन्य जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाता है।

यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा को विद्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए ताकि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षा, अनुशासन, उत्तरदायित्व और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विद्यालयों को विषैले, खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है, साथ ही प्राथमिक चिकित्सा किट विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई हैं।

क्षमता निर्माण और आपातकालीन तैयारी राज्य की विद्यालय सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से शैक्षणिक प्रशासकों, शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों के लिए विद्यालय सुरक्षा, आपदा तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और जोखिम न्यूनीकरण पर नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शैक्षणिक प्रशासकों और शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और विद्यालय सुरक्षा पर आपदा राहत और आपातकालीन विभाग (डीआरजी) का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

आपातकालीन स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए छात्रों और विद्यालय के कर्मचारियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए, ओडीआरएएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन सेवा विभाग जैसी एजेंसियों के सहयोग से विद्यालय स्तर पर मॉक ड्रिल और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं।

आधारभूत संरचना की सुरक्षा और आपदा से निपटने की क्षमता को भी उचित प्राथमिकता दी गई है। स्कूल भवनों की योजना और निर्माण चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए उपयुक्त प्रावधानों के साथ किया जाता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में, भवनों को उपयुक्त आधार स्तरों के साथ डिजाइन किया जाता है, जबकि चक्रवात और भूकंप से बचाव को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार खिड़कियों और क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पट्टियों जैसे संरचनात्मक प्रावधानों को शामिल किया जाता है। आवश्यकतानुसार अग्नि सुरक्षा उपाय और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, और जोखिमों को कम करने के लिए अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रत्येक सरकारी विद्यालय के लिए 2,000 रुपये का विद्यालय सुरक्षा अनुदान जारी किया गया है, औरनिधि का उपयोग विद्यालयों की सुरक्षा और तैयारियों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया गया है। इस प्रकार की वित्तीय सहायता से विद्यालयों को आवश्यक सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है।

स्कूलों में सुरक्षा उपायों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग और जवाबदेही तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है। स्कूल सुरक्षा संकेतक क्लस्टर, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों की निगरानी अनुसूची का हिस्सा हैं। निर्धारित सुरक्षा संकेतकों को शामिल करते हुए, स्कूल सुरक्षा पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) नियमित रूप से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, एनडीएमए, ओएसडीएमए और ओडिशा सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। 2025-26 की अंतिम तिमाही की क्यूपीआर संदर्भ के लिए संलग्न है। ये आवधिक रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान, अनुवर्ती कार्रवाई और निरंतर सुधार को सुगम बनाते हैं।

निष्कर्ष

विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा ओडिशा, पंचायती राज एवं पेयजल विभाग, ओएसडीएमए और अन्य संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से ओडिशा सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक, बहुस्तरीय और एकीकृत ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे में नीति और संस्थागत तंत्र, विद्यालय प्रबंधन की जवाबदेही, संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा, आपदा तैयारी, सुदृढ़ अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मॉक ड्रिल, वित्तीय सहायता, सामुदायिक भागीदारी और नियमित निगरानी एवं रिपोर्टिंग शामिल हैं। इन निरंतर प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में एक सुरक्षित, सुदृढ़ और बाल-अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध हो और वह प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियों और अन्य संभावित जोखिमों की रोकथाम एवं प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो।





ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର

ମାଲଜାନଗିରି,୮/୯(ଇମିସ): ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲଜାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଦଭାବନା ଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେଦାରର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥି ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ନେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ଜେନା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କମଲ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି ଓ ତାହାର ପ୍ରଶମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

स्कूल सुरक्षा सप्ताह पालन दिवस – झारसुगुड़ा

अग्निशामक यंत्र के साथविद्यार्थियों को तालिम









9.17. सुरवी - बच्चों का त्योहार

राज्य स्तरीय बाल महोत्सव; शिशु महोत्सव - सुरवी 2025 का आयोजन बाल दिवस की पूर्व संध्या पर 12 से 14 नवंबर, 2025 तक राज्य मुख्यालय (भुवनेश्वर) में तीन दिनों के लिए पहले ही किया जा चुका है।

इस राज्य स्तरीय समारोह में, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्रतिभाओं के चयन की प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए लगभग 2,500 बच्चे, साथ ही राज्य भर से 1200 मार्गदर्शक शिक्षक और अधिकारी राज्य मुख्यालय में एकत्रित हुए। इस अवसर के उपलक्ष्य में आयोजित इन तीन दिनों के दौरान इन बच्चों को विभिन्न कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों और फील्ड ट्रिप में भाग लेने का अवसर मिला। इसने राज्य के कई दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण अवसरों में भाग लेने के लिए एक शानदार मंच प्रदान किया।

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री ने 'शिशु दिवस समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इन तीन दिनों के दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए।

राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि अक्टूबर-नवंबर 2025 के दौरान विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर भी एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ताकि राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए युवा प्रतिभाओं और समूहों का चयन किया जा सके। यह मंच छात्रों को अपनी छिपी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर प्रदान करता है।
















ବୃତ୍ତି ସଚେତନତା




ବୃତ୍ତି ସଚେତନତା


EducationOdisha @SMEOdisha · Nov 12, 2025
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ 'ସୁରଭି'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
#SURAVI2025
MODEL UNITED NATIONS
CONSULTATION OF SCHOOL STUDENTS IN ODISHA


EducationOdisha @SMEOdisha · Nov 13, 2025
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭିର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଦର୍ଶନ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖବରର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ 'ସୁରଭି ସମ୍ବାଦ'।
#SURAVI2025
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବାର୍ତ୍ତା
MODEL UNITED NATIONS
You and 7 others



9.18. मातृभाषा दिवस पर प्रदर्शनी

मातृभाषा दिवस पर प्रदर्शनी

मातृभाषा दिवस का आयोजन मातृभाषा को बढ़ावा देने और उसका जश्न मनाने की एक पहल है। विद्यालयों में मातृभाषा दिवस मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन के महत्व को उजागर करना है। 21 फरवरी, 2026 को हमारे राज्य के 42589 विद्यालयों में मातृभाषा में प्रस्तावना पाठ, शपथ ग्रहण, कथा और कविता पाठ, प्रतियोगिताएँ, पोस्टर और चित्रकला, भाषा प्रदर्शनियाँ और पठन सत्र जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं।






EDUCATION
POWERFU
WHICH YOU
CHANGE THE


"ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ"


GPS Map Camera
Burukuna, Odisha, India
46r5+pj2, Nh To Pmgy, Mpur Road, Burukuna, Odisha 759151, India
Lat 21.141651° Long 85.209074°
Saturday, 21/02/2026 09:47 AM GMT +05:30
Google



9.19. ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी)

परिचय

ओड़िशा सरकार, ओएसईपीए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट (एबीएफटी) की साझेदारी के माध्यम से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) का सफल कार्यान्वयन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान जारी रहा। इस कार्यक्रम ने खेल, अनुभवात्मक शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों और कक्षा में एकीकरण के माध्यम से उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान जैसे ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिससे छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिली।

कार्यक्रम पहुँच

- ओडिशाके 17 हस्तक्षेपजिलोंयानीअनगूल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, कटक, ढेंकनाल, जाजपुर, गंजम कालाहांडी, खोर्धा, केंदुझर, कोरापुट, मयूरभंज, नबरंगपुर, पुरी, सुंदरगढ़, संबलपुर में 500 सरकारी स्कूलों में लागू किया गया।
- शैक्षणिक वर्ष के दौरान सीधे तौर पर 1.8 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचा गया।
- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए संरचित, आयु-उपयुक्त गतिविधियाँ प्रदान की गईं।
- मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत खेल, कक्षा शिक्षण, कला, संस्कृति, पारंपरिक खेल और ओलंपिक शिक्षा।

प्रमुख पहल

1. विद्यालय के नेताओं की क्षमता निर्माण

- 500 सेअधिकप्रधानाध्यापकोंऔरप्रधानाध्यापिकाओंकेलिएजिलावारअभिविन्यासऔरक्षमता-निर्माणकार्यक्रमआयोजितकिएगए।
- स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी ओवीईपी कार्यान्वयन और एकीकरण के लिए नेतृत्व को मजबूत करना।
- मूल्य आधारित शिक्षा के लिए नवीन शिक्षण विधियों और समग्र विद्यालय स्तर के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।

2. शिक्षकों का प्रशिक्षण

- 17 जिलोंके 34 मास्टरट्रेनरोंकेलिएराज्यस्तरीयप्रशिक्षकप्रशिक्षण (टीओटी) आयोजितकियागया।
- नव नियुक्त ओवीईपी प्रतिनिधि शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
- कक्षा शिक्षण अभ्यास, गतिविधि-आधारित शिक्षण और नवीन कार्यान्वयन विधियाँ को सुदृढ़ करने के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

3. वार्षिक ओवीईपी दिवस

- ओवीईपी और पड़ोसी स्कूलों की भागीदारी के साथ सभी 17 हस्तक्षेपित जिलों में इसे मनाया गया।
- गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद, प्रदर्शनियां, परेड और ओलंपिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा शामिल थी।
- ओलंपिजिम के प्रति जागरूकता को मजबूत किया और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

4. वार्षिक ओवीईपी प्रगति समारोह

- वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष में ओवीईपी सत्रों के माध्यम से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए 1,000 उत्कृष्ट ओवीईपी शिक्षकों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया।
- सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और जमीनी स्तर के नेतृत्व को प्रोत्साहित करके शिक्षकों को प्रेरित करना।

खुलासा और पहुँच

1. अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यात्रा

- दोछात्रों, दो शिक्षकों, ओसेपा के अधिकारियों और एबीएफटी के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में स्थित आईओसी मुख्यालय और ओलंपिक संग्रहालय का दौरा किया।
- प्रतिभागियों को ओलंपिक आंदोलन, खेल प्रशासन, स्थिरता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ।
- इस यात्रा ने छात्रों और शिक्षकों को ओडिशा में ओवीईपी के कार्यान्वयन को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

2. राज्य स्तरीय सुरवी कार्यक्रम

ओवीईपी ने राज्य स्तरीय सुरवी कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 4,000 से अधिक छात्रों को इंटरैक्टिव खेल अनुभवों, रचनात्मक गतिविधियों और ओलंपिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा के माध्यम से शामिल किया गया।

3. बलियात्रा 2025

- ओवीईपीनेऐतिहासिकबलियात्रामहोत्सवकेदौरानमूल्य-आधारितखेलगतिविधियोंकाप्रदर्शनकिया, जिससे हजारों दर्शकों तक पहुंच बनी।
- छात्रोंनेपारंपरिकखेलोंऔरओलंपिकगतिविधियोंकाप्रदर्शनकिया, जिससे सामुदायिक जुड़ाव और समावेशी भागीदारी को बढ़ावा मिला।

4. विद्यालय-आधारित पहल

- ओवीईपीकीगतिविधियोंकेमाध्यमसेओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, महिला दिवस, उत्कल दिवस और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों को मनाया गया।
- ओडिशा के सभी विद्यालयों में शारीरिक गतिविधि, टीम वर्क और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक 'लेट्स मूव'अभियान को लागू किया गया।
- 500 स्कूलों मेंअभिभावक-शिक्षक संवादात्मक बैठकें आयोजित की गईं, जहां छात्रों ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ओलंपिक मूल्यों का प्रदर्शन किया।

सीखना और मूल्यांकन

- सभीकक्षाओं के लिए आयु-उपयुक्त 71 छोटे खेलों, प्रमुख खेलों, ओलंपिक सिद्धांत और विषय-एकीकृत गतिविधियों को शामिल करते हुए एक वार्षिक गतिविधि कैलेंडर लागू किया गया।

- शिक्षार्थी-केंद्रित, गतिविधि-आधारित शिक्षण विधियों को अपनाया गया जिसमें खेल को कक्षा शिक्षण के साथ एकीकृत किया गया।
- ओलंपिकके उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मानजनकमूल्यों को सुदृढ़ करते हुए छात्रों के टीमवर्क, नेतृत्व, अनुशासन, सहानुभूति, रचनात्मकता, शारीरिक फिटनेस और जीवन कौशल को बढ़ाना।

प्रभाव

- स्कूलकेनेताओंऔरशिक्षकोंकीक्षमताकोमजबूतकियागयाताकिवेOVEP को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
- खेलों, अनुभवात्मक शिक्षा और ओलंपिक मूल्यों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा दिया।
- खेलों और मूल्य आधारित शिक्षण गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि।
- अभिभावकों, स्कूलों और स्थानीय हितधारकों को शामिल करके सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

निष्कर्ष

ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) ने ओडिशा के सरकारी विद्यालयों में खेलों के माध्यम से मूल्यों पर आधारित शिक्षा को सफलतापूर्वक मजबूत किया है। उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों को दैनिक शिक्षण और अधिगम में एकीकृत करके, कार्यक्रम ने एक सकारात्मक और समावेशी विद्यालयी वातावरण बनाया है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ओडिशा सरकार, ओसेपा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच मजबूत सहयोग के माध्यम से, यह कार्यक्रम सफल रहा है और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट (एबीएफटी) के सहयोग से, ओवीईपी ने स्कूलों में खेल और ओलंपिक मूल्यों की आजीवन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार युवा नागरिकों के पोषण के लिए एक स्थायी नींव रखी है।

चित्र गैलरी:





स्कूल नेताओं का क्षमता निर्माण









शिक्षकों का प्रशिक्षण





वार्षिक ओवीईपी प्रगति उत्सव













अंतर-राष्ट्रीय क्षेत्रीय भ्रमण



9.20. बीआरसी/सीआरसीसी के माध्यम से अकादमिक सहायता

ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओसेपा) के समग्र शिक्षा ढांचे के तहत, ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी) राज्य भर में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत शैक्षणिक सहायता, निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और जमीनी स्तर की निगरानी प्रदान करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

बीआरसी और सीआरसी सहायता के मुख्य उद्देश्य

- विकेंद्रीकृतगुणवत्ताहस्तक्षेप:जिलास्तरीयप्राधिकरण (डीआईईटीएस / डीईओ) औरजमीनीस्तरकेस्कूलप्रबंधनकेबीचए कसेतुकेरूपमेंकार्यकरना।
- ऑन-साइट व्यावसायिक मार्गदर्शन: शिक्षकों को निरंतर शैक्षणिक हस्तक्षेप, आधुनिक शिक्षण-अधिगम विधियों और तत्काल समस्या निवारण के साथ सशक्त बनाना।
- रीयल-टाइम मॉनिटरिंग: विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों, मूलभूत साक्षरता उपलब्धियों और बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता पर नज़र रखना।

रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताए गए प्रमुख शैक्षणिक कार्य

1. सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ

- क्षमतानिर्माण:
- मासिकसाझाकरणबैठकें (एमएसएमएस)

2. ऑन-साइट सहायता और स्कूल निरीक्षण

- अनिवार्यक्षेत्रदौरा
- कक्षा अवलोकन

3. समावेशी शिक्षा और बाल एवं महिला शिक्षार्थी सहायता

- लक्षितसंसाधनपरिनियोजन
- उपचारात्मक योजना







ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक, बलांगीर

9.21. पुस्तकालय अनुदान

पुस्तकालय शब्द परंपरा, अर्थ और उपयोग में समृद्ध है। विद्यालय पुस्तकालय सूचना प्रदान करता है, विचारों को विकसित करता है और ज्ञान का विकास करता है, जो आज के सूचना और ज्ञान आधारित समाज में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय पुस्तकालय का यह मूलभूत उद्देश्य है कि वह विद्यार्थियों को आजीवन सीखने के कौशल से लैस करे, उनमें रचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता विकसित करे और उन्हें आदर्श एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में सक्षम बनाए। पुस्तकालय की पुस्तकें संसाधन के रूप में प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण हैं। बच्चों और पुस्तकों को सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने का आनंद अनुभव करना होगा और पठन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, सरकारी विद्यालयों के लिए पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है ताकि सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित की जा सके और पुस्तकों की खरीद सहित विद्यालय पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया जा सके।

समग्र शिक्षा योजना के तहत, सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है ताकि सभी आयु वर्ग के छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित की जा सके और पुस्तकों की खरीद सहित स्कूल पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पुस्तकों और पुस्तकालयों के लिए प्रति इकाई लागत का विवरण इस प्रकार है: प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-V) के लिए ₹5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा VI-VIII) के लिए ₹13,000, माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा IX-X) के लिए ₹15,000 और संयुक्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा XI से XII) के लिए ₹20,000।

प्रगति 2025-26:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक पठन-लेखन और समझ कौशल को बढ़ावा देना है, साथ ही बुनियादी अंकगणित कौशल विकसित करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय समिति द्वारा आयु/कक्षा के अनुरूप उपयुक्त पुस्तकों का चयन किया गया है।

- विद्यालयोंकोआयु/ग्रेड के अनुरूप उपयुक्त पुस्तकालय पुस्तकों का एक विशेष रूप से चयनित सेट प्रदान करके, और शिक्षकों को इन पुस्तकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करके, कक्षाओं में दिन-प्रतिदिन की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को समृद्ध करने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

- शिक्षामंत्रालयकेदिशानिर्देशोंकेअनुसार, पुस्तकालय पुस्तक चयन समिति ने सरकारी प्रकाशन गृहों और क्षेत्रीय/स्थानीय प्रकाशकों से आयु/कक्षा के अनुसार उपयुक्त पुस्तकों का चयन किया है।

पुस्तकालय गतिविधियाँ शुरू की गईं:

- लेखनकौशलऔररचनात्मकताकोबेहतरबनानेकेलिए, छात्रों को पहले पढ़ी गई किसी एक कहानी को लिखने या उसी तरह की कहानी को फिर से रचने और कहानी सुनाने के सत्र में सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- वर्ष 2025-26 के दौरान 4 सरकारी और 189 क्षेत्रीय प्रकाशकों से 48561 विद्यालयों के लिए पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद सफलतापूर्वक पूरी हो गई।
- पीएम श्री के बजट प्रावधान से 762 पीएम श्री स्कूलों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।
- पुस्तकालय अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान सभी विद्यालयों में 628 (404 क्षेत्रीय/स्थानीय + 224 सरकारी) पुस्तकों से संबंधित कुल 59,88,279 पुस्तकें वितरित की जा रही हैं।

- विद्यालयोंमेंपुस्तकालयसंबंधीगतिविधियोंकेकार्यान्वयनकेलिएदिशानिर्देशसभीबीईओ, सीआरसीसी और एचएम को वितरित कर दिए गए हैं।
- ओडिशा सरकार के ओडिया भाषा प्रतिष्ठान (ओबीपी) के सहयोग से सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को त्रैमासिक बाल पत्रिका "शिशु लेखा" उपलब्ध कराई जाती है।
- शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों में सुझाए गए मानदंडों के आधार पर कक्षाओं में पठन-पाठन के कोने विकसित किए गए।
- पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए पठन क्लब बनाए गए थे। पठन क्लब के अंतर्गत महीने में एक दिन पठन दिवस मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न पठन गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।
- विद्यालय में पुस्तकालय संबंधी गतिविधियों के लिए प्रति सप्ताह 2 अवधियाँ आवंटित की जाती हैं।
- पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए अवकाश के समय का उपयोग किया गया।
- सभी सरकारी हाई स्कूलों में ई-लाइब्रेरी की कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा रही है।

- डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा से लैस भौतिक पुस्तकालयों को सुनिश्चित करने के लिए, ओडिशा सरकार के विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग की एकीकृत स्वचालन प्रणाली (यूएएस) के तहत एक लाइब्रेरी मॉड्यूल (डिजिटल) विकसित किया गया है।

- यूएएस लाइब्रेरी मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है और 1040 विद्यालयों में डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। यूएएस के माध्यम से भौतिक पुस्तकालय को डिजिटल पुस्तकालय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया राज्य के सभी विद्यालयों तक समय के साथ विस्तारित की जाएगी।

निगरानी तंत्र:

- विद्यालयपुस्तकालयोंकेकामकाजकाजायजालेनेकेलिएडीईओ-सह-डीपीसीऔरएडीईओद्वारानियमितदौरे।
- नोडल अधिकारी जिलों का दौरा करके पुस्तकालय की पुस्तकों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।
- सभी डीईओ, डीपीसीएस, बीईओ, सीआरसीसीएस, बीआरसीसी, एचएम के नियमित निरीक्षण और दौरे के एजेंडे में से एक।
- ई-लाइब्रेरी की कार्यप्रणाली और छात्रों द्वारा इसके उपयोग के संबंध में जिलों से दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

पुस्तकालय में पुस्तक पठन गतिविधियाँ : एक संक्षिप्त अवलोकन





कार्यान्वयन के तौर-तरीके और औचित्य

• आयुऔरकक्षाकेअनुसारउपयुक्तपुस्तकालयपुस्तकेंसरकारीप्रकाशनगृहोंऔरस्थानीयप्रकाशकोंसेशिक्षामंत्रालयद्वारासमय-समयपरजारीपुस्तकालयदिशानिर्देशोंकेअनुसारकेंद्रद्वाराखरीदीजाएंगीऔरजिला अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों (कक्षा I- XII) को उपलब्ध कराई जाएंगी। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यात्मक ई-पुस्तकालय की शुरुआत की जाएगी। ई-पुस्तकालय प्रणाली के तहत डिजिटल पठन/अधिगम सामग्री जैसे कहानी पुस्तकें, दृश्य, वीडियो और ऑडियो आदि पुस्तकालय के कंप्यूटरों में संग्रहीत की जा सकती हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पुस्तकालय गतिविधियों (दिशानिर्देशों में विस्तृत) का संचालन किया जाएगा और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल मॉनिटरिंग ऐप और राज्य एवं जिला अधिकारियों द्वारा भौतिक निगरानी के माध्यम से पुस्तकालय पुस्तकों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

➢पुस्तक चयन प्रक्रिया: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुस्तक चयन प्रक्रिया पर केंद्रित है।

आयु और कक्षा के अनुरूप उपयुक्त पुस्तकालय पुस्तकों का चयन करना कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पुस्तक चयन समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय चयन समिति उपलब्ध 700-800 अच्छी पुस्तकों की एक विस्तृत सूची तैयार करती है। पुस्तकों का केंद्रीकृत चयन पूरे राज्य में संग्रह की एकरूपता बनाए रखने में सहायक होता है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नई शिक्षा नीति (एनईपी) में उल्लिखित मापदंडों के अनुसार विद्यालय श्रेणीवार पुस्तकालय पुस्तकों का चयन किया गया है। इसके बाद, पुस्तकों की खरीद के लिए केंद्रीय आदेश दिए जाते हैं और उन्हें जिला मुख्यालयों को भेजा जाता है।

स्कूल में वितरण: पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। पुस्तकालय की पुस्तकों की स्टॉक एंट्री और भौतिक सत्यापन केवल विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। हालांकि, प्राप्ति और वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एंट्री जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी की जाएगी।

➢उपयोग: स्कूल में पुस्तकें पहुँचने के बाद, हेडमास्टर की यह ज़िम्मेदारी है कि वे पुस्तकों का भौतिक सत्यापन करें, उन्हें लाइब्रेरी रजिस्टर में दर्ज करें और छात्रों के उपयोग के लिए स्कूल में उपलब्ध लाइब्रेरी कक्ष में सुरक्षित रखें। छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल रीडिंग कॉर्नर स्थापित करते हैं और सीखने के लिए एक समृद्ध वातावरण बनाते हैं। बच्चों के अनुकूल कई चीज़ें जैसे कि कविता कॉर्नर और मैसेज बोर्ड विकसित किए गए हैं। लाइब्रेरी की पुस्तकों को प्रदर्शित करने के लिए नवीन और कम लागत वाले तरीके अपनाए गए हैं ताकि बच्चे उन्हें आसानी से देख सकें।

अपेक्षित परिणाम

दैनिक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को समृद्ध बनाना। प्रारंभिक अवस्था में ही पढ़ने की आदत विकसित करना जिससे बच्चों की पठन क्षमता में वृद्धि होगी। छात्रों को भाषा कौशल, कहानी सुनाने, आलोचनात्मक सोच और अन्य कौशलों में सहायता करना। महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों, नए विचारों और वास्तविक जीवन की स्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना। साहित्यिक कौशल, शब्दावली का विकास करना और ज्ञान का आधार तैयार करना। विभिन्न विषयों से संबंधित कौशल, क्षमताओं, व्यवहार और मूल्यों में सुधार करना।

क्र.सं	गतिविधि	मुख्य निष्पादन संकेतक
1	पुस्तकालय	विद्यालय में नामांकित कुल छात्रों और पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की कुल संख्या का अनुपात: 3:1 (लगभग)
2		विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो पुस्तकें उधार लेने वाले छात्रों का प्रतिशत।
3		मूलभूत स्तर के विद्यार्थियों में से आयु-उपयुक्त मौखिक पठन प्रवाह प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत।
4		प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों में से आयु-उपयुक्त मौखिक पठन प्रवाह प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत।
5		मध्य स्तर के विद्यार्थियों में से आयु-उपयुक्त मौखिक पठन प्रवाह प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत।



9.22. मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान

कार्यकारी सारांश

सितंबर 2024 में विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया निपुन ओडिशा मिशन, ओडिशा की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर आधारित और भारत सरकार के निपुन भारत मिशन (5 जुलाई 2021 को शुरू किया गया) के अनुरूप, इस पहल का लक्ष्य 2026-27 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप, कक्षा 3 के अंत तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है।

यह रिपोर्ट मिशन की 2025-26 तक की प्रगति का समेकित विवरण प्रस्तुत करती है, जो विभाग द्वारा प्रकाशित NIPUN ओडिशा कॉफी टेबल बुक पर आधारित है, जिसमें मिशन की एक वर्ष की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। इस वर्ष के दौरान, लगभग 45,000 सरकारी स्कूलों में शिशु वाटिका पूर्व-प्राथमिक अनुभाग खोले गए; NIPUN ओडिशा मेला सभी 30 जिलों, 314 ब्लॉकों और 4,500 से अधिक क्लस्टरों में आयोजित किया गया; कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए पहला वार्षिक एफएलएन मूल्यांकन (एएफए) आधारभूत सर्वेक्षण किया गया; और प्रवेश उत्सव और खादी चुआन के माध्यम से शिक्षक क्षमता निर्माण, कक्षा परिवर्तन और सामुदायिक लामबंदी पर निरंतर प्रयास जारी रहे।

PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के उत्साहजनक परिणामों के आधार पर, जिसमें ओडिशा ने मूलभूत साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया, मिशन की आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं में शिशु वाटिका को मजबूत करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, कक्षाओं में नवाचार लाना, सामुदायिक भागीदारी को गहरा करना और एक समानांतर संख्यात्मकता अभियान के साथ-साथ राज्यव्यापी पठन प्रोत्साहन अभियान शुरू करना शामिल है।

मिशन के बारे में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को स्कूली शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है, और सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप सुलभ, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का आह्वान किया गया है। इसके जवाब में, भारत सरकार ने 5 जुलाई 2021 को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन 'निपुण भारत' की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक पूरा करना है।

इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से, 3 से 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल प्राप्त कराने हेतु निपुन ओडिशा मिशन का गठन किया गया। यह मिशन राज्य के स्तंभों के विकसित करने का दीर्घकालिक विजन है।विकसित ओडिशा 2036 के तहत राज्य सरकार नेराज्य को एक उन्नत और समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है

जो बच्चे बचपन से ही पढ़ने, लिखने और गणित के मूलभूत कौशल में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, वे उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। शिशु वाटिका में कक्षा 3 तक की शिक्षा उस व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है।
मिशन के दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता समानता है: प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी स्थान या पृष्ठभूमि का हो, गुणवत्तापूर्ण मूलभूत शिक्षा का हकदार है। इसे शिक्षण सामग्री की समयबद्ध उपलब्धता, शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और सिख्यना सोपान के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की व्यवस्थित निगरानी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण बच्चे की मातृभाषा में शुरू होता है, और विद्यालय की भाषा को धीरे-धीरे शामिल किया जाता है; कई विद्यालय ग्रामीण, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए बहुभाषी शिक्षण का भी उपयोग करते हैं।

प्रमुख उपलब्धियां 2024-25 से 2025-26 तक

मिशन का पहला वर्ष राज्यव्यापी उपलब्धियों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ा, जिसमें शुभारंभ और प्रणाली निर्माण से लेकर सामुदायिक लामबंदी और मूल्यांकन तक की प्रक्रिया शामिल थी:

समय	सफलता
सितंबर 2024	निपुन ओडिशा मिशन का शुभारंभ
अक्टूबर 2024	सिखियाना सोपान (बाल-वार ट्रैकिंग उपकरण) का राज्यव्यापी प्रसार
जनवरी 2025	लगभग 45,000 सरकारी स्कूलों में शिशु वाटिका का उद्घाटन
फरवरी 2025	निपुण ओडिशा मेला मूलभूत शिक्षा का राज्यव्यापी सामुदायिक उत्सव है।
मार्च 2025	वार्षिक एफएलएन मूल्यांकन (एएफए) - कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का आधारभूत मूल्यांकन
अप्रैल 2025	प्रवेश उत्सव एवं खादी चुआं विद्यालय नामांकन एवं स्वागत अभियान
जून 2025	ग्रीष्मकालीन शिक्षण कार्यक्रम
जुलाई'25	प्रारंभिक कक्षाओं में पठन प्रवाह और समझ को मजबूत करने के लिए राज्यव्यापी पठन अभियान (आरसी) का शुभारंभ।
अगस्त	निपुन विद्यालया (एनवी) पहल का शुभारंभ; चरणबद्ध तरीके से सभी 30 जिलों में 5,250 विद्यालयों को एफएलएन उत्कृष्टता के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए।
सितम्बर25	10 जिलों (अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, गंजम, क्योंझर, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगड़ा और सुंदरगढ़) में पायलट आधार पर जिला एनआईएपयूएन सेल (डीएनसी) की स्थापना; पठन अभियान की निरंतरता
अक्टूबर'25	निपुन सप्ताह राज्य भर के स्कूलों में कक्षा और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से मूलभूत शिक्षा का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है।
नवम्बर'25	डीईओ और एडीईओ द्वारा निपुन विद्यालया स्कूलों की निरंतर पहचान और उन्हें गोद लेने से राज्य 5,250 स्कूलों के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है।
दिसम्बर25	जिला समीक्षा बैठकों (डीआरएम) और ब्लॉक समीक्षा बैठकों (बीआरएम) के माध्यम से जिला स्तरीय समीक्षा, राज्य संचालन समिति (एसएससी) की बैठक और 9वीं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की बैठक, निपुन विद्यालय और डीएनसी की प्रगति का आकलन करने के लिए आयोजित की गई।

मिशन स्नैपशॉट

निम्नलिखित संकेतक वर्ष के दौरान हासिल किए गए कार्यान्वयन के पैमाने को दर्शाते हैं:

सूचक	2025-26 स्नैपशॉट
शिशु वाटिका की स्थापना हुई	-45,000 सरकारी स्कूल
निपुन ओडिशा मेले के अंतर्गत आने वाले जिले	30 जिले
ब्लॉक कवर किए गए	314 ब्लॉक
क्लस्टर कवर किए गए	4,500+ क्लस्टर
एफएलएन-अनुरूप विद्यालयों को लक्षित किया गया (2025-26)	23,827 स्कूल
आयु समूह कवर किया गया	3 से 8 वर्ष (शिशु वाटिका से ग्रेड 3 तक)
NIPUN विद्यालय लक्षित (2025-26, प्रारंभिक चरण)	5,250 स्कूल
जिला निपुन प्रकोष्ठ (डीएनसी) स्थापित (पायलट परियोजना)	10 जिले

कार्यक्रम स्तंभ

शिशु वाटिका - व्यापक स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा



शिशु वाटिका के कक्षाओं को बाल-अनुकूल शिक्षण स्थानों के रूप में पुनः डिजाइन किया गया है।

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सबसे बड़े विस्तारों में से एक के तहत, ओडिशा के लगभग 45,000 सरकारी स्कूलों में शिशु वाटिकाएं स्थापित की गईं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंच बनी। कक्षाओं को बाल-अनुकूल स्थानों के रूप में पुनः डिज़ाइन किया गया, और स्कूलों को सीखने के कोने व्यवस्थित करने, बच्चों की आंखों के स्तर पर सामग्री प्रदर्शित करने और सुरक्षित वातावरण बनाने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस पहल का उद्देश्य घर और औपचारिक शिक्षा के बीच के अंतर को कम करना है, जिससे बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले स्कूल के लिए तैयार होने के कौशल विकसित करने में मदद मिल सके। शिशु वाटिका परिसरमौखिक भाषा, पूर्व-संख्यात्मक कौशल, शारीरिक गतिविधि, सामाजिक और भावनात्मक विकास को पोषित करें, ताकि बच्चे आत्मविश्वास और आवश्यक तैयारी कौशल के साथ प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर सकें।

प्रवेश उत्सव और खड्डीस्पर्शे
प्रवेश उत्सव में सामुदायिक भागीदारी - विद्यालय में स्वागत अभियान।



ओडिशा के जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए गए जीवंत स्थानीय अभियानों के माध्यम से निपुन ओडिशा कार्यक्रम को प्रत्येक जिले में शुरू किया गया, जिससे बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान का संदेश राज्य के हर कोने तक पहुंचा। बच्चों के स्कूल के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से परिवारों को व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र दिए गए, जिससे बच्चों और अभिभावकों दोनों में गर्व, अपनेपन और उत्साह की भावना पैदा हुई।

प्रवेश उत्सव और खादी चुआन में अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) ने सक्रिय भूमिका निभाई, स्वागत समारोहों में भाग लिया, कक्षाओं को तैयार करने में मदद की और शिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया। इस सहभागिता ने बच्चे की स्कूली शिक्षा यात्रा के प्रति साझा स्वामित्व की भावना को मजबूत किया और नियमित उपस्थिति तथा सीखने में सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

निपुन (NIPUN) ओड़िशा मेला – सामुदायिक गतिशीलता





निपुन ओडिशा मेले ने शिक्षकों, अभिभावकों और सामुदायिक नेताओं को एक साथ लाया।

निपुन ओडिशा मेला मूलभूत शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान के रूप में शुरू किया गया था। सभी 30 जिलों, 314 ब्लॉकों और 4,500 से अधिक क्लस्टरों में आयोजित इस मेले ने यह सुनिश्चित किया कि बड़े शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक, हर समुदाय को इसमें भाग लेने का अवसर मिले।

इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान में हुई प्रगति का जश्न मनाना था। इसके लिए पठन प्रदर्शन, कहानी सुनाना, भूमिका-निर्वाह और रचनात्मक अभिव्यक्ति के स्टॉल लगाए गए, जिससे माता-पिता और आगंतुकों को यह प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला कि बच्चे भाषा और संख्याओं के साथ किस प्रकार जुड़ रहे हैं। विशेष सत्रों में माता-पिता को घर पर सीखने में सहायता करने के सरल तरीके भी बताए गए, जिससे यह बात पुष्ट हुई कि मूलभूत शिक्षा विद्यालय, घर और समुदाय की साझा जिम्मेदारी है।

कक्षा परिवर्तन एवं जादुई पीटारा



जादूई पिटारा के माध्यम से खेल-आधारित शिक्षण केंद्र बनाए गए हैं।
एफएलएन कक्षाओं में अधिगम दो संरचित शिक्षण पद्धतियों द्वारा निर्देशित होता है: भाषा के लिए संतुलित साक्षरता पद्धति और संख्यात्मक कौशल के लिए मूर्त-प्रतिनिधित्वात्मक-अमूर्त (सीआरए) पद्धति। साक्षरता किट और जीकेए किट के सहयोग से, शिक्षक गतिविधि-आधारित, व्यावहारिक अधिगम के माध्यम से पाठों को जीवंत बना रहे हैं।

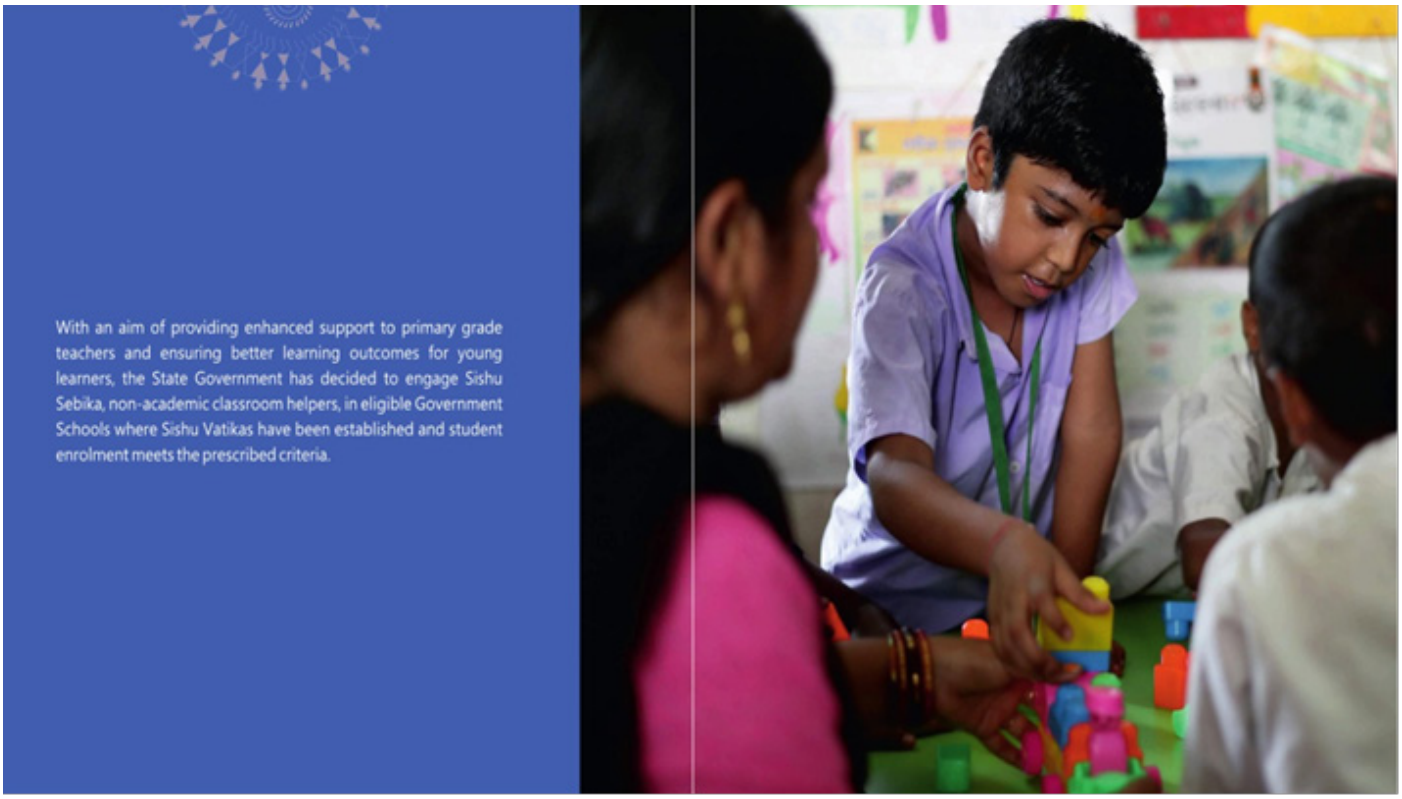
खेल आधारित शिक्षा मिशन का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है। जादूई पिटारा के माध्यम से, खिलौनों, पहेलियों, कठपुतलियों, फ्लैशकार्ड, वर्कशीट और स्थानीय संस्कृति से जुड़े सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे विकास के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सीखते हैं: शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सांस्कृतिक और आदत निर्माण। कक्षाओं को साक्षरता कॉर्नर, संख्या ज्ञान कॉर्नर और अन्य रचनात्मक स्थानों से समृद्ध किया गया है जो अन्वेषण और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के तहत, ओडिशा ने 2025-26 तक 23,827 स्कूलों को एफएलएन-अनुरूप, प्रिंट-समृद्ध, सुरक्षित और बाल-अनुकूल कक्षाओं में बदलने का लक्ष्य रखा है।

शिक्षक क्षमता निर्माण

निरंतर शिक्षक क्षमता निर्माण मिशन के हर पहलू का आधार है। क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों (सीआरसीसीएस) द्वारा संचालित मासिक क्लस्टर बैठकें, सहभागी अधिगम की रीढ़ हैं, जो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को कक्षा के अनुभव साझा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने, नई गतिविधियों का प्रदर्शन करने और छात्र अधिगम डेटा की समीक्षा करने के लिए एक साथ लाती हैं। ये बैठकें सामूहिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देती हैं और शिक्षकों को अपनी कक्षा शिक्षण पद्धति को निरंतर परिष्कृत करने में मदद करती हैं।

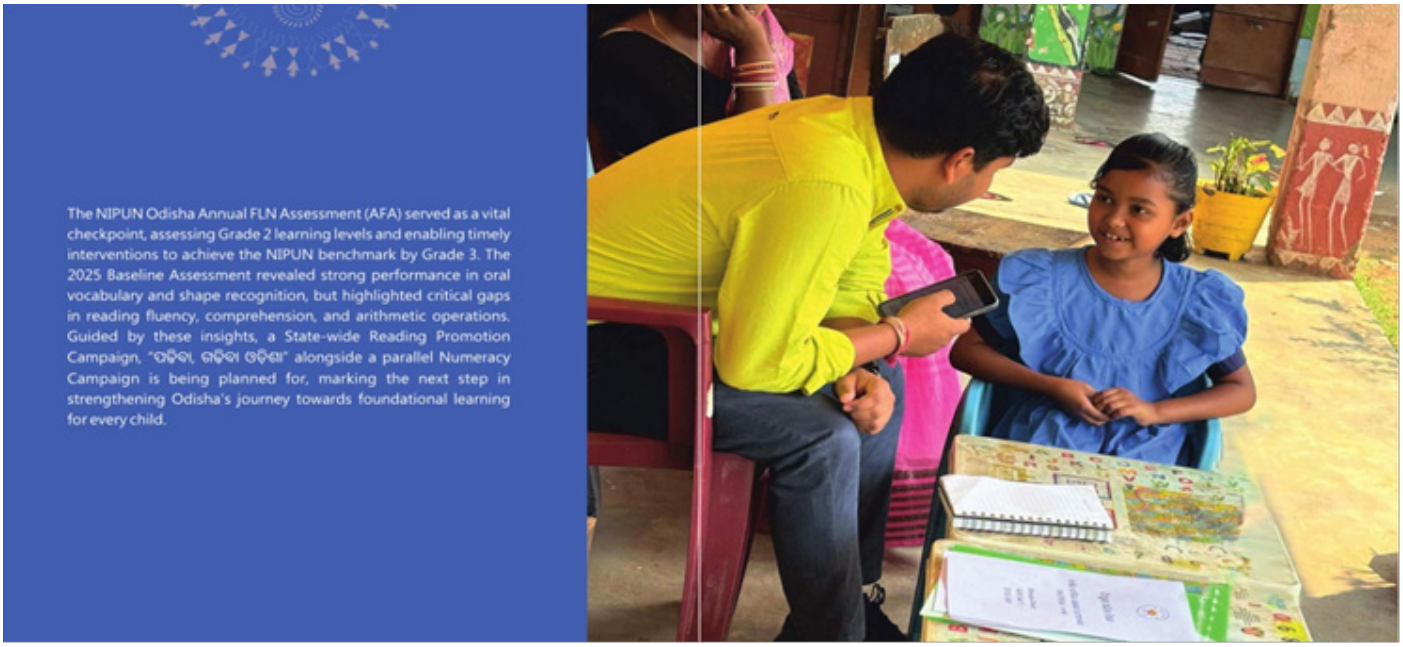
शिशु सेविकाएँ



शिशु सेबिका शिशु वाटिका कक्षाओं में समर्पित, गैर-शैक्षणिक सहायता प्रदान करते हैं।

प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को सहायता प्रदान करने और छोटे बच्चों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने उन योग्य सरकारी विद्यालयों में शिशु सेवाकर्मियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है जहाँ शिशु सेवाकर्मी शैक्षणिक कक्षा सहायक नियुक्त किए गए हैं और छात्रों का नामांकन निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। शिशु सेवाकर्मी बच्चों की स्वच्छता, भोजन, सुरक्षा और कल्याण में सहायता करते हैं और उन्हें सरल खेल और समूह गतिविधियों में शामिल करते हैं, जिससे शिक्षकों को शिक्षण पद्धति और व्यवस्थित निर्देश पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।

निगरानी एवं मूल्यांकन



वार्षिक एफएलएन मूल्यांकन सीखने के स्तर पर नज़र रखता है ताकि समय पर हस्तक्षेप किया जा सके।

2024 में मिशन के साथ शुरू किया गया सिख्याना सोपान, एक अग्रणी बाल-केंद्रित ट्रैकिंग उपकरण है जो शिक्षकों को साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में प्रत्येक बच्चे की प्रगति की सटीक निगरानी करने में सक्षम बनाता है। पिछले एक वर्ष में, इसने शिक्षण-अधिगम पद्धतियों में सुधार किया है, साथ ही जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और यह स्पष्टता प्रदान की है कि प्रत्येक बच्चा आयु-उपयुक्त कौशल प्राप्त करने में किस स्तर पर है।

एनआईपीयूएन ओडिशा वार्षिक एफएलएन मूल्यांकन (एएफए) एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में कार्य करता है, जो कक्षा 2 के अधिगम स्तरों का आकलन करता है और बच्चों को कक्षा 3 तक एनआईपीयूएन के मानक तक पहुंचने में मदद करने के लिए समयोचित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाता है। 2025 के आधारभूत मूल्यांकन में मौखिक शब्दावली और आकृति पहचान में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पता चला, जबकि पठन प्रवाह, बोध और अंकगणितीय संक्रियाओं में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया गया। इन निष्कर्षों ने मिशन की 2025-26 की अग्रिम योजना को सीधे तौर पर प्रभावित किया।

निपुन (NIPUN) विद्यालया - स्कूलों में एफएलएन उत्कृष्टता का प्रदर्शन

मिशन के पहले वर्ष के दौरान सुदृढ़ किए गए बुनियादी ढांचे और कक्षा शिक्षण पद्धतियों के आधार पर, ओएसईपीए ने निपुन विद्यालयों (एनवी) के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश (पत्र संख्या 9100/पेड/25 दिनांक 22 अगस्त 2025) जारी किए। निपुन विद्यालय उन चयनित विद्यालयों का समूह है जो मूलभूत शिक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और शैक्षिक सुधार में तेजी लाने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। निपुन विद्यालयों की परिकल्पना यह है कि निपुन कक्षाओं के सभी बच्चे शैक्षणिक वर्ष के अंत तक कक्षा-स्तरीय दक्षताएं प्राप्त कर लें, ताकि कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चा निपुन स्तर का हो जाए। प्रारंभिक चरण में, सभी

30 जिलों के 5,250 विद्यालयों को निपुन विद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। प्रत्येक डीईओ, एडीईओ (अकादमिक), बीईओ, एबीईओ-सह-बीआरसीसी और सीआरसीसी 2025-26 में कम से कम एक विद्यालय को गोद लेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों में इसका विस्तार किया जाएगा।
यह पहल तीन घटकों पर आधारित है: एफएलएन-अनुरूप आधारभूत संरचना जिसमें शामिल हैं
बाला (बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड) हस्तक्षेप, अच्छी रोशनी और हवादार कक्षाएँ, आयु-उपयुक्त बैठने की व्यवस्था, साक्षरता, संख्या ज्ञान और रचनात्मक कोने, और टैबलेट, टीवी, टच पैनल बोर्ड, दीक्षा प्लेटफॉर्म और पाठ्यपुस्तकों में क्यूआर कोड जैसे डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग; चार दिन शिक्षण, एक दिन पुनरावलोकन और एक दिन मूल्यांकन के 4+1+1 मॉडल पर आधारित उन्नत कक्षा अभ्यास, 120 मिनट का साक्षरता और 90 मिनट का संख्या ज्ञान कार्यक्रम, और 4-ब्लॉक और कंक्रीट-रिप्रेजेंटेशनल-एब्स्ट्रैक्ट (सीआरए) दृष्टिकोण; और सभी बच्चों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत छात्र अधिगम परिणाम (एसएलओ) की उपलब्धि।

निपुन विद्यालयों में कक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, निपुन विद्यालय कक्षा लेनदेन सूचकांक विकसित किया गया है, जो पांच भारित क्षेत्रों - शिक्षण रणनीतियाँ (25%), छात्र सहभागिता (20%), शिक्षण में प्रयुक्त सामग्री (20%), प्रतिक्रिया एवं मूल्यांकन (20%), और समय एवं कार्य प्रबंधन (15%) - के आधार पर विद्यालयों का मूल्यांकन करता है। रेटिंग्स को मेंटर अवलोकन प्रारूपों, सीआरसीसीएस द्वारा आभासी निगरानी, सिखियाना सोपान प्रविष्टियों और मासिक जिला डैशबोर्ड के माध्यम से संकलित किया जाता है, जिससे डीपीएमयू को प्रत्येक अधिग्रहीत विद्यालय में कक्षा अभ्यास का एक संरचित, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सभी एफएलएन घटकों के अनुकरणीय निष्पादन को प्रदर्शित करने वाले विद्यालयों को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो एक वर्ष के लिए वैध होते हैं और नवीनीकरण के लिए पुनर्मूल्यांकन के अधीन होते हैं।

जिला निपुन प्रकोष्ठ (डीएनसी) - जिला स्तरीय शासन को सुदृढ़ बनाना
सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत रूप देने और जिला स्तर पर कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, ओसेपा ने (पत्र संख्या 9690/Ped/25 दिनांक 10 सितंबर 2025)पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अनगूल, भद्रक, ढेंकनाल, गंजाम, क्योंझर, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपड़ा, रायगढ़ा और सुंदरगढ़ सहित 10 जिलों में जिला निपुन प्रकोष्ठ (डीएनसी) स्थापित करने कादिशानिर्देश जारी किया। प्रत्येक जिले में डीएनसी निपुन से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, उनकी निगरानी करने और समन्वय करने के लिए प्राथमिक सहायक इकाई के रूप में कार्य करती है।

प्रत्येक डीएनसी की अध्यक्षता डीईओ-सह-डीपीसी द्वारा की जाती है, जिसमें एडीईओ (अकादमिक) नोडल अधिकारी और डीआईईटी के प्रधानाचार्य नोडल अधिकारी/सह-प्रमुख होते हैं। इन्हें शिक्षाशास्त्र समन्वयक सदस्य-संयोजक के रूप में सहयोग देते हैं, साथ ही डीआईईटी के 2-3 संकाय सदस्य, कम से कम दो बीईओ/एबीईओ, 1-2 सीआरसीसी, साक्षरता और संख्या ज्ञान विशेषज्ञों से गठित 10-15 अकादमिक विशेषज्ञों का एक पैनल और एक एनजीओ सहयोगी या राज्य निपुन प्रकोष्ठ का प्रतिनिधि भी शामिल होता है। सदस्यों का चयन डीईओ और डीआईईटी के प्रधानाचार्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, और अंतिम संरचना को जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

डीएनसी तीन प्रमुख उद्देश्यों का अनुसरण करता है - अकादमिक, जिसमें प्रभावी एफएलएन शिक्षण और अधिगम पद्धतियों,

पर्याप्त संसाधनों और शिक्षक विकास को सुनिश्चित करना शामिल है; निगरानी और डेटा उपयोग, जिसमें कक्षा अवलोकन उपकरण, वार्षिक मूल्यांकन सर्वेक्षण, एनएएस, यूडीआईएसई और सिखियन सोपान रजिस्टर जैसे उपकरणों का उपयोग करके एक मजबूत जिला निगरानी प्रणाली का निर्माण करना शामिल है; और सामुदायिक जुड़ाव, जिसमें विद्यालयों, अभिभावकों और समुदायों, विशेष रूप से मातृ समूहों के बीच साझेदारी को मजबूत करना शामिल है। डीएनसी जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू), जिला समीक्षा बैठकों (डीआरएम) और ब्लॉक समीक्षा बैठकों (बीआरएम) के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है, इन प्लेटफार्मों को जमीनी स्तर की जानकारी प्रदान करता है और राज्य स्तरीय मार्गदर्शन को जिला स्तर पर लागू करता है।

राज्य स्तरीय समीक्षा-सह-मार्गदर्शन कार्यशाला

23 फरवरी 2026 को, ओएसईपीए ने भुवनेश्वर के एक सरकारी हाई स्कूल में ओडिशा के निपुन कार्यक्रम पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला और समीक्षा-सह-अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी 30 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, एडीईओ, डीआईईटी के प्रधानाचार्य, जिला शिक्षाशास्त्र समन्वयक और राज्य के अधिकारी, साथ ही सहयोगी संगठन भी शामिल हुए। एक दिवसीय कार्यक्रम प्रगति की समीक्षा करने, मिशन की प्राथमिकताओं पर सहमति मजबूत करने और मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के परिणामों में सुधार के लिए जिलों और राज्य की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। उद्घाटन सत्र में विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग के आयुक्त-सह-सचिव और ओएसईपीए के राज्य परियोजना निदेशक ने संबोधित किया।

कार्यशाला का आयोजन सात तकनीकी सत्रों के इर्द-गिर्द किया गया था, जिनमें से कई सत्रों में गंजाम, संबलपुर, अनगूल, रायगढ़ा, मयूरभंज, पुरी, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, खोर्धा और ढेंकनाल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जिला केस स्टडी शामिल थीं।

- सत्र 1: नईपहल - कक्षाV और VIII का मूल्यांकन
- सत्र 2: अधिगम का मूल्यांकन - PARAKH, SLAS, FLS और वार्षिक FLN मूल्यांकन से प्राप्त जानकारियों का उपयोग करना
- सत्र 3: अधिगम के लिए/अधिगम के रूप में मूल्यांकन - कक्षा अभ्यासों में सुधार
- सत्र 4:विद्यालयों में NIPUN (NIPUN विद्यालय) के प्रदर्शन हेतु लक्ष्य और रणनीतियाँ, जिसमें प्रतिभागियों के लिए एक इंटरैक्टिव FLN प्रश्नोत्तरी शामिल है।
- सत्र 5: डीपीएमयू, डीआरएम, बीआरएम, जिला एनआईपीयूएन प्रकोष्ठ और एनआईपीयूएन ऐप को शामिल करते हुए एनआईपीयूएन शासन को सुदृढ़ बनाना
- सत्र 6: शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास
- सत्र 7: डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल खान अकादमी और करियर परामर्श

कार्यशाला का समापन जिलों और राज्य के लिए प्रमुख कार्य बिंदुओं के एक समेकित सेट और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें एनआईपीयूएन विद्यालयों और जिला एनआईपीयूएन प्रकोष्ठों के विस्तार को तेज करने और आने वाले वर्ष में मूल्यांकन-आधारित शैक्षणिक योजना को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान किया गया।

मैदान से आवाजें



Playing Their Way to Learning

For Puspanjali Mohapatra, Class 1 FLN teacher at Brajamohan Pattnaik Upper Primary School, Sambalpur the difference in her classroom is clear. "Today I taught the concept of Math 'greater than-smaller than' through song and play. The students not only participated actively but also answered correctly," she shares.

The school, which caters to Classes 1-8 and now includes Sishu Vatika, is a model FLN school. Classrooms for Grades 1-3 are equipped with literacy and numeracy corners, wall paintings, green boards at floor height for early writing practice, shelves for organised storage, and sand corners where children write on coloured sand. These features make lessons more interactive and accessible for young learners.

Puspanjali also credits FLN teacher capacity-building sessions for improving her classroom transactions. "The training has shown us how to use play-based methods effectively. It makes concepts easier to understand and recall," she says.

Parents have noticed the change. One remarks, "Our children don't want to miss school anymore. They even dislike holidays and enjoy sharing their classwork at home."

For Puspanjali, the shift is about more than engagement-it is about building strong foundations. "When learning is joyful, children learn faster and remember longer," she reflects.

पुष्पांजलि महापात्रा, कक्षा 1 एफएलएन शिक्षक, ब्रजनोहन पटनायक उच्च प्राथमिक विद्यालय, संबलपुर।

संबलपुर के ब्रजमोहन पटनायक अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 की एफएलएन शिक्षिका पुष्पांजलि मोहपात्रा के लिए, उनकी कक्षा में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है: गणितीय अवधारणाओं की खेल-आधारित शिक्षा से उनके विद्यार्थियों की सहभागिता और सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनका विद्यालय, जो एक शिशु वाटिका के साथ-साथ कक्षा 1-8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला एक आदर्श एफएलएन विद्यालय है, साक्षरता और संख्या ज्ञान के कोने, दीवार चित्रकारी,प्रारंभिक लेखन अभ्यास के लिए फर्श-हाइट ग्रीन बोर्ड, व्यवस्थित भंडारण और स्पर्शनीय लेखन अभ्यास के लिए रेत के कोने की व्यवस्था है।

पुष्पांजलि ने अपनी कक्षा में शिक्षण को बेहतर बनाने का श्रेय एफएलएन के शिक्षक क्षमता-निर्माण सत्रों को दिया है। उनका कहना है कि खेल-आधारित शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण से बच्चों के लिए अवधारणाओं को समझना और याद रखना आसान हो गया है। अभिभावकों ने भी इस बदलाव को महसूस किया है और पाया है कि बच्चे अब स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहते हैं और घर पर अपने कक्षा कार्य को साझा करने का आनंद लेते हैं। पुष्पांजलि के अनुसार, जब सीखना आनंददायक होता है, तो बच्चे तेजी से सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं, यही वह लक्ष्य है जिसे मिशन बड़े पैमाने पर प्राप्त करना चाहता है।





9.23. खेल और शारीरिक शिक्षा

विद्यालयों में खेलकूद से बच्चों और शिक्षा प्रणाली दोनों को अपार लाभ मिलते हैं।

खेल बच्चों के शारीरिक, जीवन-शैली, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के अनेक क्षेत्रों में लाभ प्रदान करते हैं। खेल बच्चों के मूलभूत शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो भविष्य में जीवन-शैली और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए आवश्यक हैं। उचित तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर, ये सामाजिक कौशल और व्यवहार, आत्म-सम्मान और विद्यालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होते हैंऔर कुछ परिस्थितियों में शैक्षणिक और संज्ञानात्मक विकास में भी योगदान देते हैं। खेलों के अनेक लाभ हैं। शारीरिक शिक्षा बच्चों को अपने और दूसरों के शरीर के प्रति सम्मान विकसित करने में मदद करती है, मन और शरीर के एकीकृत विकास में योगदान देती है, स्वास्थ्य में एरोबिक और एनारोबिक शारीरिक गतिविधियों की भूमिका की समझ विकसित करती है, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को सकारात्मक रूप से बढ़ाती है, और सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास तथा शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है।

यह अन्य लोगों से मिलने और संवाद करने, विभिन्न सामाजिक भूमिकाएँ निभाने, विशेष सामाजिक कौशल (जैसे सहिष्णुता और दूसरों के प्रति सम्मान) सीखने और टीम/सामूहिक उद्देश्यों (जैसे सहयोग और एकजुटता) के अनुरूप ढलने के अवसर प्रदान करता है, और यह उन भावनाओं का अनुभव प्रदान करता है जो जीवन के बाकी हिस्सों में उपलब्ध नहीं होती हैं।

समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य पूर्व-विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक एक एकीकृत/समग्र विद्यालय प्रणाली प्रदान करना है। इससे बच्चों को स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुगमता प्राप्त होगी और उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप पूर्व-विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

खेल अनुदान के तहत, प्रत्येक सरकारी विद्यालय को इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरण खरीदने पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये तक का खेल अनुदान प्राप्त होगा।

विद्यालयों में खेल अनुदान के प्रमुख उद्देश्य:

- विद्यार्थियोंकोशारीरिकगतिविधियोंऔरखेलकूदमें भाग लेने के माध्यम से फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में सहायता करना।
- छात्रों की शारीरिक क्षमताओं को प्रोत्साहित करना और विकसित करना तथा छात्रों को व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एक साझा रुचि के लिए एक साथ लाकर छात्रों में टीम भावना के विकास को प्रोत्साहित करना।
- छात्रों में गर्व, खेल भावना और नैतिक व्यवहार जैसे अच्छे दृष्टिकोण विकसित करना।
- छात्रों के बीच अच्छे संबंध विकसित करना और बनाए रखना
- अच्छे चरित्र पर केंद्रित मूल्य-आधारित खेल कार्यक्रम प्रदान करना।
- छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधारलाना।

- मूल्यवान क्षमताओं और योग्यताओं के विकास के अवसर प्रदान करना, और सामाजिक नेटवर्क और सामुदायिक सामंजस्य विकसित करना।

कार्यप्रणाली

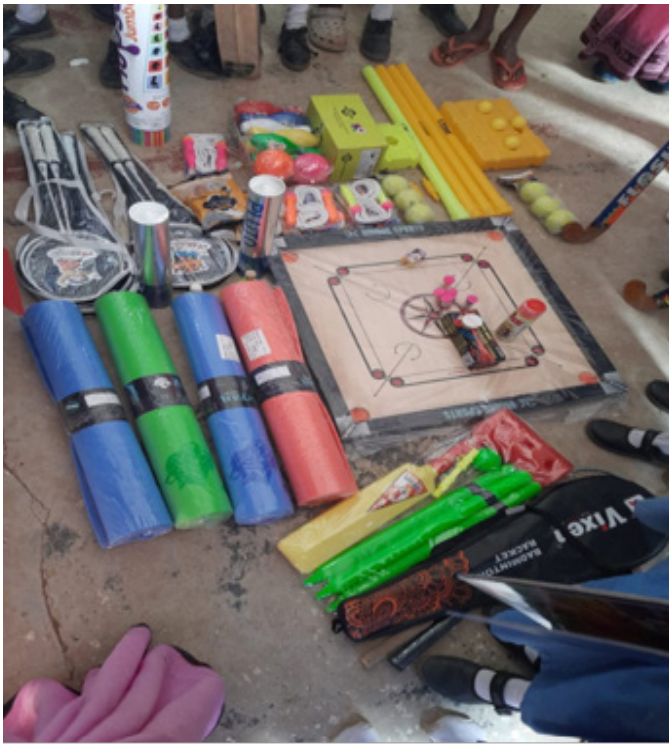
- विभागने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें स्कूलों द्वारा खरीदे जाने वाले आयु-उपयुक्त खेल उपकरणों की एक सांकेतिक सूची शामिल है। स्कूल खेल के मैदान आदि सहित स्कूल में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधार पर खेल-विशिष्ट उपकरणों का चयन करता है।

पात्र लाभार्थी:
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, लागू मानदंडों के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं।

वित्तीय लाभ/सहायता:

समग्र शिक्षा के मानदंडों और वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) के अनुमोदित नियमों के अनुसार विवेचित विद्यालयों को खेल उपकरण और खेल/शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खेल उपकरणों का वितरण













विद्यालयस्तरीय क्रीड़ा दिवस – ढेंकानाल

9.24. व्यावसायिक शिक्षा

पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने सितंबर 2011 में स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण (VSE) की योजना शुरू की, जिसके तहत रोजगारक्षम शिक्षा को स्कूली प्रणाली में एकीकृत किया गया। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के तहत संचालित यह योजना स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा और व्यावसायिक करियर तक संरचित मार्ग प्रदान करती है, साथ ही व्यावसायिक कौशल के प्रमाणीकरण को भी सक्षम बनाती है।

समग्र शिक्षा ओडिशा, केंद्र प्रायोजित इस योजना को माध्यमिक (कक्षा IX-X) और उच्च माध्यमिक (कक्षा XI-XII) स्तरों पर लागू कर रही है ताकि वैकल्पिक करियर मार्ग उपलब्ध कराया जा सके, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम की जा सके और रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। व्यावसायिक शिक्षा (वीई) को एक अतिरिक्त या ऐच्छिक विषय के रूप में पेश किया जाता है।

एनईपी 2020 व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य अकादमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 50% और 2030 तक 100% शिक्षार्थियों को कवर करना है। ओडिशा सतत विस्तार के माध्यम से इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

संक्षिप्त विवरण - एनएसक्यूएफ के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय (कक्षा IX-XII)

वीई कार्यक्रम का पैमाना	ओड़िशा के 30 जिलों में फैले 935 विद्यालयों (जिनमें 95 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं) में 95,479 छात्र नामांकित हैं। लड़के: 50,537 | लड़कियां: 44,942
व्यावसायिक व्यापार/क्षेत्र	परिधान, कृषि, ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी-आईटीईएस, खुदरा, प्लंबिंग, दूरसंचार, पर्यटन एवं आतिथ्य, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, बीएफएसआई (15 क्षेत्र, 27 नौकरी भूमिकाएँ)
प्रभावित स्कूलों का प्रकार	840 माध्यमिक विद्यालय | 95 उच्च माध्यमिक विद्यालय
व्यावसायिक प्रशिक्षकों की संख्या	935 स्कूलों में 1870 व्यावसायिक प्रशिक्षक (वी.टी.)
व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता	30 जिलों में कार्यान्वयन के लिए 23 वीटीपी (व्यावसायिक विकास कार्यक्रम) को शामिल किया गया है।
शामिल जिलों की संख्या	ओडिशा के सभी 30 जिले



क्षेत्रों और नौकरी की भूमिकाओं का वितरण

क. माध्यमिक

सेक्टर	नौकरी भूमिका	स्कूलों की संख्या
कृषि	सोलानेसी फसल संवर्धक	135
परिधानों	सिलाई मशीन ऑपरेटर	45
ऑटोमोटिव	चार पहिया वाहन सेवा सहायक	271
बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा	माइक्रोफाइनांस कार्यकारी	8
सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	सहायक सौंदर्य चिकित्सक	48
निर्माण	सहायक राजमित्री	18
इलेक्ट्रॉनिक्स	जूनियर फील्ड तकनीशियन (घरेलू उपकरण)	267
खाद्य प्रसंस्करण	बेकिंग तकनीशियन	12
स्वास्थ्य देखभाल	गृह स्वास्थ्य सहायक-प्रशिक्षु	10
आईटी आईटीईएस	घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर	245
नलकारी	सहायक प्लम्बर जनरल	82
शक्ति	उपभोक्ता ऊर्जा मीटर तकनीशियन	4
खुदरा	खुदरा स्टोर संचालन सहायक	230
दूरसंचार	ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिसर	3
पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार	खाद्य एवं पेय सेवा - प्रशिक्षु	302

ख. उच्चत्त माध्यमिक

सेक्टर	नौकरी भूमिका	स्कूलों की संख्या
कृषि	सूक्ष्म सिंचाई तकनीशियन	12
परिधान	सहायक फैशन डिजाइनर	2
ऑटोमोटिव	चार पहिया वाहन सेवा तकनीशियन	30
सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	सहायक सौंदर्य चिकित्सक	10
निर्माण	निर्माण पेंटर और डेकोरेटर	10
इलेक्ट्रॉनिक्स	फील्ड तकनीशियन वायरमैन कंट्रोल पैनल	19
खाद्य प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण	19
स्वास्थ्य देखभाल	सामान्य ड्यूटी सहायक-प्रशिक्षु	3
आईटी आईटीईएस	सीआरएम घरेलू आवाज	8
नलकारी	प्लंबर जनरल	11
खुदरा	खुदरा बिक्री सहायक	26
पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार	काउंटर सेल्स कार्यकारी	40

इस अनुभाग में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान समग्र शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियों की प्रगति प्रस्तुत की गई है।

2.1 छात्र नामांकन और कवरेज

- सभी30 जिलों के 935 स्कूलों में 95,479 छात्र नामांकित हैं (लड़के: 50,537, लड़कियाँ : 44,942)।
- 840 माध्यमिक विद्यालयों और 95 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल एजुकेशन (VE) लागू किया जा रहा है।
- इसमें 3 नए क्षेत्र शामिल हैं: स्वास्थ्य सेवा, 15 व्यावसायिक क्षेत्र और 27 रोजगार भूमिकाएँ, बिजली और बीएफएसआई।
- 935 स्कूलों में 1,870 व्यावसायिक प्रशिक्षकों (वीटी) को तैनात किया गया है।
- सभी 30 जिलों में 23 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) कार्यरत हैं।
- 100 नए WB-STARS स्कूल प्रयोगशालाएँ सफलतापूर्वक स्थापित की गईं।

कुल नामांकित छात्र	95,479 छात्र (लड़के: 50,537| लड़कियां: 44,942)
वीई लागू करने वाले स्कूल	840 माध्यमिक + 95 उच्च माध्यमिक = 935 विद्यालय
नए स्कूल (डब्ल्यूबी-स्टार्स)	विश्व बैंक की STARS परियोजना के तहत 100 नए स्कूलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना पूरी हुई।
नए व्यापार शुरू किए गए	स्वास्थ्य सेवा (होम हेल्थ एड), बीएफएसआई, पावर

2.2 व्यावसायिक प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण

राज्य स्तरीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग (ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स - टी) का आयोजन 2,122 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए 18 बैचों में एक साथ कई स्थानों पर किया गया।

- प्रशिक्षणके 18 बैचएकसाथ 3 स्थानोंपरआयोजितकिएगए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी अभिविन्यास सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- नव नियुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों और व्यावसायिक समन्वयकों (वीसीएस) के लिए ऑनलाइन मार्गदर्शन कार्यक्रम
- सत्रों में विषयवस्तु प्रस्तुति, शिक्षण विधियों, रोजगार कौशल और उद्योग के रुझानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2.3 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यपुस्तकों का विकास एवं वितरण

- सभी 12 व्यावसायिकव्यवसायोंकेलिएपाठ्यपुस्तकेंविकसितकीगईहैं - राज्यबोर्डद्वाराजाँचऔरअनुमोदनकियागयाहै।
- 2,32,315 विद्यार्थियों (माध्यमिक कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12) को व्यावसायिक पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध कराई गईं।
- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में 100% समय पर वितरण सुनिश्चित किया गया।
- ओडिया माध्यम में पाठ्यपुस्तकें विकसित की गईं; विषय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए संदर्भ पुस्तिका कार्यशाला आयोजित की गई।

2.4 आकलन और प्रमाणीकरण

सत्र	विभाग	आकलन कक्षा-10	प्रमाणीकरण कक्षा-10	आकलन कक्षा-12	प्रमाणीकरण कक्षा-12
2025-26	कृषि	4191	4191	366	366
	परिधानों	980	980	NA	NA
	ऑटोमोटिव	5342	5342	477	477
	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा	883	883	170	170
	निर्माण	291	291	274	274
	इलेक्ट्रॉनिक्स	8252	8252	339	339
	खाद्य प्रसंस्करण	333	333	342	342
	आईटी आईटीईएस	7726	7726	305	305
	नलकारी	3211	3211	199	199
	खुदरा	6900	6900	526	526
	दूरसंचार	53	53	NA	NA
	पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार	10882	10882	921	921

2.5 हब और स्पोक मॉडल

- 268 हबस्कूलऔर 268 स्पोकस्कूलकार्यरतहैं।
- स्पोक स्कूलों से हब स्कूलों तक यात्रा करने वाले 8,998 छात्रों के लिए परिवहन भत्ता प्रदान किया गया।
- आयोजित गतिविधियों में शामिल हैं: उद्योग भ्रमण, अतिथि व्याख्यान, डेमो लैब, कौशल मेले।
- स्पोक स्कूल के औसतन 40 छात्र हब स्कूल की सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं।

2.6 उद्योग संबंध और साझेदारी

- गुणवत्तापूर्णसहभागिताऔरविशेषज्ञसहायताकेलिए 15 सेक्टरस्किलकाउंसिल (एसएससी) केसाथएसएलए (सर्विसलेवलएग्रीमेंट) पूरेकिएगए।
- निम्नलिखित संस्थाओं के साथ नई साझेदारियां स्थापित की गईं: भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, वन विभाग, बागवानी विभाग, ओएमएफईडी, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
- उद्योग भ्रमण, अतिथि व्याख्यान और इंटर्नशिप के अवसरों के लिए जिला स्तरीय उद्योग मानचित्रण शुरू किया गया है।
- चार विद्यालयों में दोहरी मोड कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें नए रोजगार पद शामिल हैं: गृह स्वास्थ्य सहायक, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खट्टे फलों का उत्पादक।
- एसएससी विशेषज्ञों के साथ 5 राज्य स्तरीय बूट कैंप/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

2.7 पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा (कौशल बोध)

- PSSCIVE के समन्वय से मास्टर ट्रेनर्स के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- कौशल बोध की पाठ्यपुस्तकों का ओडिया में अनुवाद किया गया है और एससीईआरटी द्वारा इनकी जाँच की गई है।
- पीएबी 2025-26 के तहत 762 पीएम-श्री स्कूलों में योजना लागू करने के लिए बजट स्वीकृत।

2.8 वीटीपी चयन - नया ईओआई

- संशोधितदिशा-निर्देशोंकेसाथनएव्यावसायिकप्रशिक्षणभागीदारोंकेचयनकेलिएरुचिकीनईअभिव्यक्ति (ईओआई) जारीकीगई।
- राज्य, जिला और वीटीपी के बीच जिला विकेंद्रीकरण और वीई कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व को मजबूत करने हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
- बोली लगाने से पहले की बैठकें पारदर्शी तरीके से आयोजित की गईं और प्रश्नों के उत्तर दिए गए।
- मौजूदा और नए स्कूलों के लिए 23 नए वीटीपी (VTP) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे कार्यक्रम के संचालन में निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- विकेंद्रीकृत वीटीपी प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर जिला अधिकारियों की क्षमता निर्माण का आयोजन किया गया।

2.9 लंबित स्कूल - पूर्ण कार्यान्वयन

- सभी 311 लंबितपीएबी-अनुमोदितस्कूल (2021-22 से 2023-24 केबीचअनुमोदित) एकलनिविदाप्रक्रियाकेमाध्यमसे

2025-26 मेंकार्यान्वितकिएजाएंगे।

- एकल निविदा प्रक्रिया ने त्वरित खरीद सुनिश्चित की, प्रशासनिक बाधाओं को कम किया और VT/VC की समयबद्ध तैनाती को सक्षम बनाया।

2.10 शासन सुधार त्रि-पक्षीय समझौता

- 23 वीटीपी, राज्य सरकार और सभी 30 जिला प्रशासनों के बीच त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ।
- जिला स्तर पर नेतृत्व को व्यावसायिक उद्यम (वीई) के कार्यान्वयन, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन में संस्थागत रूप दिया गया है।
- बेहतर निगरानी के लिए जिला स्तर पर वीसी रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है।
- जिला स्तर पर संसाधित वीटी और वीसी पारिश्रमिक के लिए वीटीपी प्रतिपूर्ति।
- अतिथि व्याख्यान और उद्योग भ्रमण के लिए आवंटित धनराशि सीधे विद्यालय स्तर पर दी जाती है।
- जिला वित्त समन्वयकों (एफसी) और जनजातीय समन्वयकों के लिए नई प्रतिपूर्ति प्रक्रिया पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2.11 व्यावहारिक मूल्यांकन और एसएससी संबंध

- कक्षा 10 औरकक्षा 12 (माध्यमिकऔरउच्चमाध्यमिक) में 72,455 छात्रव्यावहारिकमूल्यांकनमेंशामिलहुए।
- सभी व्यवसायों में 12 सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) कार्यरत हैं।
- सभी 12 एसएससी के साथ व्यावहारिक मूल्यांकन, प्रमाणन, क्षमता निर्माण और उद्योग संबंधों को शामिल करते हुए नए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्रमाणित एसएससी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा 1 जनवरी से 10 फरवरी, 2026 तक मूल्यांकन किया गया।

2.12 निकास सर्वेक्षण

- माध्यमिकऔरउच्चमाध्यमिककक्षाओंमेंनिकाससर्वेक्षणमें 97% भागीदारीदर्जकीगई।
- वीटीपी में फेरबदल और नई ईओआई प्रक्रिया के बावजूद सर्वेक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो गया।
- मुख्य निष्कर्ष: गैर-पारंपरिक व्यवसायों में लड़कियों का नामांकन बढ़ रहा है; व्यावहारिक प्रशिक्षण से उच्च स्तर की संतुष्टि।
- साक्ष्य-आधारित योजना और VT/VC रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए निकास सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया गया।

9.25. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

1. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शिक्षा क्षेत्र में प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए कुशल और प्रभावी जानकारी प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमआईएस संगठन की कार्यकुशलता, प्रभावशीलता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, डेटा प्रबंधन में सुधार करती है, संचार और सहयोग को सुगम बनाती है तथा समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती है।

2. समग्र शिक्षा के अंतर्गत एमआईएस (मल्टी-इंफॉर्मेशन सिस्टम) समय पर सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके निर्णय लेने की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय, नामांकन, शिक्षक और सुविधाओं से संबंधित जानकारी जमीनी स्तर से एकत्रित की जाती है और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के तहत वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत एमआईएस वास्तुकला और दायरा:

राज्य, 30 जिला परियोजना कार्यालयों और 316 ब्लॉक/शहरी संसाधन केंद्र कार्यालयों में पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे के साथ सूचना प्रबंधन प्रणाली इकाई स्थापित की गई है। सभी क्लस्टर संसाधन केंद्र भी कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से सुसज्जित हैं ताकि सीआरसीसी (संसाधन प्रबंधन केंद्र) को सुदृढ़ बनाया जा सके। राज्य, जिला और ब्लॉक के एमआईएस कर्मी व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से जुड़े हुए हैं ताकि सुचारू संचार हो सके और प्रणाली का संचालन आसानी से हो सके। कुछ ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों में वर्चुअल बैठकों और सम्मेलनों के लिए मिनी कॉन्फ्रेंस रूम स्थापित किए गए हैं।



समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:-

3. डेटा प्रबंधन: एमआईएस विभिन्न डेटाबेस और पोर्टलों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। इसमें छात्रों, शिक्षकों, सुविधाओं, परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक सूचनाओं से संबंधित डेटा को एकत्र करना, संग्रहीत करना, व्यवस्थित करना और पुनः प्राप्त करना शामिल है।

4. सूचना की सुगमता: एमआईएस सूचना तक आसान पहुंच को सुगम बनाता है।
प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए। यह हितधारकों को किसी भी समय स्थान के अनुसार स्कूली शिक्षा, पहुंच, छात्रों के बने रहने, स्थानांतरण, स्कूल छोड़ने, बुनियादी ढांचे की स्थिति, छात्र प्रदर्शन आदि से संबंधित प्रासंगिक डेटा और रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

5. प्रशासनिक सहायता: एमआईएस छात्रों के प्रवेश, नामांकन, शिक्षकों के युक्तिकरण और संसाधन आवंटन सहित प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है। यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार करता है।

6. निर्णय सहायता: एमआईएस प्रशासकों और नीति निर्माताओं को निर्णय सहायता प्रणाली प्रदान करता है। यह रिपोर्ट, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है जो पाठ्यक्रम प्रक्रियाओं के विकास, संसाधन आवंटन, बजट और रणनीतिक योजना से संबंधित निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

7. प्रदर्शन मूल्यांकन: एमआईएस विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन को सक्षम बनाता है। यह व्यक्तिगत छात्र प्रदर्शन का आकलन करने, शिक्षक प्रभावशीलता की निगरानी करने और निर्धारित लक्ष्यों और मानकों के आधार पर समग्र संस्थागत प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायक होता है।

8. संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन: एमआईएस संगठन को संसाधनों की प्रभावी ढंग से योजना बनाने और प्रबंधन करने में सहायता करता है। यह पुस्तकों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी जैसी शैक्षिक सामग्रियों के इन्वेंट्री प्रबंधन में सहायक होता है। यह बजट निर्माण, खरीद और व्यय ट्रैकिंग आदि सहित वित्तीय प्रबंधन में भी सहयोग प्रदान करता है।

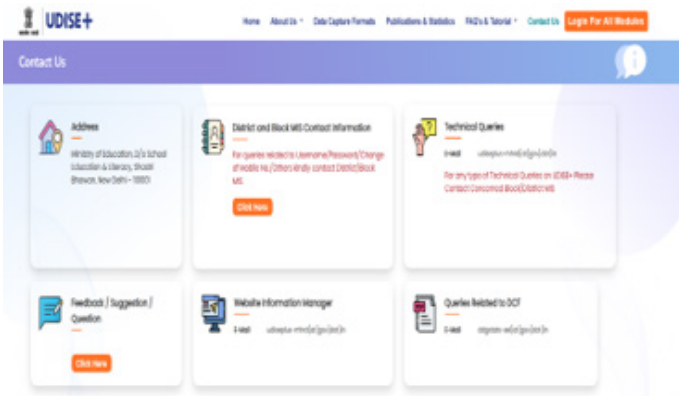


एमआईएस के अंतर्गत डेटाबेस और ई-गवर्नेंस गतिविधियाँ:

1. एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस (UDISE+):समय पर और सटीक डेटा

प्रभावी योजना और निर्णय लेने का आधार है। इस दिशा में, एक सुचारू रूप से कार्य करने वाली सतत शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। UDISE+ शिक्षा मंत्रालय, ओडिशा सरकार के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है। ओडिशा राज्य के 61592 विद्यालय, 343569 शिक्षक और 77,88,412 बच्चे UDISE+ प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। UDISE+ ऑनलाइन है और 2018-19 से पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से छात्रों के नाम सहित वास्तविक समय में डेटा एकत्र कर रहा है। UDISE+ के माध्यम से एकत्रित जानकारी का उपयोग योजना बनाने, संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करने और विभिन्न शैक्षिक पहलों को लागू करने औरसंबंधित कार्यक्रमों की निगरानी और प्रगति का आकलन करने के लिए यह प्लेटफॉर्म स्कूल के प्रदर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की निगरानी,माप और रिकॉर्ड रखता है। 2024-25 के दौरान, यूडीआईएसई+ प्लेटफॉर्म को काफी मजबूत किया गया है ताकि सभी नामांकित छात्रों के लिए एक अद्वितीय, आजीवन 12 अंकों का पहचानकर्ता प्रदान करने के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी तैयार की जा सके। एपीएएआर आईडी डिजिलॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का माध्यम होगी, जिससे छात्र अपनी सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, सीखने के परिणाम और ओलंपियाड, खेल, कौशल प्रशिक्षण या किसी भी क्षेत्र में प्राप्त अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहीत कर सकेंगे। छात्र भविष्य में उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए इस क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। ओडिशा ने वर्ष 2025-26 के लिए छात्र विवरण के साथ यूडीआईएसई+ पोर्टल पर 66% एपीएएआर आईडी तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। एकीकृत स्वचालन प्रणाली (यूएएस) के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए छात्र-वार जानकारी वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराई गई है।

एकीकृत स्वचालन प्रणाली (यूएएस)



2. परिसंपत्ति एवं निधि प्रबंधन (एएफएम):

सभी की प्रगति की ऑनलाइन स्पॉट निगरानी के लिएसमग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत सिविल कार्यों के लिए, जिसमें ओम्बाडीसी, पीएमएसएचआरआई, एसटीएआरएस, पीएसएसएस, पीआर एवं डीडब्ल्यू विभाग, आरडी विभाग जैसे विभिन्न स्रोत शामिल हैं, परिसंपत्ति एवं निधि प्रबंधन एप्लिकेशन विकसित किया गया है। राज्य स्तर पर घटकवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य एएफएम में अपलोड किए जाते हैं। राज्य, जिला और block.it स्तर पर संबंधित गतिविधियों की मासिक भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इससे विद्यालयों को सौंपे गए सिविल कार्यों की प्रगति की निगरानी करने, लंबित सिविल कार्यों को शीघ्र पूरा करने के साथ-साथ निधि प्रबंधन और यूसी संग्रह में सहायता मिलती है। सभी विद्यालयों के परिसंपत्ति रजिस्टर भी स्कूल लॉगिन में अपडेट किए जाते हैं।

3.उपस्थितिऐप: सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए।सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपस्थिति ऐप विकसित किया गया है। प्रत्येक कार्य दिवस में प्रधानाध्यापक मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करके प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा शिक्षक/सह-कक्षा शिक्षक नियुक्त करेंगे और तदनुसार संबंधित कक्षा शिक्षक अपने साथ-साथ आवंटित कक्षा/अनुभाग के छात्रों की नाम सहित उपस्थिति दर्ज करेंगे। यह स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए आवश्यक है।

9.26.ओड़िशा शिक्षा सर्वेक्षण

परिचय



साक्ष्य-आधारित शैक्षिक योजना को सुदृढ़ करने और सार्वभौमिक विद्यालय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ओडिशा सरकार के विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ने ओडिशा शिक्षा सर्वेक्षण (ओएसएस) का शुभारंभ किया है। यह एक प्रौद्योगिकी-आधारित पहल है जिसमें सभी 30 जिलों में 0-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल करते हुए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद सर्वेक्षण में पहचाने गए विद्यालय से बाहर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए जाते हैं। ओएसईपीए और समग्र शिक्षा के तत्वावधान में 2025 में आयोजित यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

पहली बार, राज्य ने प्रौद्योगिकी आधारित जनगणना स्तर पर प्रत्येक बच्चे की गणना की और एक सत्यापित, बाल-वार डेटाबेस तैयार किया। मूल रूप से, ओएसएस समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है - अंतिम छोर तक पहुंचना, जमीनी हकीकतों को समझना और प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक प्रशासन के केंद्र में रखना।

रणनीति



IIT मद्रास द्वारा विश्लेषण के लिए एक डैशबोर्ड का विकास, ऑफ़लाइन कार्यक्षमता से लैस एक विशेष रूप से निर्मित मोबाइल एप्लिकेशन ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों और सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी त्रुटिरहित डेटा संग्रह को सक्षम बनाया। बच्चों को कभी नामांकित नहीं, स्कूल छोड़ने वाले या वर्तमान में नामांकित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और डेटा फ़ील्ड में आयु, लिंग, मातृभाषा, विकलांगता का प्रकार, प्रवास स्थिति और परिवार की जानकारी शामिल की गई थी।ओएसएस को एक बहुस्तरीय, प्रौद्योगिकी-संचालित पहल के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, डिजिटल अवसंरचना, विश्लेषण और सामुदायिक कार्रवाई को एकीकृत किया गया था। कार्यान्वयन एक व्यापक प्रक्रिया के तहत किया गया: 1.5 लाख शिक्षकों का राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण; जनसंख्या के आकार के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करने हेतु बस्ती से विद्यालय तक का मानचित्रण; कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने के लिए कामाख्यानगर ब्लॉक (ढेंकनाल जिला) में एक पायलट सर्वेक्षण; सीखने के घंटों के नुकसान से बचने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान राज्यव्यापी घर-घर जाकर गणना; मानकीकृत डेटा संकलन; जिला-स्तरीय डेटा सत्यापन;और IIT मद्रास द्वारा विश्लेषण के लिए एक डैशबोर्ड का विकास।


ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା
ବ୍ରଜ-ଶ୍ରେମିନିଗୁଡା











ऑफ़लाइन कार्यक्षमता से लैस एक विशेष रूप से निर्मित मोबाइल एप्लिकेशन ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों और सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी त्रुटिरहित डेटा संग्रह को सक्षम बनाया। बच्चों को कभी नामांकित नहीं, स्कूल छोड़ने वाले या वर्तमान में नामांकित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और डेटा फ़ील्ड में आयु, लिंग, मातृभाषा, विकलांगता का प्रकार, प्रवास स्थिति और परिवार की जानकारी शामिल की गई थी।

एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध था, जिससे इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई। दैनिक बैकअप और बहु-स्तरीय डेटा सत्यापन ने राज्य-स्तरीय संकलन से पहले सटीकता सुनिश्चित की। अंतिम रूप से संशोधित डेटा को IIT मद्रास के साथ मिलकर विकसित किए गए एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में एकीकृत किया गया, जिससे जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विद्यालय और बाल स्तर पर डेटा का दृश्यीकरण संभव हुआ।

सर्वेक्षण के आंकड़ों ने 'आसा स्कूल जिबा' अभियान की नींव रखी - एक समन्वित सामुदायिक आंदोलन जिसने साक्ष्यों को कार्रवाई में रूपांतरित किया। विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठकें, पदयात्राएं, शिक्षा सभाएं, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के नामांकन के लिए मेगा अभियान और सचेतनता रथ अभियान ने शिक्षकों, अभिभावकों, पीआरआई सदस्यों और समुदायों को एकजुट किया। श्रम, कौशल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास और एसएसईपीडी विभागों के साथ अंतरक्षेत्रीय समन्वय ने प्रवासन, बाल विवाह, विकलांगता और आर्थिक असुरक्षा जैसे मूल कारणों का समाधान किया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं (आईईपी), घर-आधारित शिक्षा, सक्षम केंद्रों से संपर्क और पीएम पोषण से शुष्क राशन सहायता लागू की गई। आदिवासी भाषा सीखने वाले बच्चों के लिए, सर्वेक्षण ने बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) स्कूलों की पहचान और एमएलई शिक्षकों की आवश्यकता को समझने में मदद की। स्कूल से बाहर रहने वाले बड़े बच्चों के लिए लचीले खुले स्कूलिंग मार्ग प्रदान करने के लिए एनआईओएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चुनौतियों की पहचान करने से लेकर सहानुभूति और नवाचार के साथ प्रतिक्रिया देने तक, ओएसएस ने दिखाया कि कैसे डेटा गहन मानवीय समाधानों की ओर ले जा सकता है।

उपलब्धियाँ

इस सर्वेक्षण में 90 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया और 1 करोड़ से अधिक बच्चों (0-18 वर्ष की आयु) की गणना की गई, जिनमें से 70 लाख से अधिक स्कूली बच्चे (6-18 वर्ष) थे। इस सर्वेक्षण में 2,33,888 स्कूल से बाहर (OoSC) बच्चों की पहचान की गई, जिनमें 1,83,216 स्कूल छोड़ने वाले और 50,672 ऐसे बच्चे शामिल थे जिन्होंने कभी नामांकन नहीं कराया था। राज्य में 94,997 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की भी पहचान की गई, जिनमें से 13,165 बच्चे स्कूल से बाहर थे। इसके अतिरिक्त, बहुभाषी शिक्षा सहायता की आवश्यकता वाले 11,81,988 बच्चों और मौसमी प्रवास से प्रभावित 7,725 बच्चों का मानचित्रण किया गया।

सभी 6,794 ग्राम पंचायतों में कोई भी बस्ती अछूती नहीं रही। 'आसा स्कूल जिबा' अभियान के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, प्रत्यक्ष नामांकन, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, राज्य मुक्त विद्यालय संस्थान (एसआईओएस), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस), व्यावसायिक संस्थानों आदि के माध्यम से अब तक 70 हजार से अधिक स्कूली बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, लक्षित सहायता तंत्रों के माध्यम से 5000 से अधिक बाल एवं शिशु सहायता ऋणी बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है।

प्रभाव

सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक बच्चे और शिक्षक के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाकर, इस पहल ने एक डिजिटल रूप से ट्रैक करने योग्य प्रणाली स्थापित की, जिससे पहचान से लेकर पुनः नामांकन तक संपूर्ण निगरानी संभव हो सकी। इससे मैन्युअल निर्भरता समाप्त हुई और एक पारदर्शी, प्रत्यक्ष सेवा वितरण प्रणाली स्थापित हुई। IIT मद्रास द्वारा डिज़ाइन किया गया इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, जिसकी जिला स्तरीय उपयोगकर्ता पहुंच है, जिलों को विस्तृत डेटा का उपयोग करके छात्रावास विस्तार, विद्यालय उन्नयन, एमएलई शिक्षकों की तैनाती और लक्षित ब्रिज कोर्स की योजना बनाने में सक्षम बनाता है। सर्वेक्षण के माध्यम से पहचानी गई पहुंच संबंधी कमियों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 परियोजना अनुमोदन बोर्ड और समग्र शिक्षा के पूरक बजट को तैयार किया गया है।

इस पहल से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ सामने आई हैं: आदिवासी भाषा के छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर 4.84% है - जो ओडिया माध्यम के छात्रों की 2.28% दर से दोगुने से भी अधिक है; विशेषीकृत भाषा बोलने वाले बच्चों के स्कूल छोड़ने या कभी दाखिला न लेने की संभावना गैर-विशेषीकृत भाषा बोलने वाले बच्चों की तुलना में तीन गुना से अधिक है; 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों के डेटा ने शिशु वाटिका की योजना बनाने में मदद की, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु के कभी दाखिला न लेने वाले युवाओं की मैपिंग ने कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान की है।

9.27. विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, ओएसईपीए ने समग्र शिक्षा परियोजना की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों, पहलों, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी, ट्रैकिंग और संचालन के लिए ओडिशा सरकार के विज्ञान एवं शिक्षा विभाग के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके-ओडिशा) की स्थापना की है।

(i) अवलोकन:

- एनडीईएआरशिकायतवीएसकेस्टार्टरपैकेज (एनसीईआरटीकेमाध्यमसेकेंद्रीकृतनिगरानीडैशबोर्ड) केलिएयूआरएलयानीhttps://vsk.odisha.gov.in बनाया गया है।
- एनसीईआरटी ने 6 नंबर ऐप यानी निष्ठा, दीक्षा, पीएम पोषण, एनएएस, यूडीआईएसई+, पीजीआई को एकीकृत किया है। वीएसके-डैशबोर्ड में।
- वीएसके-ओडिशा डैशबोर्ड और अन्य संबंधित प्रोग्रामों के माध्यम से उपरोक्त अनुप्रयोगों का वास्तविक समय प्रदर्शन।

(ii) औचित्य:

- वीएसकेकासुचारू संचालन।
- ओडिशा में शैक्षिक पहलों, कार्यक्रमों और अन्य पहलों की वास्तविक समय में निगरानी और ट्रैकिंग के लिए राज्य परियोजना कार्यालय का समर्थन करें।
- विद्यालय व्यवस्था की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना।
- विद्यालयों के वास्तविक समय के प्रदर्शन संकेतक प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड विकसित करना।

(iii)तौर-तरीके:

कार्यान्वयन का स्तर: राज्य (VSK)

लक्ष्य समूह:

इसमें अभिभावक, छात्र, एचएमएस, सीआरसीसी, एबीईओ, बीईओ, एडीईओ, डीईओ और जिला स्तर के सभी अधिकारी और कर्मचारी जैसे हितधारक शामिल हैं।

रणनीतियाँ:

- शैक्षिकगतिविधियोंकीवास्तविकसमयमेंनिगरानीकेलिएउन्नतप्रौद्योगिकियोंकोतैनातकरकेएकमजबूतकेंद्रीकृतनिगरानीप्रणाली कोलागूकरेंऔरउसकारखरखावकरें।
- फील्ड कर्मियों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक परिभाषित किए गए।
- ट्रैकिंग, फीडबैक और सपोर्ट के लिए कुशल सिस्टम बनाना।
- शिकायत दर्ज करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच का डिजाइन और कार्यान्वयन करना और शिकायत समाधान के लिए एक उत्तरदायी और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- डैशबोर्ड के प्रभावी उपयोग के लिए वीएफएस सहयोगियों को क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करें।

(iv) अपेक्षित परिणाम:

- राज्यस्तरपरकेंद्रीकृतनिगरानीतंत्र।
- यह क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

• यह सभी शैक्षिक हितधारकों के लिए ट्रैकिंग, फीडबैक और समर्थन की सुविधा प्रदान करता है।
• विद्यालयीय व्यवस्था में शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीकृत सहायता डेस्क।
• स्कूलों के प्रदर्शन के वास्तविक समय के संकेतकों के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड।

(v) प्रदर्शन संकेतक (केपीआई)

• राज्यस्तरपरनिगरानीकीजानेवालीशैक्षिकगतिविधियोंका कवरेज।
• फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी और स्कूलों के वास्तविक समय के प्रदर्शन संकेतकों में सटीकता।
• शैक्षिक हितधारकों की संख्या पर सक्रिय रूप से नजर रखी गई और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।
• शैक्षिक हितधारकों को प्रदान की गई सहायता की प्रभावशीलता।
• हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायतों के समाधान में लगने वाला समय।
• विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों पर नज़र रखने में समय की बचत।

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एक प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा निगरानी और निर्णय-सहायता केंद्र है जिसे डेटा-संचालित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली में शासन और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया है।

मुख्य उद्देश्य

1. एकीकृत निगरानी

• यहविभिन्नशैक्षिकप्रणालियोंऔरयोजनाओंकेडेटाकोएकहीप्लेटफॉर्मपरएकत्रितकरताहै।
• यह स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक कार्यक्रमों की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

2. डेटा-आधारित निर्णय लेना

• यहराज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर प्रशासकों को डैशबोर्ड और विश्लेषण प्रदान करता है।
• इससे कमियों की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

3. बेहतर अधिगम परिणाम

• यहउपस्थिति, मूल्यांकन, स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के प्रदर्शन और अन्य प्रमुख संकेतकों पर नज़र रखता है।
• छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन करता है।

प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र

• उपस्थिति निगरानी (छात्रों और शिक्षकों की)
• मूल्यांकन ट्रैकिंग
• स्कूल प्रशासन की निगरानी
• मान्यता और अनुपालन निगरानी
• अनुकूलीशिक्षणऔरडिजिटलशिक्षाविश्लेषण
• शिकायतनिवारणऔरनागरिकप्रतिक्रियाप्रणाली
• कॉल सेंटर/सीआरएम-आधारित अनुवर्ती तंत्र

फ़ायदे

• शैक्षिकडेटातकवास्तविकसमयमेंपहुँच
• बेहतरयोजनाऔरसंसाधनआवंटन
• पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि
• समस्याओं और कार्यान्वयन संबंधी कमियों की तेजी से पहचान
• विभिन्न शिक्षा विभागों के बीच बेहतर समन्वय

राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र (आरवीएसके)

राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के नेतृत्व में 5ए डेटा फ्रेमवर्क को एकीकृत करने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्तर की पहल है।

• उपस्थिति
• आकलन
• प्रत्यायन
• प्रशासन
• अनुकूली शिक्षा

राज्यों को राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और विश्लेषण को सक्षम बनाने के लिए अपने शैक्षिक डेटासेट और डैशबोर्ड को आरवीएसके के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

हमारे राज्य VSK की वर्तमान स्थिति

तकनीकी समर्थन:

• वर्तमानमेंवीएसके 9 वीएफएससहयोगियोंकेसाथकार्यरतहै। ओडिशासरकारकेविज्ञानएवंप्रौद्योगिकीविभागकेराज्यपरियोजनाकार्यालय (ओएसईपीए) मेंएकवर्चुअलफील्डसपोर्ट (वीएफएस) औरइंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) केंद्र स्थापित किया गया है।

तकनीकी इन्फ्रा सपोर्ट:

• VSK के लिए अलग सर्वर
• सीआरएम सॉफ्टवेयर (अमियो और आर्किज़) कॉलिंग सेटअप
• टिकटिंग उपकरण
• वीडियो वॉल

• अपनाईगईप्रौद्योगिकीविवरण:

• AMEYO: (i) यह वेब-आधारित कॉलिंग एप्लिकेशन पहले से ही सहयोगियों द्वारा इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। (ii) इस एप्लिकेशन के माध्यम से सभी डेटाबेस तक पहुँचा जा सकता है, जैसे सभी कॉल रिकॉर्ड, कॉल कनेक्ट न होने के कारण और उपयोगकर्ता निपटान सुविधाएं, जैसे कॉल बैक, निर्धारित कॉल बैक।

• ARCHIZ: (i)यह वेब-आधारित CRM एप्लिकेशन AMEYO कॉल मैनेजर एप्लिकेशन के साथ एकीकृत है। (ii) इस एप्लिकेशन के माध्यम से एसोसिएट्स स्टेकहोल्डर्स की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। (iii) इस एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनबोर्डिंग, कंटेंट, फॉलो-अप और टास्क जैसे संपूर्ण डैशबोर्ड तक पहुँचा जा सकता है।

• टिकटिंगटूल: (i) इस तकनीक के साथ, विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हितधारकों द्वारा मौजूदा सीआरएम एप्लिकेशन का उपयोग करके एक टिकट (शिकायत/प्रश्न) उठाया जा सकता है और इसे संबंधित प्राधिकरण को अग्रेषित किया जा सकता है और समाधान की स्थिति को अपडेट किया जा सकता है।

वर्षबार कॉल की स्थिति

क्र.सं	साल भर के लिए	कुल कॉल			जुड़ी हुई कॉल(निपटाया या सुलझाया)			बिना जुड़े कॉल (कॉल विचाराधीन है)		
		आईबी	ओबी	कुल	आईबी	ओबी	कुल	आईबी	ओबी	कुल
1	2021	3755	14095	17850	3046	7523	10569	709	6572	7281
2	2022	21776	32425	54201	16385	17350	33735	6917	15578	22495
3	2023	36601	16188	52789	21037	8622	29659	15620	7510	23130
4	2024	42439	17334	59773	18775	9785	28560	23664	7549	31213
5	2025	25078	18594	43672	24538	12135	36673	540	6459	6999
6	2026	8215	4634	12849	7843	3179	11022	372	1455	1827
कुल		137864	103270	241134	91624	58594	150218	47822	45123	92945

कॉल पहल:

क्र.सं	प्रत्यक्ष दर	हस्तक्षेप	हितधारक	कॉल पहल
1	डीएचएसई	डीएचएसई	छात्र/अभिभावक	जूनियर मेरिट छात्रवृत्ति और यूनाकेडमी छात्रवृत्ति (इनबाउंड)
2	डीईई	डीईई	माता-पिता/शिक्षक	आरटीई पारादर्शी
3	ओसेपा	पुस्तकालय	डीईओ/एडीईओ	स्कूल के ई-लाइब्रेरी और प्रयोगशाला प्रभारी का नाम और नंबर प्राप्त करने के लिए
4	ओसेपा	एमआईएस एवं आईसीटी	प्रधान शिक्षक	उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए यूडीआईएसई कोड जनरेशन
5	ओसेपा	एमआईएस एवं आईसीटी	प्रधानाचार्य/डीईओ/ प्रभारी	
6	ओसेपा	एमआईएस एवं आईसीटी	शिक्षक	शिक्षाज्योति पोर्टल के लिएहाई स्कूल शिक्षक को सुविधा प्रदान करना
7	ओसेपा	एमआईएस एवं आईसीटी	प्रोग्रामर	यूडाईस के गैप के लिए प्रोग्रामर की आवश्यकता है
8	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	सीटीएस का डेटा सैनिटाइजेशन
9	ओसेपा	सिविल	प्रधानशिक्षक	पीएमश्री-एससीवाईएएफ के लिए एचएमएस को बुलाना

10	ओसेपा	एमआईएस एवं आईसीटी	प्रधानशिक्षक	यूडिस + गैप के लिए आह्वान
11	ओसेपा	सामुदायिक गतिशीलता	शिक्षक	निजुक्ति मेला के लिए पीजीटी शिक्षकों को आह्वान
12	ओसेपा	सिविल	शिक्षक	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ट्रैकर भरने की स्थिति
13	ओसेपा	एमआईएस	प्रधानशिक्षक	विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थिति
14	ओसेपा	बालिका शिक्षा	योजना समन्वयक	“एक पेड़ मां के नाम 2.0” के तहत वृक्षारोपण
15	ओसेपा	शिक्षा शास्त्र	शिक्षक	स्कूल प्रगति पत्रक अद्यतन
16	ओसेपा	एसआईओएस	शिक्षक, प्रधानशिक्षक	एचएस को एचएसएस में अपग्रेड करना
17	ओसेपा	पहुँच	शिक्षक	छात्र शिक्षक यूएएस उपस्थिति ऐप जानकारी
18	ओसेपा	योजना		आत्मरक्षा प्रशिक्षण की तस्वीरें एकत्र करना
19	ओसेपा	योजना	बीईओ	शिखाना सोपना कॉलिंग
20	ओसेपा	एसआईओएस	एडीईओ	एसआईओएस स्कूल का दौरा
21	ओसेपा	पहुँच	शिक्षक	स्कूल प्रगति अद्यतन पत्रक (अपडेट)
22	ओसेपा	योजना	योजना समन्वयक	पीएमश्री का आह्वान
23	ओसेपा	योजना	योजना समन्वयक	पीएमश्री पोर्टल में एसक्यूएएफ अपडेट
24	ओसेपा	एसआईओएस	छात्र	एसआईओएस (प्रवेश स्थिति) आवेदन
25	ओसेपा	डीएचएसई	शिक्षक	यूडाईस+ अपडेट
26	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	गोदावरी आदर्श विद्यालय का गूगल फॉर्म भरना
27	डीएचएसई	डीएचएसई	छात्र-अक्षिभावक	जूनियर मेरिट और पीएसएमटीएस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं
28	ओसेपा	सिविल	शिक्षक	कलिंग स्टेडियम में निजुक्ति मेला
29	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	कॉलिंग पर स्पिल
30	ओसेपा	सिविल		भाषाई मानचित्रण डेटा भर जाता है
31	ओसेपा	सिविल	नोडल अधिकारी	(स्वच्छ परीक्षा हरित विद्यालय रेटिंग) के तहत नामांकित विद्यालय
32	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	शौचालय की स्थिति
33	ओसेपा	डीएचएसई	शिक्षक	रेलवे भवन के पास नियुक्ति मेला
34	ओसेपा	ओसेपा		शिक्षा सभा ट्रैकर भरना
35	ओसेपा	योजना	योजना समन्वयक	पीएमश्री ट्रैकर भरें और लैंग्वेज लैब फॉर्मेट भरें
36	ओसेपा	पहुँच		स्कूलों की सूची का चयन 26-27
37	ओसेपा	शिक्षा शास्त्र	शिक्षक	शिक्षाज्योति पोर्टल
38	ओसेपा	डीएचएसई	शिक्षक,उम्मीदवारों	प्रेरण प्रशिक्षण; शुरुआती प्रशिक्षण
39	ओसेपा	एमआईएस-आईसीटी	शिक्षक-अभिभावक	बाल निगरानी सर्वेक्षण 2025-26
40	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	जीएमएपीवी चरण-2 फॉर्म भरें
41	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	लड़कियों के शौचालय की संतृप्ति की स्थिति

42	डीएचएसई	डीएचएसई	शिक्षक	पीजीटी काउंसलिंग
43	ओसेपा	एमआईएस-आईसीटी	शिक्षक	छात्र प्रगति विद्यालय अभी शुरू नहीं हुआ है
44	ओसेपा	सिविल	एसटीसी	जीएमएपीवी पर चरण 2 के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले गणमान्य व्यक्तियों का विवरण।
45	डीएचएसई	डीएचएसई	शिक्षक-अभिभावक	पाठ्यपुस्तक का सुधार (दीक्षा)
46	डीएचएसई	डीएचएसई	डीईओ	यूसी सबमिशन, अतिथि संकाय पारिश्रमिक और हैकाथॉन
47	ओसेपा	एमआईएस-आईसीटी	एसटीसी-डीईओ	परिसंपत्ति और निधि प्रबंधन
48	ओसेपा	स्कूल छात्र हेल्पलाइन	शिक्षक-छात्र	स्कूल छात्र हेल्पलाइन
49	ओसेपा	पिरामल फाउंडेशन	योजना समन्वयक	विद्यालय सुरक्षा सप्ताह
50	ओसेपा	शिक्षाशास्त्र	एडीईओ-डीईओ	एचडीडी के लिए प्रमाणपत्र साझा करने के लिए
51	ओसेपा	एमआईएस	डीईओ-एडीईओ	टीकाकरण ट्रैकर भरने के लिए
52	ओसेपा	स्थापना	शिक्षक (उम्मीदवार)	जूनियर टीचर भर्ती योजना हेल्पलाइन
53	ओसेपा	शिक्षक प्रशिक्षण	योजना समन्वयक	फीफा विश्व कप के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी
54	ओसेपा	शिक्षक प्रशिक्षण	संपर्क अधिकारी पदाधिकारी	फुटबॉल टूर्नामेंट
55	ओसेपा	शिक्षाशास्त्र	शिक्षक-एचएम	एलआरपी के लिए स्कूल निगरानी
56	ओसेपा	एचएसटी सेल	योजना समन्वयक शिक्षक-एचएम	एचएसटी हेल्प लाइन दीवार पेंट
57	ओसेपा	शिक्षाशास्त्र	क्रमादेशक	स्वयं सहायता समूहों की स्थिति (मिशन शक्ति)
58	ओसेपा	सामुदायिक लामबंदी	शिक्षक	सुरवी की यात्रा योजना के ट्रैकर को भरना
59	ओसेपा	शिक्षक प्रशिक्षण	शिक्षाशास्त्र समन्वयक	एचएसटी कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
60	ओसेपा	सामुदायिक लामबंदी	जनजातीय समन्वयक	पीटीएम का प्रारूप भरना
61	ओसेपा	एचएसटी सेल	बाईओ	एचएसटी शिकायतें
62	ओसेपा	विभिन्न हस्तक्षेप	डीईओ-एडीईओ	असेंबली SAQ
63	ओसेपा	शिक्षाशास्त्र	योजना समन्वयक	एफएलएन-प्रारंभ

उपरोक्त जानकारी में विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों की हितधारकवार पहल की स्थिति और ओएसईपीए के हस्तक्षेप शामिल हैं।

वीएसके ओडिशा डैशबोर्ड की स्थापना और विकास की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

10. योजना प्रक्रिया और कार्यान्वयन व्यवस्था

समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो पूर्व-विद्यालय से लेकर कक्षा बारहवीं तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना न केवल बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी)2020 की सिफारिशों के अनुरूप भी है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

राज्य स्तर पर, समग्र शिक्षा की योजना प्रक्रिया में राज्य वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार करना शामिल है। AWPB में राज्य की शिक्षा संबंधी प्राथमिकताओं और समग्र शिक्षा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। इसमें राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित बजट भी शामिल है। राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में योजना समिति योजना तैयार करती है। राज्य स्तरीय योजना प्रक्रिया में योजना के तहत हुई प्रगति की निगरानी, डेटा संग्रह, कमियों का विश्लेषण, अन्य विभागों, संबंधित विभागों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समन्वय, समय और बजट का आवंटन, और राज्य एवं मंत्रालय स्तर पर मूल्यांकन शामिल है।

जिला स्तर पर, समग्र शिक्षा की योजना प्रक्रिया में प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (AWPB) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें निचले स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाया जाता है।AWPB जिले की विशिष्ट शिक्षा प्राथमिकताओं और स्थानीय स्तर पर समग्र शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। जिला स्तरीय टीम समग्र शिक्षा की योजना तैयार करने, समन्वय करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना और बजट इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं को शामिल किया जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।
राज्य और जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रियाओं में शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों और समुदाय के सदस्यों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल होता है। ये योजनाएँ आवश्यकताओं के आकलन और पूर्व कार्यान्वयन अनुभवों की समीक्षा पर आधारित होती हैं और इनसे साक्ष्य-आधारित और डेटा-संचालित होने की अपेक्षा की जाती है।

योजना प्रक्रिया में विस्तृत बजट और व्यय योजना का विकास भी शामिल है, जिसमें प्रस्तावित रणनीतियों और गतिविधियों को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का विवरण दिया गया है। योजना तैयार करते समय, योजना टीम एक यथार्थवादी बजट योजना सुनिश्चित करती है जो व्यावहारिक,व्यवहार्य और समग्र शिक्षा योजना की समग्र शिक्षा प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप हो।

योजनाएँ तैयार हो जाने के बाद, योजना के स्तर के आधार पर राज्य या जिला स्तर पर उनकी समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया

होती है। इस समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाएँ समग्र शिक्षा योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हों, साक्ष्य-आधारित हों, डेटा-संचालित हों और वित्तीय मानदंडों के भीतर हों।

समग्र शिक्षा योजना में योजना टीम का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक आवश्यक घटक है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हितधारकों के पास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हो।

जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण

- प्राप्तदिशा-निर्देशोंकेअनुसारसमग्रशिक्षाकेअंतर्गतवार्षिककार्ययोजनाऔरबजट 2026-27 कीतैयारीकेलिएअभिविन्यासऔरक्षमताविकासकार्यक्रमशुरूकिएगएहैं।
- एसपीओ और डीपीओ के सभी हस्तक्षेप प्रमुखों की मूल्यांकन मानदंडों और कार्यक्रम संबंधी एवं वित्तीय मानदंडों पर क्षमता निर्माण हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है।

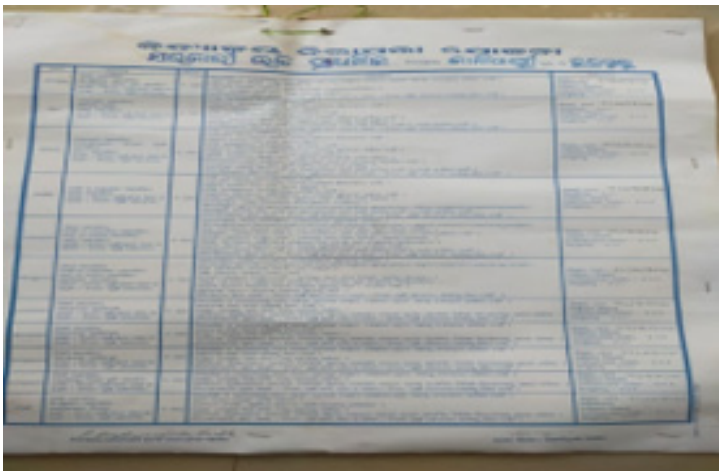
वार्षिक योजना को अधिक यथार्थवादी और आवश्यकता आधारित बनाने के लिए, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सीआरसीसी, बीआरसीसी, बीईओ, डीपीसी, समन्वयक, डीईओ, शिक्षा प्रशासक और डीपीओ स्तर पर कार्यरत पेशेवरों जैसे सभी हितधारकों को विद्यालय विकास योजना और जिला वार्षिक योजना तैयार करने के माध्यम से योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

विद्यालय विकास योजना

आरसीएफसीई अधिनियम 2009 का अध्याय-IV (धारा 22) यह इंगित करता है कि विद्यालय अपनी स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की भागीदारी से अपनी योजनाएँ (एसडीपी) विकसित करेंगे। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और एनडीएमए द्वारा जारी विद्यालय सुरक्षा नीति-2016 इस पर केंद्रित हैं।

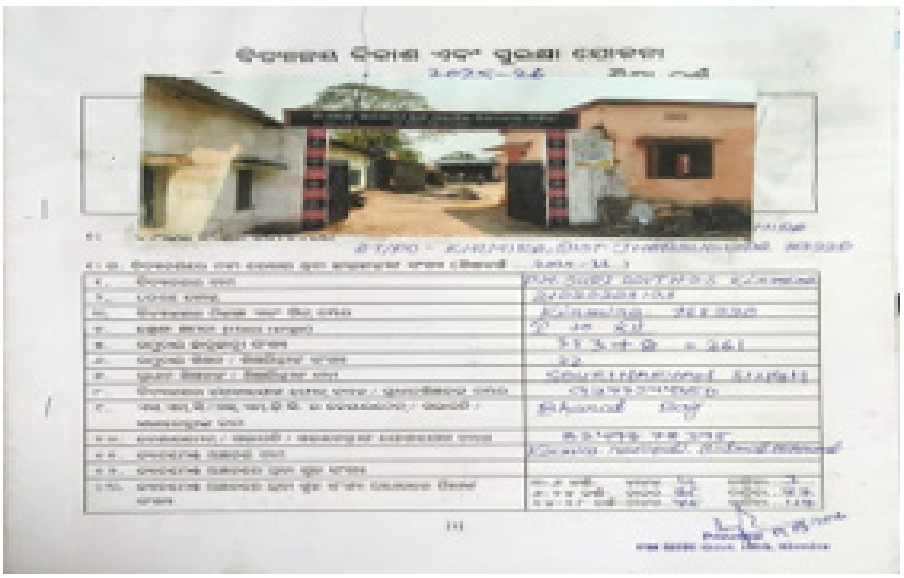


विद्यालयआपदा प्रबंधन योजना का निर्माण



- सभीविद्यालयोंकोजिलाअधिकारियोंद्वाराउड़ियाभाषामें विद्यालयआपदाप्रबंधनयोजनाकाप्रारूपऔरदिशानिर्देशउ पलब्धकराएजातेहैं।
- स्कूल आपदा प्रबंधन योजना/स्कूल सुरक्षा योजना को एसडीपी तैयार करने के दौरान पूरा करना सुनिश्चित किया गया है।
- दिशा-निर्देशों के माध्यम से सभी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर योजना बनाने और विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय संसाधनों का पता लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। जैसे स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच। ग्रामीण विकास और पेयजल विभाग द्वारा पेयजल सुविधाओं की जाँच।
- डीडीएमए, पंचायती राज एवं घरेलू कामगार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग, एमपी-एलएडी, एमएलए-एलएडी, बीआरजीएफ विभाग जैसे निधि/संसाधनों के स्रोत हैं।

आवश्यकता आधारित योजना



- योजनातैयारकरनेकेदौरान, स्कूलों, बाल जनसंख्या, नामांकन और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों से संबंधित सभी प्रासंगिक डेटा और जानकारी का उपयोग यू-डीआईएसई+ और फील्ड सर्वेक्षणों से किया गया है।
- पीएबी द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं, कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर), शोध अध्ययनों और सीएजी की लेखापरीक्षा सिफारिशों आदि पर विधिवत विचार किया गया है।
- समग्रशिक्षाकेअंतर्गत सभी हस्तक्षेपों के लिए गतिविधि-वार योजना बनाई गई है, जिसमें मौजूदा कमियों, उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक रणनीतियों को ध्यान में रखा गया है।
- बेहतरशिक्षासुविधासुनिश्चितकरनेकेलिएविद्यालयों/बस्तियोंकोमूलभूतइकाईमानागयाहै।
- पहुँच योजना तैयार करने के लिए, जमीनी स्तर के डेटा और स्कूल मानचित्रण डेटा का उपयोग किया गया है। सभी जिलों को प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूलों को खोलने के लिए जमीनी जरूरतों का आकलन करने का निर्देश दिया गया था।
- धारा 12(1)(सी) के अनुसार 25% आरक्षण के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए योजनाएँ जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई हैं।

- प्राथमिक स्तर पर पढ़ने, लिखने, समझने और गणित जैसे मूलभूत कौशलों और दक्षताओं में मौजूद कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने पर जोर देते हुए एक व्यापक गुणवत्ता योजना तैयार की गई है।
- आकांक्षी जिलों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
- सिविल वर्क्स प्लान को बिजली, शौचालय और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है।
- एसएमसी/एसएमडीसी सदस्यों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके और उन्हें इस प्रक्रिया से अवगत कराया जा सके।
- छात्रों को स्कूल में बनाए रखने पर मौसमी छात्रावासों के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, प्रवासन-प्रवण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- 2026-27 में, आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंच, परिवहन सुविधाओं, मौसमी छात्रावासों, विशेष प्रशिक्षण, आवासीय छात्रावासों के साथ-साथ सीखने के परिणामों में सुधार पर केंद्रित गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है।
- एनईपी 2020 के अनुसार, सभी सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की गई है।





स्थानीय स्वशासन की भागीदारी

- आरटीईकेतहतपीआरआईकोस्थानीयप्राधिकरणघोषितकियागयाहै।
- ग्राम पंचायत स्तर की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति का अनिवार्य संचालन।
- समग्र शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों तथा इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में आकांक्षी जिलों की प्राथमिकता के संबंध में विशेष बैठक के माध्यम से सभी पीआरआई सदस्यों को जागरूक करना।
- विद्यालय में उपस्थिति, छात्रों के बने रहने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष पीटीएम/एसएमसी का आयोजन।
- अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षा (ओडिशा में OSSAAT के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ)

AWPB के विकास के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया

- भारतसरकारकेशिक्षामंत्रालयद्वारानिर्धारितवार्षिकयोजनातैयारकरनेकीप्रक्रियाकेसंबंधमेंसभीडीपीसीऔरटीमकीक्षमतानिर्माण व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है।
- वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार करने के पहले चरण में, विद्यालय स्तर पर विद्यालय सुधार/विकास योजना तैयार की जाती है। प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) सक्रिय समुदाय सदस्यों और शिक्षकों के सहयोग से विद्यालय स्तर की योजना तैयार करने की पहल करती है, जिसे "विद्यालय विकास योजना (एसडीपी)" कहा जाता है। प्रारंभ में, तैयारी का चरण एसएमसी की बैठक से शुरू होता है, जो आरटीई अधिनियम की धारा 21 और भाग-वी के अनुसार सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है।
- एसडीपीमेंमुख्यरूपसेबुनियादीढांचेकेविकासमेंकमियोंकीपहचान, छात्रों की उपलब्धि, मौजूदा शिक्षकों की आवश्यकताएं, अभिभावकों की अपेक्षाएं, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया आदि शामिल हैं। इस प्रकार, एसडीपी प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकताओं को प्रदान करती है, जिसे अंततः जिला स्तर पर संकलित किया जाता है।
- इसकेअलावा, जिला योजनाओं की तैयारी के लिए, यूडीआईएसई+ से प्राप्त डेटा, जिसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, शिक्षकों और ब्लॉक स्तर के एमआईएस समन्वयकों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ तैयार किया जाता है।
- राज्यस्तरपरAWP&B की तैयारी जिला स्तरीय योजनाओं के मूल्यांकन और समेकन पर निर्भर करती है। जिला परियोजना समन्वयक, ADEO, सभी जिला स्तरीय समन्वयक, प्रोग्रामर, SR.TC (जिला विशिष्ट योजना दल)'जिला वार्षिक कार्य योजना एवं बजट' तैयार करता है और उसे संकलित करके PRABANDH पोर्टल पर अपलोड करता है।
- राज्य स्तर पर जिला योजनाओं को एकत्रित करके एक 'एकीकृत राज्य समेकित योजना' तैयार की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य स्तर पर वार्षिक कार्य योजना और बजट के समेकन के दौरान, OSEPA, TE और SCERT, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सभी हस्तक्षेपों को शामिल किया जाता है।

एकीकृत AWP और B के लिए गतिविधियों का कार्यक्रम			
क्र.सं	गतिविधियाँ	दिनांक	प्रतिभागी
1	जिला योजनाओं को अंतिम रूप देना और उनका समेकन करना।	नवंबर से फरवरी 2026 तक	जिला योजना टीम
2	राज्य स्तर पर एकीकृत जिला AWP और B 2026-27 का मूल्यांकन	मार्च	जिला योजना टीम - ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड
3	एसपीओ में जिला AWP&B सबमिशन	मार्च	और 30 जिलों ने मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लिया और PRABANDH पोर्टल के माध्यम से योजना तैयार करके प्रस्तुत की।
4	राज्य योजना को अंतिम रूप देना	मार्च	हस्तक्षेप प्रमुख, योजना टीम
5	PRABANDH पोर्टल के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय को एकीकृत AWP और B 2026-27 का ऑनलाइन सबमिशन।		



योजना प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम :

- समग्रशिक्षाकेअंतर्गतयोजनाप्रक्रियाएकसंरचित, सहभागी और आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जिसमें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर हितधारकों को शामिल किया जाता है। योजना प्रक्रिया मोटे तौर पर इस प्रकार है:
- ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की अध्यक्षता में एक योजना दल का गठन किया जाता है, जिसमें बीआरसीएस, एमआईएस-सह-योजना समन्वयक, टीसी, बीआरटीएस, एबीईओ और सीआरसीसी शामिल होते हैं।
- जिला स्तर पर, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) की अध्यक्षता में एक योजना दल का गठन किया जाता है जिसमें डीआईईटी, सभी हस्तक्षेप प्रमुखों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह दल समग्र शिक्षा की पहचान की गई आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और प्रावधानों के अनुसार योजनाओं की जांच, संकलन और मूल्यांकन करता है। यूडीआईएसई+ डेटा, एसडीपी डेटा के साथ, योजना का आधार होता है।
- योजनाप्रक्रिया में समन्वय और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी जिला कलेक्टरों से अनुरोध है कि वे महत्वपूर्ण

कमियों और विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, डिजिटल पहलों और अन्य शैक्षिक हस्तक्षेपों जैसे क्षेत्रों में।

शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका

- TE & SCERT को अकादमिक प्राधिकरण घोषित किया गया है।
- एससीईआरटी के निदेशक को एसआईईएमएटी का निदेशक घोषित कर दिया गया है और डीईओ, बीईओ और प्रशिक्षण प्रबंधकों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं।
- एनआईओएस और टीई एवं एससीईआरटी के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण को उन्नत किया जा सके।

अभिसरण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, एसटीएससी, आरडी, खेल, ऊर्जा, डब्लू एंड सी, स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायत राज, अग्नि सुरक्षा, ओएसडीएमए, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई आदि जैसे अन्य संबंधित विभागों के साथ-साथ नागरिक समाज के साथ समन्वय और अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- एमजीएनआरईजीएसकेतहतचारदीवारी, रसोई उद्यान, हरित बाड़ जैसी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- केंदुझर, कोरापुट और सुंदरगढ़ जैसे डीएमएफ जिलों में भवनों, एसीआर आदि के निर्माण के लिए धनराशि का समन्वय किया जाएगा।
- ओडिशा कौशल विकास मिशन - स्कूलों में कौशल विकास।
- ओम्बाडीसी सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर जैसे जिले एबी के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धनराशि का समन्वय करेंगे।
- सीएसआर फंड - शौचालय, पेयजल सुविधाएं आदि जैसी गतिविधियां।
- एसएफसी/सीएफसी- ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना विकास जैसी विभिन्न विद्यालय स्तरीय गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी।
- जल स्वच्छता मिशन - सुरक्षित पेयजल सुविधा का प्रावधान।
- स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनसंपर्क एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और विकास विभाग के साथ समन्वय भी किया गया।

एसएमसी और एसडीपी-नुआपड़ा, ओडिशा



11. सामाजिक अंकेक्षण

समग्र शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों के लिए समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना पूर्व-विद्यालय शिक्षा और शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम), मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, समग्र प्रगति कार्ड, अधिगम परिणामों की निगरानी और बच्चों के प्राथमिक स्तर पर आगे बढ़ने में सहायता, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं की चरणबद्ध नियुक्ति, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति, 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता निर्माण, बिना बैग वाले दिन और इंटर्नशिप, और 16-19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को खुली शिक्षा के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

इस योजना में विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए अलग से वजीफा, ब्लॉक स्तर के संसाधन केंद्रों के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन की पहचान और सहायता, आवासीय छात्रावासों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) सहित स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, व्यावसायिक शिक्षा के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल, स्मार्ट क्लासरूम, दीक्षा और एससीईआरटीएस में मूल्यांकन प्रकोष्ठों को सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।समग्र शिक्षा के एमएमएमईआर घटक के अंतर्गत, प्रतिवर्ष कम से कम 20% विद्यालयों का सामाजिक लेखापरीक्षा करने का प्रावधान किया गया है, ताकि पांच वर्ष के चक्र में सभी विद्यालयों को कम से कम एक बार कवर किया जा सके। प्रगति की नियमित निगरानी और मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों और घटकों के लिए प्रमुख लक्ष्य और मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) भी निर्धारित किए गए हैं।

सामाजिक अंकेक्षण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा, स्कूलों में पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण जवाबदेही तंत्र है। इसका उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा विद्यालय एवं समुदाय स्तर पर सहभागी शासन को सुदृढ़ करना है।

मुख्य उद्देश्य

- शिक्षाकेअधिकार (आरटीई) अधिनियमकेतहतसभीपात्र बच्चों को समान रूप से हकदारियों का प्रावधान सुनिश्चित करना।
- विद्यालय के आधारभूत संरचना और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का आकलन करना।
- छात्रों के नामांकन, उनकी पढ़ाई जारी रखने और शिक्षा पूरी करने की निगरानी करना।
- UDISE+ के माध्यम से उपलब्ध विद्यालय संबंधी जानकारी को साझा करने और सत्यापित करने में सुविधा प्रदान करना।
- सहभागी शासन को मजबूत करने के लिए हितधारकों के बीच शैक्षिक संवाद शुरू करना।
- विद्यालयों के समग्र विकास के लिए समुदाय-संचालित और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों के अधिकारों और हकों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना।

ओड़िशा में कार्यान्वयन की स्थिति

1. संशोधित सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 12 सितंबर 2023 को प्राप्त हुए।

2 ओएसएसएटी (ओडिशा सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी) और ओडिशा सरकार के साथ 18 नवंबर

2022 को सामाजिक अडीटके कार्यान्वयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

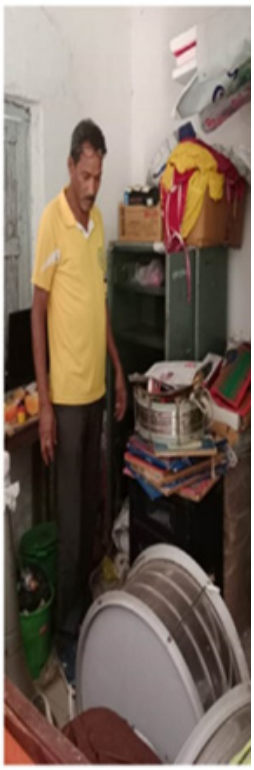
3. कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुगम बनाने और उसकी निगरानी करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
4. ओडिशा के सभी सरकारी स्कूलों को पांच साल के चक्र में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें हर साल लगभग 20% स्कूलों को शामिल किया जाएगा।
5. पहले चरण में, 10,000 सरकारी स्कूलों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिसमें प्रति क्लस्टर दो स्कूलों को शामिल किया जाना था। 2025-26 के दौरान, 20,000 स्कूलों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू की गई है।
6. प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जिला सामाजिक लेखापरीक्षकों और ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षकों की बैठकें आयोजित की गई हैं।
7. सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जा रही है ताकि समुदाय के सदस्यों और हितधारकों को मुद्दे उठाने, निष्कर्षों को सत्यापित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।
8. सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य भर में समग्र शिक्षा संबंधी पहलों के कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता को मजबूत करना है।



विद्यालय स्तर पर सामाजिक अडीट

समग्र शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई। इस प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों की भागीदारी रही, जिन्होंने विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन और संसाधनों के उपयोग की समीक्षा की। लेखापरीक्षा प्रक्रिया ने उपलब्धियों पर चर्चा करने, कमियों की पहचान करने और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक निगरानी को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान किया।







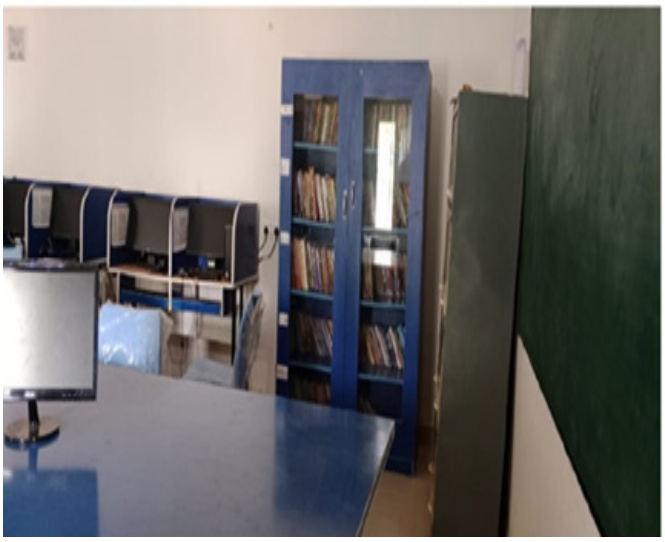
















(जिला और स्कूल स्तर पर सामाजिक अडीट प्रसेस)

12. ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा)

दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) भारत का राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विकसित किया गया है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है।

दीक्षा के प्रमुख उद्देश्य

- छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय के नेतृत्वकर्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराएं।
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण का समर्थन करें।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षिक सामग्री बनाने, होस्ट करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाना।
- ऑनलाइन मूल्यांकन, प्रमाणन और शिक्षण विश्लेषण को सुगम बनाना।
- देशभर में डिजिटल शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देना।
- दीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) की एक पहल है।
- दीक्षा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, और यह पोर्टल और मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है।
- शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और दीक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के प्रसार के लिए सर्वोत्तम प्लेटफार्मों में से एक के रूप में कार्य करती है।
- इस प्लेटफॉर्म में विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने, होस्ट करने और साझा करने की तकनीकी क्षमताएं हैं। यह पोर्टल देश भर के रचनाकारों द्वारा डिज़ाइन और एकत्रित किए गए सभी डिजिटल संसाधनों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है।
- डिजिटल सामग्री अपलोड करने, मूल्यांकन डिजाइन करने, विषय-सूची तैयार करने, सभी संसाधनों को एक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने और पाठ्यक्रम के उपयोग पर डेटा प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन ढांचा विकसित करके पाठ्यक्रम बनाना बहुत आसान बना दिया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

1. डिजिटल शिक्षण सामग्री

- पाठ्यपुस्तकें, वीडियो, सिमुलेशन, क्विज़ और इंटरैक्टिव संसाधन।
- पाठ्यपुस्तकों में मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके संबंधित डिजिटल सामग्री तक पहुंचा जा सकता है।

1. शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास

- यहसंस्थानसततव्यावसायिकविकास (सीपीडी) पाठ्यक्रमआयोजितकरताहै।
- यह शिक्षकों के लिए वार्षिक व्यावसायिक विकास के 50 घंटे की एनईपी 2020 की आवश्यकता का समर्थन करता है।

3. अधिगम प्रबंधन व्यवस्था (एलएमएस)

- ऑनलाइनपाठ्यक्रमोंकानिर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी।
- प्रगति की निगरानी और प्रमाणपत्र निर्माण।

4. मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण

- ऑनलाइनपरीक्षाएं, असाइनमेंट और प्रमाणन कार्यक्रम।

• शिक्षार्थी के प्रदर्शन और पाठ्यक्रम पूर्णता की स्थिति की निगरानी।

5. विश्लेषण और रिपोर्टिंग

• यहपाठ्यक्रमकीखपत, सामग्री के उपयोग और शिक्षार्थी की सहभागिता पर डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रदान करता है।

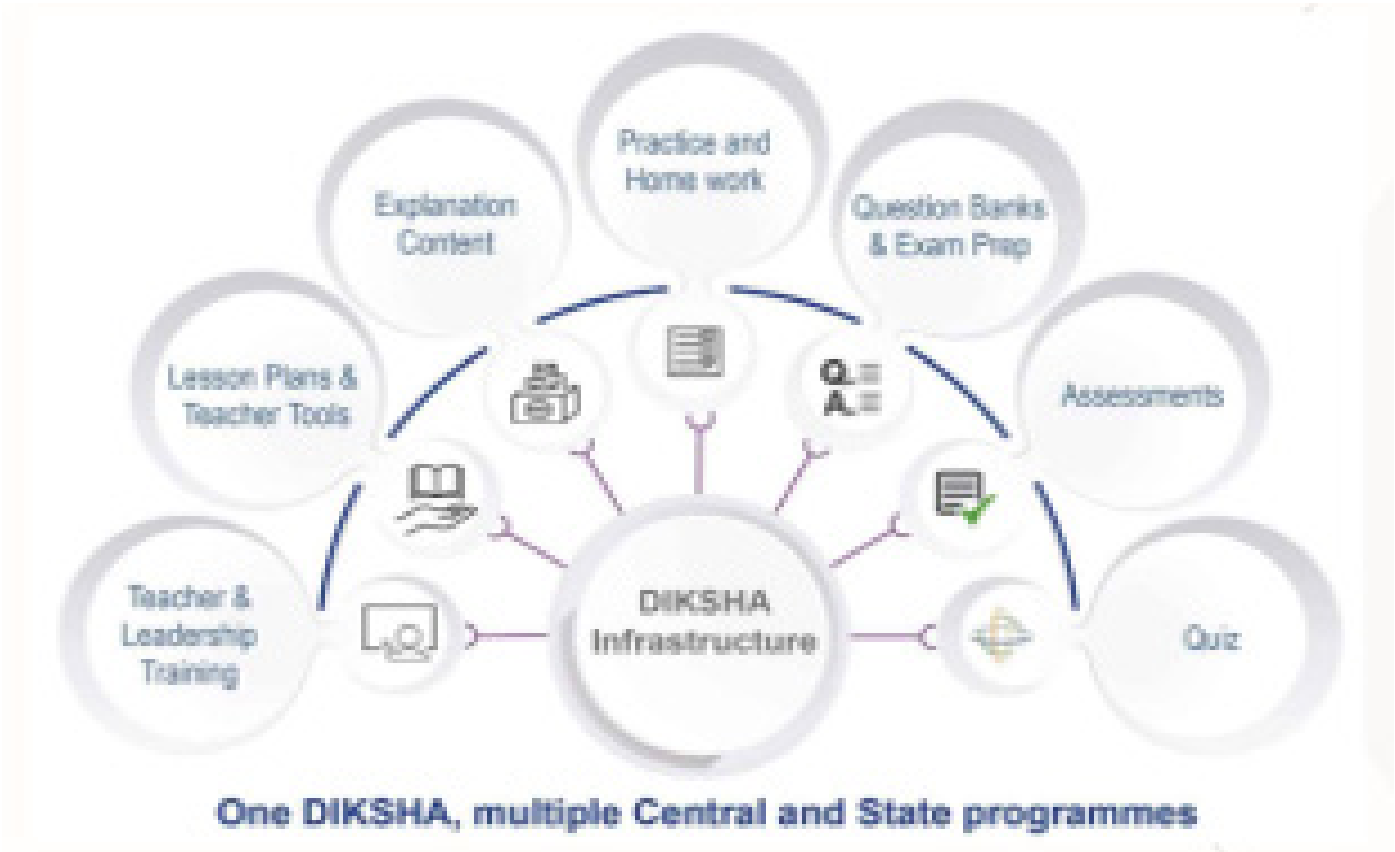
फ़ायदे

• कभीभी, कहीं भी सीखने के संसाधनों तक पहुंच।
• मानकीकृत और विस्तार योग्य शिक्षक प्रशिक्षण।
• बहुभाषी सामग्री समर्थन.
• डेटा आधारित तरीके से सीखने और प्रशिक्षण के परिणामों की निगरानी।
• राज्य की शिक्षा संबंधी पहलों के साथ एकीकरण।

विजन और मिशन

शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से छात्रों द्वारा अधिगम परिणामों की प्राप्ति की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

• शिक्षकएवंनेतृत्वप्रशिक्षण
• पाठ योजना एवं शिक्षक उपकरण
• स्पष्टीकरण सामग्री
• अभ्यास और गृह कार्य
• प्रश्न बैंक और परीक्षा की तैयारी
• आकलन
• प्रश्नोत्तरी



उद्देश्य

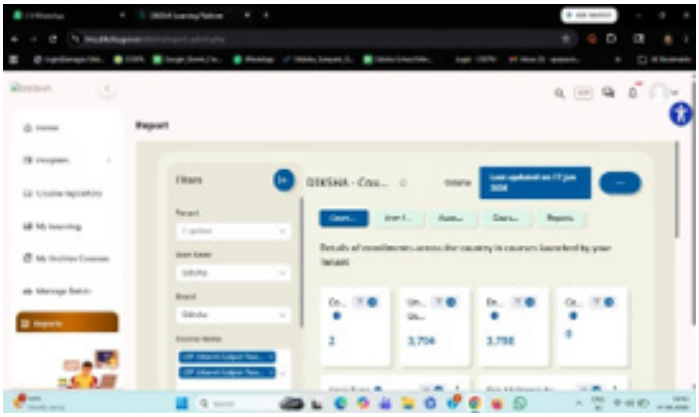
ज्ञान
शिक्षकों की शिक्षण-अधिगम सामग्री और अधिगम-केंद्रित शिक्षणशास्त्र के संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाना।

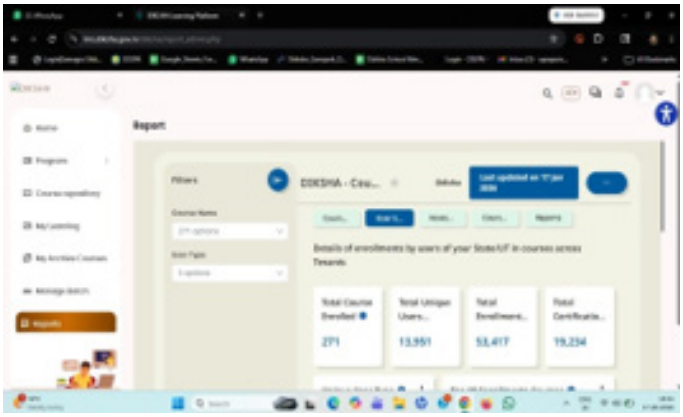
प्रेरणा
छात्रों की अधिगम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक और आवश्यकता-आधारित डिजिटल सामग्री बनाने और संकलित करने में शिक्षकों को प्रेरित करना।

सहकर्मी अधिगम और सहयोग
बच्चों के लिए सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने हेतु शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन चर्चा मंच के माध्यम से जोड़ना।

प्रगति

- DIKSHA 1.0 के तहत, ओडिशा ने DIKSHA प्लेटफॉर्म पर 36 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उपयोग 43.12 लाख से अधिक शिक्षकों ने किया है, जिससे 17.70 करोड़ से अधिक कंटेंट प्ले हुए हैं और 85,40,585 घंटे का लर्निंग एंगेजमेंट हुआ है। यह राज्य में डिजिटल व्यावसायिक विकास पहलों की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है।
- DIKSHA 2.0 (नया एलएमएस DIKSHA पोर्टल) के तहत, ओडिशा ने कक्षा IX के विषयों को पढ़ाने वाले माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक शुरू किया और आयोजित किया है। इस पाठ्यक्रम को 3,798 से अधिक शिक्षकों ने पूरा किया है, जिससे राज्य में शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में योगदान मिला है।
- दीक्षा पार्टल पर अपलोड़ किए गए ई-संपर्क की संख्या
- ई-सामग्री05 भाषाओं में (ओडिया, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू) उपलब्ध है।
- क्यूआर कोड से सक्रिय की गई पाठ्यपुस्तकों की संख्या –168
- कक्षा नौवीं और दसवीं के लिए 1262 ई-सामग्री तैयार की गई है। ये सामग्रियां दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। इनमें ओडिया, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और संस्कृत विषय शामिल हैं। ये सामग्रियां राज्य के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं।





13. स्कूली छात्रों के लिए हेल्पलाइन

ओड़िशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) द्वारा विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग के अंतर्गत शुरू की गई स्कूल छात्र हेल्पलाइन, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्थापित हो चुकी है। एक सक्रिय संचार मंच के रूप में परिकल्पित यह हेल्पलाइन छात्रों, विद्यालयों और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच एक सेतु का काम करती है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में, हेल्पलाइन ने एक बहुआयामी सहायता तंत्र के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया। इसने न केवल शैक्षणिक चिंताओं बल्कि भावनात्मक कल्याण, विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों का भी समाधान किया। तेजी से विकसित हो रहे शैक्षिक परिवेश में छात्रों की बढ़ती विविध आवश्यकताओं को देखते हुए, हेल्पलाइन ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का विस्तार किया, भाषा की सुलभता को बढ़ाया और अपने मानव संसाधन आधार को मजबूत किया।

कक्षा 1 से 10 में नामांकित 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे टोल-फ्री नंबर 1800-345-6722 या 14417 के माध्यम से हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। वे शिक्षा के अधिकार से संबंधित अपनी चिंताओं को साझा करने या वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे सुझाव देने के लिए ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायतें www.studenthelplineodisha.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती हैं।

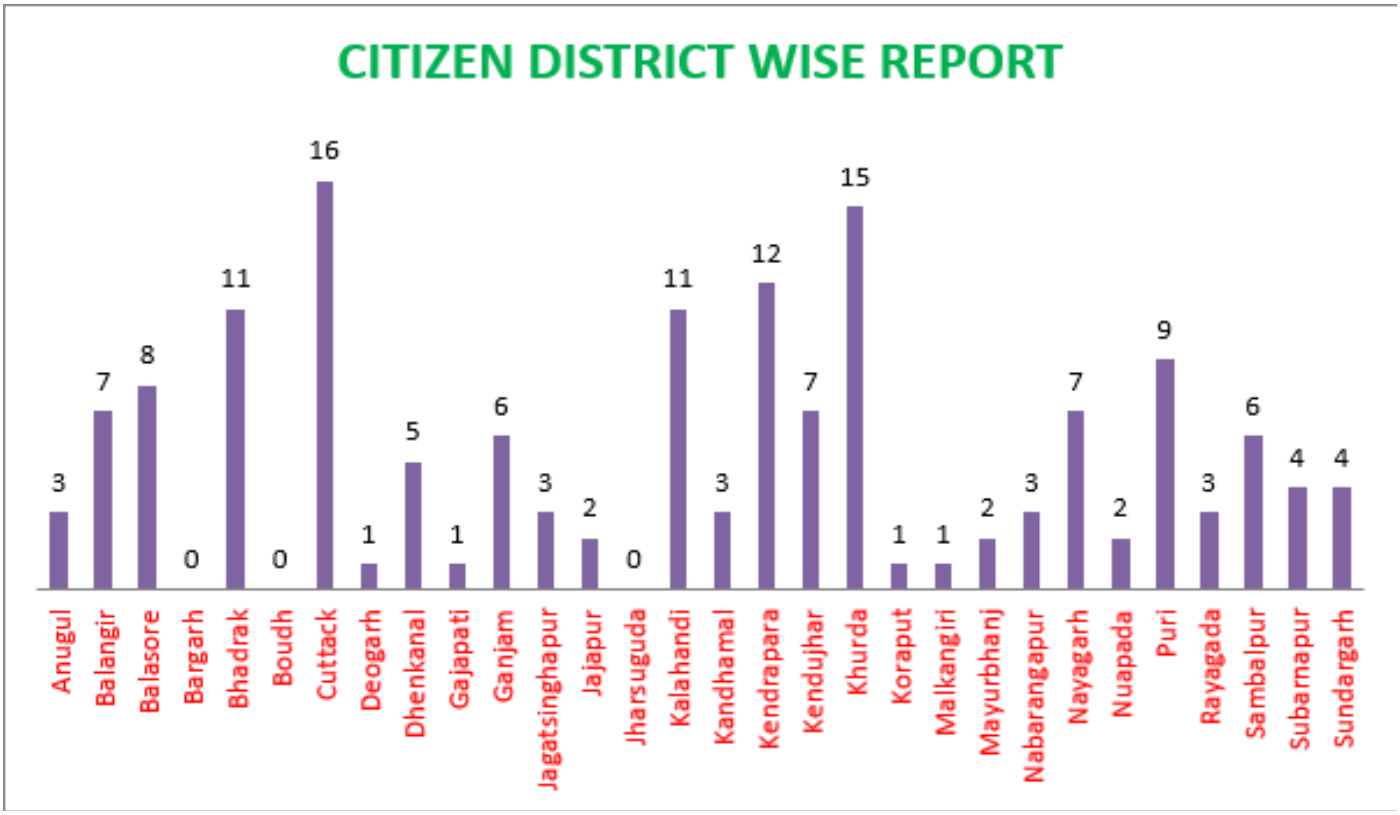
प्राप्त सभी मामलों को 32 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख मुद्दों की पहचान करने के लिए इन श्रेणियों का विभिन्न दृष्टिकोणों से सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार की पहल को समस्या की आवश्यकता और व्यापकता के अनुसार विभिन्न स्तरों - जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और विद्यालय - पर लागू किया जाता है।

हेल्पलाइन मामलों की स्थिति:

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान, स्कूल स्टूडेंट हेल्पलाइन पर 150 कॉल दर्ज की गईं, जो छात्रों के बीच इस सेवा के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास का संकेत है। हेल्पलाइन ने शैक्षणिक मुद्दों, शिक्षकों से संबंधित शिकायतों, बुनियादी ढांचे से जुड़ी चिंताओं, मध्याह्न भोजन संबंधी शिकायतों, भावनात्मक और परामर्श सहायता सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया।

छात्रों पर केंद्रित टोल-फ्री सेवा के रूप में कार्यरत यह हेल्पलाइन फोन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। यह एक सुरक्षित, गोपनीय और सहायक वातावरण प्रदान करती है जहाँ छात्र खुलकर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और समय पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की सुविधा ऑनलाइन और फोन कॉल के माध्यम से सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक उपलब्ध है। शिकायत निवारण के अलावा, हेल्पलाइन सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने, अभिभावकों के साथ मिलकर काम करने और स्कूल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके समस्याओं का समाधान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, छात्रों और अभिभावकों को, विशेष रूप से परीक्षाओं और अन्य तनावपूर्ण समय के दौरान, परामर्श सहायता भी प्रदान की जाती है।

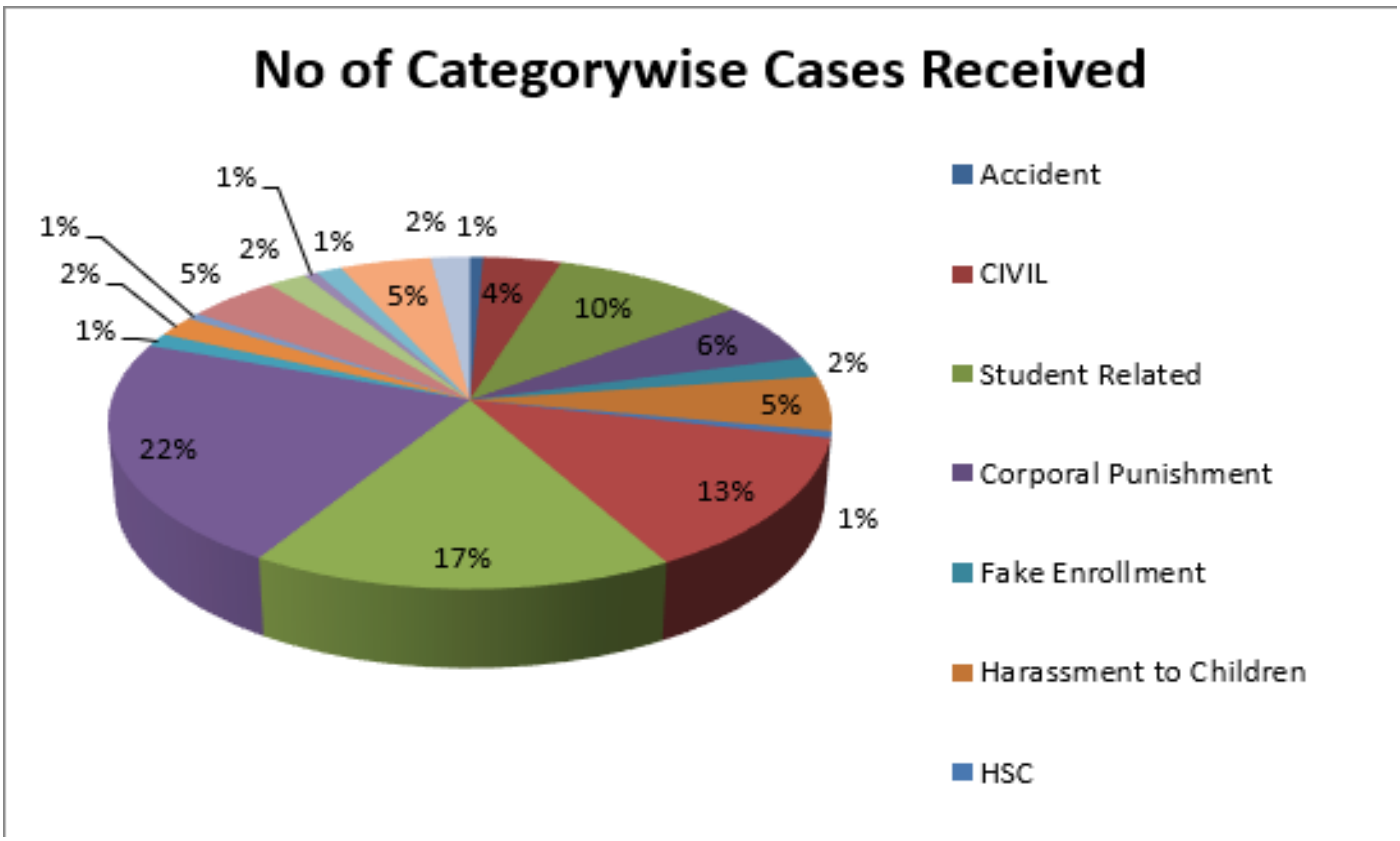
1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच कुल 150 वैध मामले दर्ज किए गए। इन्हें 32 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें ग्राफ़िक प्रस्तुति में स्पष्टता के लिए आगे व्यापक खंडों में समूहीकृत किया गया। नीचे दिए गए ग्राफ़ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ज़िला और श्रेणीवार मामलों के वितरण को दर्शाते हैं।



चित्र 1:कटक, खोर्धा और केंद्रापड़ा जैसे तटीय जिलों में शिकायतों की संख्या अधिक दर्ज की गई, जबकि बरगढ़, बौद और झारसुगुड़ा जैसे गैर-तटीय जिलों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

शिकायत वर्ग

वर्ग के हिसाब से मिले मामलों की संख्या



(चित्र 2 : महिलाओं से संबंधित मुद्दे शिकायतों की सबसे बड़ी श्रेणी थे)

व्याख्या: कुछ जिलों में मामलों की अधिक संख्या बेहतर जागरूकता, सुलभता और जनसंख्या घनत्व के कारण हो सकती है। जिलों में भिन्नता कम रिपोर्टिंग वाले क्षेत्रों में लक्षित जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को उजागर करती है।

गतिविधियाँ :

नशीली दवाओं के दुरुपयोग जागरूकता पहल

स्कूल के छात्रों में मादक द्रव्यों के सेवन को लेकर बढ़ती चिंता के जवाब में, हेल्पलाइन ने कक्षा VI-X के छात्रों को लक्षित करते हुए एक केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम लागू किया।

उद्देश्य:

- छात्रोंकोमादकपदार्थोंकेसेवनकेहानिकारकप्रभावोंकेप्रतिजागरूककरना।
- स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को बढ़ावा देना।
- नशे की लत वाली चीजों के शुरुआती संपर्क को रोकने के लिए।

प्रमुख गतिविधियाँ:

- विद्यालयस्तरपरआयोजितअभिविन्यासकार्यक्रम।
- क्षेत्रीय भाषा में जागरूकता सामग्री का वितरण।
- रैलियों का आयोजन और सामुदायिक सहभागिता संबंधी पहल।
- छात्रों और अभिभावकों के लिए परामर्श सत्र।

निरीक्षणात्मक विषय :

- शैक्षणिकफोकसमेंगिरावट.
- व्यवहारमेंबदलावजैसेचिड़चिड़ापनऔरगोपनीयता।
- अनियमितउपस्थितिऔरपढ़ाईसेविमुखता।



(नशे सेवन के दुष्परिणाम के बारे में सचेतनता रैली, सरकारी हाईस्कूल, शेरगढ़)



(नागाबस्त नोडाल हाईस्कूल, निमापड़ा, पुरी)



(सरकारी यूजीएचएस, कृष्णछाई, शेरगढ़, गंजाम)

राज्य भर के विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में स्कूल स्टूडेंट हेल्पलाइन एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। पहुँच और विस्तार के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार की गुंजाइश अभी भी है। निरंतर प्रयासों, रणनीतिक हस्तक्षेपों और बेहतर समन्वय के साथ, हेल्पलाइन विद्यार्थियों के कल्याण में सुधार और समग्र शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

14. टीई एवं एसईसीआरटी

यह व्यापक रिपोर्ट शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान ओडिशा में समग्र शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, 30 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) और 4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (बीआईईटी) द्वारा आयोजित प्रमुख शैक्षणिक, शिक्षणशास्त्रीय और क्षमता निर्माण गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल (एफएलएन) को सुदृढ़ करना, मूल्यांकन गतिविधियाँ, नवीन शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम), एफएलएन और अन्य विषयों पर शिक्षकों के संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठकें, ई-सामग्री का विकास, शिक्षण पद्धतियाँ, डीआईईटी-सीआरसी संपर्क तंत्र और अन्य पहलुओं पर केंद्रित हैं।

2025-26 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के 30 डीआईईटी और 04 बीआईईटी में संकाय सदस्यों के वेतन, कार्यक्रम और गतिविधियों, वार्षिक अनुदान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी सहायता, मूल्यांकन और एससीईआरटी, डीआईईटी और बीआईईटी के लिए दीक्षा के लिए नीचे उल्लिखित बजट को मंजूरी दी।

गतिविधि का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	उपयोग किए गए धनराशि (लाखों में)
वेतन	2518.7037	2518.7037
कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ	685	675.62168
वार्षिक अनुदान	655	652.27129958
प्रौद्योगिकी सहायता	84	82.1134158
आकलन	10	10
दीक्षा	8	8
अनुसंधान	128	125.76839
कुल	4088,7073	4072.478485

समग्र शिक्षा, 2025-26 के अंतर्गत एससीईआरटी, डीआईईटी और बीआईईटी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(क)मूल्यांकन (एससीईआरटी)

1. प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन पर शिक्षक पुस्तिका का विकास

कक्षा मूल्यांकन पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए, तकनीकी शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा संस्थान (एससीईआरटी) ने प्रक्रिया-आधारित मूल्यांकन पर एक शिक्षक पुस्तिका विकसित की है। यह पुस्तिका शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी मूल्यांकन लागू करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह पुस्तिका डीआईईटी संकाय और सीआरसीसी के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। डीआईईटी ने सीआरसीसी को प्रक्रिया-आधारित मूल्यांकन पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया है।



2.परखराष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024 की रिपोर्ट के प्रसार पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन



परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024 रिपोर्ट के प्रसार पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला 25 जुलाई 2025 को आरआईई भुवनेश्वर के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य पीआरएस 2024 के प्रमुख निष्कर्षों को साझा करना, राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध ओडिशा के प्रदर्शन का आकलन करना और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सहायता करना था।

3. परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट के प्रसार और जिला-विशिष्ट कार्य योजना के विकास पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का संचालन



पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024 की रिपोर्ट के प्रसार पर क्षमता निर्माण कार्यशाला अगस्त 2025 में एससीईआरटी, ओडिशा के सम्मेलन कक्ष में तीन चरणों में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को समझना, मुख्य शिक्षण अंतर्दृष्टियों, छात्रों के औसत प्रदर्शन में रुझानों पर ध्यान केंद्रित करना, मूल्यांकन डेटा की व्याख्या करना, सीखने की कमियों का विश्लेषण करना और जिले में शक्तियों या आवश्यकताओं की पहचान करना है। साथ ही, पीआरएस के निष्कर्षों से प्राप्त कमियों को दूर करने और शक्तियों का लाभ उठाने के लिए जिले-विशिष्ट, डेटा-आधारित कार्य योजनाएं तैयार करना भी इसका उद्देश्य है।

4. स्कूली शिक्षा के तीनों चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) का संशोधन



स्कूली शिक्षा के तीनों चरणों के लिए मौजूदा एचपीसी (स्वास्थ्य प्रदर्शन मानदंड) को संशोधित करने के लिए 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पारख (PARAKH) और एनसीईआरटी द्वारा विकसित एचपीसी, स्कूलों में एचपीसी के उपयोग पर 6500 शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और अन्य राज्यों द्वारा विकसित एचपीसी का विश्लेषण किया गया। 16 से 18 दिसंबर तक तीन दिवसीय समीक्षा कार्यशाला आयोजित की गई और एचपीसी को अंतिम रूप देकर मुद्रण के लिए ओएसईपीए (OSEPA) को प्रस्तुत किया गया।

5. कक्षा V और VIII की वार्षिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन ढांचा विकसित करना



विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा के लिए एक व्यापक मूल्यांकन ढांचा तैयार करने हेतु 6 और 7 नवंबर 2025 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों, डीआईईटी संकाय, शिक्षकों और ओएसईपीए ने भाग लिया।

6. कक्षा V और VIII की वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक का विकास



नवंबर माह के दौरान दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं (17 से 21 नवंबर और 26 से 29 नवंबर) जिनका उद्देश्य मूल्यांकन रूपरेखा के अनुरूप कक्षा 5 और 8 के विभिन्न विषयों के लिए प्रश्न बैंक तैयार करना था। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ, डीआईईटी संकाय, शिक्षक और ओएसईपीए ने भाग लिया।

7. कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नों का विकास



मूल्यांकन रूपरेखा के आलोक में सभी विषयों में अभ्यास प्रश्नों के दो सेट विकसित किए गए और स्कूलों के बीच वितरण के लिए ओएसईपीए को प्रस्तुत किए गए।

8. एचपीसी के उपयोग पर शिक्षक मार्गदर्शिका का विकास:



फरवरी और मार्च में आयोजित कार्यशाला के दौरान समग्र प्रगति कार्ड के उपयोग पर शिक्षक पुस्तिका विकसित और अंतिम रूप दी गई।

9. जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एफएलएस 2026 पर अभिविन्यास कार्यक्रम का संचालन।

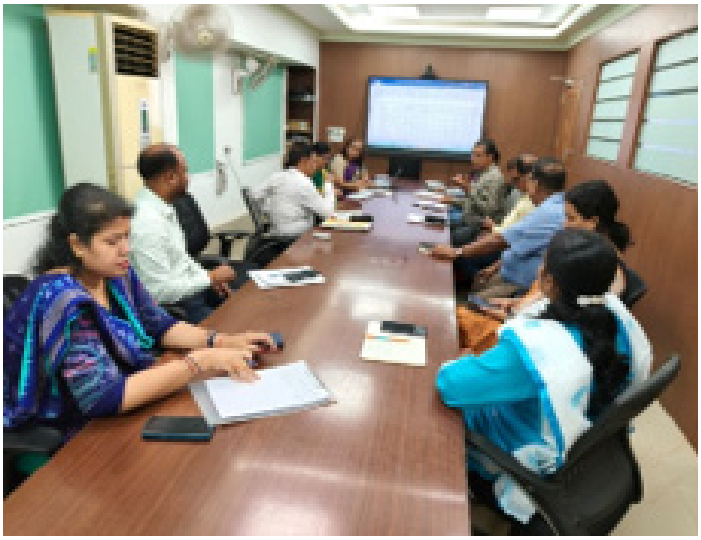
भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के सम्मेलन कक्ष में

31.03.2026 को एफएलएस पर एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 30 जिलों के 60 प्रतिभागियों के साथ-साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल हुए।

10. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक एफएलएन मूल्यांकन अध्ययन पर तैयारी बैठक का आयोजन



11 .वार्षिक एफएलएन मूल्यांकन अध्ययन 2025-26 की तैयारी के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना और उसे सुव्यवस्थित करना था। प्रमुख हितधारकों ने मूल्यांकन ढांचे, उपकरणों, नमूनाकरण और कार्यान्वयन समयसीमा पर चर्चा की। बैठक में प्रक्रियाओं के मानकीकरण, क्षेत्रीय कर्मियों के प्रशिक्षण और डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित की गईं और रसद एवं निगरानी संबंधी पहलुओं की भी समीक्षा की गई।



12. समग्र प्रगति कार्डों के उपयोग पर प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास पर कार्यशाला का आयोजन

विद्यालय शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थान (डीटीई एवं एससीईआरटी) के सम्मेलन कक्ष में विद्यालयों में मूल्यांकन पद्धतियों को सुदृढ़ करने हेतु समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) के उपयोग पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों और शिक्षक प्रशिक्षकों को एक साथ लाया गया।

मॉड्यूल को सहयोगात्मक रूप से डिज़ाइन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रशिक्षण सामग्री को योग्यता-आधारित मूल्यांकन सिद्धांतों के अनुरूप बनाना और छात्रों के समग्र विकास पर नज़र रखने के लिए एचपीसी (होलीस्टिक प्रोग्रेस कार्ड) का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इस कार्यशाला के दौरान होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के उपयोग पर दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया।



मूल्यांकन (DIETs)

पोस्ट परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण गतिविधियाँ

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा के ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस-2024) रिपोर्ट कार्ड पर बहु-चरणीय ज़िला और ब्लॉक-स्तरीय अभिविन्यास एवं प्रसार कार्यशालाओं का आयोजन किया, ताकि डेटा-आधारित शैक्षिक योजना को सुदृढ़ किया जा सके और अधिगम परिणामों में सुधार किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र स्तर के प्रमुख हितधारकों - जिनमें एडीईओएस, बीईओएस, एबीईओ, ज़िला संसाधन समूह (डीआरजी) और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक (सीआरसीसी) शामिल हैं - को मूल्यांकन निष्कर्षों का विश्लेषण करने, अधिगम अंतरालों की पहचान करने और लगभग 3000 सबसे कमज़ोर शैक्षिक दक्षताओं को लक्षित करने के बारे में जागरूक करना था। सभी 30 ज़िलों के प्रशासकों और शैक्षणिक सलाहकारों ने ज़िला रिपोर्ट कार्डों की व्याख्या करने और ब्लॉक-स्तरीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए गहन बहु-चरणीय सत्रों में भाग लिया। सूचित निर्णय लेने और लक्षित विद्यालय-स्तरीय हस्तक्षेपों के लिए मूल्यांकन साक्ष्यों का लाभ उठाकर, ये कार्यशालाएँ अधिगम अंतरालों को पाटने और राज्य भर में शैक्षिक मानकों को ऊपर उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती हैं।





• मुख्यउद्देश्य:

• PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण के परिणामों के बारे में शैक्षिक हितधारकों को जागरूक करें और छात्रों के सीखने की कमियों का पता लगाएं।

• लक्षित शैक्षणिक हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए सबसे कम प्रदर्शन करने वाली दक्षताओं की पहचान करें।

• मूल्यांकनडेटाकोव्यावहारिककक्षारणनीतियोंमेंपरिवर्तितकरकेनिरंतरसीखनेकीप्रगतिसुनिश्चितकरें।

• जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर कम प्रदर्शन करने वाली दक्षताओं (कम प्रदर्शन वाली क्षमताओं) में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करें।



(ख) एफएलएन गतिविधि (एससीईआरटी)

1. एनईपी 2020 के अनुसार, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 2027 तक एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीई एवं एससीईआरटी निदेशालय ने मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक के लिए जून 2026 से मार्च 2027 तक नौ प्रकार की सामग्री विकसित की है।

प्रत्येक माह डीआईईटी के प्रधानाचार्यों और संकाय सदस्यों के साथ सामग्री साझा की जाती है। डीआईईटी संकाय सदस्य सीआरसीसी को उस विषयवस्तु के बारे में जानकारी दी गई है जिसके आधार पर वे स्तरीय बैठक का नेतृत्व करेंगे।

2.बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) के लिए चौथी राज्य संचालन समिति की बैठक का आयोजन राज्य में एफएलएन कार्यक्रम की गतिविधियों की समीक्षा करने और एफएलएन कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु आयुक्त-सह-सचिव, विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग, ओडिशा, बीबीएसआर की अध्यक्षता में 26.09.2025 को किया गया।

एफएलएन गतिविधियाँ (डीआईईटी)

मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठकें (एमसीएम) और डीआईईटी-सीआरसी संपर्क

समग्र शिक्षा 2025-26 के अंतर्गत, ओडिशा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने डीआईईटी-सीआरसी संबंधों को सुदृढ़ करने और शिक्षकों के लिए एक सशक्त शैक्षणिक सहायता प्रणाली स्थापित करने हेतु मासिक क्लस्टर बैठक (एमसीएम) की विषयवस्तु के प्रसार पर कई अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान, डीआईईटी ने क्लस्टर और विद्यालय स्तर पर शिक्षण रणनीतियों के एकसमान प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों (सीआरसीसी) के लिए नियमित रूप से 9 मासिक एमसीएम अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) का कार्यान्वयन, सिख्यना सोपान रजिस्टर के माध्यम से दर्ज की जाने वाली संरचित 120-मिनट और 90-मिनट की कक्षा गतिविधियाँ, पाठ योजना निर्माण (सिख्यना प्रस्तुति कार्यक्रम), कक्षा अवलोकन उपकरण (सीओटी), योगात्मक मूल्यांकन विश्लेषण, निपुन स्कूल पहल और उपस्थिति मानक संचालन (एसओपी) शामिल थे। विभिन्न समूहों में साझा शिक्षण और अकादमिक मार्गदर्शन को सुगम बनाकर, इन कार्यक्रमों ने सीआरसीसी को कक्षा प्रथाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने, समूह-स्तरीय शिक्षण योजना को बढ़ाने और राज्यव्यापी शिक्षक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सफलतापूर्वक सशक्त बनाया।

मुख्य उद्देश्य:

- शिक्षकोंकीप्रभावीक्षमतानिर्माणऔरकक्षामेंमार्गदर्शनकेलिएसीआरसीऔरसीआरसीसीकोआवश्यकशैक्षणिकउपकरणोंसेलैसकरें।
- राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण सामग्री और पाठ योजना का समान रूप से प्रसार सुनिश्चित करना।
- सिखियाना सोपान और कक्षा अवलोकन उपकरण (सीओटी) के माध्यम से एफएलएन कक्षा लेनदेन (120 मिनट / 90 मिनट) और मूल्यांकन ट्रैकिंग के संरचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।





जिला स्तरीय टीएलएम प्रदर्शनियाँ (2025-26)

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने परिणाम-आधारित शिक्षण सहायक सामग्री को बढ़ावा देने और रचनात्मक शिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) प्रदर्शनियों का आयोजन किया। एक दिवसीय प्रदर्शनियों ने शिक्षकों, क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों (सीआरसीसी) और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) और गैर-एफएलएन दोनों स्तरों को कवर करने वाली बहुआयामी शिक्षण सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य किया। शिक्षण प्रभावशीलता को मजबूत करने के उद्देश्य से, इस पहल ने शिक्षकों को अधिगम परिणामों (एलओ) के अनुरूप शिक्षण सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कक्षा में उपयुक्त शिक्षण सामग्री के एकीकरण पर जोर दिया। कम लागत वाली और गतिविधि-आधारित शिक्षण सामग्री के बहुआयामी अनुप्रयोगों के प्रति प्रमुख शैक्षणिक पदाधिकारियों को जागरूक करके, इन प्रदर्शनियों ने सफलतापूर्वक अनुभवात्मक अधिगम को सुदृढ़ किया और राज्य भर में प्रारंभिक बचपन एवं प्राथमिक शिक्षा पद्धतियों को मजबूत किया।





मुख्य उद्देश्य:

अधिगम परिणाम (एलओ) आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) की तैयारी और उपयोग को प्रोत्साहित करें।

शिक्षकों को रचनात्मक विचारों और नवीन शिक्षण उपकरणों को साझा करने के लिए एक सहयोगात्मक मंच प्रदान करना।

उपयुक्त शिक्षण विधियों (टीएलएम) के कार्यात्मक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और कक्षा शिक्षण में उनके सक्रिय उपयोग को सुनिश्चित करें।

(ग) दीक्षा (एससीईआरटी)

1. अंतःक्रियात्मक ई-सामग्री के विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ



ओडिशा के एस.सी.ई.आर. के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने जनवरी 2025 के दौरान दो चरणों में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर के डी.आई.टी. और बी.आई.टी. के शिक्षकों के डिजिटल सामग्री विकास कौशल को मजबूत करना था। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मास्टर प्रशिक्षकों को कक्षा प्रथम से आठवीं तक के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इंटरैक्टिव ई-सामग्री को डिजाइन और विकसित करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से सशक्त बनाना था। कई व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों को डिजिटल शिक्षण पद्धति, अनुदेशात्मक डिजाइन सिद्धांत, मल्टीमीडिया एकीकरण, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस निर्माण और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों/सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई।

2. TE और SCERT ने PM ई-विद्या चैनलों के लिए 500 ई-पाठ विकसित



ओडिशा के एससीईआरटी के आईसीटी सेल ने विभिन्न डीआईईटी के मास्टर ट्रेनर्स और फैकल्टी सदस्यों के सहयोग से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सफलतापूर्वक 500 उच्च गुणवत्ता वाले ई-पाठ विकसित किए हैं।
पूर्ण किए गए ई-पाठों को एससीईआरटी ओडिशा द्वारा प्रबंधित पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल 138 और 139 के कंटेंट पूल में एकीकृत कर दिया गया है।

मार्च 2025 से मासिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इन डिजिटल पाठों का नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों सहित राज्य भर के छात्रों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो रही है।



3. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, एससीईआरटी ओडिशा द्वारा पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल 138 और 139 का प्रबंधन

ओड़िशा राज्य के शिक्षा विभाग (एससीईआरटी) को पीएम

ई-विद्या डीटीएच चैनल 138 और 139 के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो राज्य भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। दोनों चैनल एससीईआरटी ओडिशा के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के समन्वय और तकनीकी सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ नियमित रूप से मासिक प्रसारण कार्यक्रम तैयार करता है, जिससे कक्षावार और विषयवार ई-सामग्री की व्यवस्थित योजना सुनिश्चित होती है।



4. टीईएवं एससीईआरटी ने डीआईईटी, बीआईईटी और ईटीईआई की 62 वेबसाइटों को नया रूप दिया है, विकसित किया है और अपग्रेड किया है।

ओड़िशा राज्य के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग (एससीईआरटी) के आईसीटी सेल ने राज्य भर में डीआईईटी, बीआईईटी और ईटीईआई के लिए 66 अलग-अलग वेबसाइटों का सफलतापूर्वक विकास और पुनर्रचना की है। सभी वेबसाइटें जुलाई 2025 में लॉन्च की गईं। ये वेबसाइटें एससीईआरटी ओडिशा की मूल वेबसाइट के एकीकृत ढांचे के तहत बनाई गई हैं, जिससे सभी हितधारकों के लिए एकरूपता, सुगम पहुंच और आसान नेविगेशन सुनिश्चित होता है।

पुनर्रचित वेबसाइटों में शैक्षणिक गतिविधियों, संकाय विवरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रकाशन, निविदाएं, डाउनलोड और अन्य आवश्यक अपडेट सहित अद्यतन संस्थागत जानकारी शामिल है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक वेबसाइट आधुनिक डिजाइन मानकों, प्रतिक्रियाशील लेआउट, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस और संरचित सामग्री संरचना का पालन करती है।

डीआईईटीएस द्वारा आयोजित दीक्षा संबंधी गतिविधियाँ

बुनियादी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल पर सशक्तिकरण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा भर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने डिजिटल एकीकरण, नवीन शिक्षण विधियों और आदर्श शिक्षण वातावरणों के माध्यम से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल (एफएलएन) को सुदृढ़ करने हेतु लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप किए। डीआईईटी ने एफएलएन



शिक्षकों के लिए बुनियादी आईसीटी कौशल पर बहु-चरणीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जा सके। पाठ्यक्रम में मूलभूत कंप्यूटर संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस वर्ड), डेटा प्रबंधन (एमएस एक्सेल), प्रस्तुति निर्माण (एमएस पॉवरपॉइंट), ग्राफिक डिजाइन (पोस्टर और बैनर) और गूगल फॉर्म्स और शीट्स जैसे डिजिटल मूल्यांकन उपकरण शामिल थे। साथ ही, एफएलएन मॉडल कक्षाओं, समर्पित डीआईईटी प्रयोगशाला प्रदर्शन विद्यालयों सहित जिलों में आदर्श एफएलएन अवसंरचना स्थापित की गई, और रेत के गड्ढे, मुद्रित सामग्री से भरपूर वातावरण और विशेष एफएलएन कॉर्नर वाले बहु-संवेदी शिक्षण स्थान बनाए गए। इसके अतिरिक्त, लर्निंग आउटकम (एलओ) आधारित पाठ योजनाओं, नियमित मासिक कक्षा निगरानी और राज्यव्यापी ब्लॉक-स्तरीय अभिनव शिक्षण प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए क्यूआर-स्कैनर बिल्डिंग ब्लॉक एप्लिकेशन और दीक्षा पोर्टल जैसे डिजिटल उपकरणों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया गया था।

मुख्य उद्देश्य:

- प्राथमिकस्तरकेशिक्षकोंमेंबुनियादीसूचनाएवंसंचारप्रौद्योगिकी (आईसीटी) दक्षताविकसितकरेंताकिवेकक्षामेंहोनेवालेलेन-देनकेलिएप्रौद्योगिकीकालाभउठासकें।
- सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पद्धतियों को प्रदर्शित करने के लिए एफएलएन मॉडल क्लासरूम और प्रयोगशाला प्रदर्शन विद्यालयों की स्थापना करें।
- पाठ योजनाओं, मुद्रित सामग्री से भरपूर वातावरण और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ संरेखित अधिगम परिणाम (एलओ) को अपनाने को बढ़ावा दें।



डिजिटल शिक्षण संसाधनों और ई-सामग्री का विकास

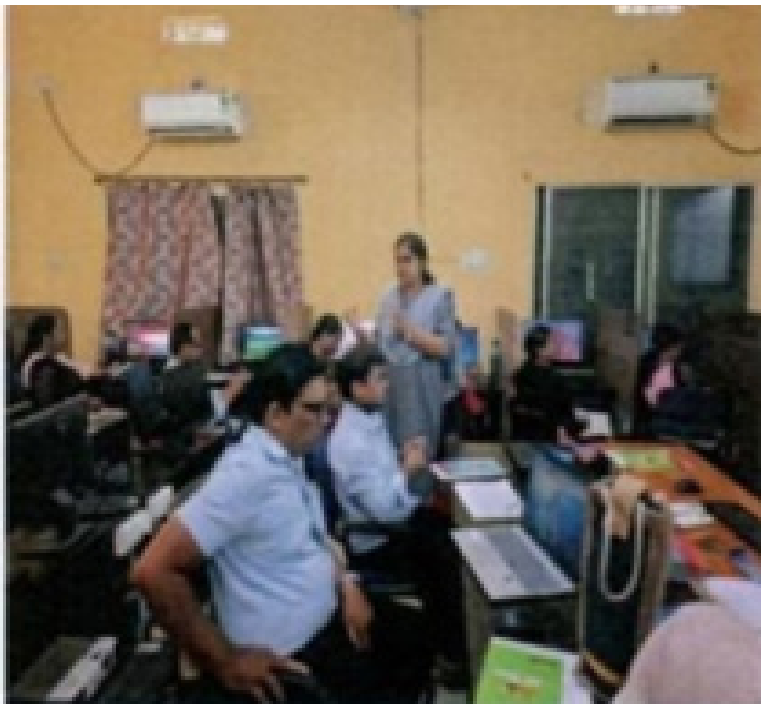
समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने डिजिटल भंडारों का विस्तार करने और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण विधियों को स्कूली शिक्षा में एकीकृत करने के लिए लक्षित ई-सामग्री विकास पहलों को क्रियान्वित किया। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक, विभिन्न शैक्षिक चरणों के अनुरूप डिजिटल



शिक्षण सामग्री को डिजाइन करने, उसकी समीक्षा करने और उसे परिष्कृत करने के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आधारभूत स्तरों के लिए, डीआईईटी ने शिशु वाटिका एफएलएन ढांचे के अनुरूप संस्कृति और भाषा के प्रति संवेदनशील डिजिटल संसाधन विकसित किए, जिनमें इंटरैक्टिव वर्कबुक, एनिमेटेड कहानी सुनाना और खेल-खेल में क्रियात्मक गीत शामिल हैं। उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए, प्रौद्योगिकी-एकीकृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कक्षा VIII के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में डिजिटल सामग्री तैयार की गई। 500 से अधिक ई-सामग्री तैयार की गई, विषय विशेषज्ञों द्वारा उसकी समीक्षा की गई और ओडिशा के तकनीकी एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत की गई, साथ ही शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए राज्यव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए YouTube जैसे आधिकारिक सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर अपलोड की गई।

- मुख्यउद्देश्य:
- मिश्रितऔरप्रौद्योगिकी-आधारितशिक्षणपद्धतिकासमर्थनकरनेकेलिएउच्चगुणवत्तावाली, पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षण सामग्री का एक डिजिटल भंडार बनाएं।
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) के लिए स्थानीयकृत, संस्कृति-संवेदनशील डिजिटल संसाधन विकसित करें।
- इंटरैक्टिव मीडिया, एनिमेटेड स्टोरीटेलिंग और डिजिटल अंग्रेजी भाषा मॉड्यूल के माध्यम से सीखने के परिणामों को बेहतर बनाएं।





तकनीकी सहायता और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा भर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) दक्षताओं को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी-आधारित शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सक्षम बनाने के लिए तकनीकी सहायता का लाभ उठाया। डीआईईटी नेप्रौद्योगिकी-आधारित शैक्षिक सर्वेक्षणों, डिजिटल मूल्यांकनों, डेटा प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री एवं मल्टीमीडिया शिक्षण संसाधनों के निर्माण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बुनियादी स्तर पर डिजिटल साक्षरता विकसित करने के लिए, एफएलएन शिक्षकों के लिए बुनियादी आईसीटी कौशल पर विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाठ्यक्रम में कंप्यूटर की मूल बातें, दस्तावेज़ प्रसंस्करण (एमएस वर्ड), डेटा प्रबंधन (एमएस एक्सेल), प्रस्तुति डिजाइन (एमएस पॉवरपॉइंट), पोस्टर/बैनर निर्माण और मूल्यांकन डिजाइन के लिए गूगल शीट्स जैसे डिजिटल टूल अनुप्रयोगों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, डीआईईटीएस ने राज्य भर में शैक्षणिक गतिविधियों को संग्रहित और प्रसारित करने के लिए डिजिटल प्रलेखन प्रणालियों की स्थापना के साथ-साथ दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसे डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा दिया।

मुख्य उद्देश्य:

- प्राथमिकस्तर (एफएलएन) केशिक्षकोंमेंडिजिटलसाक्षरताऔरमूलभूतकंप्यूटरदक्षताओंकाविकासकरना।
- शैक्षणिक सर्वेक्षणों, मूल्यांकन ट्रैकिंग और शैक्षिक योजना में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करें। डेटा-संचालित
- DIKSHA जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से भंडार, डिजिटल ई-सामग्री और मल्टीमीडिया शिक्षण उपकरण विकसित करें और उनका प्रसार करें।

जिला स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन, बहुभाषी सामग्री विकास

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने जिला सेमिनारों के माध्यम से सर्वोत्तम नवीन शिक्षण रणनीतियों को साझा करके, बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) संसाधन विकास और आधारभूत स्तर के हस्तक्षेपों (शिशु वाटिका और जादू पिटारा/कुहुका पेड़ी) द्वारा कक्षा अभ्यासों में सुधार लाने के लिए एकीकृत शैक्षणिक पहलों को क्रियान्वित किया। आदिवासी क्षेत्रों में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कोया और बोंडा जैसी स्थानीय भाषाओं में प्रासंगिक शिक्षण सामग्री विकसित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। लघु कथाओं, पारंपरिक कविताओं, पहेलियों, खेलों और स्थानीय तुकबंदियों से युक्त ये सामग्रियाँ आधारभूत स्तर के आदिवासी शिक्षार्थियों के लिए भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हुईं। साथ ही, डीआईईटी ने समर्पित बालबाटिका प्रयोगशाला और प्रयोगशाला विद्यालय स्थापित किए, जहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, प्राथमिक शिक्षकों और बच्चों के लिए आनंददायक शिक्षण तकनीकों का अभ्यास करने और टीएलएमएमएस को कक्षा की गतिविधियों के साथ संरेखित करने हेतु साप्ताहिक शनिवार को एक्सपोजर सत्र आयोजित किए गए। खेल एकीकरण, प्रक्रिया-आधारित मूल्यांकन और दक्षता-आधारित मूल्यांकन जैसे नवीन शिक्षण विधियों पर जिला स्तरीय शैक्षणिक सेमिनारों द्वारा इन पहलों को और भी बल दिया गया।इन प्रयासों ने ओडिशा भर में एक मजबूत, समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित शैक्षिक ढांचा तैयार किया है।

मुख्य उद्देश्य:

- शिक्षकों, सीआरसीसी और शैक्षिक हितधारकों के बीच नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने की क्षमता का निर्माण करना।
- साथियों के बीच ज्ञान साझाकरण, सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रसार को सुगम बनाना।

कक्षा में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन करें। सतत शैक्षणिक कार्ययोजना विकसित करें।

- शिक्षार्थी-केंद्रित, गतिविधि-आधारित शिक्षा के लिए।

बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) और जनजातीय संदर्भ:

- उद्देश्य:आदिवासीजिलोंमेंभाषाईविविधताऔर सीखनेकीबाधाओंकोदूरकरनेकेलिएस्वदेशीमातृभाषासामग्रीविकसितकरना।
- मुख्य परिणाम: कहानी की किताबें, खेल आदि का निर्माण।बुनियादी शिक्षार्थियों के लिए कोया और बोंडा भाषाओं में पहेलियाँ और कविताएँ, ताकि वे राज्य भाषा की साक्षरता में आसानी से प्रवेश कर सकें।



सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा (SEEL) पर पुनरावलोकन कार्यक्रम



समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ओडिशा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा (एसईईएल) पर विशेष रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित किए। तीन दिवसीय रिफ्रेशर सत्रों का उद्देश्य आत्म-जागरूकता, सहानुभूति और शिक्षकों को अपने छात्रों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने के लिए सशक्त बनाना था। मूलभूत जीवन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस पहल ने शिक्षकों और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों (सीआरसीसीएस) को शिक्षार्थियों में आत्म-करुणा, भावनात्मक लचीलापन और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की रणनीतियों से सुसज्जित किया। सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा को दैनिक कक्षा गतिविधियों में शामिल करके, इन कार्यशालाओं ने राज्य भर में सहायक और समावेशी विद्यालय वातावरण स्थापित करने में मदद की।

मुख्य उद्देश्य:

- सभीशैक्षिकस्तरोंपरछात्रोंकेबीचसामाजिक, भावनात्मक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना।
- शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से दृढ़तापूर्वक निपटने के लिए आवश्यक जीवन कौशल और सामना करने के तंत्र से लैस करना।
- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उनमें आत्म-जागरूकता और आत्म-करुणा विकसित करें।

(ई) गैर-आवर्ती अनुदान का उपयोग

नए सम्मेलन भवन और 3सेल की नींव रखी गई





ओडिशा सरकार के विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री नित्यानंद गोंड ने 5 फरवरी, 2026 को भुवनेश्वर स्थित शिक्षा एवं शिक्षा निदेशालय के परिसर में 3.22 करोड़ रुपये के बजट से निर्मित नए भवन की आधारशिला रखी। इस भवन में एक सम्मेलन कक्ष और तीन समर्पित प्रकोष्ठ (एफएलएन, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम) होंगे। यह पहल राज्य में शैक्षणिक योजना, मूल्यांकन प्रणाली और मूलभूत शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर शिक्षा एवं शिक्षा निदेशालय के सचिव डॉ. एन. थिरुमाला नाइक और निदेशक उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि ओडिशा में नव-परीक्षा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न पहल और दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।

निष्कर्ष

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यान्वित गतिविधियाँ ओड़िशा भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए व्यापक और समन्वित प्रयासों को दर्शाती हैं। डीआईईटी द्वारा शुरू की गई पहलों का मुख्य उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) में सुधार करना, मूल्यांकन पद्धतियों को सुदृढ़ करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, नवीन शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना और डीआईईटी-सीआरसी समन्वय, पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के परिणामों के विश्लेषण और सुधार हेतु कार्य योजना तैयार करने, जिला स्तरीय सेमिनार आदि के माध्यम से प्रभावी शैक्षणिक सहायता प्रणाली विकसित करना था। इन कार्यक्रमों के द्वारा राज्य भर में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है।

कुल मिलाकर, समन्वित प्रयास ओड़िशा में योग्यता-आधारित, समावेशी, प्रौद्योगिकी-सक्षम, अनुभवात्मक और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा की दिशा में एक मजबूत प्रगति को दर्शाते हैं। डीआईईटीएस, सीआरसीएस, शिक्षकों, शैक्षणिक पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय इन पहलों के कार्यान्वयन को और मजबूत कर सकता है और राज्य भर में छात्रों के समग्र विकास और सीखने के परिणामों में सुधार में योगदान दे सकता है, साथ ही विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए उपयुक्तता भी सुनिश्चित कर सकता है। वीडियो पाठों का मूल्यांकन विषयवस्तु की गुणवत्ता, प्रस्तुति, सहभागिता और शिक्षण प्रभावशीलता के आधार पर किया गया।

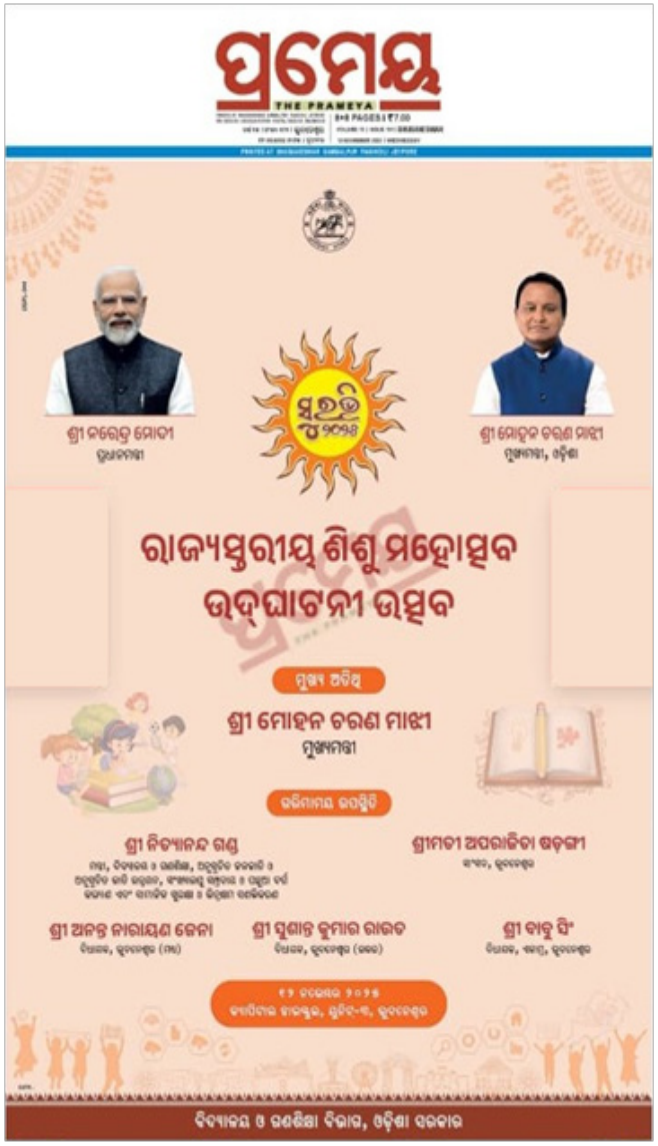
15. प्रिंट मीड़िया की एक झलक .....











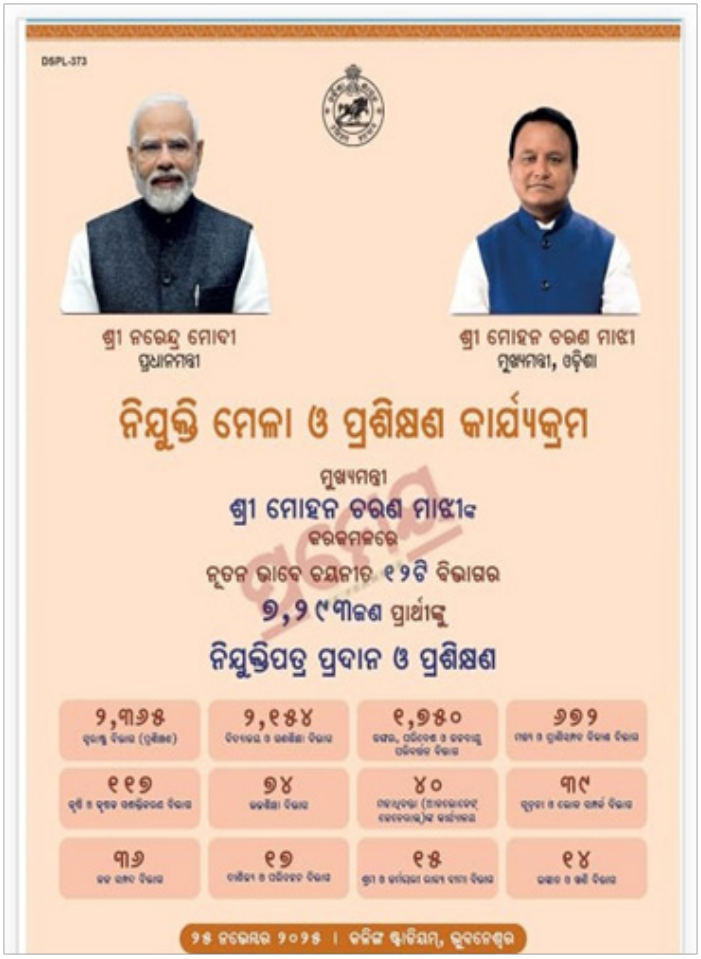


ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ 'ସୁରଭି' ଉଦ୍‌ଘାଟିତ

ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ

- ବଜେଟର ୧୪.୨% ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି
- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଟପର୍‌କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ





DSPL-373

ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ
ଜରଜମଜରେ
ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନୀତ ୧୨ଟି ବିଭାଗର
୭,୨୯୩ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

୨,୩୬୫	୨,୧୫୪	୧,୭୫୦	୬୭୨
୧୧୭	୭୪	୪୦	୩୯
୩୬	୧୭	୧୫	୧୪

୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର



5:23 PM ··· 0.1KB/s

ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଦୁର୍ନୀତି ବିଷ, ଦୂରେଇ ରୁହ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୫।୧୧(ବ୍ୟୁରୋ): ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ୧୭ ମାସରେ ମୋଟ ୩୭ ହଜାର ୩୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର

- ୭୨୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର, ୧୭ ମାସରେ ୩୭ ହଜାର ୩୨୫
- ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ସଂଜଳପତ୍ର ଭାବି ଜନତାଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର

ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବନିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଷ ମନେ କରି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହା କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ



ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର

ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୁଅ

- ୧୪ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ୧୫୪୩ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
- ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ୪୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୩୦।୧୨(ବ୍ୟୁରୋ): ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ସଂଜଳକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୁବ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିର ସାରଥି। ନବନିଯୁକ୍ତମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ୧୫୪୩ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ▸ ଭିତରେ



DSPL-443

ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ
ଜରଜମଜରେ
ନୂତନ ଭାବେ ଚୟନୀତ ୧୨ଟି ବିଭାଗର
୧,୫୪୩ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

୭୫୫	୩୯୬	୩୯୨

୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ । ଜେନ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଲୋକାର୍ପଣ

ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ



ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨୦୦ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ୧୨ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୪ ।୧୧(ବ୍ୟୁରୋ): ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର 'ଲୋଗୋ' ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଲୋଗୋକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଗାମୀ ଚାରି ବର୍ଷ (୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ) ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ୫ ଏକର ଜମି ଓ ଉତ୍ତମଗମନ ସୁବିଧା ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ୫ ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ଲୋଗୋ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରୁଛି। ମହାନ ଶିକ୍ଷବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାରେ ନିପୁଣ କରିବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀକ ବିକାଶ କରାଯିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଏନ. ବିଶ୍ୱନାଥା ନାଏକ, ଓସେପାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ପ୍ରମେୟ | Page 9 | ଦୁନିଆ | Saturday, 1 February 2025

ଯୁବକଙ୍କ ଦାବରଦନ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ

ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ର

ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭୟ ଦୂର କର

- ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବେ
- 'ବଢ଼ଉଚ ଭାରତ'କୁ ଏନ୍ତୁ ବଳାଇ
- ଏବେଠୁ ଚାକିରି ଖିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
- ୧୯ରେ ଚାଲି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

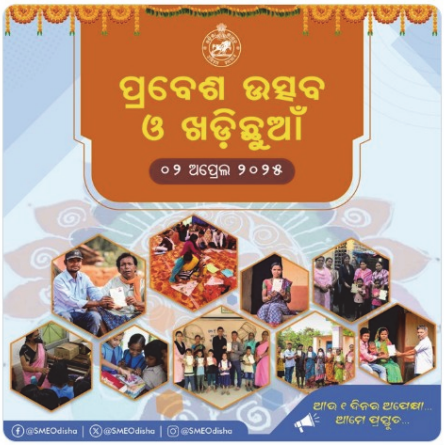


କାଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନର

सामाजिक गणमाध्यम

EducationOdisha @SMEOdisha · Apr 1, 2025

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅପ୍ରେଲ ୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ #ଓଡ଼ିଆପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ।



CMO Odisha @CMO_Odisha · Apr 2, 2025

ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଛୁଆଁଇ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। #ଖଡ଼ିଛୁଆଁ #ଓଡ଼ିଶା #ଓଡ଼ିଆପକ୍ଷ #NEP2020
Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Apr 2, 2025

ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ । ଏହି ମହାର୍ଘ ଅବସରରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।

#ଓଡ଼ିଆପକ୍ଷ୨୦୨୫



EducationOdisha @SMEOdisha · Apr 2, 2025

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। #ଖଡ଼ିଛୁଆଁ #ଶିଶୁବାଟିକା
#MohanMajhi #Odisha #SishuBatika #nep2020

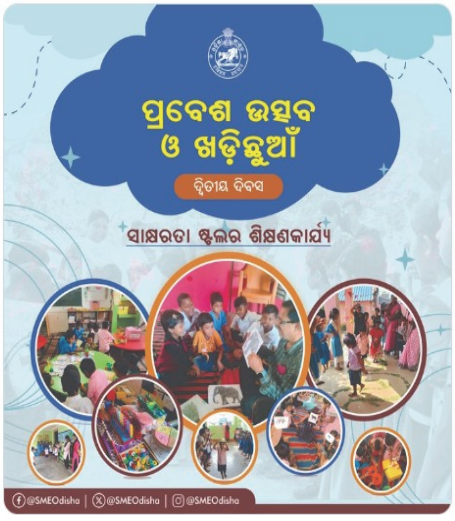
Live:



From voutube.com

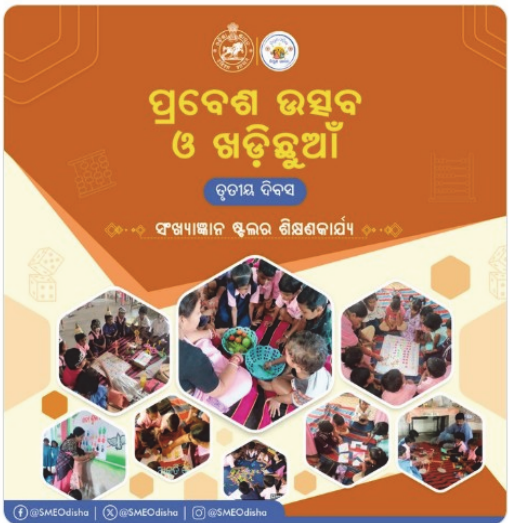
EducationOdisha @SMEOdisha · Apr 3, 2025

ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ - ୨୦୨୫
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସାକ୍ଷରତା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ...
#NEP2020 #literacy



EducationOdisha @SMEOdisha · Apr 4, 2025

ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ-୨୦୨୫
ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷଣକାର୍ଯ୍ୟ ...
#NEP2020 #FLN #NipunOdisha



EducationOdisha @SMEOdisha · Apr 19, 2025

ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ -୨୦୨୫-୨୬ର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ/ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା / ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।



EducationOdisha @SMEOdisha · Jun 5, 2025

Observation of World Environment Day across schools with great enthusiasm and commitment towards a greener future.
#WorldEnvironmentDay2025 #EkPedMaaKeNaam #MissionLiFE #Sustainability #EcoClubs #TreePlantation



EducationOdisha @SMEOdisha · Jun 21, 2025

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ - ୨୦୨୫ ଅବସରରେ "ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ" ପାଇଁ ଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଉଦ୍ଯାହର ସହିତ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି | ଏହି ଦିବସର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ...
#IDY2025 #YogaForOneEarthOneHealth #InternationalDayofYoga2025



EducationOdisha @SMEOdisha · May 17, 2025

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-୨୦୨୫। ମେ ୭ରୁ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେବେ।



EducationOdisha @SMEOdisha · Jun 6, 2025

ଆଜି ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନବ ନିଯୁକ୍ତ ୮୨୭ ଜଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ବା ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ।



EducationOdisha @SMEOdisha · Jul 29, 2025

On the eve of #AkhilBharatiyaShikshaSamagam, aids & appliances distribution and assessment camps were conducted across districts in Odisha, empowering lives through inclusive support.
#InclusiveEducation #Divyangjan #ShikshaSamagam2025



EducationOdisha @SMEOdisha · Aug 8, 2025

The Students of Odisha are Celebrating "Har Ghar Tiranga" activities in schools with fostering a deep sense of Unity & Patriotism. Some of the glimpses of the Celebration....

#HarGharTiranga2025
#harghartirnga



EducationOdisha @SMEOdisha · Aug 14, 2025

With the aim of fostering global exposure and research collaboration, we're proud to share that six brilliant students from Odisha have departed for Japan under the prestigious SAKURA Science Exchange Programme.

#Odisha #Japan #SAKURAProgramme #GlobalLearning



EducationOdisha @SMEOdisha · Aug 16, 2025

ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ତା.୧୬.୦୮.୨୦୨୫ରିଖରେ "ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା" ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପି.ଟି.ଏମ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ।

#AASASCHOOLJIBA



EducationOdisha @SMEOdisha · Sep 5, 2025

On the occasion of the State-level Guru Divas celebration, outstanding teachers were honoured with the Chief Minister's Education Award for their remarkable contributions in the field of education.

#HappyTeachersDay
#EducationAward



EducationOdisha @SMEOdisha · Sep 5, 2025

Replying to @smeodisha

Hon'ble CM Shri Mohan Charan Majhi launched 'ପଢ଼ିବା, ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା', a state-wide reading campaign by @smeodisha to boost reading skills of Class I–VIII students in govt. schools. Campaign Runs Sept '25–Mar '26 with levelled materials.

#PadhibaGadhibaOdisha
#NIPUNOdishaMission



EducationOdisha @SMEOdisha · Sep 5, 2025

Replying to @SMEOdisha

Under the guidance of Hon'ble PM Shri @narendramodi, the National Curriculum Framework (NCF) has been implemented to bring transformative changes in education. Building on this, Odisha launched its State Curriculum Framework (SCF) today.

#EducationOdisha
#NEP2020



EducationOdisha @SMEOdisha · Sep 5, 2025

Replying to @SMEOdisha

Hon'ble CM Shri Mohan Charan Majhi unveiled a Coffee Table Book marking 1 year of #NIPUNOdisha—showcasing its journey, achievements & inspiring stories in strengthening foundational skills of children up to Class III.

#FoundationalLearning
#Literacy
#Numeracy



OSEPA @OSEPA_Official · Oct 24, 2025

The State level Band Competition - 2025 has been inaugurated by Smt. Niyati Pattnaik, IAS, Director, Directorate of Higher Secondary Education (DHSE), at Government Girls' High School, Unit-VI, Bhubaneswar. Some glimpses of the programme...

#BandCompetition #EducationOdisha



OSEPA @OSEPA_Official · Nov 12, 2025

The State-level Model United Nations (MUN) under the PM SHRI Scheme in Odisha was inaugurated by Hon'ble CM in Suravi today.

HCM interacted with all the student-delegates and inspired them with his words.



OSEPA @OSEPA_Official · Oct 22, 2025

The State level Kala Utsav - 2025 has been inaugurated by Smt. Ananya Das, IAS, State Project Director, OSEPA, at Government Girls' High School, Unit-VI, Bhubaneswar. Some glimpses of the programme...

#KalaUtsav #OSEPA #EducationOdisha



EducationOdisha @SMEOdisha · Nov 12, 2025

The State-level Model United Nations (MUN) under PM SHRI scheme was inaugurated today at SURAVI by Hon'ble CM of Odisha, who interacted with participants & encouraged them.

56 students from 29 districts, selected through Model Parliament, are representing different countries.



EducationOdisha @SMEOdisha · Nov 12, 2025

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ 'ସୁରଭି'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

#SURAVI2025



CMO Odisha @CMO_Odisha · Nov 12, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜ୍ୟାପିଗାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ 'ସୁରଭି - ୨୦୨୫' ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।



EducationOdisha @SMEOdisha · Nov 13, 2025

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭିର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଦର୍ଶନ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖବରର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ 'ସୁରଭି ସମ୍ବାଦ'।
#SURAVI2025



You and 7 others

EducationOdisha @SMEOdisha · Jan 7

ରାଜ୍ୟର ୧୧୮ଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ୭ ଜାନୁଆରୀ ବାଣପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ସିଧାପ୍ରସାରଣ:



EducationOdisha @SMEOdisha · Jan 12

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗୌଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"ର ସାମୂହିକ ଗାନ କରିଛନ୍ତି।



EducationOdisha @SMEOdisha · Jan 17

ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ -୨୦୨୫-୨୬ର ୪ର୍ଥ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ/ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକର ବେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ . . .

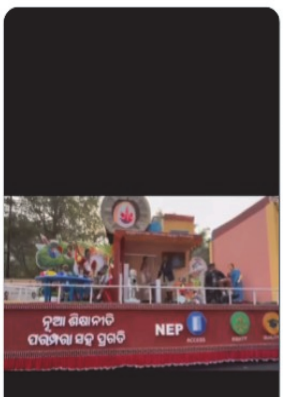


You and 7 others

EducationOdisha @SMEOdisha · Jan 26

On the occasion of the 77th Republic Day of India, the School & Mass Education Department showcased a vibrant tableau at the State-level Republic Day Celebration, 2026, highlighting the theme of PM SHRI Schools.

The tableau reflected key transformative initiatives under the
Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Feb 6

ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଟ୍-୧ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୨ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନବମ ସଂସ୍କରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବେଖିଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପରୀକ୍ଷା

Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Feb 21

'ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା' ଦିବସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ମାତୃଭାଷାରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ପଠନ , ଶପଥ ପାଠ, ଗଳ୍ପ କଥନ ଓ କବିତା ଆବୃତ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଲିଖନ, ବକ୍ତୃତା, ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭାଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପଠନ

Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Feb 27

The two-day National Conference on UDISE+ commenced today in Bhubaneswar, hosted by the School & Mass Education Department, Govt. of Odisha.

Inaugurated by Shri Dheeraj Sahu, Addl. Secy., MoE, the conference brings together senior officials from DoSEL, Samagra Shiksha, KVS,

Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Feb 28

Day 2 of the National UDISE+ Conference in Bhubaneswar focused on best practices and strengthening education data systems.

States shared initiatives to improve data quality and reporting, while representatives from CBSE and other boards emphasised greater alignment.

Dr. N.

Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Mar 19

ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପ୍ରେଲ ୨ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା "ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ" ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର

Show more



EducationOdisha @SMEOdisha · Mar 22

ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପ୍ରେଲ ୨ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା "ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ" ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର

Show more





0674-23955325 www.osepa.odisha.gov.in @osepa_official

@osepa_official OSEPAOFFICIAL